C O N T E N T S

Sixteenth Series, Vol.VIII, Fourth Session, 2015/1936 (Saka)
No.11, Tuesday, March10, 2015/Phalguna 19, 1936 (Saka)

S U B J E C T	P A G E S
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
*Starred Question No.181 to 186	12-68
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
Starred Question Nos. 187 to 200	69-118
Unstarred Question Nos. 2071 to 2300	119-640

* The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

PAPERS LAID ON THE TABLE 641-642

REPORT ON THE PARTICIPATION OF INDIAN PARLIAMENTARY DELEGATION AT THE 130TH ASSEMBLY OF THE INTER-PARLIAMENTARY UNION (IPU) 643

COMMITTEE ON PETITIONS
1st to 3rd Reports 643

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE
13th Report 643-644

SUBMISSION BY MEMBER
Re: Increasing incidents of theft at MPs residences 664

MATTERS UNDER RULE 377 676-695

(i) Need to provide adequate compensation to farmers who suffered damages to their crops due to recent unseasonal rains and hailstorms in the northern region of the country particularly in Ambala Parliamentary Constituency, Haryana
Shri Rattan Lal Kataria 677

(ii) Need to set up a Krishi Vigyan Kendra along river Tapi in Bardoli Parliamentary Constituency, Gujarat
Shri Prabhubhai Nagarbhai Vasava 678

(iii) Need to permit farmers of villages falling under the army camp area in Pulgaon in Wardha Parliamentary Constituency, Maharashtra to utilize their land for earning their livelihood
Shri Ramdas C. Tadas 679

(iv)	Need to formulate policy and programmes to improve the agricultural productivity and income of farmers in the country	
	Shri Rahul Kaswan	680
(v)	Need to consider cultivation of betel leave as an agricultural activity and extend necessary benefits to betel leave growers in Hamirpur Parliamentary Constituency, Uttar Pradesh	
	Kunwar Pushpendra Singh Chandel	681
(vi)	Need to provide subsidy for natural fertilizers	
	Shri P.P. Chaudhary	682
(vii)	Need to organize exhibitions for demonstration and promotion of the achievements of students in the field of science and technology	
	Shrimati Darshana Vikram Jardosh	683
(viii)	Need to ensure active participation of Members of Parliament in planning, execution and monitoring of Centrally sponsored development schemes in the State	
	Shrimati Rama Devi	684
(ix)	Need to provide adequate funds for construction of Gaya-Bodhgaya-Chatra railway line	
	Shri Sunil Kumar Singh	685
(x)	Need to include Jabalpur in the tourist circuit in Madhya Pradesh	
	Shri Rakesh Singh	686

(xi) Need to provide free electricity for operation of motor pumps for supply of drinking water in Chhattisgarh

Shri Tamradhwaj Sahu 687

(xii) Need to allocate funds for gauge-Conversion of railway line between Madurai and Bodinayakkanur and construction of new railway line between Dindigul-Sabarimala

Shri R. Parthipan 688

(xiii) Need to accord approval to the proposal of government of Tamil Nadu for construction of dams at Nallar and Anamalaiar in the State

Shri C. Mahendran 689

(xiv) Need to relax the conditions of eligibility for Indira Gandhi National Disability Pension Scheme

Shri Suvendu Adhikari 690

(xv) Need to release the funds allotted for various flagship schemes meant for Odisha

Shri Bhartruhari Mahtab 691

(xvi) Need to confer rights to Members of Parliament regarding construction of roads under the Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana

Shri Rama Kishore Singh 692

(xvii) Need to revive the closed sugar mills in Bihar and also provide a special package for development of silk industry in Bhagalpur in the State

Shri Kaushalendra Kumar 693

(xviii) Need to set up a AIIMS like institute in Bhagalpur, Bihar

Shri Shailesh Kumar 694

(xix) Need to safeguard the life and livelihood of people living in and around the Bodi area of Western Ghats selected for the proposed India-based Neutrino Observatory

Adv. Joice George 695

STATUTORY RESOLUTION RE: DISAPPROVAL OF RIGHT TO FAIR COMPENSATION AND TRANSPARENCY IN LAND ACQUISITION, REHABILITATION AND RESETTLEMENT (AMENDMENT) ORDINANCE, 2014

AND

RIGHT TO FAIR COMPENSATION AND TRANSPARENCY IN LAND ACQUISITION, REHABILITATION AND RESETTLEMENT (AMENDMENT) BILL , 2015 696-1039

Shri Pralhad Singh Patel 696-699

Shri Gaurav Gogoi 700-701

Shri Ranjit Singh Brahmpura 702-704

Shri H.D. Devegowda 705-716

Shri Dinesh Trivedi 717-721

Shri Chirag Paswan 722-724

Kunwar Bharatendra Singh 725-726

Shri Dushyant Chautala 727-729

Shrimati Anupriya Patel 730-732

Shri Vijay Kumar Hansdak 733-734

Shri Dileep Singh Bhuria 735-736

Shri Thota Narasimham 737-740
Shri Santosh Kumar 741-743
Shri Om Birla 744-745
Shri P.V. Midhun Reddy 746-747
Shri Asaduddin Owaisi 748-750
Shri P.P. Chaudhary 751-752
Shri N.K. Premachandran 753-757
Dr. Ramesh Pokhriyal Nishank 758-759
Shri Raju Shetty 760-761
Shri Ratan Lal Kataria 762-763
Adv. Joice George 764-765
Shri Deepender Singh Hooda 766-770
Shri Nandkumar Singh Chauhan 771-772
Shri Chaudhary Birender Singh 773-1037
Clauses 2 to 12 and 1 812-1037
Motion to pass 1037-1038

ANNEXURE – I

Member-wise Index to Starred Questions 1040
Member-wise Index to Unstarred Questions 1041-1046

ANNEXURE – II

Ministry-wise Index to Starred Questions 1047
Ministry-wise Index to Unstarred Questions 1048

OFFICERS OF LOK SABHA

THE SPEAKER

Shrimati Sumitra Mahajan

THE DEPUTY SPEAKER

Dr. M. Thambidurai

PANEL OF CHAIRPERSONS

Shri Arjun Charan Sethi

Shri Hukmdeo Narayan Yadav

Shri Anandrao Adsul

Shri Prahlad Joshi

Dr. Ratna De (Nag)

Shri Ramen Deka

Shri Konakalla Narayana Rao

Shri Hukum Singh

Shri K.H. Muniyappa

Dr. P. Venugopal

SECRETARY GENERAL

Shri Anoop Mishra

LOK SABHA DEBATES

LOK SABHA

Tuesday, March 10, 2015/Phalguna 19, 1936 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[HON. SPEAKER *in the Chair*]

श्री जय प्रकाश नारायण यादव (बाँका) : अध्यक्ष महोदया, हमने स्वाइन फ्लू पर नोटिस दिया है। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मुझे आपका नोटिस मिला है। मैं आपको बारह बजे बोलने का मौका दूंगी।

11.01 hrs

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

(Q. 181)

श्री राहुल शेवाले: अध्यक्ष महोदया, मैं प्रश्न पूछने से पहले अपनी बात रखना चाहता हूं कि समाज के लिए जो व्यक्ति खतरा है, जिन्हें हम अपराधी कहते हैं, उन्हें हम समाज से अलग जेलों में रखते हैं और यह प्रयास करते हैं कि उनमें सुधार हो। हम उन्हें किसी कार्य में प्रशिक्षित करने का भी प्रयास करते हैं, ताकि बाहर आकर वे कुछ सकारात्मक कार्य कर सकें और उनके जीवन में सुधार हो सके।

माननीय मंत्री जी ने प्रश्न के उत्तर में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा की गयी मॉडल जेल मैनुअल, 2003 को समुचित रूप से संशोधित करने का जिक्र किया है। मैं पूछना चाहता हूं कि उससे कितना काम हुआ है और क्या-क्या सुधार हुआ है?

अध्यक्ष महोदया, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि रिसोर्सफुल लोग कभी मेडिकल ग्राउंड पर तो कभी पारिवारिक दायित्व के नाम पर पैरोल का लाभ उठाते हैं, जैसे महाराष्ट्र में संजय दत्त का केस है। उसमें भी पैरोल का मिसयूज किया गया। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि पैरोल के मिसयूज को रोकने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है?

श्री किरेन रिजीजू : अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य ने कुछ स्पेसीफिक प्रश्न पूछा है। अगर पैरोल का मिसयूज हुआ है तो वहां कोर्ट है। अब जेल का मामला राज्य सरकार के अधीन आता है। किसी स्पेसीफिक मामले में अगर मिसयूज हुआ है तो वह हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। क्योंकि अगर कोर्ट के माध्यम से किसी ने पैरोल का लाभ उठाया है तो मैं उसका जवाब नहीं दे पाऊंगा। लेकिन जहां तक रिफार्म्स का सवाल है तो उस बारे में गृह मंत्रालय की तरफ से समय-समय पर हर राज्य को एडवाइजरी दी जाती है। नैशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की तरफ से हमें जो रिकमेंडेशन्स मिली है, उसे भी हमने राज्य सरकार को सूचित कर दिया है।

श्री राहुल शेवाले: अध्यक्ष महोदया, हमारे मनोवैज्ञानिक और शोध शास्त्री अपराधियों को कुछ श्रेणियों में बांटते हैं, जैसे जो अपने आस-पास के वातावरण के कारण अपराधी बनते हैं, जो किसी परिस्थिति के कारण अपराधी बनते हैं और कुछ मानसिक अपराधी होते हैं, जिनके सुधरने की उम्मीद कुछ कम होती है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि भारतीय जेलों में कुल कितने कैदी हैं और इन कैदियों पर सालाना कितना खर्चा किया जाता है? क्या हम तीसरी श्रेणी को को छोड़कर बाकी श्रेणियों के कैदियों को एक वर्क फोर्स के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि उनका सकारात्मक योगदान रहे?

श्री किरेन रिजीजू : माननीय अध्यक्ष जी, देश में कुल जेल की कैपिसिटी फिलहाल ओवरक्राउडिड है। जेल की जितनी कैपिसिटी है उससे ज्यादा लोग जेल में हैं। हमारी कोशिश है कि जितनी कैपिसिटी है, उसके हिसाब से ही हो। अंडर ट्रायल्स को जरूरत से ज्यादा समय में जेल में न रखा जाए। नैशनल एडवाइज़री कमेटी ऑन लीगल रिफार्म्स का मैं स्वयं सदस्य हूं, इसके माध्यम से हमारी कोशिश है और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसमें डायरेक्शन दी है कि जेल में जो लोग रहें, उनकी देखभाल अच्छी तरह से हो और सही मायने में कानून व्यवस्था का भी प्रावधान हो। हम इसकी भी व्यवस्था कर रहे हैं।

श्री विनायक भाऊराव राऊत: माननीय अध्यक्ष जी, अच्छे इंसानों के हाथों से भी कभी अनजाने में अपराध हो जाते हैं। जब जेल में इस तरह के अपराधी जाते हैं तो बच्चों सहित सारा परिवार प्रभावित होता है। समाज में भी उनकी छवि खराब हो जाती है। ऐसी परिस्थिति में दुर्भाग्य से उनके बच्चों का झुकाव अपराध की ओर हो जाता है। ऐसे अपराधियों के बच्चे भी देश के भविष्य का आधार हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि इनके विकास के लिए क्या सरकार ने कोई प्रावधान किया है? यदि किया है, तो वह क्या है?

श्री किरेन रिजीजू: माननीय अध्यक्ष जी, जेलों का अलग-अलग प्रावधान है। बहुत सी कमेटियों की रिपोर्ट भी आई है। जहां तक बच्चों का सवाल है, खास तौर से महिलाओं और उनके छोटे बच्चों के लिए भी प्रावधान किया गया है। ऐसी बहुत सी व्यवस्था की गई है ताकि बच्चों का मां से रिश्ता बना रहे, मैं माननीय सदस्य को इसकी डिटेल दे सकता हूं। मैं बच्चों की देखभाल और अन्य मसलों से संबंधित उचित कदम उठाने के बारे में सुझाव दे सकता हूं।

SHRI FEROZE VARUN GANDHI: I want to refer the Justice Mulla Committee report on prison reforms 1982-83 which had advocated for the rights, welfare and rehabilitation of our custodial population. It had suggested that a prison management cadre be instituted. So I just want to ask the hon. Minister as to the steps the Government is taking in this regard.

SHRI KIREN RIJIJU: Madam, besides Justice Mulla committee, there is another committee that is Justice Krishna Iyer Committee which had spoken about the issue raised by the hon. Member. As I had mentioned earlier, jail being a State subject, separate cadre if required needs to be instituted but so far what we have observed is that a majority of States and Union Territories have not fully adopted the Prison Manual which we had issued Recently, the National Human Rights Commission had made a series of recommendations based on which the Minister of Home Affairs has also written to States reminding them of the responsibilities and I can assure the hon. Member that the point raised by him will be taken up because these are not being followed strictly by all the States and Union Territories.

श्री गौरव गोगोई: माननीय अध्यक्ष जी, कल ही हमने संसद में चर्चा की थी कि दीमापुर की सैंट्रल जेल में 5,000 युवकों ने कैदी की जेल को तोड़कर बाहर निकाल लिया। यह प्रश्न प्रेजेंट रिफार्म के साथ जुड़ा है। माननीय मंत्री यहां उपस्थित हैं। 5,000 लोगों ने जाकर, मॉब ने जाकर एक व्यक्ति को जेल से छुड़ाकर मारा। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या उन्होंने स्टडी की है कि प्रेजेंट सिक्योरिटी में क्या फेल्योर था? देश में इस तरह की घटनाएं न हों, इसके लिए मंत्रालय जेल में किस तरह का रिफार्म लाएगा? यह घटना क्यों हुई? सिक्योरिटी में क्या लैप्सिस थे? इस तरह की घटना किसी के साथ न हो, इसके लिए मंत्रालय क्या करेगा?

श्री किरेन रिजीजू : माननीय अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य ने अभी पिछली 5 तारीख की घटना के बारे में जिक्र किया है, उस घटना के बारे में मैं डिटेल में तो नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि हमने उसके बारे में रिपोर्ट मांगी है। यह सही बात है कि कम से कम पाँच हजार लोग जेल में गये और अंडर ट्रायल कैदियों को पकड़कर बाहर लाये और पब्लिकली जो घटना हुई है, उसकी जानकारी हम सबको, इस सदन को और पूरे देश को है, लेकिन मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूँ कि कपूर कमेटी, जिसका गठन वर्ष 1986 में हुआ, उसमें स्पेशियली सिक्योरिटी मेज़र्स के बारे में रिक्मेंड किया गया है। जेल में किस तरह का सिक्योरिटी मेज़र्स रखना चाहिए, ताकि वे सिक्योर्ड हों क्योंकि जेल से भागने या फरार होने के केसेज़ भी आते हैं और ऐसी घटना, जो बहुत ही कम होती है, जो मॉब के आने की घटना है, यह हम लोगों के लिए एक बहुत ही विचित्र घटना है कि जेल में इतने लोग घुसकर कैदी को बाहर लेकर आ सकते हैं। उसके बारे में कार्रवाई तो की गई है। वहाँ के डिप्टी कमीश्नर, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और जेल के सीनियर

सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को सस्पेंड कर दिया गया है और भविष्य में ऐसी घटना न हो, हम लोग इसका ध्यान रखेंगे और राज्य सरकार के अधीन जो क्षेत्र आते हैं, उनके बारे में भी हम एडवाइज़री जरूर देंगे, ताकि भविष्य में ऐसी घटना न हो।

DR. MAMTAZ SANGHAMITA: Respected Madam, thank you for allowing me. I just want to know whether there is any project regarding the survey and regarding psychoanalysis of criminals especially in the context of recent increase in incidents of sexual assault as well as violent attacks and murders. If so, what actions are being taken to change their attitude or mindset, what is the fund allocated to each State for that purpose and is the Government thinking about doing so in the near future?

SHRI KIREN RIJIJU: Madam, the question is not directly related to the principal question asked but regarding finance, the Thirteenth Finance Commission had recommended financial provisions for limited States only and after 2009 the Centre has stopped funding or financial support for implementation of jail or prison reforms. The Fourteenth Finance Commission has also talked about larger fiscal space for the States to take care of their activities, especially related to prison reforms. Whatever additional information the hon. Member has asked, we can provide it later. But for the moment, I would like to state that the question is not directly related to the principal question.

(Q. 182)

श्री रत्न लाल कटारिया: माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा, पहले तो मैं इन्हें बधाई देना चाहूंगा कि पिछले वर्ष मानसून 15-20 प्रतिशत कम रहा, लेकिन उसके बावजूद पिछले वर्ष की तुलना में साढ़े आठ लाख टन अधिक अनाज की पैदावार भारतवर्ष में हुई। इसमें इस सरकार ने बहुत बड़ा योगदान दिया है।

माननीय मंत्री जी ने बहुत-सी योजनाओं का वर्णन किया है, जिन्हें भारत के किसानों के लिए हमारी सरकार ने जारी की हैं। मुझे हैरानी होती है कि नेशनल सैम्पल सर्वे की जो रिपोर्ट आई है, उसके अंतर्गत कहा गया है कि 59 परसेंट किसानों को उन योजनाओं के बारे में अब भी जानकारी नहीं है, जो उनके हित के लिए बनाई गई हैं। छोटे किसानों तक भी इन योजनाओं की पहुंच हो, उसके लिए क्या किया गया है? करनाल में 12वीं एग्रीकल्चरल साइंस कांग्रेस की कान्फ्रेंस किसानों के हितों को ले कर हुई है, उसके अंदर जो इश्यूज उठे हैं, वे मार्जिनल किसान का भला कर सकें, उसके बारे में सरकार की क्या नीति है, इस बारे में सदन को अवगत कराया जाए?

डॉ. संजीव बालियान : अध्यक्षा जी, माननीय सदस्य ने इस प्रश्न के माध्यम से अपनी चिंता व्यक्त की है। केंद्र सरकार के पास किसानों तक अपनी बात पहुंचाने का कृषि विज्ञान केंद्र एक माध्यम है। हर जिले में एक ही कृषि विज्ञान केंद्र है। इसके अलावा कृषि राज्य का विषय है इसलिए किसानों तक योजनाओं को पहुंचाने की ज्यादा जवाबदेही प्रदेश सरकार की होती है। केंद्र सरकार इसमें लगातार सहयोग करती रहती है। माननीय सदस्य ने जैसा जिक्र किया है, 12वीं एग्रीकल्चरल साइंस कांग्रेस की कान्फ्रेंस तीन से छह फरवरी को करनाल में आयोजित हुई थी। उसने काफी अनुशंसाएं की हैं। इन अनुशंसाओं से पहले भी केंद्र सरकार की तरफ से कुछ योजनाओं पर काम शुरू हो चुका है। अट्रेक्टिंग एंड रिटेंशन आफ यूथ इन एग्रीकल्चर (आर्या) स्कीम केंद्र सरकार ने शुरू की है। इंडिजिनस एनिमल्स को बढ़ावा देने के लिए गोकुल मिशन शुरू किया है। सोयल हैल्थ कार्ड प्रधानमंत्री की योजना है, इस तरह की योजनाएं पहले भी शुरू की जा चुकी हैं। इसकी स्टडी होने के बाद योजनाएं जल्दी ही शुरू की जाएंगी।

श्री रत्न लाल कटारिया : अध्यक्ष जी, वैसे तो इस वर्ष भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सिंचाई योजना के अंतर्गत एक हजार करोड़ रुपया सिंचाई के लिए बजट में रखा है। मैं आदरणीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या कारण है कि देश की आजादी के बाद 70 हजार करोड़ रुपया सिंचाई परियोजनाओं पर खर्च करने के पश्चात् भी हमारे देश का 35 प्रतिशत एरिया ही क्यों सिंचित है? विकसित राष्ट्रों में 90 प्रतिशत खेती मशीनीकरण द्वारा आधुनिक तरीके से कर रहे हैं। भारत में यह खेती केवल 40 प्रतिशत ही क्यों है?

खेती के विकास के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट आफ एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलोजी रांची में खोला गया है और नेशनल इंस्टीट्यूट आफ बायोटेक स्ट्रेस मनेजमेंट रायपुर में खोला गया है।

मैं हरियाणा प्रदेश से आता हूं और हिंदुस्तान के खाद्यान्न भंडार में हरियाणा सैकेंड लार्जेस्ट स्टेट है। मेरा लोकसभा क्षेत्र अम्बाला आरक्षित क्षेत्र है और खाद्यान्न उत्पादन में रिकार्ड तोड़ उत्पादन करता है। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या टेक्नोलोजी पर आधारित इस प्रकार का कोई इंस्टीट्यूशन खोला जाएगा, जिससे किसानों की उपज बढ़ सके, उन्हें बढ़िया किस्म के बीज मिल सकें और बढ़िया किस्म के उर्वरक उन्हें मिल सकें? क्या सरकार की कोई योजना मेरे लोकसभा क्षेत्र के लिए है?

डॉ. संजीव बालियान : माननीय सदस्य ने एक सवाल में ही बहुत सारे सवाल पूछ लिए हैं। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि इस वर्ष प्रधानमंत्री सिंचाई योजना में एक हजार करोड़ रुपया नहीं बल्कि 5300 करोड़ रुपयों का प्रावधान रखा गया है। मैं माननीय सदस्य को यह नहीं बता सकता हूं कि 70 हजार करोड़ रुपया खर्च होने के बावजूद भी अब तक हम सिंचाई तक निश्चित टार्गेट तक क्यों नहीं पहुंच पाए हैं। माननीय सदस्य ने पिछले 67 वर्षों का इतिहास मुझसे पूछा है, शायद वह मैं उन्हें न बता पाऊं।

मैं माननीय सदस्य को यह जरूर बताना चाहता हूं कि देश के अंदर कृषि में मशीनीकरण को जरूर बढ़ावा मिल रहा है। माननीय सदस्य ने दो इंस्टीट्यूट्स की बात कही है। एक इंस्टीट्यूट वीट्स और पैस्ट मनेजमेंट के लिए खोला गया है और दूसरा इंस्टीट्यूट एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलोजी का नई टेक्नोलोजी एग्रीकल्चर में नए सीड्स प्रोडक्शन, नए हाई ब्रीड सीड के लिए खोला गया है।

माननीय सदस्य ने जहां तक अपने संसदीय क्षेत्र की बात कही है, अभी-अभी हरियाणा में हार्टिकल्चर यूनीवर्सिटी खोलने का पिछले बजट में प्रावधान हुआ है।

श्री रत्न लाल कटारिया: आप अम्बाला के लिए घोषणा कर दीजिए।

डॉ. संजीव बालियान : मैं यह घोषणा नहीं कर सकता हूं, बल्कि प्रदेश सरकार यह घोषणा करेगी कि वह अम्बाला में खुलेगी या कहीं और खुलेगी, लेकिन हरियाणा में हार्टिकल्चर यूनीवर्सिटी खुलेगी। पहले भी हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार में है, जहां से मैं स्वयं पढ़ा हूं।

श्री रत्न लाल कटारिया: आप अम्बाला के लिए कुछ और दे दीजिए।

डॉ. संजीव बालियान : धन्यवाद।

श्री जय प्रकाश नारायण यादव: माननीय अध्यक्ष महोदया, जो रिपोर्ट आई है, उसे हम लोगों ने देखा है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि बिहार में डेयरी उद्योग, मत्स्य पालन और कुक्कुट पालन की दिशा में अभी तक क्या प्रयास किया गया है एवं कितने केन्द्र के द्वारा धनराशि मुहैया की गयी?

डॉ. संजीव बालियान : महोदया, माननीय सदस्य ने जो सवाल पूछा है, उसका सीधा सम्बन्ध इस प्रश्न से नहीं है। उन्हें आंकडों की जानकारी चाहिए, मैं बिहार के सम्बन्ध में ये आंकड़े उनको अलग से मुहैया करा दूंगा क्योंकि इस प्रश्न से उन आंकड़ों का कोई सीधा सम्बन्ध नहीं है।

श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी : अध्यक्ष महोदया, कृषि मंत्री जी ने जो जानकारी दी है और जिस प्रकार से कांग्रेस हुई और उसमें चर्चा हुई, उसके बाद अलग-अलग दृष्टिकोण से खेती में उत्पादन हुआ, वैसा मछली में उत्पादन करने के लिए, अभी हाल ही में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण ने 95 करोड़ मुआवजा मत्स्य किसानों को देने का निर्णय दिया है। न्यायाधिकरण ने यह भी कहा कि इसे खेती का दर्जा देना चाहिए।

मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या कृषि मंत्रालय मछली पालन व्यवसाय को खेती का दर्जा देने वाला है? इसके साथ-साथ, क्या आप उनको डीजल सब्सिडी देंगे, बोट देंगे या कोल्ड स्टोरेज देंगे और उसके एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए क्या कोई योजना बना रहे हैं?

डॉ. संजीव बालियान : महोदया, माननीय सदस्य ने फिश प्रोडक्शन के बारे में प्रश्न किया है, डीजल और बोट पर सब्सिडी देने की केन्द्र सरकार की योजना पहले से जारी है। जहां तक मत्स्य पालन को कृषि का दर्जा देने की बात है, ऐसा कोई प्रस्ताव अभी तक सरकार के पास विचाराधीन नहीं है।

माननीय अध्यक्ष : श्री वी.एलुमलाई ।

वैसे नियम 193 के तहत इस विषय पर चर्चा होनी है।

SHRI V. ELUMALAI: Hon. Speaker, Madam, thank you for allowing me. Our Makkal Mudhalvar, hon. Amma urged the Union Government to take necessary steps to get the Indian fishermen freed. The Government must prevent the harassment faced by our Indian fishermen. Indian vessels captured by the Sri Lankan Navy must be released.

I would like to know whether the Government is providing a package of Rs.1520 crore and Rs.10 crore per annum for the maintenance of deep fishing area along the Indian coast. This is necessary to protect the lives and livelihood of our Indian fishermen.

डॉ. संजीव बालियान : महोदया, माननीय सदस्य ने जो सवाल किया है, वह इस प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है।

माननीय अध्यक्ष : फिशिंग पर बहुत चर्चा हो चुकी है।

प्रश्न संख्या- 183, श्री संतोष कुमार ।

श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा : मैडम, मुझे भी एक पूरक प्रश्न पूछना है।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : एग्रेरियन क्राइसिस के बारे में नियम 193 के अन्तर्गत चर्चा होनी है।

...(व्यवधान)

(Q. 183)

श्री संतोष कुमार: अध्यक्ष महोदया, माननीय मंत्री जी का जवाब पढ़ने और देखने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन सरजमीन पर ऐसा दिखाई नहीं पड़ता है। जिस तरह का जवाब आया है, निश्चित रूप से सदन को गुमराह किया जा रहा है। जिले में गैर-सरकारी संगठन है, जो वित्तीय राशि के लिए रोना रोता है और कल्याणकारी योजना धनराशि के अभाव में पूरी नहीं हो पा रही है।

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि बिहार प्रदेश के प्रत्येक जिले में कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए क्या आप धनराशि उपलब्ध कराना चाहेंगे?

श्री थावर चंद गहलोत : अध्यक्ष महोदया, हमारे यहां हमारे विभाग की योजनाओं के तहत गैर-सरकारी संगठनों के प्रस्ताव आते हैं। वे प्रस्ताव राज्य सरकार के माध्यम से ऑनलाइन सिस्टम से आते हैं। हमारे पास आने के बाद हम उनके गुण-दोष पर विचार करते हैं। सही पाए जाने पर धनराशि स्वीकृत कर देते हैं और अगर सही नहीं पाए जाते हैं तो उनको निरस्त कर देते हैं। माननीय सदस्य पूरे जिलेवार बात कह रहे हैं, अगर वह कुछ स्पेसिफिक पूछना चाहें कि फलां एनजीओ ने प्रस्ताव दिया, उस पर कुछ हुआ या नहीं, तब मैं उसके बारे में जानकारी दे सकूंगा।

श्री संतोष कुमार: पिछले दिनों बिहार सरकार ने कई योजनाओं के प्रस्ताव भेजे हैं। जिन पर कुछ नहीं हुआ है।

माननीय अध्यक्ष: यह ठीक नहीं है, ऐसे नहीं होता है। आप पहले प्रश्न देखें, वह एनजीओज़ के बारे में है।

श्री संतोष कुमार: मैडम, आप आदेश दे दें कि जाकर मिलकर करवा लें।

माननीय अध्यक्ष: आपके पास दूसरा पूरक प्रश्न पूछने के लिए कुछ नहीं है। आप तारांकित प्रश्न डालते हैं तो उस पर अच्छी तरह से अभ्यास करके आया करें, फिर पूरक प्रश्न पूछें।

श्री निशिकान्त दुबे: अध्यक्ष महोदया, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं कि जो उत्तर है, यह कम है या नहीं के बराबर है। मैंने लिखित प्रश्न के भाग 'ग' में पूछा था कि क्या सरकार ऐसे गैर-सरकारी संगठनों की आवधिक रूप से समीक्षा/आकलन/निगरानी कराती है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, समीक्षा के दौरान किन खामियों का पता चला तथा कितने गैर-सरकारी संगठनों को कारण बताओ सूचना जारी की गई/काली सूची में डाला गया है? उसकी भी अलग-अलग सूची मुहैया नहीं कराई गई। इसलिए यह एक गम्भीर मामला है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि अगली बार उत्तर देते हुए इसे मुहैया कराएं। एनजीओ एक व्यवसाय बन गया है। पिछले दो महीने में एनजीओ के बारे में यह मेरा तीसरा प्रश्न है और उसके उत्तर के लिए कभी गृह मंत्रालय से जवाब पूछना पड़ता है, कभी इन मंत्री जी से पूछना पड़ता

है। सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल दायर हुई। वह पीआईएल कहती है कि इस देश में 943 व्यक्तियों पर एक पुलिस कांस्टेबल है, जबकि देश में 500 व्यक्तियों पर एक एनजीओ है। इस देश में 25 लाख एनजीओज़ हैं और यह सीबीआई की रिपोर्ट है, जो सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुई है। इसमें करीब 7,000 करोड़ रुपया है। इसका मतलब यह है कि पिछले छः साल में 7,000 करोड़ रुपया इन एनजीओज़ के पास गया यानि प्रत्येक साल करीब 1200 करोड़ रुपया प्रत्येक एनजीओ को दिया जाता है। इसके अलावा दो बिलियन यू.एस. डालर्स बाहर से एनजीओज़ को आता है यानि 8,000 करोड़ रुपया बाहर से आया है और 7,000 करोड़ रुपया इन्होंने दिया है। मेरे ही प्रश्न के जवाब में कहा गया कि उसमें एक पूर्व केन्द्रीय मंत्री शामिल हैं। दिल्ली प्रदेश सरकार के उप मुख्य मंत्री इसमें शामिल हैं, जिनका सेक्युलरिज्म के नाम पर एनजीओ है। मेरा कहना है कि इस सिचुएशन में जिन एनजीओज़ को काली सूची में डालने वाला सवाल है, क्या मंत्री महोदय को पता है कि लॉ कमीशन ने 2004 में एनजीओज़ के बारे में एक रिपोर्ट दाखिल की थी? उसमें सरकार को यह कहा गया कि जो मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ फंड होता है, उसके लिए उन्होंने सीआरए बनाने के लिए अनुशंसा की। पिछली सरकार जो थी, वह एनजीओज़ से गाइडेड थी। सीआरए के बारे में जो लॉ कमीशन की रिपोर्ट है, उनके खिलाफ क्रिमनल प्रोसीडिंग चलाने का मामला उन्होंने हटाया था, उसे कानूनीजामा पहनाने के लिए एनजीओज़ के बारे में मंत्री जी क्या कर रहे हैं?

श्री थावर चंद गहलोत : अध्यक्ष महोदया, कितने प्रश्नों के उत्तर दूं, यदि आप कहें तो सभी के दे देता हूं। माननीय सदस्य ने पूछा है कि क्या कोई निगरानी तंत्र है और कहीं कोई अनियमितता पाई जाती है तो क्या कोई कार्रवाई करने की व्यवस्था है? मैं कहना चाहता हूं कि निश्चित रूप से निगरानी तंत्र भी है। अगर कहीं कोई अनियमितता पाई जाती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करने की व्यवस्था भी है और हमने की भी है। सामान्यतः जब प्रस्ताव राज्य सरकार के माध्यम से आते हैं तो निगरानी की व्यवस्था, उसकी जांच-पड़ताल की व्यवस्था उनके ही अधिकार क्षेत्र में ज्यादा है। हमारे मंत्रालय की ओर से हमारे अधिकारी भी समय-समय पर जाकर सरप्राइज निरीक्षण भी करते हैं और रूटीन निरीक्षण भी करते हैं। सामान्यतः दो-चार-पांच प्रतिशत तो हम रूटीन में निरीक्षण करते ही हैं। माननीय सदस्य ने दूसरा प्रश्न पूछा था कि किस प्रकार की अनियमितता पाई जाती है। मैं कहना चाहता हूं कि जैसे ही कोई प्रस्ताव आया, उस पर स्वीकृति अगर दे दी जाती है तो हम पहली किस्त रिलीज करते हैं। दूसरी किस्त तब रिलीज करते हैं जब राज्य सरकार उसकी जांच-पड़ताल करके अनुशंसा के साथ उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजती है, वरना नहीं करते हैं। हमने जांच की और अनियमितता पाई गई, ऐसे 87 मामले हैं। हमने इन 87 एनजीओज़ को कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं। उनमें से कुछ के जवाब आए हैं, जिनमें से दस को ब्लैक लिस्टेड घोषित कर दिया गया है।

अगर माननीय सदस्य चाहेंगे तो इन सबकी सूची मैं उनके पास भिजवा दूंगा। मेरे पास अभी भी है, यदि आप कहें तो मैं पढ़कर सुना सकता हूं।

SHRI K.H. MUNIYAPPA: Madam Speaker, I want to know from the hon. Minister about voluntary organisations in the whole country. There are some organisations which are dedicated and doing very well. I am a member of the Consultative Committee for the last 20 years. I attended one meeting in which Shri Tawar Chand Gehlot was there. More than 50 per cent of the NGOs which are not actually functioning are still receiving the grants. This is the case not only now but for the last 20 years. Will he be able to find out a mechanism to trace such NGOs? There is a mechanism in which officers are inspecting and district level officers are sending their reports which are not practically correct. You may encourage the organisations which are running well. May I know from the hon. Minister as to whether he will find out a mechanism to know the number of organisations which are non- functioning because spending such a huge amount of money is not serving the purpose? I want a reply on this point.

Secondly, would the hon. Minister construct hostel buildings to strengthen the quality of education as regards the organisations which are functioning very well and whose reports are correct?

श्री थावर चंद गहलोत : अध्यक्ष जी, मैंने पहले ही निवेदन किया कि जो गैर सरकारी संगठन अर्थात एनजीओ, जिस काम में रूचि रखता है, जैसा कि माननीय सदस्य ने पूछा कि होस्टल के लिए धनराशि देंगे, अगर वे होस्टल के लिए प्रस्ताव भेजेंगे तो हम उनके गुण-दोष पर विचार करके स्वीकृति देंगे। अगर अवासीय विद्यालय चलाते हैं, नशा मुक्ति केन्द्र चलाते हैं, उसके लिए प्रस्ताव भेजेंगे तो उस पर भी देंगे। हमारी मुख्य रूप से सात योजनाएं हैं, उन सातों योजनाओं पर हम धनराशि आवंटित करते हैं। माननीय सदस्य अगर इस प्रकार की किसी एनजीओ की जानकारी देंगे तो निश्चित रूप से गुण-दोष के हिसाब से विचार करके सकारात्मक सोच के साथ उनको स्वीकृति देने की कोशिश करेंगे।

DR. A. SAMPATH: Madam Speaker, my question is regarding the welfare of old people. Our nation is now experiencing a very peculiar situation which the

Government of India has also admitted that there are more than 100 million people who are getting older and older.

Madam, while you were in the Chair, we had a discussion in this House in this Session itself regarding the welfare of very old people, geriatric and palliative care also. A Private Members' Bill was also initiated by one of the very hon. Members, Shri Bhartruhari Mahatab who is present in the House now.

My specific question is, while the hon. Minister has given an elaborate reply to this Question, in paragraph (iv) of the written statement, he has said:

"Integrated Programme for Older persons:

> The main objective of the Scheme is to improve the quality of life of the Older Persons by providing basic amenities like shelter, food, medical care and entertainment opportunities and by encouraging productive and active ageing through providing support for capacity building of Government/Non-Governmental Orgnisations/Panchayati Raj Institutions/Local bodies and the Community at large."

Madam, we all may become very old. While many of the NGOs are getting financial assistance from the Government of India for various types of activities like propagating and advertisements, the person-to-person touch like we are here for them and they are wanted by us should be there.

An atmosphere has to be created where they feel that they are wanted by us and that we are with them. There are certain organisations or institutions or NGOs which are doing a good service in community care, such as palliative and geriatric care. Is the Government of India willing to provide more financial assistance to these types of institutions or NGOs which are voluntarily engaged in geriatric as well as palliative care?

श्री थावर चंद गहलोत : अध्यक्ष महोदया, मैंने पहले भी बताया अभी फिर बताना चाहूंगा कि वृद्धजनों के लिए हम समेकित एकीकृत कार्यक्रम आयोजित करते हैं, संचालित करते हैं। उसके अंतर्गत वृद्धजन गृह का निर्माण होता है, उनका संचालन होता है। सरकारी संस्थानों के माध्यम से स्थानीय निकाय या पंचायत के माध्यम से भी इस प्रकार के वृद्धजन गृह या वृद्धाश्रम संचालित होते हैं और यदि गैर सरकारी संगठन भी

संचालित करते हैं तो उन्हें ये सब सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए हम धनराशि देते हैं। हमारा प्रयास है कि वृद्धजनों को प्रताडित नहीं होना पड़े, उन्हें ऐसा नहीं लगे कि हमने उन्हें घर से बाहर निकाल दिया है, इसलिए वृद्धजन गृह योजना भी है, वृद्धाश्रम भी है। वहां वे सारी सुविधाएं, जो परिवार का वातावरण दिलाने जैसी हैं, उपलब्ध कराने का हम काम करते हैं। माननीय सदस्य अगर कोई एन.जी.ओ. या कोई संस्थान इस प्रकार के प्रस्ताव भेजता है तो मैं निश्चित रूप से विचार करके उन पर स्वीकृति का प्रयास करूंगा।

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB: Madam Speaker, the hon. Minister, after he attained this position, has been going around the country and has been looking after the Department in his Ministry very well. He has expressed his concern when he visited the States, including our State, Odisha.

My question is a little different. We have a Commission for Children, a Commission for Women, and a Commission for Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

सीनियर सिटीजन्स की दस करोड़ से ज्यादा की आबादी साठ साल से अधिक है और यह बढ़ने वाली है और पांच, दस साल या 2050 में ये और भी ज्यादा हो जायेंगे। इसलिए मैं यही प्रार्थना करूंगा कि क्या सरकार का कोई ऐसा विचार है कि वह इस तरह का एक कमीशन सीनियर सिटीजन्स के लिए बनायें?

माननीय अध्यक्ष : सजेशन पर विचार कर लीजिए।

श्री थावर चंद गहलोत : हमारी सरकार ने वृद्धजनों के हित संरक्षण की अनेक योजनाएं बनाई हैं, हम उनके लिए चिंतित भी हैं। हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा युवा देश है और ये आज युवा हैं, कल वृद्ध होने वाले हैं। उनके बारे में देश के प्रधान मंत्री जी ने भी योजनाओं की घोषणा भी की है, पेंशन की व्यवस्था भी की है। आप कमीशन की बात कर रहे हैं, हम वृद्धजन नीति भी बना रहे हैं और जो प्रश्न आपने किया है, हम उस पर गम्भीरता से विचार भी कर रहे हैं। परंतु आज की तारीख में मैं यह नहीं कह सकता हूं कि हम बना पायेंगे कि नहीं।

श्री राजेश रंजन : मैडम, इस पर आधा घंटे की चर्चा करा ली जाए।

माननीय अध्यक्ष : आप लिखकर दे दें।

(Q. 184)

SHRI ARJUN CHARAN SETHI : Madam Speaker, the expenditure under the SRE, that is the Security Related Expenditure, is recurring in nature. First the State Government concerned makes the payment and subsequently the Central Government reimburses it. But recently it has appeared in the Press that for the operational needs of the security forces, especially for CRPF, the Central Government has asked the State Government of Odisha to make the payment.

Especially, for the CRPF, they have asked for payment from the State Government of Odisha for meeting the expenditure relating to the security forces' operational needs. It is a fact that this is security in nature. May I know from the hon. Minister how they can ask for payment of the amounts from the State Government?

श्री हरिभाई चौधरी : अध्यक्ष महोदया, ऐसी बात नहीं है, जो सिक्योरिटी रिलेटिड एक्पेंडीचर होते हैं, वे सिर्फ सुरक्षा के लिए ही होते हैं। जो खर्चा पुलिस की ट्रेनिंग के लिए होता है, उनके कैंप जाने-आने का जो खर्चा होता है, उसके लिए स्टेट को कुछ बताने का की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह सब सुरक्षा के बाबत होता है। इसलिए जो खर्चा पुलिस और सुरक्षा बल करते हैं, उसके लिए केंद्र सरकार ही पैसा देती है।

SHRI ARJUN CHARAN SETHI: In the answer, the hon. Minister has stated that for the rehabilitation of the surrendered naxalites, the Central Government has incurred some expenditure. May I know from the hon. Minister how much expenditure they have incurred especially for the rehabilitation of the surrendered naxalites?

श्री हरिभाई चौधरी : महोदया, रिहैबिलिटेशन की जो पॉलिसी है, वह राज्य सरकार डिसाईड करती है। जो पैसा केंद्र सरकार की तरफ से देना होता है, वह दिया जाता है। अभी जो सरेंडर करता है, उसको हम ढाई लाख रूपया देते हैं और डेढ़ लाख रूपये देते हैं तथा फिक्स डिपॉज़िट करते हैं। सरेंडर करने के तीन साल तक उसको हम चार हज़ार रूपये प्रति महीना वेतन भी देते हैं और ट्रेनिंग भी देते हैं।

SHRI ARJUN CHARAN SETHI : What is the total amount spent so far?

HON. SPEAKER: The State Government has to make a plan and then only they can do it.

Shri Shrirang Appa Barne.

श्री श्रीरंग आप्पा बारणे: अध्यक्ष महोदया, हमारे देश में उग्रवाद की घटनाएं कई राज्यों में होती हैं। उग्रवादी घटनाओं पर अंकुश रखने के लिए उनसे सख्ती से निपटने की जरूरत है। केंद्र सरकार, स्क्योरिटी रिलेटिड एक्सपेंडीचर स्कीम के तहत राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूँ कि पिछले तीन वर्षों में महाराष्ट्र राज्य में नक्सल प्रभावित इलाकों को उग्रवाद से निपटने के लिए कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई है तथा महाराष्ट्र सरकार की कितनी वित्तीय सहायता की मांग केंद्रीय सरकार के पास लंबित पड़ी है, इसकी विस्तृत जानकारी दें तथा इस तरह की उग्रवाद की घटनाओं को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

माननीय अध्यक्ष: आपने एक ही प्रश्न में तीन सवाल पूछ लिए हैं।

श्री हरिभाई चौधरी : अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है, वह इस प्रश्न से संबंधित नहीं है तथा यह इसके संदर्भ में नहीं है।

श्री अभिषेक सिंह: महोदया, हमारा देश इस दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। इस लोकतंत्र की आंतरिक सुरक्षा की सबसे बड़ी चुनौती वामपंथी उग्रवाद के रूप में हम देखते हैं। इस पूरी लड़ाई के केंद्रबिंदु में हमारा छत्तीसगढ़ राज्य, पूरे देश में इसका एक केंद्र बन चुका है। इस लड़ाई का जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू है, वह है वामपंथी उग्रवादरोधी रणनीति। वर्तमान में अलग-अलग राज्य अपनी-अपनी नीतियां बनाते हैं। मैं मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूँ कि क्या केंद्र सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि पूरे भारत देश में इस समस्या के निदान के लिए इंटिग्रेटिड कोई एक ऐसी नीति बने जो सभी राज्यों को समाहित करते हुए बने। उस नीति के अंतर्गत विशेष रूप से वे महिलाएं, जिन्होंने आत्मसमर्पण किया है, उनका स्किल अपग्रेड कर के, उनको रोज़गार की सुविधाएं मुहैया करा कर, उनको हम समाज की मुख्यधारा से कैसे जोड़ सकते हैं? हम कैसे यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि जिन भाइयों और बहनों का विश्वास लोकतंत्र की ओर जुड़ा है, उनको हम इस तरीके से आगे बढ़ाएं कि उनको देख कर जो बाकी भाई-बहन हैं, वे वापस समाज की मुख्यधारा में, लोकतंत्र की मुख्यधारा में लौट सकें।

श्री हरिभाई चौधरी : महोदया, जैसा कि माननीय सदस्य ने बताया है, उस प्रकार से हमने छह राज्यों को एक साथ बुलाकर अभी 9 तारीख को ही बैठक की थी। उसमें 6 केंद्रीय मंत्री थे, दो मुख्यमंत्री थे और सभी 6 राज्यों के डी.जी. भी शामिल थे। दस राज्यों और 106 जिलों का जो पूरा प्रभावित क्षेत्र है, उसके लिए हमने कड़ी नीति अपनाई है। इस एरिया के डेवलपमेंट का जो काम है, जो विकास का काम है, सिक्योरिटी के बारे में, रेल, बी.एस.एन.एल. आदि के बारे में, उसे हमने मिशन मोड पर लिया है और

मीटिंग करके एक्शन टेकन भी किया है। आज तक 106 जिलों में 9 हजार करोड़ रूपया हमने दिया है। पूरी तरह से विकास होगा तो इस एरिया में वामपंथी उग्रवाद कम होगा, ऐसा हमारा विश्वास है।

माननीय अध्यक्ष : मंत्री जी, विशेषकर महिलाओं के लिए।

श्री हरिभाई चौधरी : माननीय सदस्य ने कहा कि जो सरेंडर करते हैं, जो रिहैबिलिटेशन के लिए सरेंडर करते हैं, इन सारी स्कीम्स से हम उनकी मदद करते हैं। उनकी ट्रेनिंग करते हैं और उन्हें समझाते भी हैं।

(Q. 185)

श्री श्यामा चरण गुप्त: महोदया, इलाहाबाद लोक सभा के नैनी औद्योगिक क्षेत्र में भारत सरकार के कई बड़े-बड़े उद्योग हैं, जिसमें त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज, भारत पम्पस एंड कम्प्रेसर्स लिमिटेड, हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड तथा डिफेंस के उत्पादन की कई इकाईयाँ इस क्षेत्र में बहुत दिनों से चल रही थीं। इनमें एक-एक इकाई में हजारों एकड़ जमीन की बाउन्ड्री बनी हुई है और एक-एक इकाई में पाँच-पाँच, छह-छह हजार श्रमिक काम कर रहे थे। विगत सरकार की नीतियों से अथवा गलत प्रबन्धन से ये सभी इकाईयाँ रूग्ण हो गई हैं और अब इनमें आधे इम्प्लाई भी काम नहीं कर रहे हैं। इनको बहुत दिनों से वेतन भी नहीं दिया जा रहा है। मजदूरों के बहुत से समूह हमारे सामने आकर रोते हैं, अपना बकाया माँगते हैं और कहते हैं कि आपकी सरकार है, अब हम कहाँ जाएं।

माननीय प्रधानमंत्री जी ने अच्छे दिनों के लिए जो घोषणा की थी कि अब कोई भी अनइम्प्लॉइड नहीं हो पाएगा। हमारा इलाहाबाद स्मार्ट सिटी भी घोषित हो गया है। ऐसी स्थिति में हमें इम्प्लॉइमेंट देना है, अनइम्प्लॉइड लोगों को कहीं न कहीं एडजस्ट करना है। मैं माननीय भारी उद्योग मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि आखिर इलाहाबाद की इन रूग्ण इकाईयों को पुनर्जीवित करने के लिए क्या योजनाएं हमारे यहाँ दे रहे हैं या उन्हें इम्प्लॉइमेंट देने की आपकी कोई योजना है या नहीं है?

श्री अनन्त गंगाराम गीते : महोदया, माननीय सदस्य ने सदन के सामने जो जानकारी दी है, उस सारी जानकारी से मैं सहमत हूँ। मेरे मंत्रालय से जुड़े हुए दो उद्योग हैं, जो सदस्य के क्षेत्र में हैं। उनमें से एक भारत पम्पस एंड कम्प्रेसर्स लिमिटेड है और दूसरा त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड है। इन दो इकाईयों में से भारत पम्पस एंड कम्प्रेसर्स लिमिटेड के लिए रिवाइवल पैकेज 156 करोड़ रूपए का दिया गया है और उसके रिवाइवल के लिए प्रयास चल रहा है। मुझे विश्वास है कि भारत पम्पस एंड कम्प्रेसर्स लिमिटेड का रिवाइवल सही तरीके से हो पाएगा। त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड एक दूसरी इकाई है जो मेरे मंत्रालय से जुड़ी हुई है। जो दो अन्य इकाईयाँ हैं, जिनका मेरे मंत्रालय से सीधा कोई सम्बन्ध नहीं है। यदि उनके सन्दर्भ में कोई जानकारी आवश्यक हो तो उनसे सम्बन्धित मंत्रालयों से उपलब्ध कराई जा सकती है। त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड का मामला न्यायालय तक पहुँच गया था और न्यायालय के निर्णय के बाद अब प्रोवीजनल लिक्विडेटर उस कंपनी पर अपॉइंट किया गया है। लिक्विडेटर अपॉइंट होने के कारण कई समस्यायें, आज जो कर्मचारी उस कंपनी के हैं, उनके वेतन को लेकर या उनके वी.आर.एस. को लेकर कई समस्यायें हैं। मेरा मंत्रालय और मैं चाहता हूँ कि त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड के जो कर्मचारी हैं, कई महीने से उनको वेतन नहीं मिला है, जिन समस्याओं या कठिनाइयों का वे सामना कर रहे हैं, मैं उनसे

अवगत हूँ। जिस प्रकार से वे सदस्य को मिले थे, उसी प्रकार ये सारे कर्मचारी, उनके नेता मेरे मंत्रालय में आकर मुझसे भी मिले थे। हमने मंत्रालय की ओर से यह प्रयास किया है। एक तो लिक्विडेटर अपॉइंट होने के बाद वी.आर.एस. देना या उस प्रकार की घोषणा करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी कानपुर टैक्सटाइल मिल्स का एक प्रिसिडैन्ट है कि कानपुर टैक्सटाइल मिल्स लिक्विडेशन में जाने के बाद भी उस मिल के कर्मचारियों को वी.आर.एस. दिया गया है। जब यह प्रिसिडैन्ट मेरी जानकारी में आया है, तब हमने टैक्सटाइल मिनिस्ट्री से यह जानकारी मँगवाई है कि किस प्रकार से लिक्विडेशन में जाने के बाद भी कानपुर टैक्सटाइल मिल्स के कर्मचारियों को वी.आर.एस. दिया गया है। उसकी जानकारी हमने मँगवाई है। जैसे ही वह जानकारी आती है, आने के बाद निश्चित रूप में मंत्रालय की ओर से हम प्रयास करेंगे और उस प्रिसिडैन्ट को क्वोट करते हुए लॉ मिनिस्ट्री के पास उनकी सलाह के लिए निश्चित रूप से भेजा जाएगा। जो लॉ मिनिस्ट्री की सलाह आएगी, उसके ऊपर आगे की कार्रवाई होगी। सरकार कर्मचारियों के प्रति सहानुभूति रखती है और भविष्य में भी रखेगी और उन कर्मचारियों को जितना भी सहयोग करने की आवश्यकता है, उसके लिए पूरा-पूरा प्रयास किया जाएगा।

श्री श्यामा चरण गुप्त: माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि क्या इन ईकाइयों को पुनर्जीवित करने के भी प्रयास चल रहे हैं अथवा नहीं? अगर इन्हें पुनर्जीवित नहीं करना है, दोबारा नहीं चलाना है, रिवाइव नहीं करना है तो क्या इनको प्राइवेटाइज़ करने की भी कोई व्यवस्था बन रही है?

माननीय अध्यक्ष : दो के बारे में तो मंत्री जी ने बता दिया है।

श्री अनन्त गंगाराम गीते : माननीय अध्यक्ष जी, दो के बारे में मैंने पहले ही बता दिया है। दूसरी जो दो ईकाइयाँ हैं, उनका मेरे मंत्रालय से सीधा संबंध नहीं है। उस मंत्रालय से यदि इस संदर्भ में जानकारी चाहिए तो माननीय सदस्य अलग से उस पर यहाँ प्रश्न का नोटिस दे सकते हैं। दो के बारे में मैंने जानकारी दी है। भारत पंप्स एंड कंप्रेसर्स लिमिटेड के रिवाइवल के लिए आलरेडी मंजूरी दी गई है और रिवाइवल का काम चल रहा है और किसी भी प्रकार का निजीकरण का कोई निर्णय नहीं है या उस प्रकार का कोई विचार आज तक सरकार के पास नहीं है।

SHRI S.P. MUDDAHANUME GOWDA: Madam, it is unfortunate that a majority of the public undertakings are running under loss and are becoming sick in spite of the best infrastructure and also abundant manpower.

If we take HMT watch units, there are four units in the country. If we put all four units together, they are running under loss. The unit at Tumkur, which is

in my Constituency, has got the best infrastructure, the latest machineries and equipments and abundant manpower. That is also located in a very good place. If we are running this unit independently, it is capable of making profits.

I would like to say here that instead of putting all the units together and make the entire unit sick, the Government of India can bifurcate the unit at Tumkur to preserve the brand value of HMT watches. The Government of India can, at least, think of preserving the HMT unit at Tumkur which is capable of making profit. I request the hon. Minister to be generous towards this HMT unit at Tumkur.

श्री अनन्त गंगाराम गीते : माननीय अध्यक्ष जी, एच.एम.टी. वाच तुमकुर के बारे में माननीय सदस्य ने यहाँ प्रश्न किया है। जो प्राफिट में चलने वाले यूनिट्स हैं, उनके प्रति उन्होंने चिन्ता जताई है। लेकिन एच.एम.टी. लिमिटेड एक होल्डिंग कंपनी है, उसके तहत सारे यूनिट्स आते हैं। जो सूचना या सुझाव माननीय सदस्य ने यहाँ पर दिया है, उस पर कोई निर्णय करना आज तो संभव नहीं है, लेकिन प्रयास ज़रूर किए जाएंगे। मंत्रालय की कोशिश तो यही रही है कि जो अच्छे यूनिट्स हैं, वे चलते रहें और उनको पूरा सहयोग मिले।

श्री सुल्तान अहमद: मैडम स्पीकर साहब, यह सवाल सिक पी.एस.यूज़ के संबंध में है। पूरे देश में 65 पब्लिक सैक्टर अंडरटेकिंग्ज़ में से 11 बंगाल में हैं। टायर कार्पोरेशन, नेशनल जूट मैनुफैक्चरिंग, हिन्दुस्तान केबल्स और बर्न स्टैंडर्ड का नाम किसी ज़माने में देश के नामवर पी.एस.यूज़ में होता था, लेकिन आज इनके हज़ारों हज़ार वर्कर्स के दिन भुखमरी में गुज़र रहे हैं। इस सरकार ने बहुत ही स्वच्छता और ईमानदारी के साथ कोल ऑक्शन आदि का काम शुरू किया है। क्या सरकार की इस तरह की परिकल्पना है कि आने वाले दिनों में सिक पी.एस.यूज़. को भी ऑक्शन के जरिये हो, एफ.डी.आई. लाकर के हो या फॉरेन इन्वैस्टमेंट हो, उसको रिवाइव करने का कोई विचार है? इसलिए कि यह देखा जा रहा है कि इन पर हजारों-हजार करोड़ रुपये सालाना खर्च होते हैं, तनख्वाहें दी जाती हैं, लेकिन काम कुछ नहीं हो रहा है। क्या इस तरह की सरकार ने कुछ परिकल्पना बनाई है, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं?

श्री अनन्त गंगाराम गीते: मैं सदस्य की बात से पूरी तरह सहमत हूं। लगभग 65 इकाइयां हैं, जो हमारे सी.पी.एस.ईज़. हैं, वे सिक हैं, बीमार हैं। सरकार इस सन्दर्भ में निश्चित रूप में इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए प्रयास कर रही है। जहां तक मेरे भारी उद्योग मंत्रालय का सम्बन्ध है, हमने यह निर्णय किया है, पांच सी.पी.एस.ईज़. हैं, जो सिक हैं, जिन्हें हम चला नहीं पा रहे हैं या भविष्य में चला नहीं सकते हैं, उन्हें हमने बन्द करने का निर्णय किया है। उन्हें अच्छा पैकेज वी.आर.एस. के माध्यम से हम देने जा रहे हैं।

इसी प्रकार से जो अलग-अलग सी.पी.एस.ईज़. हैं, जो भिन्न-भिन्न मंत्रालयों के तहत आते हैं, सभी मंत्रालयों को इस प्रकार से अध्ययन करने के लिए सुझाव दिये गये हैं। हर मंत्रालय इस विषय पर अध्ययन कर रहा है और भविष्य में जो सिक यूनिट्स हैं, उनके बारे में निश्चित रूप में योग्य कदम उठाये जाएंगे।

माननीय अध्यक्ष: भगत सिंह कोशियारी जी, आपके यहां तो कोई पी.एस.यू. नहीं है न।

श्री भगत सिंह कोश्यारी: माननीय अध्यक्षा जी, मेरे यहां भी एच.एम.टी. है। पिछली बार माननीय मंत्री जी ने यह कहा था कि हम इसे बन्द नहीं करेंगे। अब मुझे पता लगा है कि उसके बन्द होने की नौबत आ रही है। मेरा एक ही निवेदन है, वह सब ने उठाया है, रुग्ण पी.एस.यूज़. का बड़ा इम्पोर्टेंट विषय है, उन्होंने उसके रिवाइवल के लिए कहा है, मेरा यह निवेदन है कि हर क्षेत्र में, जहां-जहां भी इस प्रकार के संस्थान हैं, इस प्रकार के उद्योग हैं, माननीय मंत्री जी, क्या आप वहां के स्थानीय प्रतिनिधियों को, वहां के माननीय सांसद जी के साथ मिलकर के कोई कमेटी बिठाएंगे ताकि वह बाहरी सम्पत्ति आप किसी को सस्ती दरों में न दे दें, आप उसमें केवल हस्तक्षेप करें। मेरा निवेदन है कि आप एक कमेटी बिठायें और संसद सदस्य उसमें रहें, उसके बाद आप उसके बारे में निर्णय लें, क्या आप ऐसा करेंगे?

माननीय अध्यक्ष: अगर माननीय सदस्य कोई सुझाव दें तो उस पर विचार कर लेना।

श्री अनन्त गंगाराम गीते: अध्यक्षा जी, जब मैंने अपने पहले उत्तर में कहा कि हमने पांच सी.पी.एस.ईज़. बन्द करने का निर्णय लिया तो उनमें एच.एम.टी. के तीन यूनिट्स भी हैं, उनमें से जिसका जिक्र यहां पर सदस्य ने किया है। मैं आपके माध्यम से सदन को यह जानकारी देना चाहूंगा कि जब हमने यह निर्णय किया है तो बहुत अच्छा वी.आर.एस. पैकेज हम उन्हें देने जा रहे हैं। उन्हें 2007 के पे-स्केल से हम पैकेज दे रहे हैं और इसीलिए कर्मचारी संतुष्ट रहेंगे। बहुत ही अच्छा पैकेज हम वी.आर.एस. के माध्यम से दे रहे हैं। ...(व्यवधान) सम्पत्ति के बारे में सदस्य ने जो चिन्ता यहां पर जताई है, निश्चित रूप में यह सरकार की सम्पत्ति है। इसका दुरुपयोग नहीं होगा और न ही दुरुपयोग हम होने देंगे। जहां पर आवश्यकता होगी, निश्चित रूप में जो स्थानीय सांसद हैं या जन-प्रतिनिधि हैं, उनका सहयोग भी हम लेंगे।

(Q. 186)

श्री हरीशचन्द्र उर्फ हरीश द्विवेदी: माननीय अध्यक्षा जी, मैंने माननीय मंत्री जी से पूछा था कि कृषि मेले क्या देश में लगाये जा रहे हैं...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आप थोड़े इधर हो जाइये, ताकि दिखाई दे सकें।

श्री हरीशचन्द्र उर्फ हरीश द्विवेदी: इसमें मुझे उत्तर मिला है कि राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर और क्षेत्र स्तर पर कृषि मेले या प्रदर्शनियां इसलिए लगाई जाती हैं ताकि किसानों को जागरूक किया जाये, उन्हें अधिक से अधिक सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाये। मुझे लगता है, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं, क्या संसदीय क्षेत्र स्तर पर, जिले स्तर पर और उसके नीचे गांव स्तर पर भी भारत सरकार की कोई ऐसी योजना है कि चौपाल लगाकर के और मेला लगाकर के किसानों को अधिक से अधिक जानकारी सरकारी योजनाओं की दी जाये?

श्री मोहनभाई कल्याणजीभाई कुंदरिया: माननीय अध्यक्ष महोदया, माननीय संसद सदस्य ने जो प्रश्न किया है, केन्द्र सरकार से अधिक से अधिक हर एक राज्य में कृषि मेला कैसे आयोजित होता है, 2012 से अब तक हर एक राज्य में कृषि मेले के लिए केन्द्र सरकार ने 72.62 करोड़ रुपये की राशि दी है।

12.00 hrs

अध्यक्ष जी, पूरे देश में 'आत्मा' योजना के तहत हर राज्य में, हर डिस्ट्रिक्ट में 'कृषि मेला' के आयोजन का प्रावधान है। हमारे पास एक सुझाव है कि हर एक एम.पी. के संसदीय क्षेत्र में कृषि विज्ञान केन्द्र के माध्यम से कृषि मेले का आयोजन किया जाए। इसके बारे में सांसदों के सुझावों पर 'आत्मा' योजना के तहत विचार किया जा सकता है।

श्री हरीशचन्द्र उर्फ हरीश द्विवेदी: माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि किसानों को उनकी उत्पादकता का लाभकारी मूल्य मिले, इसके लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं? दैवी आपदाओं से जो उनका नुकसान होता है, उसकी भरपाई के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है?

श्री मोहनभाई कल्याणजीभाई कुंदरिया : माननीय अध्यक्ष जी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस के आधार पर किसानों को उनकी उपज के दाम मिलते हैं और हम उन्हें इसी आधार पर दे रहे हैं।

12.01 hrs

PAPERS LAID ON THE TABLE

HON. SPEAKER: Now, the House will take up Papers Laid.

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF ENVIRONMENT, FORESTS AND CLIMATE CHANGE (SHRI PRAKASH JAVADEKAR): Madam, I beg to lay on the Table:-

(1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indian Council of Forestry Research and Education, Dehradun, for the year 2011-2012, along with Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indian Council of Forestry Research and Education, Dehradun, for the year 2011-2012.

(2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library, See No. LT 1923/16/15]

(3) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indian Council of Forestry Research and Education, Dehradun, for the year 2012-2013, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indian Council of Forestry Research and Education, Dehradun, for the year 2012-2013.

(4) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (3) above.

[Placed in Library, See No. LT 1924/16/15]

(5) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indian Council of Forestry Research and Education, Dehradun, for the year 2013-2014, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indian Council of Forestry Research and Education, Dehradun, for the year 2013-2014.

(6) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (5) above.

[Placed in Library, See No. LT 1925/16/15]

(7) A copy of Notification No. S.O. 287(E) (Hindi and English versions) published in Gazette of India dated 30th January, 2015 reappointing the United India Insurance Company Limited as the Fund Manager under the the Environment Relief Fund Scheme, 2008 for a period upto 30th June, 2015 issued under sub-paragraph (2) of paragraph 4 of the said Scheme.

[Placed in Library, See No. LT 1926/16/15]

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : अध्यक्ष महोदया, श्री रावसाहेब पाटील दानवे की ओर से, मैं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 की धारा 39 की उपधारा (3) के अंतर्गत खाद्य सुरक्षा भत्ता नियम, 2015 जो 21 जनवरी, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 48(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[Placed in Library, See No. LT 1927/16/15]

12.02 hrs

REPORT ON THE PARTICIPATION OF INDIAN PARLIAMENTARY DELEGATION AT THE 130TH ASSEMBLY OF THE INTER-PARLIAMENTRY UNION (IPU)

SECRETARY-GENERAL: Madam, I beg to lay on the Table Hindi and English versions of the Report on the participation of Indian Parliamentary Delegation at the 130th Assembly of the Inter-Parliamentary Union held at Geneva (Switzerland) from 16 to 20 March, 2014.

12.03 hrs

COMMITTEE ON PETITIONS
1st to 3rd Reports

श्री भगत सिंह कोश्यारी (नैनीताल - उधम सिंह नगर): महोदया, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर प्रस्तुत करता हूं-

(1) नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर 09 कमीशन वेंडरों के स्टॉल्स/ट्रॉलियों को मनमाने ढंग से बंद कर दिए जाने संबंधी रेलवे के आदेश के बारे में अखिल भारतीय रेल विक्रता संघ के महासचिव श्री रिंकू अग्रवाल से प्राप्त अभ्यावेदन के बारे में पहला प्रतिवेदन।

(2) मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति (एसीसी) के निर्णय को लागू न किए जाने के बारे में श्रीमती रीता कुनुर से प्राप्त अभ्यावेदन के बारे में याचिका समिति के 7वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी दूसरा प्रतिवेदन।

(3) क्रेडिट इंफार्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड में कृषि ऋण की अदायगी न करने वालों के नाम शामिल न किए जाने के बारे में श्री अमोल एम टोटे से प्राप्त अभ्यावेदन के बारे में तीसरा प्रतिवेदन।

12.04 hrs

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE
13th Report

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं-

> "कि यह सभा 9 मार्च, 2015 को सभा में प्रस्तुत कार्य-मंत्रणा समिति के तेरहवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

MADAM SPEAKER: The question is:

> "That this House do agree with the Thirteenth Report of the Business Advisory Committee presented to the House on 9th March, 2015."

The motion was adopted.

MADAM SPEAKER: Now, the House will take 'Zero Hour'.

श्री जय प्रकाश नारायण यादव (बाँका) : अध्यक्ष महोदया, देश में स्वाइन फ्लू एक गंभीर और जानलेवा बीमारी साबित हुई है। देश में और प्रदेश में हज़ारों लोगों की जानें इस बीमारी से गयीं हैं। दिन-प्रतिदिन स्थिति बहुत ही बद से बदतर होती जा रही है। स्कूलों में, कॉलेजों में आम नागरिकों की सुरक्षा को कोई पुख्ता इंतज़ाम नहीं है। हज़ारों लोग मौत के शिकार हुए हैं। खासकर, राजस्थान, महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडीशा में इस जानलेवा बीमारी से भारी खतरा उत्पन्न हुआ है। इसकी दवा का अभाव है, डॉक्टरों का अभाव है। इसे माननीय मंत्री जी और सरकार गंभीरता से लें। देश में चारों तरफ अफरा-तफरी मची हुई है। हॉस्पीटल्स में बेड की व्यवस्था नहीं है, दवा की व्यवस्था नहीं है, इसके परीक्षण की व्यवस्था नहीं है। स्वाइन फ्लू से देश में त्राहिमाम हो रहा है। इसलिए पूरा सदन और सभी माननीय सदस्य इस सरकार से यह जानना चाहते हैं कि इसके लिए आपने क्या विशेष प्रोग्राम बनाए हैं? आपने क्या विज्ञापन दिए हैं? आपने इस जानलेवा स्वाइन फ्लू बीमारी से सुरक्षा के क्या इंतज़ाम कर रहे हैं?

माननीय अध्यक्ष महोदया, यह मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं।

DR. P. VENUGOPAL (TIRUVALLUR): Madam Speaker, yesterday in this House, hon. Prime Minister and the hon. Home Minister explained the situation about the release of a separatist within a few days of forming PDP-BJP Government in Jammu and Kashmir.

We are not satisfied with the explanation tendered by the Government. We want to know what are the clarifications sought from the State Government.

Further, undeterred by the furore created by the release of the separatist, adding insult to injury, again the Chief Minister reportedly directed the DGP of Jammu and Kashmir to release about dozen more separatists and also several other prisoners. He further stated that he does not need to consult anyone on this. It is feared that there are about dozen terrorists and many hardcore criminals in that list.

Releasing separatists and militants is an anti-national act and there is no doubt that the Chief Minister of that State is acting against the interest and security of our nation.

Therefore, we feel that the BJP has to come out of the Government and order fresh elections in that State. Moreover, the PDP of Jammu and Kashmir should be banned for undertaking anti-national act of releasing separatists, militants and terrorists, which is against the security of our nation.

SHRI A. ANWHAR RAAJHAA (RAMANATHAPURAM): Thank you Madam Speaker, a national political storm is shattering us now. This is because of the irresponsible statements made by the Jammu and Kashmir Mufti Mohammed Sayeed about releasing political prisoners that may include terrorists and criminals.

The Centre's clarification that they are talking to the Jammu and Kashmir Chief Minister satisfies no one in the country. Our AIADMK has always been upholding the national unity and integrity.

Madam Speaker, during Chinese war in 1962, when Prime Minister Jawaharlal Nehru appealed for liberal contributions for defence fund, our founder leader, *Puratchi Thalaivar, MGR,* came with the first contribution cheque for the nation.

Jawaharlal Nehru immediately sent a telegram to our leader appreciating his gesture. It was a great moment in our history. Similarly, during Indo-Pak war, our beloved leader, *Puratchi Thalaivi, Amma,* as part of a South Indian Delegation from the field of cinema went to the borders to enthuse the soldiers.

The then Prime Minister Lal Bahadur Shastri was also there in that programme. Our leader, hon. *Amma* profusely removed her necklace and bangles and all the jewels on the self and gave it away for the national cause.

We, the 37 MPs present in this august House were brought up in this patriotic tradition by our founder leader, *Puratchi Thalaivar, MGR* and our hon. *Puratchi Thalaivi, Amma.*

As a committed Party dedicated to uphold the sovereignty of the country, we urge upon the Union Government to remove the Mufti Mohammed's Government which acts against the sovereignty of our nation.

डॉ. संजय जायसवाल (पश्चिम चम्पारण) : महोदया, आपने मुझे एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं आपका ध्यान मेडिकल डिवाइसेज में जो अंधाधुंध लूट चल रही है, उसकी तरफ दिलाना चाहूंगा। आज की डेट में चाहे वह कार्डीऐक इम्प्लांट्स हो, चाहे वह आर्थोपेडिक इम्प्लांट्स हो, जो मार्केट प्राइस होता है, उससे पांच गुना दाम लिया जाता है। अगर मरीज हार्ट अटैक से नहीं मरे तो वह इन इम्प्लांट्स की कीमत देखकर जरूर मर जाएगा।

मैं आपको उदाहरण के तौर पर बताता हूं। जो इम्प्लांट होता है, उसे एबॉट कंपनी चालीस हजार रूपए में इंपोर्ट करती है और इसको बाजार में डेढ़ लाख रूपए में बेचा जाता है, एक इम्प्लांट को मेडिट्रॉनिक्स तीस हजार रूपए में इंपोर्ट करती है, जबकि इसको मार्केट में एक लाख बासठ हजार रूपए में बेचा जाता है, ऐसे ही जानसन एंड जानसन पैंतालीस हजार रूपए में इंपोर्ट करती है और मार्केट में इसका प्राइज एक लाख पैंतीस हजार रूपए है। एक एंजियोप्लास्टी करने में कम से कम तीन से चार इम्प्लांट्स की जरूरत पड़ती है। एक पेशेंट को चार लाख रूपए तक देने पड़ते हैं। अगर आर्थोपेडिक इम्प्लांट की बात करें तो दस हजार रूपए की चीज पचास हजार रूपए में बेंची जा रही है। आई.वी. सेट की बात करें, तो अगर कोई दुकानदार सौ आई. वी. सेट खरीदता है तो उसे पांच सौ आई.वी. सेट फ्री में मिलते हैं। किस तरह से इन मामलों में मरीजों को डॉक्टर और दवाखाने के नेक्सस से लूटा जा रहा है।

मैं आपके माध्यम से इसके प्रति ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा और माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि जब कॉस्मेटिक में एम.आर.पी. फिक्स होता है तो मेडिकल इम्प्लांट्स में भी हर हालत में एम.आर.पी. फिक्स होनी चाहिए, जिससे मरीजों को सहूलियत मिल सके। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री शिवकुमार उदासि, श्री निशिकान्त दुबे, श्री ए.टी.नाना पाटील, श्री देवजी एम. पटेल, श्री प्रेम दास राई, डॉ. किरिट पी. सोलंकी, श्री नारणभाई काछड़िया, श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश, श्रीमती जयश्रीबेन पटेल, श्रीमती ज्योति धुर्वे, श्री राजेन्द्र अग्रवाल, डॉ. वीरेन्द्र कुमार, श्री पी.पी.चौधरी को डॉ. संजय जायसवाल द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

DR. THOKCHOM MEINYA (INNER MANIPUR): Madam, you may kindly remember that I have mentioned this particular issue on 25th February during this Session to urge the Union Government to repeal the infamous Armed Forces (Special) Powers Act, 1958.

Madam, as you know, four Commissions/Committees have recommended repeal of this Act but recently the Union Home Ministry has recommended to reject the recommendation of the Report of the Justice Jeevan Reddy Committee.

This particular Act is now in application in the State of Jammu and Kashmir and the other North-Eastern States of India. The effect is so huge that many people have been killed in fake encounters and also many people have disappeared. If once this particular Committee's Report is rejected by the Home Ministry, I am afraid things shall turn from bad to worse and I, very respectfully, want to suggest the Government that they should re-consider this. In this connection, I would like to urge the Union Government to immediately intervene and direct the Ministry of Home Affairs to re-consider its decision to reject the Report of the Jeevan Reddy Committee in public interest and immediately repeal the Armed Forces (Special) Powers Act, 1958. Thank you, Madam.

SHRIMATI KAVITHA KALVAKUNTLA (NIZAMABAD): Madam, the Health Ministry has issued a Notification to increase the size of the 'health warning' to be printed on the Beedi pack. This will have a serious effect on lakhs of Beedi workers working in our country. Cigarette and Beedi cannot be put together in the same category. The Health Ministry has put both of them in the same category. Cigarette industry is highly mechanized and very expensive. It is not labour intensive. Madam, lakhs of Beedi workers are there even in my Telangana. उनकी वजह से उनका घर चलता है। उनको एक-दो हजार रुपये घर पर मिलता है। उनको इग्जैम्पशन देने के लिए मैं मांग करती हूं।

HON. SPEAKER: Both are injurious.

SHRIMATI KAVITHA KALVAKUNTLA: Of course, there is a serious issue of non-smoking and all that अगर आप सिगरेट वर्सेज बीड़ी देखेंगे, Beedi is a native industry. It needs a great support. Therefore, through you, Madam, I request the hon. Minister to exempt Beedi industry from the ambit of the proposed Notification. And, particularly in Telangana there are lakhs of Beedi workers. I would like the Health Minister to consider this issue seriously and exempt the Beedi industry from this Notification. Thank you so much. … (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Shri Shivkumar Udasi, Shri Devji M. Patel, Shri Ravindra Kumar Pandey, Dr. Virendra Kumar, Shri Prahlad Singh Patel, Shri Janardan Singh Sigriwal, Shri Gajendra Singh Shekhawat, Shri Hariom Singh Rathore, Shri M.B. Rajesh and Shri P. Karunakaran are allowed to associate with the matter raised by Shrimati Kavitha Kalvakuntla.

SHRI ANTO ANTONY (PATHANAMTHITTA): Madam, I request the Government to take immediate steps to redress the grievances of rubber growers in the country. They are under acute financial crisis due to the declining prices of natural rubber.

Madam, 90 per cent of rubber production and 90 per cent of the rubber farmers are from Kerala. In my constituency, 90 per cent of the farmers are rubber farmers and the rubber growing area is nearly one lakh hectare.

Rubber prices have fallen from Rs.240 to Rs.120 now-a-days. After the commission taken by the traders, the farmer gets only Rs.100 per kilogram. The cost of production of rubber is Rs.150 per kilogram.

The alarming situation that now prevails in the market is that the traders withdraw from buying natural rubber from the market. Really speaking, 12 lakh rubber farmers are now starving. The Government has already collected more than Rs.800 crore from the rubber farmers as cess. The Government is now keeping that money in the Price Stabilization Fund.

If the Government is ready to use this money to buy the excess rubber from the market, 12 lakh poor farmers will be saved. Already 3.5 lakh metric tonnes of

rubber is imported to our country and big players have purposefully destroyed the price of natural rubber.

Madam, I urge the Government to intervene in this issue and take necessary steps to make sure that the rubber farmers get good prices.

HON. SPEAKER: Adv. Joice George, Shri Jitendra Chaudhury, Shrimati P.K. Shreemathi Teacher, Shri P. Karunakaran, Shri M.B. Rajesh, Shri Jose K. Mani Shri Mullappally Ramachandran and Shri N.K. Premachandran are allowed to associate with the matter raised by Shri Anto Antony.

SHRI K.C. VENUGOPAL (ALAPPUZHA): There was an assurance from the Government that they will convene a meeting. … (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: You have already raised this issue. You only associate with the issue.

… (*Interruptions*)

SHRI K.C. VENUGOPAL: So far no meeting has been convened. … (*Interruptions*)

SHRI N.K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Madam, the situation in Kerala is very serious. … (*Interruptions*) Just ask the Minister to hold a meeting. … (*Interruptions*)

SHRI K.C. VENUGOPAL: Last time when I raised this issue in 'Zero Hour', he has given me an assurance. … (*Interruptions*) Please let the Government respond on it. … (*Interruptions*) There was an assurance from the Government that a meeting of the MPs will be convened. … (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Please sit down.

… (*Interruptions*)

SHRI N.K. PREMACHANDRAN: Madam, please ask the Minister to hold a meeting. … (*Interruptions*) Direction from the hon. Chair is not being respected by the Government… (*Interruptions*) Direction from the Chair not being respected is very unfortunate. Last time when we raised the issue, hon. Speaker had directed

the Government to convene a meeting of the MPs. But so far it has not been convened. Please give a direction. … (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Prof. K.V. Thomas.

PROF. K.V. THOMAS (ERNAKULAM): Madam, due to heavy sea erosion in the country, there is a heavy damage to men and property. Sea-side is being washed out. Houses are destroyed and very often, fishermen are killed. The only solution to prevent sea erosion is to construct sea-walls and wave-breakers.

Earlier, the Government of India used to give assistance to the State Governments. But now no assistance is being given to the State Governments in this regard.

I request that adequate financial assistance should be given to the State Governments to construct protective sea-walls and wave-breakers in the coastal belt where there is serious sea erosion.

श्री विनोद कुमार सोनकर (कौशाम्बी) : अध्यक्ष महोदया, मैं गंगा-जमुना की अंतर्वेदी में स्थित कौशाम्बी जनपद से चुनकर आया हूं। यह क्षेत्र बहुत ही पिछड़ा हुआ है। उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार ने इस क्षेत्र की विशेषता को देखते हुए 4 अप्रेल, 1997 को एक अलग जनपद इलाहाबाद से काटकर बनाया जिसमें कौशाम्बी जनपद की तीन तहसील - सिरातु, मंजनपुर, चैल है और प्रतापगढ़ की कुंडा तहसील है। जब इन्हें इलाहाबाद जनपद से काटा गया तो इनके हिस्से में न कोई विश्वविद्यालय है, न मेडिकल कॉलेज है और न ही कोई इंजीनियरिंग कॉलेज है। यहां की जनता पूरी तरह से कृषि पर आधारित है। इस विषय में भारत सरकार की मौनीटरिंग रिपोर्ट 2014-15 का भी संदर्भ लिया जा सकता है जिसमें इन्होंने इस क्षेत्र को अति पिछड़ा घोषित किया है। यहां शैक्षिक व्यवस्था कोई नहीं है। इसलिए मैं भारत सरकार के कृषि मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि कम से कम एक कृषि विश्वविद्यालय कौशाम्बी जनपद में खोलने की कृपा करें जिससे वहां जो लोग कृषि पर निर्भर हैं, उन्हें शिक्षित किया जा सके और आधुनिक खेती से जोड़ा जा सके। उस जनपद में पलायन है, बेरोजगारी है, क्योंकि वह जनपद पूरी तरह से उद्योगविहीन है, वहां एक भी उद्योग नहीं है। मेरा कृषि मंत्री जी से निवेदन है कि वहां एक सरकारी कृषि विश्वविद्यालय खोलने की कृपा करें जिससे उस क्षेत्र का समुचित विकास किया जा सके।

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत (जोधपुर) : अध्यक्ष महोदया, एक बहुत पिछड़ी हुई गरीब जाति नायक राजस्थान में निवास करती है। मैं उनके 60 सालों के दर्द को आपके साथ बांटना चाहता हूं। इसलिए आपका थोड़ा

सा समय का संरक्षण चाहता हूं। पौराणिक रूप से जो नाग, निषाद, यक्ष प्रजाति के लोग हैं, उस प्रजाति से यह जाति आती है और ऑस्ट्रेलाइट प्रजाति की अन्य जातियां भील, गरासिया, कोल में से एक नायक जाति भी है। इन सारी जातियों को भारत सरकार की अनुसूची में एसटी के अंतर्गत दर्ज किया गया है। नायक समाज के लोगों की संस्कृति, रीति-रिवाज, पहनावा, परिधान सब कुछ एसटी के अनुरूप है। भारत सरकार के ट्राइबल डिपार्टमैंट ने वर्ष 2003 में एक डौक्यूमैंट्री बनाई थी जिसमें नायक जाति को एसटी की जाति मानते हुए प्रदर्शित किया था। इसके अतिरिक्त राजस्थान उच्च न्यायालय ने भी वर्ष 2008 के अपने एक फैसले में इसे एसटी जाति के अंतर्गत माना था। इसके साथ ही 1871 के क्रिमिनल जनजातियों के एक्ट में भी इस जाति को क्रिमिनल जनजाति मानते हुए उसके अधीन रखा गया था।

लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारत सरकार का जब गजट नोटिफिकेशन हुआ, जब राजस्थान की अनुसूची बनाई गई, उस अनुसूची में इस समाज को 57वें नंबर पर रखा गया, इसे एस.टी. का दर्ज किया गया। इस जाति को एस.सी. में भी 10वें नंबर पर दर्ज किया गया, इस कारण उहापोह की स्थिति बन गई। कुछ स्थानों पर इस समाज के लोगों को एस.टी. का सर्टिफिकेट दिया जाता है जबकि कुछ स्थान पर एस.सी. का सर्टिफिकेट दिया जाता है। यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, एक ही परिवार के सदस्य को एक ही स्थान पर कभी एस.सी. और कभी एस.टी. का सर्टिफिकेट दिया जाता है। वस्तुतः यह स्थिति इसलिए उत्पन्न हुई क्योंकि जब इंग्लिश और हिन्दी में गजट का नोटिफिकेशन छापा गया, हिन्दी में तो नायक लिखा हुआ है, लेकिन अंग्रेजी वर्जन जब लिखा गया तब स्पेलिंग में NAYAKA दर्ज कर दिया गया, जबकि नायका नाम की कोई जाति ऐसी नहीं है। अनेक बार भारत सरकार और राजस्थान सरकार के बीच इस बारे में स्पष्टीकरण हुआ है और इस स्थिति को ठीक करने के लिए वार्ता हुई है। अनेक बार इसके लिए प्रतिवेदन भी प्रस्तुत किए गए हैं। लेकिन उहापोह की स्थिति आज भी विद्यमान है। जिस कारण अत्यंत ही गरीब और पिछड़ी जाति के लोग जो छोटे-छोटे घरों में बहुत ही गरीबी की स्थिति में रहते हैं। उनको उनका जायज हक नहीं मिल पा रहा है। मैं आपके माध्यम से सदन और सरकार का ध्यान इस विषय की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूं। इन लाखों गरीब लोगों के दर्द को समझते हुए इस दिशा में तुरंत निर्णय होना चाहिए।

धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : श्री देवजी एम. पटेल को श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री अरविंद सावंत (मुम्बई दक्षिण) : महोदया, मैं एक अत्यंत ही गंभीर विषय को आपके माध्यम से रेल मंत्री जी के सामने रखना चाहता हूं। बेरोजगारी हमारे यहां एक जटिल प्रश्न है। 20 जून, 2013 को * नाम के एक शख्स ने बताया कि मंत्री महोदय का रेलवे रिक्रूटमेंट में कोटा होता है। ऐसा कहकर दिल्ली में उन लोगों को बुलाया। दिल्ली में * नाम के शख्स से पहचान करा दी। नाम जानबूझकर ले रहा हूं क्योंकि जांच के लिए अच्छा होगा, ये बड़े लोग नहीं हैं, न विधायक हैं न नगर सेवक हैं।

माननीय अध्यक्ष : नाम मत लीजिए।

श्री अरविंद सावंत: आप चाहें तो नाम निकाल दीजिए, मुझे कोई हर्ज नहीं है, इन दोनों व्यक्तियों ने कहा कि रेलवे की रिक्रूटमेंट के बारे में कल अर्जी लाकर देता हूं, अर्जी लाकर दी गई, अर्जी लाकर देने के बाद बकायदा रेलवे रिक्रूटमेंट्स बोर्ड की तरफ से फोन आया कि आपने जो अर्जी भरी है वह स्वीकृत हुई है और आपको दो दिन में कॉल आ जाएगा। बाद में रेलवे रिक्रूटमेंट्स बोर्ड की साइट् से भी मेल आ गया कि आपका रिक्रूटमेंट्स फार्म मिला है। फिर उन्हें मेडिकल टेस्ट के लिए भेजा गया, रेलवे की अस्पताल में उनकी मेडिकल हुई। मेडिकल होने के बाद कृषि भवन में किसी आई.ए.एस. लेवल के किसी अधिकारी ने इंटरव्यू ली, उनके पास कृषि भवन का इंट्री पास आज भी उपलब्ध है, आठ दिन बाद उन्हें अप्वाइटमेंट लेटर मिला। अप्वाइटमेंट लेटर मिलने के बाद उनसे कहा गया कि आपको ट्रेनिंग के लिए जाना पड़ेगा। चंदौसी, मुरादाबाद में ट्रेनिंग हुई, उनसे कहा गया कि आपको इलाहाबाद जाना पड़ेगा, फिर कलकता के दत्तुबाग में उनकी ट्रेनिंग हुई। बेसिक पेमेंट मिला, आई-कार्ड मिला, सर्विस बुक बनाया गया। उसके बाद तहसील से चरित्र प्रमाणपत्र लाने के लिए कहा गया। तहसील से प्रमाणपत्र भी दिया गया। प्रमाणपत्र देने के बाद दानापुर बिहार में उनको तीन महीने स्टेशन पर ट्रेनिंग की ड्यूटी कराई गई, अप्रैंटिंस जैसी ट्रेनिंग कराई गई। दानापुर डिवीजन, ड्रेस कोड, नेम प्लेट, आई-कार्ड, पास, पेमेंट, पे-स्लिप सब दी गई, सब कुछ देने के बाद स्टेशन ड्यूटी का लेटर देने के लिए कहा गया, बिहार में अप्वाइटमेंट के लिए लेटर दे दिया गया। मेरे पास उनकी सारी फाइल है, आई-कार्ड है, रेलवे का ऑरिजनल लेटर है। इसमें महाराष्ट्र के 40 बच्चे हैं इसके अलावा और भी बहुत सारे लोग हैं जिन्हें फंसाया गया है, हरेक व्यक्ति से सात लाख रुपये लिए गए। जो लोग यह सब कर रहे थे वे आज कई महीने से गायब हैं, उनको पता चला कि अब फंस गए हैं, फंसने के बाद जांच शुरू हुई, * के लड़के से लेकर जो रेलवे का शख्स था, आज कोई नहीं मिलता है, सात लाख हरेक व्यक्ति से लिए गए हैं। मैं आपके माध्यम से रेल मंत्री जी से जांच के लिए अनुरोध करता हूं।

---

* Not recorded.

अगर जरूरत पड़े तो सी.बी.आई. भी इसकी जांच करे। इन बच्चों को न्याय दें। ऐसी मांग जीरो ऑवर में मैं आपके माध्यम से करता हूं।

धन्यवाद।

SHRI N.K. PREMACHANDRAN: Thank you, Madam Speaker. My 'Zero Hour' submission is in respect of the rights and privileges of Members of Parliament in respect of *Prime Minister's Gram Sadak Yojana* (PMGSY).

The existing guidelines for the implementation of PMGSY are not suitable for prioritizing the roads for development as per the local requirements. The District Rural Road Plan prepared by the consultancy -- it is being prepared by the consultancy and not by the Government -- in association with the officials is not subjected to the scrutiny of the Committee under the Chairmanship of Members of Parliament responsible for evaluating the work under PMGSY.

Earlier, the roads proposed by the Members of Parliament were given due priority. The utility-value fixed for the roads by the officials are not cross-checked by the concerned MP. The proposals given by the MP is considered only on the basis of the utility-value fixed by the officials during the time of road-mapping. At the time of road-mapping, we have no role and nothing is being consulted. As far as we are concerned, PMGSY is for having inter-linking of rural roads, especially, in the remote areas and when they fix the utility-value, it will be very low utility-value as far as the most remote and rural areas are concerned. So, our suggestions and proposals are being negated without any justification, and the only justification that they are saying is that the utility-value is low.

So, my submission is that the local requirements and the special emergent situations are not considered for prioritizing the work. Hence, the decisions of the concerned officials on the basis of the utility-value override the priority proposals given by the MPs. Therefore, the present guidelines are against the principles followed earlier.

Hence, I urge upon the Government of India, especially, the Ministry of Rural Development to change the guidelines so as to make the development of

rural roads more effective subject to the proposals of the hon. MPs also. Thank you, Madam.

SEVERAL HON. MEMBERS : Madam, we would like to associate with the issue raised by Shri N.K. Premachandran.

HON. SPEAKER: Yes, you can associate.

… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: It is an important issue, which has been raised by the hon. Member. Therefore, you can associate with the issue raised here.

… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Shri M. B. Rajesh, Shri Mullappally Ramchandran, Shri Anto Antony, Dr. A. Sampath, Shri Jose K. Mani, Adv. Joice George and Shri Sankar Prasad Datta are permitted to associate with the issue raised by Shri N.K. Premachandran.

श्री डी.एस.राठौड़ (साबरकांठा) : माननीय अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे शून्य काल में बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभार मानता हूं। मेरे मत क्षेत्र साबरकांठा, नडियाद, कपदवंज-मोडासा से न्यू बोर्ड गेज रेलवे लाइन शामलाजी रेलवे स्टेशन तक चलती है। यह रेल लाइन 1978 से पेंडिंग है, जिसकी वजह से वहां गुड्स ट्रेन का प्रावधान नहीं हो पा रहा। इस कारण सारा गुड्स(माल-सामान) रोड के माध्यम से जाता है। कपदवंज-मोडासा न्यू बोर्ड गेज लेन, जो शामलाजी तक पहुंचती है, उस 22 किलोमीटर लेन के लिए 55 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इस रूट के चालू न होने से रोज करीब पांच हजार यात्रियों को रेल सुविधा नहीं मिल पाती, जिसका फायदा रेलवे को नहीं मिल पाता। इस रूट के लिए भारत सरकार के रेल मंत्रालय से बहुत बार पत्र-व्यवहार करके आगे की कार्यवाही करने के लिए कहा गया, लेकिन आज तक उसमें कोई प्रगति नहीं हुई।

इस रूट से दिल्ली-उदयपुर और गुजरात के मोडासा-कपदवंज-नडियाद-वडोदरा-सूरत एवं मुम्बई के नागरिकों को बेहतर रेल सुविधा मिलने वाली है। हाल ही में अहमदाबाद में हुई वेस्टर्न रेलवे के जनरल मैनेजर के साथ हुई बैठक में भी यही प्रश्न उठाया गया था...(व्यवधान)

गुजरात, खेडा, साबरकांठा और राजस्थान के सांसदों को भी यही डिमांड है कि यह लाइन जल्दी शुरू की जाये।

माननीय अध्यक्ष: श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत को श्री डी.एस. राठौड़ द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

SHRI K.C. VENUGOPAL: Thank you, Madam. The controversial and unfortunate statement made by the Sri Lankan Prime Minister, Shri Ranil Wickramasinghe, remarks that Indian fishermen may be shot if they intrude into Sri Lankan waters. This has stoked strong apprehensions among the fishermen community across the coastal areas.

DR. P. VENUGOPAL (TIRUVALLUR): Madam, I had also raised this issue yesterday in the House. … (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Yes, I know about it. Yesterday only you had raised it.

… (*Interruptions*)

SHRI K.C. VENUGOPAL: The statement, which he justified later suggests that : "if someone tries to break into my house, I can shoot. If he gets killed, law allows me to do that". It is a threatening statement to the fishermen community that is trying to make both ends meet by engaging in fishing. That statement is unfortunate. The Government should take adequate measures to ensure the safety and security of fishermen community in Indian waters. The Government should facilitate the release of Sri Lankan fishermen straying into the Indian waters, and also ensure that Indian fishermen and their boats are released by Sri Lanka.

The present remarks by the Sri Lankan Prime Minister pose a threat and also hurt the feelings of fishermen across the country.

Madam, our hon. Prime Minister is in Sri Lanka today. I think the apprehension among the people of India will be expressed by the hon. Prime Minister to his Sri Lankan counterpart.

SOME HON. MEMBERS: Madam, we want to associate.

HON. SPEAKER: All of you are permitted to associate with the issue raised by the hon. Member.

SHRI MALLIKARJUN KHARGE (GULBARGA): The Prime Minister who will be in Sri Lanka can bring it to the notice of President Maithripala Sirisena so that it will be helpful, and the issue could be resolved peacefully.

HON. SPEAKER: Adv. Joice George, Shri Sankar Prasad Datta, Dr. K. Kamaraj and Dr. P. Venugopal are permitted to associate with the issue raised by Shri K.C. Venugopal.

SHRIMATI KIRRON KHER (CHANDIGARH): Madam Speaker, the Right to Education Act made education a fundamental right under the Indian Constitution. However, today that fundamental right of thousands of children across India is being violated because of this Act.

Across India, schools are being shut down for not following infrastructural norms, size of classroom, not having a playground, not having a gymnasium, etc. Yet, these private schools are the schools that charge a very low fee and provide quality education for the children who are not getting that standard of teaching in most Government schools, except perhaps in Kendriya Vidyalayas or such like schools. Despite poor quality of education, the Government cannot take any action against these Government-run schools under the RTE.

मेरे पास बहुत लोग काम के लिए आते हैं, नौकरी के लिए आते हैं और कहते हैं कि मैं 8वीं, 10वीं, 12वीं पास हूं। जब मैं उनसे कहती हूं कि किसी पेपर या किताब की दो लाईन पढ़कर सुनाइए तो वे एक लफ्ज़ भी नहीं पढ़ पाते हैं। मेरा कहना है कि सरकारी स्कूल से सर्टीफिकेट दिए जा रहे हैं लेकिन एजुकेशन नहीं मिल रही है।

So, when that the state of education in most Government-run schools, why are private schools being shut down without proper inspection into what is being taught there? There was one problem which most of these schools were facing. They were not being recognized by the respective State Governments. Archaic rules and regulations governing the recognition process are so restrictive that they can only be satisfied by schools with huge capital. The tragedy is that we do not know how many such schools have been shut down. हजारों स्कूल बंद हो चुके हैं, लाखों

बच्चे, कम से कम पांच लाख बच्चे एजुकेशनली डिस्पलेस हो चुके हैं, कोई स्कूल नहीं है जहां वे जा सकें। एच.आर.डी. मिनिस्ट्री के पास सिवाय पंजाब, हिमाचल प्रदेश के आंकड़े भी नहीं हैं। This is a very serious issue that needs to be addressed at the highest level because it is a question of the future of our children. हम कहते हैं- पढ़ाओ - लिखाओ। अगर उन्हें सुविधा ही नहीं मिलेगी तो आने वाली पीढ़ियों का क्या होगा?

Firstly, schools are being shut down. Is this being done for the right reasons? Secondly, unless we know how many children are affected, how can we work on ensuring that they get quality education which is their fundamental right? We need good education, not just a piece of paper with 'recognized' written on it. I would request the Government to please look into this matter urgently and take necessary action at the earliest because so many children are going without any education. Thank you.

HON. SPEAKER: Dr. Udit Raj, Shrimati Anju Bala, Shrimati Rekha Verma, Sadhvi Savitri Bai Phule, Shri Shivkumar Udasi, Shri Devji M. Patel, Shrimati Rama Devi, Shrimati Jyoti Dhurve, Shri Gajendra Singh ShekhawatShri Dushyant Chautala and Shri Sher Singh Ghubaya are is permitted to associate with the issue raised by Shrimati Kirron Kher.

श्री अनिल शिरोले (पुणे): माननीय अध्यक्ष जी, देश में विगत दो महीने से स्वाइप फ्लू के कारण 1200 से अधिक मृत्यु हुई हैं और हजारों लोग बीमार हुए हैं। कई राज्यों में टैमी फ्लू की गोलियां भी कम हो रही हैं। मौसम बदलाव के कारण स्वाइन फ्लू बढ़ रहा है। इस परिस्थिति में क्या सरकार ने देश भर में एलौपेथी उपचार के अलावा पारंपारिक उपचार पद्धति जैसे आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी में उपलब्ध चिकित्सा के इलाजों के उपयोग का प्रयास किया है? इसके लिए सरकार द्वारा जन जागृति तथा प्रसार माध्यमों से कितना प्रयास किया गया है? आयुर्वेद चिकित्सा में स्वाइन फ्लू, डेंगु, चिकनगुनिया, बर्ड फ्लू आदि संक्रमण से होने वाले रोगों का सटीक, सस्ता और लाभदायक इलाज गरीबों के लिए उपलब्ध है। सरकार ने इसके उपयोग और प्रचार के लिए क्या कदम उठाए हैं?

माननीय अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों को फिर बताना चाहती हूं कि आप स्टेट्स के मैटर यहां उठाते हैं, यह अलाउड नहीं है।

श्री रवीन्द्र कुमार राय (कोडरमा) : माननीय अध्यक्ष महोदया, मेरा अनुरोध है कि इस विषय को गंभीरता से लिया जाए, यह दो राज्यों का मामला है। जिस व्यक्ति के साथ घटना घटी है, वह झारखण्ड का है, जहाँ पर घटना घटी है, वह उत्तर प्रदेश है। किसान हर वर्ष धान कटने के बाद अयोध्या जाते हैं और श्री कृष्णदेव वर्मा 24 दिसम्बर को तीर्थयात्रा पर अयोध्या गये। वे 28 तारीख को वहाँ से लौट रहे थे। फ़ैजाबाद रेलवे स्टेशन पर कुछ लोग उसे उठाकर ले गये। उसे ले जाकर, बेहोश करके उसकी दोनों आँखें निकाल ली। आँखें निकालकर बिना उसकी सिलाई किये हुए, उसे स्टेशन के बाहर फेंक दिया। वह रोता-चिल्लाता रहा। बाद में किसी पेट्रोलिंग पार्टी ने उठाकर उसे हॉस्पीटल में भर्ती कराया।

इस विषय पर मैंने फ़ैजाबाद के माननीय सांसद, वहाँ के डी.सी. तथा एस.पी. को फोन करके बताया, लेकिन अभी तक वे अपराधी नहीं पकड़े गये हैं। मैं झारखण्ड सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूँ, वहाँ के मुख्यमंत्री ने इस पीड़ित व्यक्ति को एक लाख रुपए की मुआवज़ा राशि दी। मैंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को अनुरोध पत्र भेजा कि वहाँ घटना घटित हुई है और अपराधियों ने ने इनकी दोनों आँखें निकाल ली। आप कल्पना नहीं सकते, मैं उस पीड़ित व्यक्ति के घर गया था, बड़ी दर्दनाक स्थिति है कि तीर्थस्थान पर दोनों आँखें निकाल ली गईं। मैं आपके माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार से और भारत सरकार से अनुरोध करना चाहता हूँ कि उस परिवार को जिसके छोटे-छोटे बच्चे हैं, गरीब परिवार है, उसे सहायता मिले, उसे सहयोग मिले और ऐसी दर्दनाक घटना पर रोक लगाने की आवश्यकता है।

SHRI KESINENI SRINIVAS (VIJAYAWADA): Madam, Hyderabad–Vijayawada Section of National Highway 65 is an important corridor in Andhra Pradesh and Telangana States, connecting two Capitals. However, this section is still two-lane in Nandigama and Kanchikacherla, by-passes. It is understood that four-laning of Nandigama-Vijayawada Section of National Highway 65 was completed during 2002-2004 and only a two-lane by pass was constructed in Nandigama and Kanchikacherla towns. This has become a bottleneck in Hyderabad-Vijayawada corridor leading to accidents in town limits of Nandigama and Kanchikacherla. The issue of four-laning of these by-passes has been pending with the Government of India but so far no action has been taken on four-laning of these two crucial by-passes. With the bifurcation of Andhra Pradesh and

declaration of Vijayawada as the Capital, the situation in these two-lane by-passes is going to be much more worsened. In view of the above, it is requested that the necessary instructions may be issued for taking up four-laning of these two by-passes at an early date.

श्री बदरुद्दीन अजमल (धुबरी): माननीय अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे एक महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दिया।

अध्यक्ष महोदया : कल इस पर चर्चा हो चुकी है।

SHRI BADRUDDIN AJMAL: Madam, I would like to draw the attention of the House towards a pathetic, barbaric and condemnable incident of alleged 'racial attack' on a student named Arbaz Uddin Ahmed from Guwahati, Assam in Delhi by his neighbours in such inhuman manner that he is battling for his life in hospital while guilty are yet to be arrested. … (*Interruptions*)

अध्यक्ष महोदया : यह मामला कल ही उठ चुका है।

SHRI BADRUDDIN AJMAL: Arbaz Uddin Ahmed has been living at a rented room in Amar Colony of Lajpat Nagar, New Delhi for preparing for IAS examination. As he was living alone, his some neighbours often passed racial comments against him. It seemed that they were finding reasons to provoke him but he always overlooked the issue. On 4th March, he was standing at the balcony when a group of four, five persons came to him and started beating him with giving reason that the victim used to eat chicken etc., a dish of the non-vegetarian meal in his home despite several warnings. They have beaten him so badly that his legs, hands and several other parts including teeth were fractured. Initially, the police refuted to register an FIR against the attackers. Later, an FIR was lodged and he identified the culprits but no arrest was made even after five days of the incident.

I would request the hon. Home Minister, through this august House to look into the matter seriously and order an inquiry and immediate action may be taken against those who were involved in the racial attack on Arbaz Uddin Ahmed to

avoid any such heinous incident in future. Arbaz Uddin was the student from the North-East. There are other students from the North-East who are facing such attacks. They are facing these attacks on their lives. I remember last year, a 19 year old Arunachal Pradesh student Nido Tania was killed in racial attack in this very Lajpat Nagar area of Delhi. The Committee set up after the death of Nido Tania revealed that the national capital is on the top in racial discrimination against people from northeast region. Thousands of people from northeast regions, both men and women, boys and girls are living here to pursue education and earn livelihood. Despite assurance by the Government, racial discrimination, sexual harassment and attack on the students and people of northeast region has not stopped. This is a very serious matter. Such things should not happen.

HON. SPEAKER: Shri Jitendra Chaudhury, Shri Sankar Prasad Datta and Shri Radheshyam Biswas are allowed to associate with the matter raised by Shri Badruddin Ajmal.

SHRI JITENDRA CHAUDHURY (TRIPURA EAST): Madam, I am sure you will also support the issue I am raising here. In this House also, we applaud when our sportsperson get medals in any international event. I would like to raise that kind of issue here.

The young people of Tripura and the State Government have been requesting for making available the Assam Rifles ground at Agartala for development of multi-discipline sports complex of international standard for holding important sports events. Over 3,500 sportspersons and eminent personalities of the State had submitted a representation addressed to the then Prime Minister of India for handing over the ground, which was being used for holding important national level sports prior to the 1971 Indo-Pak war. Keeping in view the importance of promotion of sports as an integrated strategy in dealing with extremist/insurgent activities in an effective manner and channelizing the youth energy for constructive purpose, this matter was taken up with the then Prime Minister in April, 2011 and also on December, 2014 when our present

Prime Minister made his visit to Tripura, the Council of Ministers had submitted a similar memorandum to the Prime Minister. So, I would like to request the Minister of Defence to hand over the land having area of 49.90 acre in the heart of Agartala city without any premium. As you know, land is very scarce in our hilly State. The Ministry is asking to pay more than Rs 300 crore. Why is the Government asking for money for development of sports complex for youth? Since this has been the sentimental issue of people of Agartala city and the State of Tripura as a whole, I request the hon. Minister to look into the matter on priority and the entire Assam Rifles Ground complex may be handed over to the State Government for building up a multi-discipline sports complex free of cost.

HON. SPEAKER: Shri Sankar Prasad Datta and Adv. Joice George are allowed to associate with the matter raised by Shri Jitendra Chaudhury.

*SHRI K. PARASURAMAN (THANJAVUR): Hon. Madam Speaker. Vanakkam. The city of Thanjavur, often referred as the granary of Tamil Nadu, has been well recognised by UNESCO. This world famous Thanjavur city should be declared as one among the heritage cities of the country. I thank Makkal Muthalvar Hon. Puratchithalaivi Amma for this opportunity and with whose blessings I am now a Member of Parliament representing Thanjavur constituency in Lok Sabha. The Union government has selected 12 cities of the country as heritage cities under HRIDAY (Heritage City Development Scheme). I urge through you Madam Speaker that Thanjavur City should be included and declared as the 13th heritage city of the country under the HRIDAY Scheme. King Karikal Chola had built the Kallanai Dam (Grand Anicut) which is benefitting several lakhs of people of this area even now. King Raja Raja Chola the great built Lord Brahadeeswarar Temple in Thanjavur 1000 years ago. This grand temple was built exclusively with granite. Modern day cement was not used for construction of this temple as this temple stands a testimony for the architectural marvel of Chola dynasty. The Cholas, the Nayakkars, and the Marathas ruled Thanjavur for several decades in the past and had remarkable achievements to their glory. Thanjavur is a temple city. Hon. President of India visited the Mariamman temple of Thanjavur during last year. Several rivers flow in and around this city. Thanjavur paintings, Thanjavur Veena (a musical instrument), artistic plates, dancing doll and several other cultural marvels add glory to this city.

HON. SPEAKER: Yes we know Thanjavur is important.

SHRI K. PARASURAMAN: Thanjavur city is known for its rich tradition, temples, historical monuments, dance forms, art work, etc. I therefore urge through this august House that Thanjavur city, having a traditional glory of thousands of years, should be included and declared as a heritage city under HRIDAY Scheme. Thank you.

---

* English translation of the speech oringinally delivered in Tamil

12.47 hrs

SUBMISSION BY MEMBER

Re: Increasing incidents of theft at MPs residences

SHRI KALYAN BANERJEE (SREERAMPUR): Thank you, Madam, for giving me this chance to raise an important issue.

I am raising an issue regarding burglary, thievery, and insecurity at MPs' flats in Delhi. Our leader Shri Sudip Bandopadhyaya is ill. He is in Kolkata. Last week also, he could not attend Parliament.

On the 7th March, at his residence at No. 18 Maulana Azad Road, everything was stolen. Thieves came and everything in the house was stolen including the things in the *puja ghar*. He has lodged an FIR on 7th March but the police did not take any step. Again, last evening around 5 p.m. or 5.30 p.m., a person attempted to steal everything there but his attempt was thwarted.

I must say that earlier our Chairman of the House Committee took up the issue of general security of all the MPs' flats but no result has come out. I am making a request through you that when the MPs are not in the flats or residences, security must be provided to the fullest extent. At his accommodation, in his house, full security should be given. It always happens when a number of MPs do not stay there. So, the security should be stepped up.

He has lodged an FIR. I have given the reference. We want the police to take the necessary steps.

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): मैडम, श्री सुदीप बन्दोपाध्याय जी के घर का मामला हमारी जानकारी में है। निश्चित रूप से जब सदन का सत्र खत्म हो जाता है तो कई माननीय सदस्य वापस चले जाते हैं। कई बार

ऐसी सूचना आती है कि घरों में छोटी-मोटी चोरियां हो जाती हैं और जैसा माननीय सदस्य ने बताया, सुदीप बन्दोपाध्याय जी के यहां काफी सामानों की चोरी हुई है। हाउसिंग कमेटी के चेयरमैन ने इसके बारे में अधिकारियों की बैठक की थी। हम फिर से सम्बन्धित अधिकारियों और दिल्ली पुलिस के कमिश्नर के साथ समीक्षा बैठक करके यह तय करेंगे कि अधिक से अधिक सुरक्षा हो। जिस केस को माननीय सदस्य सदन के संज्ञान में लाए हैं, उस पर निश्चित रूप से कार्रवाई होगी।

श्री राजेन्द्र अग्रवाल (मेरठ): अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए धन्यवाद देता हूं।

महोदया, बिजली विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की लापरवाही तथा विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार के कारण क्षेत्र में आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। पिछले तीन-चार महीनों में घटित हुई कुछ प्रमुख घटनाओं को मैं यहां सदन के सम्मुख प्रस्तुत करना चाहता हूं। 23 सितम्बर, 2014 को मेरठ के पंचगांव में सुरेश तोमर, बनवारी, रमेश और मनोज नामक किसानों की लगभग छः बीघे खेत की खड़ी फसल तार गिरने की वजह से जल गयी। दिनांक 28 नवम्बर, 2014 को ग्राम जई में जमशेद के घर में तार टूटकर गिर जाने से नौ पशु जल कर मर गए। 2 दिसम्बर, 2014 को ग्राम लडपुरा में तार टूटकर गिर जाने से 18 साल के सोनू की मृत्यू हो गयी। 3 दिसम्बर, 2014 को ग्राम स्याल में कालू नामक किसान की आठ बीघे खेत की खड़ी गन्ने की फसल जलकर नष्ट हो गयी। 28 फरवरी, 2015 को ग्राम माछरा में बिजली का तार गिरने से खेत में काम कर रहे किसान मुनिराज शर्मा की मृत्यू हो गयी।

अभी दिनांक 5 मार्च, 2015 को हापुड़ के ग्राम सिमरौली में तार टूटने से लोकेन्द्र कुमार शर्मा की मौके पर मृत्यु हो गई एवम् उसकी पत्नी और बेटा झुलस गए। अध्यक्ष महोदया, ये घटनाएं बिजली विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार और काम न करने का नमूना हैं। जर्जर तारों को बदलने का बार-बार अनुरोध किया जाता है, परंतु अधिकारियों के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। होता यह है कि तारों को बिना बदले ही बदला हुआ दिखा दिया जाता है। इन सारी दुर्घटनाओं के बीच अधिकारियों की संवेदनहीनता और भी अधिक निंदनीय है। ग्राम सिमरौली में 5 मार्च को हुई दुर्घटना के सिलसिले में मैं दिनांक 7 मार्च को पीड़ित के घर गया। जब मैंने क्षेत्र के अधिशासी अभियंता से पूछा कि क्या उन्हें इस घटना की जानकारी है और वह इस सम्बन्ध में क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि अभी तक इस परिवार के लोग उनसे मिले नहीं हैं। मैंने जब पुनः पूछा कि क्या वह स्वयं या विभाग का कोई अधिकारी पीड़ित के परिवार से मिलने गया है, तो उन्होंने बताया कि अभी तक नहीं गया है।

अध्यक्ष महोदया, दुर्घटनाओं से पीड़ित परिवार इसी प्रकार की संवेदनहीनता का शिकार होते हैं। अशिक्षा एवम् अल्पशिक्षा के कारण ये गरीब ग्रामीण अपना पक्ष भी ठीक से नहीं रख पाते। इस तरह किसी भी प्रकार के दंड के भय से मुक्त ये संवेदनहीन अधिकारी इन्हें प्रताड़ित करते रहते हैं। मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि इन घटनाओं की व्यापक जांच कराई जाए, पीड़ितों को शीघ्र उचित मुआवजा दिलाने की व्यवस्था की जाए और ऐसी दुर्घटनाओं के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। ये सब लोग पीड़ित हैं, इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

माननीय अध्यक्ष: ठीक है। श्री पी. करुणाकरन। मेरा सबसे अनुरोध है कि वे थोड़े शब्दों में अपनी बात कहेंगे तो मैं ज्यादा सदस्यों को एकोमोडेट कर सकूंगी।

SHRI P. KARUNAKARAN (KASARGOD): Madam, with your kind permission I would like to place a very serious issue before this House.

Lakhs of Indians are working in foreign countries, particularly in the Gulf countries, and a good number of them are from the State of Kerala. The Government of India is getting a good portion of the foreign exchange as they are sending money to India but it is sorry to say that we are not able to give anything in return even in the last Budget also.

Madam, it is shocking to say that Indian Airlines and Air India have raised the flight charges recently. There was no justification for that. We know that in international market the price of petroleum products has declined, including the fuel used in these flights. At the same time, it is said by the Indian Airlines and Air India that 40 per cent of their expenditure is due to fuel price rise. If you see, it has come down. They are really looting these passengers. They usually come to India during puja or Christmas. This is not the season but the national carrier treats it as the seasonal issue and they are looting the poor passengers.

So, I would urge upon the Government to intervene in this matter. We are not able to give anything to them but at least we should give them transport facility at the cheaper rate or at the minimum rate.

HON. SPEAKER: Adv. Joice George and Shri Sankar Prasad Datta are permitted to associate with the issue raised by Shri P. Karunakaran.

SHRI SHIVKUMAR UDASI (HAVERI): Thank you, Madam, Speaker for giving me this opportunity to raise an important issue of price drop of cotton in this country.

We have 14 crore farmers out of which 11 crore are small and marginal farmers. Specifically to talk about cotton, Madam, we grow around 4 crore bales of cotton every year. In the last one week or 15 days the price of cotton has come down seriously and they have been affected by this. The price per bale of cotton is

around Rs.15,000. So, the entire cotton market will be around Rs.60,000 crore. Earlier, the price was more than Rs.20,000 to Rs.25,000 per bale. Hence, the market of total cotton grown in our country was around Rs.80,000 to Rs.1,00,000 crore. Farmers are losing that much of money for which the Government has to intervene through CCI and purchase cotton so as to protect the farmers' interest.

I want to make one general point here. Agriculture should be brought into an industry status. We call it subsidy for farmers. We call it incentives for the corporate. They call it sops for the middle class. So, agriculture should be given an industry status.

HON. SPEAKER: Shri Devji M. Patel is permitted to associate with the issue raised by Shri Shivkumar Udasi.

PROF. A.S.R. NAIK (MAHABUBABAD): Madam, around 3000 employees of the Ballarpur Industries which is located in the Fifth Scheduled Area of my Constituency are on strike. प्रधानमंत्री साहब जब भी बात करते हैं तो आदिवासियों के कल्याण और स्वदेशी की बात ज्यादा होती है।

This Ballarpur Industries was started by the Thapar Group of industries. The Grasim Industries used to buy pulp which is useful for the preparation of thread. But now it is available through imports. Now because of import of pulp, the Ballarpur Industry is on the verge of closure. They are now asking for the permission of the Government for the shut down, with the result, 3000 employees of the Company which include *adivasis* are on strike for the last 20 days.

I would request the Government to intervene. This is located on the banks of the Godavari river. Water is available there. Within a radius of 40 kilometres, sufficient coal is available. If they want, they can go for thermal power generation plant also. But they are not doing it and we do not know the reasons. आज स्वदेश में विदेशियों के लिए मेक इन इंडिया की बात चल रही है तो फिर सरकार विदेश से इसका इम्पोर्ट क्यों कर रही है? इसकी वजह से आदिवासी एरिया में स्थित कम्पनी क्लोज़र की स्थिति में है।

श्री नारणभाई काछड़िया (अमरेली) : महोदया, मैं आपके माध्यम से सरकार को यह जानकारी देना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र गुजरात में अफ्रीकन-एशियन सिंह की संख्या गुजरात में और खास कर सौराष्ट्र में सासन-गिर में इतनी ज्यादा संख्या बढ़ गयी है कि वहां के रहने वाले स्थानीय लोगों के लिए रहने की बहुत दिक्कत रहती है। सासन-गिर 1412 किलोमीटर का अभ्यारण्य का क्षेत्र है। इसमें छः राष्ट्रीय राजमार्ग निकलते हैं और कई छोटे-छोटे रास्ते भी निकलते हैं। इसकी वजह से शेरों के विचरण में बाधा पहुंचती है और उनका शिकार भी हो सकता है। गुजरात सरकार ने वन्य जीव बोर्ड के माध्यम से वर्ष 2011 में एक प्रपोज़ल केन्द्र सरकार को भेजा था कि 270 किलोमीटर का वहां रिंग रोड बनाया जाए, जिसकी लागत छः सौ करोड़ रुपये है। मेरी आपके माध्यम से सरकार से मांग है कि गुजरात सरकार द्वारा भेजे गए प्रपोज़ल को केन्द्र सरकार जल्द से जल्द मंजूरी दे।

श्री दुष्यंत चौटाला (हिसार) : अध्यक्ष जी, आपने मुझे शून्य काल में बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

महोदया, हम भारतीय रेल की बात देश की प्रगति के लिए करते हैं कि यह देश की प्रगति में सबसे कामयाब है। भारतीय रेल बजट जिस प्रकार से पेश किया गया, एक चीज सामने आयी कि हम नई ट्रेनों की ओर नहीं, बल्कि डेवलपमेंट की ओर ले जाना चाहते हैं। मैं सदन के समक्ष रखना चाहूंगा कि रेलवे को आगे ले जाने में सबसे बड़ा योगदान किसी का है तो थर्ड और फोर्थ क्लास कर्मचारियों का है।

माननीय अध्यक्ष : आप इस बात को रेल बजट डिसक्शन में बोलिए। रेल बजट पर अभी डिसक्शन होना है।

श्री दुष्यंत चौटाला : हिसार में 115 साल पुराना रेलवे स्टेशन है। मुझे वहां के कर्मचारियों के पास पिछले दिनों जाने का मौका भी मिला था, जहां मैंने हालात देखे कि वहां पीने के पानी की भी व्यवस्था नहीं है, सीवरेज की व्यवस्था नहीं है, मेडिकल फेसिलिटिज़ नहीं हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से अपील करता हूं कि जिस तरह से सरकार रेलवे का प्रगति की ओर लेकर जा रहे हैं, थर्ड और फोर्थ क्लास के रेलवे के इम्पलोइज़ की अक्मॉडेशन पर भी ध्यान रखें और उनके इनफ्रास्ट्रक्चर पर भी ध्यान देने का काम करें।

डॉ. सत्यपाल सिंह (बागपत) : मैडम, आपकी कृपा दृष्टि हुई, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : यह होती रहती है, अगर आप थोड़े में बोलेंगे और समय का ध्यान रखेंगे।

डॉ. सत्यपाल सिंह: मैडम, मैं हाथ उठाता रहता हूं, लेकिन कई दिनों से आपकी कृपा दृष्टि नहीं होती।

मैडम, मेरा बागपत क्षेत्र नेशनल कैपिटल रीज़न का पार्ट है और दिल्ली से 15 किलोमीटर दूर से शुरू होता है। दिल्ली के चारों तरफ सबसे खराब रोड अगर किसी क्षेत्र की है तो मेरे क्षेत्र की है। मैं इसे दिल्ली-सहारनपुर नेशनल हाईवे बनाने के लिए कई महीनों से प्रयत्न कर रहा हूं। मुख्यमंत्री जी से मैंने

पत्र व्यवहार किया। उनके पर्सनल ट्विट हैं, वह कहते हैं कि जिस कम्पनी को उन्होंने ठेका दिया, यह स्टेट हाईवे है, वह कम्पनी बना नहीं सकती है क्योंकि उसकी फाइनेंशियल पोजीशन बहुत खराब है।

13.00 hrs

और वे पुरानी सरकार को कोसते हैं। लेकिन इतना होते हुए भी मैंने उन्हें लिखा कि इसे निरस्त करके नेशनल हाईवे अथारिटी को दिया जाए। भारत सरकार ने उसके लिए 343 करोड़ रुपये सैंक्शन किये हैं और जब तक स्टेट गवर्नमैन्ट उसके लिए नो ऑब्जैक्शन नहीं देगी, नेशनल हाईवे अथारिटी उसे बना नहीं सकती। मेरा यह प्रिविलेज मोशन है, क्योंकि एक सांसद को उन्होंने गलत इंफोर्मेशन दी है और राइटिंग में दी है। एक तरफ ये बातें हैं और दूसरी तरफ मुझे लिख रहे हैं कि कंपनी को 721 दिन, लगभग दो साल के लिए बढ़ाकर कांट्रैक्ट दे दिया है। उनका कांट्रैक्ट सितम्बर, 2014 में खत्म हो गया था। दो साल के बाद वहां समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं रहेगी तो दो साल तक कुछ नहीं होगा। वहां लाखों लोग रहते हैं, उन लाखों लोगों ने क्या पाप किया है कि न भारत सरकार उस पर ध्यान देती है और न यू.पी. सरकार उस पर ध्यान देती है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आपकी तरफ से भारत सरकार को एक डायरेक्शन जानी चाहिए कि जल्दी से जल्दी इसे नेशनल हाईवे में परिवर्तित किया जाए। धन्यवाद।

श्री शेर सिंह गुबाया (फ़िरोज़पुर) : मैडम, मैं एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर पिछले दिनों से बोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन टाइम नहीं मिल सका। एन.डी.ए. की सरकार में मोदी साहब ने नारा दिया है कि मेक इन इंडिया स्किल्ड करके हमारे नौजवानों को रोजगार देना है। पांच तारीख के पंजाबी ट्रिब्यून के फ्रंट पेज पर खबर छपी है कि पंजाब में आठ हजार से ज्यादा इंडस्ट्रीज बंद हो चुकी हैं और लगभग 600 इंडस्ट्रीज का पता नहीं चल रहा है कि वे कहां गईं। जो इंडस्ट्रीज वहां बंद हो गई हैं, उसके कारण मजदूर, इंजीनियर्स, स्किल्ड वर्कर्स और कुछ डिप्लोमा होल्डर्स के साथ-साथ हजारों, लाखों की संख्या में कामगार बेकार हो गये हैं और उनकी रोटी-रोजी खत्म हो गई है।

मैडम, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस तरफ आकर्षित करना चाहता हूं कि उन इंडस्ट्रीज का क्या होगा, क्या उसमें बैंक सैक्टर का फाल्ट है या किसी और स्कीम का फाल्ट है, जिसके कारण वे इंडस्ट्रीज बंद हो गई। पिछली यू.पी.ए. की सरकार ने पंजाब के साथ इनजस्टिस किया था, उन्होंने नेबरिंग स्टेट को इनसैन्टिव्ज दे दिये, लेकिन पंजाब को नहीं दिया। मैं समझता हूं कि यह भी इसका एक मुख्य कारण है।

इसलिए मैं केन्द्र सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि पंजाब को भी दूसरी स्टेट्स की तरह इंसैन्टिव्ज दिये जाएं, ताकि पंजाब में भी इंडस्ट्रीज चल सकें, कामगार काम पर वापस आ सकें और वहां के सब लोगों की रोजी-रोटी चल सके। धन्यवाद।

श्री सुशील कुमार सिंह (औरंगाबाद) : अध्यक्ष महोदया, सबसे पहले मैं इस बात के लिए अपने आदरणीय प्रधान मंत्री जी और आदरणीय शिक्षा मंत्री, श्रीमती स्मृति ईरानी जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने पिछले वर्ष 2014 के बजट में बिहार प्रदेश को एक आई.आई.एम. दिया। लेकिन उसमें अभी परेशानी यह है कि बिहार के गया जिले में आई.आई.एम. की स्थापना होनी है, वहां राज्य का मगध विश्वविद्यालय है। उसके परिसर में जमीन मिलनी थी और उसी जमीन पर आई.आई.एम. की स्थापना होनी थी। लेकिन इसमें काफी विवाद उठ खड़ा हुआ है, उस विश्वविद्यालय के शिक्षकेतर कर्मचारी संघ और अन्य लोगों ने इसका विरोध शुरू कर दिया। ये बातें वहां के स्थानीय अखबारों में भी आई हैं और काफी प्रयास हुआ कि वे जमीन दे दें, लेकिन अभी तक उसमें सफलता नहीं मिली है।

मेरा आपके माध्यम से सरकार को और माननीय शिक्षा मंत्री जी को एक सुझाव है कि उसी जिले में भारत सरकार की एक बहुत बड़ी जमीन है, जो रक्षा मंत्रालय की है, यह लगभग 1700 एकड़ जमीन है, जो सालों-साल से परती है। वहां रक्षा मंत्रालय की अनुमति से एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना भी हुई है, जिसमें 300 एकड़ जमीन उसे दी गई है। बाकी की लगभग 1400 एकड़ जमीन वहां अभी उपलब्ध है। वह जमीन भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय की है, उसी जमीन का उपयोग करके आई.आई.एम. की स्थापना वहां हो जाए, यही मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं।

श्री पी.पी.चौधरी (पाली) : माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे एक महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया। मैं सदन का ध्यान राष्ट्रीय पक्षी मोर की वास्तविक स्थिति की ओर आकर्षित करते हुए बताना चाहूंगा कि मोर को देखते ही विश्व भर में भारत की छवि दीखने लगती है, लेकिन भारत देश में मोर की संख्या में दिन-प्रतिदिन कमी दर्ज की जा रही है। मोर की घटती संख्या का सबसे बड़ा कारण इसका शिकार किया जाना है। साथ ही जल स्त्रोतों का अतिक्रमण और जंगलों में पेड़ों की अंधाधुंध कटाई के कारण भी हमारा राष्ट्रीय पक्षी खतरे में है। सरकार ने मोर को राष्ट्रीय पक्षी का दर्जा दे रखा है। सभी राज्यों के वन विभागों ने भी इसे संरक्षित वन्य जीवों की अनुसूची में प्रथम शामिल कर रखा है। परंतु फिर भी मोर के शिकार की बढ़ती घटनाओं के बावजूद इनके रोकथाम की कोई कारगर योजना नहीं बन सकी है। वर्तमान में मोरों का शिकार जहरीला दाना खिला कर किया जा रहा है। राजस्थान राज्य के वन्य जीव प्रेमियों द्वारा मोर चालीसा लिख कर इनके संरक्षण और जागरूकता का कार्य किया जा रहा है। इसी तर्ज पर मेरा भारत सरकार से अनुरोध है कि वन्य जीवों के संरक्षण के लिए जागरूकता का अभियान चलाया जाए और शिक्षा पाठ्यक्रमों में भी वन्य जीव संरक्षण को शामिल किया जाए।

श्री भगवंत मान (संगरूर): अध्यक्ष महोदया, मैं आपका ध्यान नैशनल हाईवे-1 की ओर दिलाना चाहता हूँ। नैशनल हाईवे-1, जो दिल्ली से अमृतसर तक जाता है, उस पर जगह-जगह जो टोल प्लाजा हैं, वहां पर बहुत भारी रकम वसूल की जाती है। वहां जगह-जगह डाईवर्ज़न लिखा रहता है। जो पुल हैं, वे अनकंप्लीट हैं, अभी पूरे नहीं हुए हैं और सड़कों की हालत बहुत ही खराब है। टोल प्लाजा के आस-पास दो-तीन किलोमीटर सड़क ठीक है। अमृतसर तक इतनी भारी रकम वसूल की जाती है कि जितना गाड़ी का तेल लगता है उतना ही हमें टोल टैक्स देना पड़ता है यानि तेल की कीमत डबल मानी जाए। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि वे नैशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को डायरेक्शन दें कि पहले सड़क कंप्लीट करो, फिर आप उस पर टोल लगाना। पंजाब में भी जो राजमार्ग हैं, वहां भी जगह-जगह टोल बहुत ज्यादा हो गए हैं। जब नई गाड़ी खरीदी जाती है, तब लाखों रूपये रोड टैक्स के रूप में लिए जाते हैं तो वह कौन सी सड़कों का है? अगर हमने 24 घंटे के लिए सड़क रैंट पर लेनी है, तो वे कौन सी सड़कें हैं। जब गाड़ी खरीदते हैं, तब रोड़ टैक्स लिया जाता है? इसकी ओर ध्यान दिया जाना चाहिए। इस मामले में बहुत भारी लूट हो रही है।

डॉ. उदित राज (उत्तर-पश्चिम दिल्ली) : अध्यक्ष महोदया, एंटरप्राइजेज़ में एससी और एसटी का जो पार्टिसिपेशन है, वह बहुत ही कम है। वह पहले 11-12 पर्सेंट हुआ करता था, अब घट कर 9 पर्सेंट के आस-पास हो गया है और दिनों-दिन घटता चला जा रहा है, जबकि रजिस्ट्र्ड एंटरप्राइजेस केवल 7 पर्सेंट के आस-पास ही हैं। हम आपके माध्यम से एम.एस.एम.ई. मिनिस्टर से अनुरोध करेंगे कि इसके लिए कुछ किया जाना चाहिए और ज्यादातर ये लोग एपेरल में, लैदर में काम करते हैं, अनक्लीन और अनहाईजीनिक पेशे में भी अभी लगे हुए हैं। इनका रजिस्ट्रेशन भी नहीं होता है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि इनका पर्सेंटेज बढ़ाया जाना चाहिए।

माननीय अध्यक्ष : श्री राधेश्याम बिश्वास को डॉ. उदित राज द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

DR. BOORA NARSAIAH GOUD (BHONGIR): Madam Speaker, after I have become a Member of Parliament, I visited six times the Kendriya Vidyalaya Sangathan. I also made ten acres of land available to them and every parameter required is met. In fact, they have given a letter that our place is suitable for setting up a KV as per the norms as well as the availability of the Central Government employees. I have seen the list of various States which have been sanctioned Kendriya Vidyalayas. I have gone through that list. They have allotted it in many places where land was not made available to the KVs even after one year whereas I have toured the entire place and they have given a certificate that I am qualified for the sanction of Kendriya Vidyalaya. I request them to allot the KV in my constituency.

Secondly, now each MP is given six seats in Kendriya Vidyalaya. There is more demand for Kendriya Vidyalaya seats than MLA and MP seats. There are 16 lakh voters in my constituency. My request to the Government through you is to give at least one seat for one lakh people. Instead of six seats, they should make us available 16 seats so that temporarily we can meet the demands of the people.

HON. SPEAKER: Shri Bhairon Prasad Mishra is permitted to associate with the issue raised by Dr. B.N. Goud.

डॉ. वीरेन्द्र कुमार (टीकमगढ़) : अध्यक्ष महोदया, मैं जिस विषय की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, उससे संसद के हर सदस्य का संबंध रहता है। एनडीए की सरकार के समय आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, जब देश के प्रधान मंत्री थे, उस समय सांसद संसदीय क्षेत्र स्वास्थ्य मेले की शुरूआत की गई थी। आदरणीया सुषमा स्वराज जी उस समय स्वास्थ्य मंत्री थीं। उन स्वास्थ्य मेलों के कारण संसदीय क्षेत्र की जनता से सीधा संवाद, संपर्क और चिकित्सा सेवाओं में उनका सहयोग करने का एक बहुत महत्वपूर्ण सशक्त माध्यम मिला था। उसमें मेडिकल कॉलेज से भी विभिन्न विषयों के विशेषज्ञ आते थे और हर स्वास्थ्य मेले में दस हजार से बीस हजार तक क्षेत्र के मरीज एकत्रित होते थे। सांसदों को उस मेले का संयोजक बनाया जाता था।

महोदया, मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहता हूँ कि जिस तरह से स्वास्थ्य मेलों का आयोजन उस समय प्रारम्भ किया गया था, उन स्वास्थ्य मेलों का फिर से आयोजन प्रारम्भ किया जाना

चाहिए। उसके लिए आठ लाख रूपए की राशि भी दी जाती थी, आठ लाख रूपए का बजट एलोकेशन किया जाता था, अब उसे बढ़ाकर पच्चीस लाख रूपए का बजट एलोकेशन किया जाना चाहिए। हर संसदीय क्षेत्र में फिर से उसी तरह के स्वास्थ्य मेलों के आयोजन की केन्द्र सरकार के द्वारा शुरूआत की जानी चाहिए। मेरी आपके माध्यम से यही माँग है।

माननीय अध्यक्ष : श्री अश्विनी कुमार चौबे अपने आपको श्री वीरेन्द्र कुमार जी के विषय के साथ सम्बद्ध करते हैं।

SHRI K.R.P. PRABAKARAN (TIRUNELVELI): Madam Speaker, thank you. Mukkudal in my Tirunelveli Lok Sabha constituency, Tamil Nadu is famous for beedi industry. About two lakh workers are engaged in beedi industries in and around my constituency. Since this occupation is hazardous to health, Mukkudal has got a big hospital, which started functioning from 2004-05 with adequate facilities for Out-Patient and In-Patient Departments with a capacity of thirty beds and other diagnostic equipment like x-ray, scan, ECG, Operation Theatre and also ambulance facilities.

But this Beedi Workers Central Hospital does not have adequate number of doctors and other para-medical staff. The x-ray, scan and ECG machines are not functioning. Ambulance service is also not there. As a result, the poor beedi workers and their family members are facing a lot of difficulties and they are also not able to afford huge cost of medicines and treatment from outside.

I shall, therefore, humbly urge upon the Union Ministry of Labour, in coordination with the Ministry of Health and Family Welfare to augment the health facilities in this Hospital by appointing adequate number of doctors, nurses and medical attendants besides providing adequate medicines, etc. to the Beedi Workers Central Hospital, Mukkudal, Tirunelveli District, Tamil Nadu, which will benefit a large number of poor beedi workers in this region. Thank you very much.

श्री देवजी एम. पटेल (जालौर): महोदया, आपने मुझे एक महत्वपूर्ण विषय पर अपनी बात कहने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं राजस्थान के जालौर सिरोही क्षेत्र से आता हूँ। मेरे क्षेत्र के एक साइड में पाकिस्तान का बार्डर है और दूसरी साइड में गुजरात है। हमारे यहाँ से प्रवासी बहुत बाहर

जाते हैं। मेरे यहाँ जालौर-समदड़ी-भीलड़ी रूट में ट्रेन का आवागमन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि रानी की वाऊ से कुछ अवरोध आ रहा है। प्रवासी ज्यादा होने के कारण मानपुर हवाई पट्टी को हवाई अड्डे के रूप में विकसित करने के लिए हमने एक प्रपोजल भेजा है। अम्बा जी धाम बगल में बना हुआ है, बृह्म कुमारी का माउंट आबू के अन्दर बहुत बड़ा सेंटर है, आप भी वहाँ पधार चुकी हैं।

मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि आबू रोड में हवाई अड्डे को विकसित करके अगर वहाँ हवाई सेवा शुरू करें तो मेरे क्षेत्र के लोगों को आने-जाने में बहुत सुविधा होगी। मैं आपके माध्यम से सरकार से इसके लिए माँग करता हूँ। धन्यवाद।

श्री चन्द्रकांत खैरे (औरंगाबाद) : महोदया, आपने मुझे एक महत्वपूर्ण विषय पर अपनी बात कहने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। इस वर्ष के रेलवे बजट में फुल फ्लैज्ड रेलवे यूनिवर्सिटी खोलने की घोषणा की गई है। आपको पता ही है कि मराठवाड़ा महाराष्ट्र का बहुत इंपोर्टेंट क्षेत्र है और मेरे संभाजी नगर, औरंगाबाद एडब्ल्यूबी में सारी लैंड वगैरह उपलब्ध है।

महोदया, मैं आपके माध्यम से रेल मंत्री जी से माँग करूँगा कि यह रेलवे यूनिवर्सिटी मेरे संसदीय क्षेत्र में खुलनी चाहिए। इसका कारण यह है कि यह एशिया में सबसे बड़ी ग्रोइंग सिटी है और यह दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कोरीडोर का बहुत बड़ा सेन्टर होने जा रहा है। इससे उसका अधिक विस्तार हो जाएगा।

माननीय अध्यक्ष : रेल मंत्री आपके यहीं के हैं।

श्री चन्द्रकांत खैरे : महोदया, यह रेलवे यूनिवर्सिटी के लिए आदर्श शहर है, क्योंकि यहाँ सारा इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध है। दस एकड़ लैंड तो रेलवे की सिटी में ही है। उस पर इन्क्रोचमेंट होता जा रहा है। वहाँ पर और भी बहुत जमीन उपलब्ध है।

महोदया, मेरी आपके माध्यम से रेल मंत्री जी से माँग है कि रेलवे यूनिवर्सिटी हमारे यहाँ संभाजीनगर (औरंगाबाद) में ही खुलनी चाहिए। धन्यवाद।

श्री निशिकान्त दुबे (गोड्डा) : महोदया, आपने मुझे समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। अभी लैंड एक्ट की चर्चा चल रही है, मेरे यहाँ सन्थाल परगना टेनेन्सी एक्ट है, जिसके कारण भाई न तो भाई की जमीन खरीद सकता है और न ही बेच सकता है। इस कारण से यदि वहाँ स्कूल बनाना है, कॉलेज बनाना है तो वह सरकार ही बना सकती है। मेरे यहाँ की जो स्थिति है, 35 परसेंट महिलाएं ही केवल लिटरेट हैं, अभी 8 मार्च को आपने महिला दिवस मनाया है। हमारे यहाँ 70 परसेंट बच्चे कुपोषण के शिकार हैं। इस स्थिति में आप समझ सकते हैं कि जहाँ 80 परसेंट से ज्यादा लोग गरीब हैं, 70 परसेंट से ज्यादा बच्चे कुपोषित हैं, महिलाओं का लिट्रेसी रेट 35 परसेंट है, मेरा पूरा इलाका शैड्यूल 5 का इलाका है जिसमें

सैन्ट्रल गवर्नमैंट का ही दायित्व बनता है कि वह डैवलपमैंट करे। इसलिए मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से मांग करता हूँ कि 12वीं पंचवर्षीय योजना में जो ट्राइबल यूनिवर्सिटी खोलने की मांग आई है, उसमें सैन्ट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी मेरे इलाके में खुले। धन्यवाद।

HON. SPEAKER: The House stands adjourned to meet again at 2.15 p.m.

13.16 hrs

The Lok Sabha then adjourned for Lunch till Fifteen Minutes past Fourteen of the Clock.

14.16 hrs

The Lok Sabha re-assembled after Lunch at Sixteen Minutes past Fourteen of the Clock.

(Hon. Deputy Speaker *in the Chair*)

MATTERS UNDER RULE 377 *

HON. DEPUTY SPEAKER: Hon. Members, the matters under Rule 377 shall be laid on the table of the House. The Members who have been permitted to raise matters under Rule 377 today, and are desirous of laying them may personally hand over the text of the matter at the Table of the House within 20 minutes.

Only those matters shall be treated as laid for which text of the matter has been received at Table within stipulated time. The rest will be treated as lapsed.

* Treated as laid on the Table.

(i) Need to provide adequate compensation to farmers who suffered damages to their crops due to recent unseasonal rains and hailstorms in the northern region of the country particularly in Ambala Parliamentary Constituency, Haryana

SHRI RATTAN LAL KATARIA (AMBALA): I would like to bring it to the kind notice of Hon. Agriculture Minister that heavy rains and strong wind at the rate of 55 k.m. per hour have not only paralysed the life of common man in North India but have flattened wheat crops in northern region states. 70 per cent of the wheat is Agyeti (advanced) type of wheat. These varieties of wheat have been flattened by the winds, most of the damaged crops are likely to survive but huge damages are bound to occur between the range of 10-20 per cent. Meteorological department of Haryana Agriculture University have recorded rain from 20 mm to 55 mm which is above the normal rain. This excess rain will not only harm the farmers financially but it may lead to crop diseases such as yellow rust and karnal blunt. More rain will not be beneficial for the crops as high velocity wind and hailstorms have damaging effect on the crops. I myself have visited several areas of my Ambala Lok Sabha on 1st of March and interacted with the farmers. They are demanding adequate financial help because the flattened crops will not only hamper further growth of the crops but also make it difficult for farmers to harvest them. The untimely rains have added to the worry of farmers. After a brief spell of good weather, farmers were expecting bumper crops, but this untimely heavy rains and hailstorms have shattered the dreams of our farmers. Not only wheat but crops like Potato, Dalhan and Mustard have also been badly affected.

On account of the untimely rains, two farmers have already died and one has committed suicide. Therefore, I humbly request the Hon. Minister to direct all the northern states to make special provision in this regard by the respective State Government. I also demand that Rs 10,000/- per acre may be awarded to those farmers who suffered loss after assessing the same.

(ii) Need to set up a Krishi Vigyan Kendra along river Tapi in Bardoli Parliamentary Constituency, Gujarat

श्री प्रभुभाई नागरभाई वसावा (बारदोली) : हमारा संसदीय क्षेत्र बारदोली सूरत जिले में आता है । यहाँ पर वर्षों पहले से कृषि विज्ञान केन्द्र खुला है । यह कृषि विज्ञान केन्द्र मौजूदा समय में शहर के अन्दर हो गया है जिससे किसानों को शहर में आने-जाने में परेशानी होती है । इस परेशानी का मुख्य कारण है कि शहर के अन्दर अत्यधिक ट्रैफिक हो गया है और कृषि विज्ञान केन्द्र का ज्यादा से ज्यादा उपयोग ग्रामीण किसानों के लिए होता है ।

अतः मेरा माननीय कृषि मंत्री जी से निवेदन है कि हमारे जिले में तापी नदी के किनारे मांडवी में राज्य सरकार की जमीन उपलब्ध है, वहाँ पर किसानों के हित में देखते हुए एक कृषि विज्ञान केन्द्र खोलने का विचार किया जाए ।

(iii) Need to permit farmers of villages falling under the army camp area in Pulgaon in Wardha Parliamentary Constituency, Maharashtra to utilize their land for earning their livelihood

श्री रामदास सी. तडस (वर्धा) : मैं माननीय रक्षा मंत्री जी का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र वर्धा के पुलगांव में बने आर्मी कैम्प की ओर आकृष्ट करते हुए कहना चाहता हूं कि यह आर्मी कैम्प एशिया का सबसे बड़े कैम्पों में से एक है । इस कैम्प के परिधि में लगभग 50 गांवों को आर्मी संरक्षण जोन में रखा गया है जिस कारण से यहां के किसान अपनी जमीन को न तो बेच सकते हैं और न ही किसी तरह के उद्योग धंधे लगा सकते हैं । किसानों की हालत दयनीय हो गई है । आये दिन किसान लोग कर्ज के बोझ से आत्महत्या कर रहे हैं । जब किसान कर्ज के बोझ को दूर करने हेतु अपनी जमीन बेचना चाहते हैं तो प्रशासन रोड़ा बनकर खड़ा रहता है ।

अतः मेरा केन्द्र सरकार से निवेदन है कि किसानों को उनकी माली हालत को देखते हुए उनके जमीन को जो संरक्षण जोन में रखा गया, उसे आम जमीन की तरह हर कार्य करने की अनुमति प्रदान करने का कष्ट किया जाए एवं आर्मी कैम्प में और अधिक सुविधा एवं विद्यालय तथा कॉलेज की स्थापना करने में सहयोग कराने की कृपा की जाए ।

(iv) Need to formulate policy and programmes to improve the agricultural productivity and income of farmers in the country

श्री राहुल कस्वां (चुरू) : भारत में किसान की स्थिति अत्यंत दयनीय है । अगर कृषि के विषय पर गंभीरता से कार्य नहीं किया गया तो भविष्य में ओर भी विकराल रूप धारण कर लेगी । भारत में कुल जनसंख्या का लगभग 6 प्रतिशत अर्थात् 75 करोड़ लोग कृषि एवं कृषि आधारित कार्यों पर जीवन-यापन करते हैं । वर्ष 2013 के अनुसार कृषि एवं कृषि आधारित कार्यों का सकल घरेलू उत्पाद में केवल 13.7 प्रतिशत ही योगदान है व प्रति व्यक्ति वार्षिक आय 18266 रूपये ही है जो गैर कृषि कार्य करने वाली जनसंख्या की प्रति व्यक्ति आय लगभग 1 लाख 74 हजार रूपये है, जो कृषि आधारित जनसंख्या की प्रति व्यक्ति आय की तुलना में 10 गुणा अधिक है । अमेरिका में कुल जनसंख्या का 1 प्रतिशत (मात्र 25 लाख) लोग कृषि पर आधारित है और अमेरिका का कुल कृषि उत्पाद 46 लाख 54 हजार करोड़ रूपये है अर्थात कृषि पर आधारित लोगों की प्रति व्यक्ति आय 1.86 करोड़ रूपये वार्षिक से भी अधिक है जो भारत की तुलना में हजार गुणा से भी अधिक है । भारत में फसल बीमा के लिए वर्ष 2013 में मात्र 3 हजार करोड़ रूपये दिया गया है जो कुल कृषि उत्पाद का 0.23 प्रतिशत ही है जो कुल उत्पादन की तुलना में नगण्य है । यह राशि किसान की मदद करने में अपर्याप्त है । अमेरिका में वर्ष 2013 के अनुसार 7.20 लाख करोड़ रूपये का फसल बीमा किया गया है जो कुल कृषि उत्पाद का 16 प्रतिशत के लगभग है । भारत में व्यापक स्तर पर कृषि आधारित आधारभूत संरचनाएं जैसे सिंचाई का विकास, उत्तम किस्म के बीज आदि की व्यवस्था की जानी चाहिए तथा कृषि संबंधित नई तकनीकों एवं विधियों का प्रयोग केवल प्रयोगशालाओं में ही न करके किसानों के खेतों में जाकर किया जाना चाहिए ताकि किसान एक-दूसरे को देखकर उसका अनुसरण कर अधिक से अधिक लाभान्वित हो सके जिससे किसान की दयनीय स्थिति में सुधार हो सके ।

अतः मेरा केन्द्र सरकार से निवेदन है कि किसान की दशा में सुधार के लिए कदम उठाए जाएं ।

(v) Need to consider cultivation of betel leave as an agricultural activity and extend necessary benefits to betel leave growers in Hamirpur Parliamentary Constituency, Uttar Pradesh

कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल (हमीरपुर): मेरे संसदीय क्षेत्र हमीरपुर (उत्तर प्रदेश) में बहुत बड़ें पैमाने पर पान की खेती होती है और लाखों लोग पान व्यवसाय में लगे हुए हैं और कड़ी मेहनत व लगन से महोबा के प्रसिद्ध पान प्रजाति को जीवित रखे हुए हैं । विगत वर्ष हुई दैवीय आपदा से हुए भयंकर नुकसान को भी झेलकर गरीबी व अभाव का जीवन जीने को मजबूर हैं क्योंकि पान की खेती कृषि क्षेत्र में शामिल नहीं हैं इस वजह से कृषि क्षेत्र से मिलने वाली सुविधाएं (बीमा आदि) का लाभ नहीं मिल पाता है जिसकी वजह पान कृषक दिन-प्रतिदिन पलायन को मजबूर हो रहे हैं ।

अतः मेरा केन्द्र सरकार से आग्रह है कि पान की खेती को कृषि क्षेत्र में शामिल किया जाए ताकि बुंदेलखण्ड के गरीब पान किसानों को उनका हक मिल सके ।

(vi) Need to provide subsidy for natural fertilizers

श्री पी.पी.चौधरी (पाली) : कैमिकल फर्टिलाइजर अर्थात् यूरिया और पेस्टीसाईड्स एंड कैमिकल पर सब्सिडी हेतु पिछले 3 वर्षों में कुल यूरिया पर 168788.04 करोड़ रूपये की सब्सिडी उर्वरक कंपनियों को जारी की गई जिसमें 66270.27 करोड़ रूपये आयातित कंपनी तथा 102517.77 करोड़ रूपये स्वदेशी यूरिया कंपनियों को दिए गए हैं । इसी प्रकार आयातित पेस्टीसाईड्स एंड कैमिकल हेतु 52780.87 करोड़ रूपये विदेशी तथा 63355.65 करोड़ रूपये स्वदेशी पेस्टीसाईड्स एंड कैमिकल कंपनियों को सब्सिडी के रूप में जारी किए गए हैं ।

मैं कहना चाहता हूँ कि कैमिकल फर्टिलाइजर के रूप में तो सब्सिडी जारी की जाती है लेकिन प्राकृतिक उर्वरकों पर किसी प्रकार की कोई सब्सिडी जारी नहीं की जाती है जिसके चलते किसान जैविक खेती की ओर आकर्षित नहीं होते ।

रासायनिक खाद का प्रयोग पारंपरिक प्राकृतिक खाद्य के तरीके की जड़ से खत्म करता जा रहा है। रसायनों के प्रभाव से जमीन भी धीरे-धीरे बंजर होने लगती है और कीड़ों के अधिक पनपने की संभावना बनी रहती है जिससे बचने के लिए किसान अत्यधिक मात्रा में कीटनाशकों का प्रयोग करने लगते हैं । कुछ कीटनाशक तो सिस्टमेटिक होते हैं जो पानी या खाद के साथ घोलकर प्रयोग में लिए जाते हैं जिसका असर प्लांट के अंदर और उपज के अंदर तक हो जाता है । ये कीटनाशक ऊपर से स्प्रे किए जाने वाले कीटनाशकों से कहीं अधिक हानिकारक होते हैं । ऐसे कीटनाशक मानव शरीर के लिए अत्यंत हानिकारक होते हैं । हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस समस्या से किसान को निजात दिलाने के लिए हाल ही में राजस्थान में 'भूमि स्वास्थ्य कार्ड स्कीम' जारी की है जो अपने आप में पहला निर्णय है जिससे किसानों को अपनी जमीन में रसायनिक खाद के प्रयोग की जानकारी मिल सकेगी और किसान कम लागत में अधिक उत्पादन कर सकेगा । इसके साथ-साथ आमजन को सुरक्षित खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाई जा सकेगी । किसान चाहते हुए भी जैविक खाद और स्प्रे का प्रयोग नहीं कर पा रहा क्योंकि ये कैमिकल खाद व स्प्रे से अधिक महंगे हैं । जैविक खाद पर सब्सिडी नहीं दी गई तो हम चाहते हुए भी जैविक खेती को प्रोत्साहन नहीं दे पाएंगे ।

अतः मेरा केन्द्र सरकार से निवेदन है कि जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए प्राकृतिक खाद को सब्सिडी देने की कृपा की जाए ।

(vii) Need to organize exhibitions for demonstration and promotion of the achievements of students in the field of science and technology

श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश (सूरत) : भारत में कई ऐसे मेधावी छात्र या व्यक्ति हैं जिनको कुछ न कुछ नया करने का शौक होता है । कई बार ऐसी खोज कर देते हैं कि अगर उसे सुनिश्चित तौर पर देश के विकास में या लोगों की भलाई में लगाया जाए तो उसके देश को अच्छे परिणाम मिल सकते हैं, पर उनके समक्ष संसाधनों की कमी रहती है । मेरा आग्रह है कि देश में इंजीनियरिंग में पढ़ने वाले छात्रों के लिए ऐसी व्यवस्था खड़ी की जाए ताकि वे उनके ऐसे प्रोजेक्ट का डेमेन्स्ट्रेशन पूरे देश के सामने कर सकें और उनके ज्ञान एवं प्रतिभा को देश के हित में उपयोग करने का अवसर प्रदान किया जाए । मसलन जिस तरह 'पुस्तक मेला' लगता है, उस प्रकार 'वैज्ञानिक मेला' या 'मॉडल मेला' या 'इंजीनियरिंग एक्जीविशन' लगे जिसमें सिर्फ विद्यार्थियों के प्रोजेक्ट का प्रदर्शन हो और उनके बीच में स्पर्धा हो । ऐसी बेवसाइट शुरू करें जिससे देशभर में यदि किसान किसी भी क्षेत्र में ऐसा कार्य या शोधन किया हो, उसे वह प्रदर्शित कर सकें ।

(viii) Need to ensure active participation of Members of Parliament in planning, execution and monitoring of Centrally sponsored development schemes in the State

श्रीमती रमा देवी (शिवहर): आज देश में केन्द्र प्रायोजित योजनाआं की संख्या 66 है और केन्द्र सरकार अपने बजट में इनके लिए ढाई लाख करोड़ रूपये से अधिक आवंटन करती है । केन्द्र सरकार के कुल योजनागत बजट का 44 प्रतिशत इन्हीं केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के माध्यम से खर्च होता है । फिलहाल केन्द्र सरकार के 33 मंत्रालय और विभाग केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के लिए दिशा-निर्देश तैयार करते हैं जबकि इनका क्रियान्वयन राज्यों में होता है । बारहवीं पंचवर्षीय योजना से पहले केन्द्र प्रायोजित योजनाओं की संख्या 147 थी परंतु अब इनकी संख्या घटाकर 66 कर दी गई है । राज्यों को अधिक वित्तीय स्वायत्तता देने के नाम पर सांसदों के अधिकारों को कम नहीं किया जा सकता । आज व्यवहारिक रूप से राज्य सरकारों की नजर में वास्तविक रूप से सांसदों की कोई अहमियत नहीं है । जन-समस्याओं को हल करने की जिम्मेदारी मुख्य रूप से जन-प्रतिनिधियों विशेषकर सांसदों की होती है क्योंकि आम जनता को अपने सांसद को सम्पर्क करना ज्यादा आसान होता है ।

प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की तर्ज पर अगर केन्द्र प्रायोजित 66 योजनाओं में स्थानीय सांसद को योजना एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन की समीक्षा एवं अनुश्रवण के कार्य से जोड़ा जाता है तो इसका अच्छा परिणाम होगा । इसके लिए केन्द्र सरकार को खासकर प्रधानमंत्री कार्यालय को विशेष रूचि लेकर केन्द्र प्रायोजित योजनाओं में सांसदों के अहम रोल का प्रावधान कानूनी रूप से होना चाहिए । अर्थात् योजनाओं को चयनित करते समय सांसदों के द्वारा उन योजनाओं का अनुमोदन जरूरी कर देना चाहिए । ऐसा करने से राज्य सरकार के जो अधिकारी योजनाओं में गोलमाल करते हैं, उस पर लगाम लगेगा और यह देश हित एवं व्यापक जनहित में होगा । सांसदों को खोई प्रतिष्ठा वापस मिलेगी और संसदीय प्रजातंत्र मजबूत होगा ।

अतः मेरा प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के चयन से लेकर क्रियान्वयन तक में स्थानीय सांसद के द्वारा समीक्षा एवं अनुश्रवण कानूनी रूप से जरूरी कर दिया जाए ।

(ix) Need to provide adequate funds for construction of Gaya-Bodhgaya-Chatra railway line

श्री सुनील कुमार सिंह (चतरा) : मेरा संसदीय क्षेत्र चतरा (झारखण्ड) बहुत ही पिछड़ा क्षेत्र है । आवागमन की सुविधाओं का अत्यंत अभाव है । पूरा चतरा जिला रेलवे से अछूता है । चतरा से गया रेलवे लाइन प्रोजेक्ट का अंतिम सर्वेक्षण पूरा हो गया है । चतरा जिले में 37.672 एकड़ भूमि के लिए भूमि अधिग्रहण का कार्य भी लगभग हो चुका है । 2007-08 के बजट में चतरा-गया रेल लाइन निर्माण के सर्वे की स्वीकृति दी गई थी । इसके बाद 2009 में तत्कालीन रेल मंत्री द्वारा इस रेलवे का शिलान्यास बिहार में किया गया था ।

गया-बोधगया-चतरा लाइन की कुल लागत 549.75 करोड़ है जिसमें वर्ष 2013-14 में 1860.28 लाख तथा 2014-15 में 10 लाख आवंटन के बाद शेष 53104.72 लाख रूपयों की आवश्यकता है ।

रेल बजट 2015-16 में 1 करोड़ रूपये तथा 2014-15 का संशोधित परिव्यय 1 करोड़ रूपये किया गया है । शेष 531 करोड़ राशि अगर प्रतिवर्ष 1 करोड़ रूपये दिए जाएंगे तो 531 वर्ष इसे पूरा होने में लगेंगे । इस गति से पांच सदी लग जाएंगी । चतरा व गया दोनों ही महत्वपूर्ण स्थान हैं जहां जैन, बौद्ध व हिन्दू सबके आस्था का केन्द्र है ।

अतः मेरा माननीय रेल मंत्री जी से निवेदन है कि गया-बोधगया-चतरा रेल लाइन के लिए पर्याप्त राशि का आवंटन कर शीघ्र कार्य प्रारंभ कराया जाए तथा घोषित समय सीमा पांच वर्ष में कार्य को पूर्ण करवाने की व्यवस्था की जाए ।

(x) Need to include Jabalpur in the tourist circuit in Madhya Pradesh

श्री राकेश सिंह (जबलपुर) : मेरा संसदीय क्षेत्र जबलपुर (म0प्र0) पर्यटन की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण स्थल है । सम्पूर्ण भारत के केन्द्र स्थल भी जबलपुर के नजदीक ही है । पर्यटन की दृष्टि से इस क्षेत्र में असीम संभावनाएं हैं । विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल भेड़ाघाट जहां संगमरमर की चट्टानों के बीच वॉटरफॉल है। इसके अतिरिक्त बरगी डेम, डुमना नेचर रिजर्व, रानी दुर्गावती समाधि स्थल, मदन महल का किला इत्यादि अनेक महत्वपूर्ण स्थानों के साथ जबलपुर से 200 किलोमीटर के रेडियस में देश के प्रसिद्ध नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, घुघवा फॉसिल्स पार्क, पंचमढ़ी, खजुराहो, अमरकंटक, चित्रकूट इत्यादि स्थित है । अत्यंत महत्वपूर्ण बात यह है कि इन क्षेत्रों में पर्यटन के सभी फ्लेवर सम्मिलित हैं ।

जबलपुर में जहां धार्मिक एवं ऐतिहासिक टूरिज्म तथा एडवेंचर टूरिज्म हैं वहीं कान्हा, बांधवगढ़, पेंच, वाइल्ड लाइफ टूरिज्म तथा इको टूरिज्म के लिए जाने जाते हैं । खजुराहो में हेरिटेज टूरिज्म हैं जहां पूरे विश्व के पर्यटक अमरकंटक में धार्मिक तथा इको टूरिज्म हैं, घुघवां फॉसिल्स पार्क में डायनासोर के करोड़ों वर्ष पुराने फॉसिल्स हैं । इस तरह पर्यटकों हेतु सभी आवश्यक पर्यटनीय आकर्षण इस सर्किट में उपलब्ध हैं।

माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश में पर्यटन के 50 नए सर्किट निर्माण तथा उनमें आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर निर्मित करने की घोषणा की है जो अत्यंत सराहनीय है ।

अतः मेरा केन्द्र सरकार से आग्रह है कि जबलपुर (म0प्र0) को टूरिस्ट सर्किट शामिल करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट किया जाए ।

(xi) Need to provide free electricity for operation of motor pumps for supply of drinking water in Chhattisgarh

श्री ताम्रध्वज साहू (दुर्ग) : वर्तमान समय में पूरे देश में आम जनता को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना सरकार के लिए एक कठिन एवं चुनौती भरा कार्य हो गया है । केन्द्र व राज्य की सरकारें अनेक प्रकार की योजनाएं बनाकर इस कार्य को कर रही हैं जो विभिन्न कारणों से अपर्याप्त होता है ।

विशेषकर छत्तीसगढ़ में नल-जल योजना, स्पॉटसोर्स आदि के माध्यम से गाँव में पेयजल उपलब्ध कराने का काम सरकार कर रही है । इस कार्य में लगने वाले बिजली बिल सरपंचों को पटाने का जिम्मा दिया गया है । सरपंचों के पास इस हेतु अलग से कोई फंड नहीं होता । बिजली बिल नहीं पटने के कारण विद्युत विभाग लाइन काट देता है । गाँव वालों को पीने का पानी 1-2 किलोमीटर दूर से लाना पड़ता है ।

अतः मेरा केन्द्र सरकार से निवेदन है कि प्रत्येक गाँव में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हेतु प्रत्येक गाँव में 1 एचपी या 2 एचपी के पम्प को निःशुल्क विद्युत प्रदान करने हेतु योजना बनाकर तत्काल आवश्यकता वाले राज्यों को आदेश जारी करेंगे जिससे आम जनता को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जा सके ।

(xii)Need to allocate funds for gauge-Conversion of railway line between Madurai and Bodinayakkanur and construction of new railway line between Dindigul-Sabarimala

SHRI R. PARTHIPAN (THENI): I would like to bring it to the kind notice of the Government that Madurai - Bodinayakkanur railway line is in my parliamentary constituency. Due to broad-gauge conversion in the year 2010, rail services were stopped on this rail route. A study for financial estimation was done in the year 2011 and since then the work has not commenced. Transportation of people and several business activities have been affected. Even though a new railway line between Dindigul-Sabarimala (Kerala) was announced, no work has begun in this regard. Several lakhs of pilgrims and devotees of Lord Sri Ayyappa belonging to the States of Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Karnataka and Maharashtra are affected due to lack of adequate rail connectivity to Sabarimala. The pilgrims are now forced to travel by overcrowded buses. There were expectations that there would be announcements in this regard in the railway budget presented on 26 February 2015. It is highly disappointing that no allocation has been made for these rail projects in the current budget. I, therefore, urge the Ministry of Railways to allocate funds for these projects and expedite their implementation.

(xiii) Need to accord approval to the proposal of government of Tamil Nadu for construction of dams at Nallar and Anamalaiar in the State

SHRI C. MAHENDRAN (POLLACHI): Tamil Nadu Government has prepared a Blue Print to construct two dams at Nallar and Anamalaiar at a cost of Rs.1,540 crore. These dams with a capacity of 9.5 tmc will utilise fully the waters from both Upper Nirar and Lower Nirar Dams which release 7 tmc and 2.5 tmc respectively. The Upper Nirar Dam that gets water from southwest monsoon is currently diverted through Solayar Dam, Parambikulam and Thunakkadavu Dams and reaches Tirumoorthy Dam through Contour Canal covering a distance of 120 Kilometers. The inflow of water is heavy during the rainy seasons. This excess water can be taken to a distance of 14.4 Kilometers through a canal and tunnel to the dam to be constructed at Nallar which is 3214 ft. above sea level. Two power sub-stations with a capacity of 125 megawatt each can be set up there to generate 200 megawatt of electricity. The water can be further taken to Tirumoorthy Dam which is at a height of 1336 ft. above sea level. This will irrigate 5,000 acres of dry land while increasing drinking water supply. Additional 250 megawatt capacity power generation unit can also be set up there. The water transmission loss will be minimised.

Hence, I urge upon the Union Government to take steps to obtain clearance from Central Water Authority to construct the Nallar and Anamalaiar Dam Projects.

(xiv) Need to relax the conditions of eligibility for Indira Gandhi National Disability Pension Scheme

SHRI SUVENDU ADHIKARI (TAMLUK): I would like to share the information that a flagship social welfare programme of Govt. of India namely National Social Assistance Programme was started by the Union Ministry of Rural Development with a noble mission in pursuit of article 41 of our Constitution. Indira Gandhi National Disability Pension Scheme is one of 'five major components of National Social Assistance Programme' and as per present criteria, a person, to become a beneficiary under this social scheme, must belong to a BPL family and has to be within the age group of 18 to 64 years with severe or multiple disabilities having 80 per cent or more disabilities or combination of two or more disabilities. If all these criteria are fulfilled, a beneficiary will be given an assistance of Rs. 300 per month. But, I would like to emphasize that whenever a social assistance programme is formulated, it must have a great vision to provide relief to maximum number of distressed people, more precisely all the distressed people in our society. But in my view the present Disability Pension Scheme is not capable of covering all the distressed if the present criteria are not changed suitably. After all, pension is given to the disabled persons because they cannot earn their livelihood independently. But the present amount given as pension is not sufficient for them. Besides, the persons with less than 80 per cent disabilities also find their lives in uncertainties without social support and it is not that a person, if he/she is not of minimum 18 years, does not need such support.

I, therefore, earnestly request Hon'ble Union Minister of Rural Development to withdraw the age bar and fix the minimum disability percentage as 10 per cent instead of present 80 per cent for a person to become eligible for the scheme. I would further request for enhancing the amount of pension being linked to inflation index.

(xv) Need to release the funds allotted for various flagship schemes meant for Odisha

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Inadequate allocation for flagship schemes is hurting the development process of Odisha. This is affecting important plan schemes like Accelerated Irrigation Benefit Programme (AIBP) and Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana. Such drastic reduction has adversely affected the liquidity position of Odisha Government and would seriously impact the implementation of various plans and programmes of Odisha Government for which expenditure commitment has been made.

Odisha has spent Rs. 1088.62 crore in 2012-13 and Rs. 967.57 crore in 2013- 14 for implementation of the Accelerated Irrigation Benefit Programme (AIBP). Government of India have released only Rs. 38.24 crore in 2012-13 and Rs. 15.23 crore in 2013-14 against an allocation of Rs. 1036.66 Crore in 2012-13 and Rs. 850 crore allotted by the Planning Commission in 2013-15. Reimbursement claim approximately Rs. 970 crore under AIBP pertaining to the year 2012-13, 2013-14 and 2014-15 is pending.

Similarly under Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana the shortfall is around Rs. 522 crore. There is also substantial shortfall in release in Central assistance for other flagship schemes like ICDS, RAMSA, RUSA, NRLM. I would urge upon the Government to release the funds urgently for which financial commitments were made.

(xvi) Need to confer rights to Members of Parliament regarding construction of roads under the Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana

श्री रामा किशोर सिंह (वैशाली) : हमारा संसदीय क्षेत्र वैशाली (बिहार) विश्व प्रसिद्ध पर्यटक और ऐतिहासिक स्थल है परंतु इस क्षेत्र के ग्रामीण सड़कों की स्थिति जर्जर है । इसके अतिरिक्त क्षेत्र की कई महत्वपूर्ण सड़कें बारहमासी सड़कों से नहीं जुड़ी हैं और कई अन्य महत्वपूर्ण सड़कों को जोड़ने की आवश्यकता है । प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना केन्द्र प्रायोजित योजना है परंतु राशि संबंधित राज्य सरकार को आवंटित और विमुक्त की जाती है जिसके कारण संवेदकों और राज्य सरकार की उदासीनता के कारण सड़कों का निर्माण कार्य अधूरा रहने के कारण आम लोगों को कठिनाई होती है । अतः संबंधित सांसदों को उक्त योजना के अंतर्गत सड़क निर्माण की अनुशंसा का अधिकार देना बेहतर होगा ।

अतः मेरा केन्द्र सरकार से आग्रह है कि क्षेत्र की निर्माणाधीन और अधूरी सड़कों के निर्माण कार्य को शीघ्र पूरा कराने की व्यवस्था करते हुए माननीय सांसदों को उक्त योजना के अंतर्गत नई सड़कों के निर्माण कराने का अधिकार प्रदान कराने की व्यवस्था की जाए ।

(xvii) Need to revive the closed sugar mills in Bihar and also provide a special package for development of silk industry in Bhagalpur in the State

श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा) : आम चुनाव के समय माननीय प्रधानमंत्री जी ने बिहार के लोगों से वायदा किया था कि मैं ही बिहार को उन्नति के पथ पर ला सकता हूँ और यह भी कहा था कि बिहार की सभी बन्द पड़ी चीनी मिलों को फिर से चालू किया जाएगा । इसी प्रकार भागलपुर, जो कि रेशम उद्योग के लिए विख्यात था, आज अपना अस्तित्व खोता जा रहा है । उसे भी विकसित किया जाएगा, जिससे कि वहाँ के करीब पाँच लाख बुनकरों की स्थिति में सुधार लाया जा सके । वे अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी विशेषकर बुनकरों के लिए योजनायें बनवा रहे हैं, उसी के साथ भागलपुर को भी जोड़ा जा सकता है।

उत्तर बिहार की बन्द पड़ी चीनी मिलों में लाखों लोग कार्यरत थे । वे आज भुखमरी के कगार पर हैं । किसानों की हालत दयनीय होती जा रही है । गन्ना का उत्पादन बन्द करना पड़ा, क्योंकि चीनी मिलें बन्द हो चुकी हैं । बेरोजगारी बढ़ती ही जा रही है । राज्य सरकार अपने सीमित संसाधनों से इसका विकास नहीं कर सकती है ।

अतः मेरी माँग है कि केन्द्र सरकार विशेष पहल कर बिहार की बन्द पड़ी चीनी मिलों को आर्थिक मदद प्रदान करे । साथ ही साथ भागलपुर में भी रेशम आधारित उद्योगों की स्थापना और विकास हेतु बिहार राज्य के लिए विशेष पैकेज मुहैया कराये, जिससे कि वहाँ का सर्वांगीण विकास किया जा सके । बहुत-बहुत धन्यवाद ।

(xviii) Need to set up a AIIMS like institute in Bhagalpur, Bihar

श्री शैलेश कुमार (भागलपुर): बिहार राज्य के लिए बजट 2015-16 में भारत सरकार द्वारा दूसरे एम्स के लिये घोषणा की गई है । बिहार राज्य के भागलपुर जिला सहित आस-पास के कई जिलों में मल्टी स्पेशियलिटी अस्पताल नहीं हैं जिसके चलते गंभीर रूप से घायल, बीमार व्यक्तियों का इलाज नहीं हो पाता है । बिहार राज्य के पूर्वी सीमा पर स्थित भागलपुर में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के खोले जाने की आवश्यकता है अगर यह संस्थान भागलपुर में स्थापित किया जाता है तो बिहार सहित झारखण्ड तथा पश्चिम बंगाल के गरीब मरीजों को इसका सीधा लाभ मिल सकेगा । इस क्षेत्र में एम्स जैसे संस्थान की सुविधा नहीं होने से गंभीर बीमारियों तथा दुर्घटना में घायल लोगों को पटना तथा दिल्ली ले जाना पड़ता है जिससे गरीब मरीजों का आर्थिक बोझ बढ़ जाता है । साथ ही साथ लम्बी दूरी तक इलाज के लिए जाने के क्रम में मृत्यु हो जाती है ।

अतः मेरा केन्द्र सरकार से निवेदन है कि बिहार राज्य के भागलपुर में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) की इकाई खोले जाने को मंजूरी देने का कार्य किया जाए जिससे गंभीर बीमारियों तथा दुर्घटना में घायल लोगों का अति तत्काल समुचित इलाज कराया जा सके ।

(xix) Need to safeguard the life and livelihood of people living in and around the Bodi area of Western Ghats selected for the proposed India-based Neutrino Observatory

ADV. JOICE GEORGE (IDUKKI): The proposed India-based Neutrino Observatory (INO), the largest underground science laboratory in the world, is coming up in Bodi Hills of the Western Ghats which is in the highly deformed portion of the Suruli ductile Shear Zone. The proposed observatory will cause heavy blasting and dislocation of rocks underneath the Bodi Hills. There are many reservoirs within 50 km radius of the proposed site. The people in the region are worrying as the blasting of ones of rock will severely affect the aquifer, the rivers and the reservoirs. Moreover, the local population is worrying about radiation hazards too. Several agitations have reportedly taken place in the area against the INO project. Till date, there is no consultation with the neighbouring state Kerala about the project, even though the INO site was on Kerala – Tamil Nadu border. Hence, I urge upon the Government to intervene to safeguard the life and livelihood of people in the area.

14.17 hrs

STATUTORY RESOLUTION RE: DISAPPROVAL OF RIGHT TO FAIR COMPENSATION AND TRANSPARENCY IN LAND ACQUISITION, REHABILITION AND RESETTLEMENT (AMENDMENT) ORDINANCE, 2014
AND
RIGHT TO FAIR COMPENSATION AND TRANSPARENCY IN LAND ACQUISITION, REHABILITATION AND RESETTLEMENT (AMENDMENT) BILL, 2015 – Contd.

HON. DEPUTY SPEAKER: Shri Prahlad Singh Patel.

श्री प्रहलाद सिंह पटेल (दमोह): उपाध्यक्ष महोदय, मैं भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 का संशोधन करने वाले विधेयक के समर्थन में अपनी बात कहने के लिए यहां पर खड़ा हूं।

हमारी सरकार के नेतृत्व के प्रति हमारा अपना भरोसा मेरे समर्थन का एक बड़ा आधार है। इस सरकार का काम-काज और सरकार की विश्वसनीयता, जो हम पूरे दावे और विश्वास के साथ कह सकते हैं कि वह कभी किसान विरोधी नहीं हो सकती। हम यह मानते हैं कि जो 1894 से लेकर 2013 तक 100 वर्ष के बाद उस कानून में संशोधन करने की जो गति हमारी पूर्ववर्ती सरकारों में रही है, वह किसान के लिए सर्वाधिक कष्टकारी समय रहा है। मैं यह मानता हूं कि इसमें जो सत्य और तथ्य है, उससे परे जो भ्रमों की बात हो रही है, उस पर इस सदन को जरूर पारदर्शिता के साथ विचार करना चाहिए। हम पूरे विश्वास के साथ यह कहते थे कि किसी उद्योगपति को लाभ देने की कोई जरूरत नहीं है या किसी प्रकार का संदेह करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जितने भी वक्ता इसके पहले बोले, जो हमारे प्रतिपक्ष में थे, उन्होंने इस बात का आरोप लगाया, लेकिन आज सरकार ने उस मंशा को भी साफ कर दिया कि अगर कोई शब्दावली है तो उसको संशोधनों के माध्यम से स्पष्ट कर दिया कि हम किसी प्राइवेट संस्था के लिए भी किसान की जमीन का अधिग्रहण नहीं करेंगे, जो सदन में सरकार लेकर आ रही है।

दूसरे सबसे बड़ी बात होती है कि जब कानून बनता है तो राज्य उसके नियम बनाते हैं। कुछ परम्पराएं हैं, जो हम सब राजनेताओं के साथ चलती हैं। हम जन-प्रतिनिधि हैं, कानून तो 100 साल तक अंग्रेजों का चलता रहा, लेकिन न्याय के लिए हम सब लड़ते रहे, हम जैसे लोग किसानों का आन्दोलन चलाते रहे, क्योंकि, वह कानून, जिसकी यह बात की जा रही है, 2013 में जिसका संशोधन लाया गया था, उसको 118 साल तक इस कष्ट को देश के किसानों ने झेला। इसके लिए जिम्मेदार कौन है, इसका

फैसला यह सदन करेगा, देश करेगा, लेकिन मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं कि आज जो कानून लाया जा रहा है, जो संशोधन के साथ आपके सामने, सदन के सामने है, इसमें किसान का विरोध नहीं हो सकता। यह कानून संरक्षण देता है। किसान की ज़मीन के बदले ज़मीन दी जाएगी, यह जुमला भी चलता रहा है। हम लोग भी इस बात की वकालत करते रहे हैं, लेकिन रकबा घटने के बाद अब वह इस देश में संभव नहीं है। अब दूसरी बात आती है कि उसका मूल्य उसे मिलेगा या नहीं? विस्थापन के बाद उसे जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, वे उसे मिलेंगी या नहीं? यह राज्य के नियम के तहत तय होगा कि वह उसकी भरपाई कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तीसरी बात, उसके बाद भी यह बचेगी कि हम सब मिल कर कुछ ऐसी परंपराओं को स्थापित करें कि गरीब किसान को उसका नुकसान न हो। उसके बच्चों का भविष्य भी सुरक्षित रहे। इसका साफ परिणाम है कि इस विधान के बाद जो सरकार संशोधन लेकर आना चाहती है, उसमें कहा गया है कि जो पूर्णतः कृषि पर आश्रित हैं, अगर उस परिवार की ज़मीन ली जाएगी तो उसी प्रतिष्ठान में उस परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाएगी। यह सरकार का वादा है। आप कैसे कह सकते हैं कि हम किसानों का हित नहीं देख रहे हैं? मुझे लगता है कि बात यह आती है कि जब कभी हम विस्थापन करते हैं या उन्हें मुआवज़ा देते हैं तो हम उन्हें उसकी कीमत दे पा रहे हैं या नहीं।

उपाध्यक्ष जी, हमारे मित्र सिंधिया जी अभी यहां नहीं हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं। हम मध्य प्रदेश से आते हैं। मध्य प्रदेश में एक समय चरनोई भूमि, जो मवेशियों के लिए हुआ करती थी, वह 7.5% थी। इन लोगों ने सारी भूमि को बांटकर उसे 2% पर लाकर खड़ा कर दिया। कानून होने के बावज़ूद भी ये राज्य सरकारों के कामकाज हैं। आज सरकारी ज़मीन नहीं है। मैंने ही यह प्रश्न उठाया है कि इस देश में ऐसी कितनी ग्राम पंचायत हैं, जहां पर स्कूल और किसी भी प्रकार के मैदानों को बनाने के लिए एक एकड़ भी सरकारी ज़मीन नहीं हैं? उसका जवाब आ रहा है। पर, मेरे पास जो आंकड़े हैं, उसके अनुसार लगभग बीस हजार से ज्यादा ऐसी पंचायतें हैं, जिनके पास एक एकड़ ज़मीन भी सार्वजनिक हित के लिए नहीं है। कभी तो आपको इसे लेना पड़ेगा। लेकिन आप ज़मीन के बदले उन्हें क्या देंगे? यह सबसे अहम सवाल है। जब कभी कानून बना था कि हम मार्केट रेट का चार गुणा देंगे। वह आज भी है, बल्कि उससे भी बढ़कर इसमें मिला है।

महोदय, मैं एक आंकड़ा देना चाहता हूं। वर्ष 2013 का कानून बना। कानून बनने के पन्द्रह महीनों के बाद भी देश की कोई भी राज्य सरकार एक डेसिमल ज़मीन भी अधिग्रहित करने का साहस नहीं जुटा सकी। यह उसका प्रमाण है। लेकिन जैसे ही यह सरकार वर्ष 2014 में यह अध्यादेश लेकर आयी, उसके बाद मेरे पास एक आंकड़ा है कि एन.एच.ए.आई. के लिए किसानों की ज़मीन अधिग्रहित की गयी, जो राज्य सरकारों के माध्यम से की गयी। उन्हें जो पहले मुआवज़े के रूप में 60,000-70,000 करोड़ रुपये

मिलना था, इस कानून के तहत उन्हें लगभग 1,40,000 करोड़ रुपये मुआवज़े के तौर पर दिया गया। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या इसमें किसानों का हित नहीं है? हमें यह तय करना पड़ेगा कि हम देश को क्या बताना चाहते हैं, देश के सामने क्या संदेश देना चाहते हैं?

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे यहां एक बाणसागर परियोजना थी। मोरारजी देसाई जी ने उसका भूमि पूजन किया था, अटल जी ने उसका लोकार्पण तब किया जब मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गयी। भूमि विवाद के कारण वह लगभग 40 सालों तक पड़ी रही। जहां से मैं आता हूं, रानी अवन्तिबाई सागर, जिसे वर्ष 1982 में पूरा हो जाना चाहिए था, सिर्फ़ ज़मीन के विवाद के कारण वह आज भी पूरा नहीं हो सका है। गोल्डेन क्वाडिलेटरल परियोजना, जो अटल बिहारी वाजपेयी लेकर आए थे, दक्षिण से लेकर उत्तर तक का जो कॉरिडोर है, आज वह मेरे प्रदेश में और महाराष्ट्र में पेंच अभ्यारण्य के कारण रूका है और वह सिर्फ़ और सिर्फ़ जमीन विवाद के कारण ही रूका है। अगर उसका जिम्मेदार कोई है तो मैं कह सकता हूं कि उसके लिए कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। मैं यह केवल आरोप की दृष्टि से नहीं कह रहा हूं।

हमारे सिंधिया जी उस दिन इस पर भाषण कर रहे थे। अभी वह यहां नहीं हैं। मणिखेरा बांध उनके लोकसभा क्षेत्र में आता है। श्री सक्लेचा जी ने उसका भूमि पूजन किया था, शिवराज जी ने उसका लोकार्पण किया। सरकारें आती गयीं और चली गयीं, लेकिन हम ज़मीन का विवाद नहीं निपटा पाए। अगर वह काम किसी ने किया तो हमारी पार्टी की राज्य सरकारों ने किया। नियम बनाने में हम सिर्फ लीक पर चलने के आदी नहीं हैं। हम ऐसा नहीं करते कि जो कानून में लिखा है, वही कर दो।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बारे में कहूंगा कि पंजाब में एक तरीका अपनाया गया। उसे सरकार को भी ध्यान में रखना चाहिए। सर्किल रेट और मार्केट रेट के बीच में कई ज़गहों पर बहुत अन्तर होता है। हम जनप्रतिनिधियों को उसमें जरूर रखें, क्योंकि मैंने कहा कि कानून, नियम और कई परंपराएं भी होती हैं। अगर कभी हमें राज्य सरकारों को कोई हिदायत देनी पड़े तो हमें देनी चाहिए कि सिर्फ कलक्टर के भरोसे नहीं, कहीं न कहीं उसमें जनप्रतिनिधियों की हिस्सेदारी भी करनी चाहिए। तब जाकर उसका ठीक प्रकार से मुआवज़ा बंटेगा।

महोदय, मैं आपको इसका भी एक उदाहरण देना चाहता हूं।

HON. DEPUTY SPEAKER: I want to inform the hon. Members that the Bill is going to be taken up for voting very soon. I am having a long list of nearly 20 members who want to speak on this Bill.

Therefore, I am requesting you to be very brief and do not take more than five minutes.

श्री प्रहलाद सिंह पटेल : उपाध्यक्ष जी, मैं दो या तीन मिनट में अपनी बात समाप्त कर दूंगा, आपको दोबारा घंटी नहीं बजानी पड़ेगी।

मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, मेरी ही सरकार है, मैं एक आंदोलन सिंगरौली में चला रहा था। एक एस्सार नाम की वहां कंपनी है। वहां जमीन अधिग्रहीत की गई, अधिकारी ने उसका पंचनामा बना लिया। अधिकारी ने सब जमीन के आगे सिंचित लिख दिया। अधिकारी ने घर जाकर अपनी हैंडराइटिंग में उसके पहले अ लिख दिया तो वह असिंचित हो गया। ये जो प्रक्रियाएं हैं, राज्य के नियमों के साथ जो खिलवाड़ करने वाले लोग हैं, इनको कैसे रोकेंगे, यह राज्य का विषय है। मैं समझता हूं कि सदन को इस बात की चिंता करनी चाहिए कि किसान लुटता कहां है, किसान की तकलीफ कहां है। मुझे लगता है कि अगर हम इस पर सार्थक बहस करेंगे तो इस अधिनियम पर जो चर्चा होगी, वह देश के किसान के हित में होगी। अगर हम एक-दूसरे के खिलाफ बोलेंगे, इससे कोई रास्ता निकलने वाला नहीं है। बहुत सारे ऐसे बिंदु हैं, जो कानून समझने वाले हमारे मित्र हैं, वे उस पर अपनी बात कहेंगे। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि हम सब यहाँ पर किसान और मजदूर के लिए जवाबदेह हैं। मैंने अपनी बात यहीं से शुरू की थी, लेकिन जो वास्तव में तकलीफ है, वह है हमारे मनों की खटास। मुझे लगता है कि हम सब एक-दूसरे के बारे में सिर्फ राजनीतिक तरीके से विरोध करने के लिए हैं। हम जब सेन्ट्रल हॉल में बैठते हैं, तो हमें पता चलता है कि बड़ी परियोजनाओं के लिए जमीन चाहिए, विकास के लिए जमीन चाहिए। लोग कह सकते हैं कि किस कीमत पर चाहिए। मैं किसान का बेटा हूँ, मेरे घर में एक पाई भी कहीं और से नहीं आती है।

अंत में, मैं दुष्यंत कुमार जी की बात कहकर अपनी बात समाप्त करता हूँ। मैं इसे पहले बोलता, लेकिन आखिर में बोल रहा हूँ कि कुछ बहुत गहरी दरारें पड़ गई हैं मन में, मीत अब यह मन नहीं है एक धरती है। हम एक बच्चे की तरह पढ़ते थे, 'वीर भोग्य वसुंधरा'। हमारी सरकार का जो मत है, मेरे गुरूदेव ने मुझसे कहा था, 'वीर योग्य वसुंधरा'। हम ऐसे कानून बनाएं, जो आम गरीब आदमी को हित पहुँचाने वाले हों, संरक्षण करने वाले हों, इस खुले मन से आप विचार करेंगे तो मुझे लगता है कि इस अध्यादेश का आप भी समर्थन करेंगे। मैं इसका समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री गौरव गोगोई (कलियाबोर): महोदय, वर्ष 2013 में इस संसद में एक ऐतिहासिक बिल पारित हुआ। एक ऐसा बिल जिसमें उद्योग और किसानों के बीच में एक सन्तुलन लाया गया। एक ऐसा बिल जिसमें प्रगति, विकास और अधिकार को बराबर देखा गया। इससे पहले यदि भूमि का अधिग्रहण होता था तो वर्ष 1984 के कानून के हिसाब से होता था। उस बिल में किसानों की जमीन जबरन ली जाती थी और उनको मुनासिब मुआवजा भी नहीं दिया जाता था। लेकिन वर्ष 2013 में ऐसा भूमि अधिग्रहण बिल आया, जिसने किसानों के सालों के संघर्ष को सुना और किसानों को मजबूत बनाने के लिए उसकी तरफ सम्मान और दोस्ती का हाथ बढ़ाया गया और सहमति, सामाजिक प्रभाव का आकलन, पुनर्वास, पुर्नस्थापन, जमीन वापसी का प्रावधान और अन्य कई ताकत किसानों की दी गईं। इसमें कोई शक नहीं है कि इस ऐतिहासिक बिल में जिसे हम भारत में लाए, वर्ष 1984 के बाद इस बिल को लाने में किसानों के साथ अगर कोई कंधा से कंधा मिलाकर चल रहा था तो वे राहुल गाँधी जी थे, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। भारत में जब भी कोई गरीब और कमजोर अपनी आवाज उठाता है तो उसको अमीर और ताकतवर कुचल देते हैं। ...(व्यवधान) आज यही हुआ। इस नई सरकार को सात महीने भी नहीं हुए और उन्होंने वर्ष 2013 के भूमि अधिग्रहण बिल को सात महीने में नकार दिया। जिस अधिनियम को लाने में सात साल तक चर्चा हुई, दो स्टैंडिंग कमेटीज की रिपोर्ट आयीं और विभिन्न संशोधनों के बाद लाया गया, उसे आपकी सरकार ने 9 महीने में ही निकाल दिया। सहमति और सामाजिक प्रभाव का आकलन, जो पिछले अधिनियम के दायें और बायें बाजू थे, इन दायें और बायें बाजू को नई सरकार ने काटकर फेंक दिया है। मैं पूछना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों हुआ? क्या किसान आन्दोलन पर आ गया था, क्या किसान आपके घर के बाहर आन्दोलन कर रहे थे कि सहमति का क्लॉज हटा दीजिए, क्या किसान आन्दोलन पर आया था कि सामाजिक प्रभाव का आकलन हटा दीजिए, नहीं, किसानों की यह माँग नहीं थी। किसान चाहता था कि ये दो मूल तत्व इस संशोधन में रहें। आपने किनकी आवाज सुनी, आपने बड़े उद्योगपतियों की आवाज सुनी, बड़े पूंजीपतियों की आवाज सुनी, जो कॉरपोरेट बोर्ड रूम में बात करते हैं, जो कहते हैं कि लैंड एक्वीजिशन में बहुत समय लग रहा है, कन्सेंट के कारण बहुत समय लग रहा है। सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट के लिए प्रोजेक्ट बहुत एक्सपेंसिव हो गए हैं। आज उन कॉरपोरेट बोर्ड रूम की आवाज संसद के इस मन्दिर में सुनाई दे रही हैं, इससे ज्यादा शर्मनाक बात नहीं हो सकती है।

लेकिन, मैं कहना चाहूंगा कि बी.जे.पी. सरकार को इस नये अधिनियम को लाने के लिए बहुत काम करना पड़ा है। सबसे पहला काम वर्ष 2013 के अधिनियम पर कीचड़ फेकने का काम शुरू हुआ। मैं पूछना चाहता हूं कि इतनी अर्जेन्सी क्या थी? आपकी सरकार नई आयी है। आप पहले वर्ष 2013 के अधिनियम को लागू करते। आप पहले उसे अध्ययन करते कि कितने प्रोजैक्ट्स लैण्ड ऐक्विजिशन के कारण रुके हुए हैं। आप उसे अध्ययन करते कि कितने रेलवे प्रोजेक्ट्स और डिफेन्स प्रोजेक्ट्स भूमि अधिग्रहण के कारण रुके हुए हैं, उसके बाद आप उनके लिए रास्ता निकालते, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। प्राइवेट कम्पनी, वन मैन कम्पनी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनर्शिप, एन.जी.ओज. सोसायटी, ऐसे लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए उसमें घुस सकते हैं। आपने उनके लिए आपने रास्ता खोल दिया है, उनके लिए आपने दरवाजे खोल दिए हैं। उद्योगपति ने इस सरकार को सिर्फ झुकने के लिए कहा। आपने किसानों की अमानत को बलिदान कर दिया। आप जिन किसानों के विश्वास से इस संसद में आए हैं, आज आपने उनको पीठ दिखा दी।

मैं कहना चाहता हूं कि कुछ दिन पहले वित्त मंत्री अरुण जेटली जी ने कहा था कि हमें उद्योग को बुरा नाम नहीं देना चाहिए। मैं विनम्रता से कहना चाहता हूं कि किसानों और कृषि को भी बुरा नाम नहीं देना चाहिए। अगर एक सिपाही हमारे देश की सीमा की सुरक्षा करता है तो एक किसान हमारे भारत के भविष्य, बढ़ती आबादी के लिए खाद्य की सुरक्षा करता है। आज किसान और जवान को विपरीत पक्ष में न रखिए। यह न कहें कि आज किसान उन्नति के खिलाफ हैं। किसान भारत की उतनी ही चिन्ता करते हैं, जितनी भारत की चिन्ता सिपाही करते हैं।...(व्यवधान) आज बहुत सारे संशोधन आए हैं, लेकिन ये कॉस्मैटिक चेन्जेज हैं। वर्ष 2013 के विधेयक की जो मूल आत्मा है - सोशल इम्पैक्ट असेसमेन्ट और कन्सेन्ट, आज वे दो आत्मायें हैं लेकिन वह आवाज आपकी अमैण्डमेन्ट में सुनायी नहीं पड़ रही है।

मैं आपसे विनम्रता से रिक्वेस्ट करता हूं कि हम अभी कुछ समय बाद वोट करेंगे। आप वोट करने से पहले गांधी जी का मूल मंत्र याद करिए, किसी महत्वपूर्ण निर्णय से पहले किसी गरीब आदमी के बारे में चिन्ता करिए। आज मैं आपसे वही रिक्वेस्ट करता हूं कि आप वोट करने से पहले अपनी आंख बंदकर, अपने संसदीय क्षेत्र के किसी एक किसान के घर के बारे में चिन्ता करिए, उसके बाद आप गरीब और कमजोर के पक्ष में वोट करिए, न कि अमीर और ताकतवर के पक्ष में। इतना कह कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं, धन्यवाद।

*SHRI RANJIT SINGH BRAHMPURA (KHADOOR SAHIB): Hon'ble Deputy Speaker Sir, I am grateful to you for giving me the opportunity to speak on the 'Land Acquisition' Bill.

Sir, Punjab is the granary of the country. It provides 40 to 50% foodgrains in the central pool. Although the area of Punjab is hardly 1.54% of the total area of the country, but the farmers of Punjab produce a bumper harvest of foodgrains by the dint of their sweat and blood. The land of Punjab is also very fertile.

Sir, due to the burgeoning population and spread of towns and cities, the farmers are also losing fertile and cultivable land. It is a matter of grave concern. So, only non-cultivable land should be acquired for industrial etc. purpose.

Sir, although India is largely self-sufficient as far as food-grains is concerned, but if monsoons fail, the production of foodgrains suffers and self-sufficiency in food-grains becomes a casualty. So, Punjab Government has followed a policy of seeking the consent of people whose land is being acquired. They are also provided adequate compensation at the prevailing market rate. As a result, the land acquisition policy in Punjab has been followed without any complaints or problems.

Sir, the land acquisition policy of Punjab has been followed since long. It has been a great success. Keeping our experience of Punjab in view, we demand that several amendments must be made in the present bill.

Sir, the Land Acquisition Bill, 2013 as well as the amended Bill are not providing adequate compensation to farmers at the market rate. The policy of Punjab seeks the consent of farmers and does not indulge in injustice towards the farmers. Forcible acquisition of land is never done. So, the consent of majority of

* English translation of the speech originally delivered in Punjabi.

land-owners, whose land is being acquired, must be taken. No other method of acquisition of land should be adopted.… (*Interruptions*)

Sir, the interest of landowners, whose land is being acquired, must be taken into account. They must be provided prevailing market rate for the land acquired. They shold be provided eviction allowance also and a land-pooling system should be envisaged. They should be included in the decision-making process and treated as partners.

Sir, for fixing the compensation package, a district committee is formed under the D.C. of the area. The Lok Sabha Member of the area, the MLA of the area, the Block Chairman, Local Village Head or Mayor etc. are part of the committee. This committee also holds consultations with concerned landowners and other stakeholders.

Sir, Punjab has successfully adopted this committee system for land-acquisition and we have never faced any problem in this process. No land-owner has ever felt that injustice has been done to him. As per the other option, all land owners follow the land-pooling system. As per this policy, the landowners are provided 50% share in the business and trade areas. So, the land-owners become willing stakeholders and partners in this process. Multi-crop land is acquired only if it is absolutely necessary to do so.

Sir, we suggest that the Central Government should keep in mind the successful Land-Acquisition Policy of Punjab while finalizing the Central Land Acquisition Policy. The Government must acquire land only for public interest. The Government must not interfere on behalf of private industrialists as far as land- acquisition is concerned. Land-owners must be made partners in this process.

Sir, as per the first option, the prevailing market-rate and eviction-allowance must be provided to the land-owners whose land has been acquired. For, fixing the compensation of the land acquired, a committee under the D.C. of the area should be constituted. The M.P. and MLA of the area, the Block

Chairman, Village Headman or Mayor etc. should be a part of this committee, as is the case in Punjab. The stakeholders are also consulted before the rate of compensation is fixed. There had been no problem in Punjab and this process has been a success.

Sir, the second option is regarding the land-pooling system as per the Punjab Land Policy. I have already mentioned it earlier. The states must be given the right to fix the market-rate of the land acquired and it should be acceptable to the state as well as the Central Government.

HON. DEPUTY SPEAKER: Shri Ranjit Singh, please wind up.

SHRI RANJIT SINGH BRAHMPURA: Sir, this is my maiden speech. I am concluding.

Sir, the farmers must be permitted to move the courts for grievance redressal. Social impact assessment process must be continued. All affected people -- whether farmers, land owners, landless labourers or those dependant on that land directly or indirectly, should also be adequately compensated.

Thank you.

SHRI H.D. DEVEGOWDA (HASSAN): Mr. Deputy Speaker, Sir, I am requesting you and requesting the entire House to hear me out. This issue is with regard to the farmers. Yesterday, the hon. Minister for Parliamentary Affairs was kind enough to give us an assurance that we will have threadbare discussion and then the House will appreciate to give their support. With this background, I would like to highlight some of my own experience with my fight for the cause of the farmers. I am still fighting for the cause of the farmers. Sir, two Bills are before me, one is of 2013 and the other is of 2015. When the Bill of 2013 was passed, I was not in the House. My health was bad. Let us be frank. I am not advocating for the Bill of 2015 or 2013. The issue is, after the 2013 Bill was passed, *The Hindu* had given an article. I will quote from that. They say, "Now for the Mysore-Bangalore infrastructural corridor, the farmers will get reasonable price for the land they have lost." This is written by *The Hindu* and not by anybody else. The 2013 Act has provided so many benefits to the farmers. I do not want to deal with it clause by clause. When the amendments are going to be put to vote, at that time I may intervene to express my views.

Yesterday, I came late to this House from Bangalore. I have gone through an article written by *Frontline.* Again, it is a publication of the same newspaper, *The Hindu.* The article is published by *The Hindu* group. There, they have categorically mentioned this. I am telling this for the benefit of the entire House. We are all farmers. We are all coming from the farming community. There is no question of 'x', 'y', 'z'. Let us discuss threadbare. Do not curtail the time. I know the value of time. I do not want to unnecessarily waste my time or waste the valuable time of the House.

> "The definition of 'public purpose', which was wholly debated even within the Parliamentary Standing Committee on Rural Development headed by the present Speaker of the Lok Sabha, Sumitra Mahajan, was altered to make it possible for the Government to acquire land for the private hospitals and educational institutions…'' "And, Section 3 of the Companies Act provides to acquire land through the Ordinance. The definition 'private companies', includes all kinds of private companies like proprietorship, partnership, corporations and non-profit organisations."

The article was very interesting. I was enlightened. While coming from Bangalore, I had read the entire article. It gives how the 2013 Act has made all necessary provisions to safeguard the interests of the farmers. They have not opposed any development. Yesterday, the hon. Minister of Parliamentary Affairs was telling us how we are facing problems. Mr. Ananthkumar, you are also from Karnataka. Is there any problem for irrigation projects? Does anybody oppose it whether in the Cauvery basin or Krishna basin? I had been Minister for Irrigation for six years. I had never faced any problem of land acquisition so far as construction of major, medium or minor irrigation projects were concerned. Has anybody opposed the railway projects? I do not think that any Member of this House, from any side, is opposed to the construction of railway projects or national highway projects.

Sir, with my little experience I can say that nobody has opposed the acquisition of land for the railway projects; nobody has opposed construction of any irrigation projects; nobody has opposed construction of national highways. Some foreign investors are going to come to our country to invest in some of these projects.

The Statement of Objects and Reasons of this Bill is similar to the one given in 2013 Bill. But there were certain provisions to protect the farmers, which they want to amend. The consent of the farmers is one of them. Fear of the Government in the consent of farmers is 80 per cent in some cases and 70 per cent in some other cases. It may be difficult. Why? No farmer is going to oppose any project if it is going to provide reasonable compensation, fair compensation. That

was my experience as the Prime Minister and as the Chief Minister of Karnataka, though for a very short time, for ten and a half months here and for one and half years there in Karnataka.

Dr. Manmohan Singh was the Finance Minister during the Government of Shri Narasimha Rao. At that time, they had also taken the decision because the country was facing a major problem so far as our economy was concerned. We were about to go for a debt trap as 150 tons of gold was pledged. It was done to protect the interests of this country; the image of this country. At that time, the World Bank or the IMF had put some conditions to provide financial assistance. We were forced to accept that. Some people had opposed from this side and said that it was the Budget prepared by the World Bank. I have heard all those speeches at that time.

Sir, with this background, we have taken several decisions to invite some of the foreign investors in Karnataka. I mentioned the name of Shri Ananthkumar because he is a Minister today.

Sir, Karnataka is the hub of IT sector. When the Prime Minister of Singapore and Shri Ratan Tata came to Karnataka, during my period, I laid the foundation stone of a project.

Today there are so many IT companies. If I am given an opportunity tomorrow to speak on the General Discussion on Budget, I may take a few minutes. I do not want to make an elaborate speech. How many companies have come? We have not made any complaint. We have given land. Madam the late Indira Gandhi had laid the foundation stone of Hospet Steel Plant. When was the land provided? It was provided during our period. When was the decision taken to give land to Toyota Automobile Company? Did we hesitate to give land? No. I can quote innumerable instances. There is no dispute on providing land for infrastructure, whether it is industrial sector, automobile sector, manufacturing sector or service sector. So many five-start hotels were built, but there was no dispute. So many mega hospitals have come up, but there is no dispute at all.

In my home constituency, we had reserved 1,200 acres in 2007 itself, expecting that an IIT would come up there at that time because I had supported the UPA-I Government. So, I do not want to raise that issue now. I may bring a case study – I can only say it a case study now – to the notice of the entire House of Bangalore-Mysore Infrastructure Corridor which was initiated during my period. I agree with you. I do not want to make any personal attack against anybody about this company itself. It is a case study. Sir, I sent a copy of this book to all the judges of the Supreme Court. I was fed up. I also sent a copy of this book to all the High Court judges as to how things have happened. That is why, when it was ordered by the Chief Justice of the Karnataka High Court that this entire issue should be inquired into by the Lokayukta headed by Justice Santosh Hegde, who was a former judge of the Supreme Court, that was stayed. During the Janata Dal-BJP Government, we had taken a decision to enquire into the whole dispute by a Commission of Inquiry headed by a retired Chief Justice. It was also stayed. Then, the same Janata Dal-BJP Government took a decision to cancel this project and invite the global tenders because he had not deposited even a single rupee up to 2002.

That is why, I am going to read out my written speech, with your kind permission, without making any insinuation against anybody. I will not mention any name.

HON. DEPUTY SPEAKER: It would be better if you say it very briefly because the time available is less.

SHRI H.D. DEVEGOWDA: I cannot read this at the same speed which I had got in 1991.

HON. DEPUTY SPEAKER: Otherwise, you can tell the salient features.

SHRI H.D. DEVEGOWDA : Yes, Sir.

Sir, while speaking on the Land Acquisition Bill, I wish to draw the attention of the entire House to some very crucial and fundamental aspects of land acquisition for public-private partnership which, unless adequately taken care of,

turn the law into an instrument of loot in the name of development of infrastructure.

I am a former Chief Minister and had a brief stint as Prime Minister. I am not oblivious to the developmental needs of the country and to boost public infrastructure. I am also not against the public-private partnership model in principle. I wish to see the infrastructure development and the country to progress as much as the present Government.

At the same time, through this august House I wish to share the most bitter and damaging experience that the State of Karnataka went through, which the country must know in order to structure laws in a manner that they cannot be abused with impunity by a nefarious nexus of bureaucrats, politicians and fraud entrepreneurs. In this amendment Bill, the bureaucrats have been given safety that unless the State Government or the Central Government give sanction, you cannot touch the bureaucrats. How, in this particular project, bureaucrats have colluded and taken the shares from that company or have taken land from the company in the name of their wife and their children? A land, which was available at Rs. 80,000 in 1995 is costing Rs. 20 crore per acre today. How can we allow this? Hence, we will oppose this amendment tooth and nail. The bureaucrats have to be protected! This is why I wish to put before this house as to why the safeguards introduced by the existing legislation are not required to be diluted. In fact, more robust safeguards are to be built further to ensure that the poor are not trampled, and farmers are not ruined and sacrificed at the alter of endless and merciless greed of a few.

The poor of this country and the farmers who feed the country always try to serve the country at the cost of their own suffering. If they are called upon to make sacrifice for greater public good, then they always come forward. Otherwise, how can so many roads, dams, irrigation tanks and all other public infrastructure come into existence? We have been guilty of not recognizing their sacrifice and failed to provide them with minimum compensation. Their sacrifice for the country has not

been any less than those who lay their lives on the borders or in the war. In fact, a majority of our soldiers come from farmers' families and from rural background.

In 1995, when I was the Chief Minister of Karnataka, the Governor of Massachusetts paid a visit along with a delegation of American businessmen. An MoU was signed by me, as Chief Minister of the State, with a consortium of American companies to develop the highway between Bangalore and Mysore on the premise that no contribution in cash or kind will be required from the State of Karnataka. Now, they are cursing me. The consortium will bring foreign investment and will buy at market rate both the Government and the private lands, identified through scientific method, so that productive agricultural land is utilized to the minimum.

The consortium was asked to submit a technical report along with the financial report. By a Government Order, the project was sanctioned on the basis of Government of India policy initiated in 1991 to attract foreign investment on a Build Own Operate Transfer (BOOT) basis with a total requirement of 18,000 acres of land, with right to develop five townships -- now, they are smart cities. Our hon. Prime Minister says smart cities. In those days, we had prescribed how five townships have to be built, and I do not want to say beyond that -- and to collect toll with combined Return on Investment of 17.4 per cent. The townships were to be developed as counter magnets away from Bangalore to decongest the city of Bangalore and bring development and jobs in the areas between the two important cities in Karnataka. The entire infrastructure built in terms of roads and common infrastructure in townships was to revert to the Government after the period of BOOT was over meaning thereby that the entire land for roads and 55 per cent land allotted for townships were to be reverted to the Government.

15.00 hrs

What happened from then onwards, from 1995 till date, is a living nightmare for Karnataka.

In 1996, by a stroke of destiny, I had to leave my office of Chief Minister of Karnataka to come to Delhi. This was misused by the promoters and a few vested interests in Karnataka bureaucracy to turn this project into a purely real estate project with no investment, either foreign or Indian, and the entire effort by the company was to acquire the Government land using the provisions of the Land Acquisition Act.

Secondly, both the American partners exited after charging some consultancy fees and the project was transferred to a SPV with no foreign participation or equity, formed with seven shares of Rs. 10 each. The visit of the Governor of Massachusetts was only used as a sham to grab this project. No foreign investment came. None was intended to be brought. This was the first level of fraud.

The second level of fraud was played when a PIL was filed in Karnataka High Court by a private individual in 1997 challenging the powers of the Government to award the project to a private party to develop roads and townships, which the PIL alleged amounted to delegation of powers vested in State to a private party.

It is not a *sub-judice* matter, Sir. Immaculate record was built in with the help of prospective employees. The then PWD Secretary filed an affidavit before the High Court justifying the project on the premise that entire land for toll roads and 55 per cent land of townships will revert to the Government. That PWD Secretary is now one of the partners in the company. How can you protect such officers?

HON. DEPUTY-SPEAKER: That is all right. You have already mentioned that point.

SHRI H.D. DEVEGOWDA: I do not want to make any *extempore* speech.

The company also sought concessions from land acquisition body, that is, Karnataka Industrial Development Authority, by representing that out of 20,193 acres, 6,999 acres meant for toll roads and 55 per cent of township land, that is,

14,255 acres of land out of 20,193 acres or nearly 70 per cent, will revert to the Government. The High Court convinced by these beneficial aspects of project, dismissed the PIL and upheld the policy decision of the Government. The Court also refused to go into the question of land requirement as premature as land acquisition was not initiated by then.

The third level of fraud was played as soon as SLIP against the Karnataka High Court dismissing the PIL was dismissed in 1999. One by one, all assumptions which resulted in judicial approval of the project were fraudulently altered to the detriment of the State, all by interpolating in the record and removing or suppressing original decisions. The project coordinating office of the Government and KIADB were itself mostly conveniently housed in the company's premises.

HON. DEPUTY-SPEAKER: Please come to the point. What do you want to say? You have already mentioned these things. Please mention what you want now.

SHRI H.D. DEVEGOWDA: Just by creating a bureaucratic note, the amount of land to be reverted to the Government was reduced from 14,255 acres to 11,800 odd acres. A fraudulent premise was created to sell even land acquired for toll road in Bengaluru itself, when all toll road land had to revert to the Government creating a scope of illegal and fraudulent gain of over Rs. 30,000 crore. This affidavit was filed by the Chief Secretary against dishonest people. … (*Interruptions*)

HON. DEPUTY SPEAKER: You are quoting a case. That is all right. What you want to say finally, you say that.

… (*Interruptions*)

SHRI H.D. DEVEGOWDA: I want to give it in a nutshell. If anything is *sub judice,* you can reject it. … (*Interruptions*)

HON. DEPUTY SPEAKER: That is not the point.

… (*Interruptions*)

SHRI H.D. DEVEGOWDA: Not a single paisa was invested by this company. By altering original decision that Government land was to be allotted at market price, it was made available at Rs.10 per acre per annum. Shri Yediyurappa ji is sitting here. He knows that.

SHRI K.C. VENUGOPAL (ALAPPUZHA): He is taking notes. … (*Interruptions*)

SHRI H.D. DEVEGOWDA: It is not done by him. It is done by the previous Government. I am not naming any party Government. Comfort letter was obtained to mortgage this leased land to raise loans, and with that initial instalment of about Rs.180 crore loan only the first tranche was paid to KIADB to acquire private land as also other expenses, including design and consultancy fees to foreign consortium members to buy their exit and also to associate companies under some sham consultancy and fee heads. Further, the company was also granted comfort for developing initially a four lane tar road instead of six lane concrete roads, further reducing its expenses. I have written a letter to almost all the Chief Ministers including Dr. Amma. Please pardon me. I have written a detailed letter to the Prime Minister. He has acknowledged it. Had the Prime Minister been here, I would have asked him this question.

Company is charging heavy toll, highest in the country by developing a portion of tar road itself. A fresh round of PILs was filed challenging the project. The High Court refused to go into the aspect of how much land is actually required as a contractual factual issue which could not be gone into in the writ jurisdiction.

Another important issue is about the Global Infrastructure Consortium. Our Government, that is, JDS-BJP had taken the decision to cancel it. … (*Interruptions*)

HON. DEPUTY SPEAKER: Please say what you want. Please conclude.

… (*Interruptions*)

SHRI H.D. DEVEGOWDA: I do not want to make a lengthy speech.

HON. DEPUTY SPEAKER: You have already quoted many cases.

… (*Interruptions*)

SHRI H.D. DEVEGOWDA: They have come forward to pay the entire money that they have invested till the time. They have come forward to build the entire project paying the money what was invested till then and also to construct leaving the prime area of 1,250 acre within the city. That costs today Rs.20 crore per acre… (*Interruptions*)

HON. DEPUTY SPEAKER: Whatever you have said about the project is all right. Please try to conclude.

… (*Interruptions*)

SHRI H.D. DEVEGOWDA: It has already raised huge money by entering into joint development agreements to develop toll road land in Bengaluru, which simply translates into selling land acquired for about Rs.2 lakh per acre from farmers at Rs. 15 to Rs.20 crore per acre. … (*Interruptions*) I will send this. I will send the entire book. If you people want to support such type of fraudulent people, how can we sit here? What happened to Cogentrix? What happened to Enron? Our senior leader Shri Advaniji is sitting here. Yes, Sir. The new Government which came to power did not interfere with the decision they had taken. Ultimately what happened? The project was not implemented and the CEO was sent to prison for 30 years. Do you want to bring such type of people here? That is why you are inviting foreign direct investments. Now you want to invite 100 per cent FDI in construction of railways, highways and many other projects. Are we opposing that? The question is that we must be more careful about those fraudulent people who come into the country and grab our lands. The poor people cannot be allowed to suffer.

I must congratulate Rahul Gandhi who had taken the initiative on the Yamuna Expressway issue. He went there and he struggled with the farmers. I remember, Raj Nath Singhji and Arun Jaitley had also gone there and fought for the sake of farmers who were losing the land, against the persons who were grabbing it. Both of them agreed to bring this 2013 Bill. Why this amendment now? I am not advocating the cause of anybody. I have written a letter to Madam

Gandhi and she has replied saying that we will not allow such a thing to happen and our party is going to fight tooth and nail this type of fraud. This is the letter that I have received.

Some people are being murdered by them in the projects. I can show the photos. Cases have been registered by them. This is not a joke. They have filed a defamation suit against me for Rs.10 crore. I accepted the challenge, but they ran away. This company has run away. Are you not ashamed to protect such people? Correctly we have taken a decision to call for a global tender. They want to construct the entire project without even asking for the extra land. He has taken a decision not to give any extra land. I have got the decision taken by Yeddyurappa. It is on my table. But that is not the issue.

We not only oppose this, we may have to take further steps. We have not come here to make a speech for public consumption. Yesterday Parliamentary Affairs Minister said, you can say whatever in the public or here, we have got our own way to pass the Bill; because we have got 282 Members here, even without the cooperation of other alliance partners we can pass the Bill. I know this. You can go for a Joint Session of Parliament and have the Bill passed. That is not the issue at all. If this Bill is passed, it is going to boomerang on them. I said I am not going to contest in the next election. At the same time I remind them of what RSS chief has said about this Bill. I am not going to hold brief for RSS chief. He warned this present government to be way more careful to deal with such a complicated issue.

Not only we are going to oppose this, we are going to take this issue to the public and we will fight it till the last. Thank you very much.

SHRI DINESH TRIVEDI (BARRACKPUR): Sir, I want to thank you for this opportunity and I hope you will be as patient with me as you have just been with our hon. former Prime Minister.

HON. DEPUTY SPEAKER: I can be patient with some, not all. Therefore, please try to be very brief.

SHRI DINESH TRIVEDI: Sir, hon. former Prime Minister has said very elaborately whatever he had to say. My esteemed colleague Shri Kalyan Bandopadhyay spoke yesterday not only on the legal points but on the substantial points of this Bill.

Sir, at the very outset, let me tell you one thing. हम इस बिल का अपनी पार्टी की तरफ से जोर-शोर से विरोध कर रहे हैं। विरोध करने के साथ ही साथ, हम यह समझ नहीं पा रहे हैं कि हम इनका शुक्रिया अदा करें, इनके आभारी हों या इनको बहुत-बहुत धन्यवाद दें कि ये इस बिल को लेकर आए हैं। हम यह बात क्यों कह रहे हैं? इस बिल से आपने क्या किया है, हम आपको बताएं कि पूरे विपक्ष को एक साथ युनाइट कर दिया है और इस बिल के द्वारा आप में भी, आप अपने दिल पर हाथ रख कर कहिएगा कि डिसयुनिटी आ गई है...(व्यवधान) आप सदन से बाहर जाएंगे, तो आपको पता चलेगा।...(व्यवधान) Sir it is a very simple question. आपकी नीयत में हमें कोई शंका नहीं है कि आप जो भी कर रहे हैं आपकी समझ भी वही है कि शायद देश का भला हो। आपकी नीयत पर हमें कोई शक या शुबाह नहीं है कि आप किसी एक पर्टिकुलर पूंजीपति को ज्यादा पैसा दिलाना चाहते हैं। इस बारे में मेरे दिल में कोई शंका नहीं है। आप इस बारे में ताली तो बजा दीजिए। Sir, it is a very basic question. मेरे पास समय ज्यादा नहीं है। मुझे कहा गया है कि मेरे पास बोलने के लिए सिर्फ दस मिनट का समय है। दस मिनट में तो कोई चाय भी नहीं पी सकता है।

HON. DEPUTY SPEAKER: You have got only 5 minutes, not 10 minutes.

SHRI DINESH TRIVEDI: मेरे पास मेरी पार्टी का दस मिनट का समय है।

HON. DEPUTY SPEAKER: It is already over.

SHRI DINESH TRIVEDI: That is not true. I have got 10 minutes and I am going to exercise my right with due respect. I am going to the basics. Clause by clause, everybody has talked about it and they have demolished this. I am not going to go on that. I am going to go on substantial process of democracy. The very basic process of democracy is being subverted and I am going to tell you in a very patient manner. I am not going to get agitated about it but the fact is, this is for all of us, for this country and for the future generation which is going to come. इसमें बहुत सिम्पल बात है। It is the right of an individual, the right of an individual against the might of the State. आज भी नरीटा एयरपोर्ट पर एक किसान बैठा हुआ है। इसके मुद्दे बहुत सिम्पल हैं कि आप किस प्रकार से कानून बनाना चाहते हैं और उसकी प्रतिक्रिया क्या है। What is the process of law making? I am hitting at the basic process of law making. Even the hon. President of India mentioned that this is not the way that you come up with Ordinance after Ordinance. Sir, do the people as stakeholders have a Right to understand what is happening or we just want to bulldoze a Bill? Everybody has asked what is the hurry. You have to circulate this draft to the stakeholders. Have you consulted the people who are going to get affected? Have you consulted the political parties? We have always been talking that India means 1.2 billion people. The Bill is so complicated that it will take some time for a poor farmer to understand it. Where is the draft circulated? Even before circulating the draft, you have brought the Ordinance. I want to take you to the Committee of Secretaries meeting that was held in January 2014. The Committee of Secretaries had pronounced with due diligence and the permission of the Government that henceforth whatever law comes into being has to be first circulated in a draft form. There has to be wider discussion and after that only, the law will come, the Bill will come and we will debate.

I just want to take you to the broader points. We are all here in Parliament. I started my career in public life in consumer protection. In consumer protection, what happens? … (*Interruptions*) I am just on factual stuff. हम एक चीज का इश्तिहार

देते हैं। We advertise for one thing and give a product which is just the opposite. तो क्या होता है, हम बोलते हैं कि यह धोखाधड़ी है, क्योंकि आपने इश्तिहार तो इस चीज का दिया और आपने कहा...(व्यवधान) आपको सुनना पड़ेगा। … (*Interruptions*)

HON. DEPUTY SPEAKER: Do not divert the attention please.

… (*Interruptions*)

SHRI DINESH TRIVEDI: I am not going to yield at all. They must have the patience. This is democracy. You cannot shout me down. Please understand. … (*Interruptions*) यहां न तो रावण की चली है, न दुर्योधन की चली है, न तो कंस की चली है, अहम् किसी का नहीं चलता है, यह बात आप याद रखिये।

सर, हमने इश्तिहार की बात की। I am coming to a basic document. What is the basic document? I would urge and I would appeal to you to please listen very carefully. This basic document is a manifesto. It is the *ishtihar*. We go to the voters with the basic document called the manifesto. With your permission, I would take two minutes to read this manifesto. It says:

> "Encouraging the production of cereals and discouraging conversion of fertile farm land for dubious industrial projects."

I will tell you whose manifesto this is. It says:

> "Land acquisition for infrastructure, farmers interests will be protected."

I will read out; it will not take much time:

> "The Central and the State Governments for long have acquired land through an opaque process to hand it over to private parties under the umbrella of public purpose. The UPA Government has approved 572 special economic zones that cover 50,000 acres, three times the size of Singapore. This is clearly absurd and spells disaster for the farm sector."

Now, I come to the substantial portion and it says:

> "The BJP will adopt a National Land Use Policy, which will protect the interests of the farmers. Its implementation will be monitored by a National Land Use Authority which will work with the State Land Use Authorities to regulate and facilitate land management. The powers and functions of the National Land Use Authority will be similar to those of regulatory bodies. The BJP will bring about amendments to existing laws … The BJP will not allow the conversion of fertile farmland for industrial/commercial projects or Special Economic Zones.
>
> The entire issue of Special Economic Zones and acquisition of land for industrial use will be addressed after a careful scrutiny of the Parliamentary Standing Committee's Report …"

It says that it will be addressed 'after careful scrutiny of the Parliamentary Standing Committee Report, factoring the need to protect the farm sector' and after due discussions with the stakeholders. This is what your manifesto says. I am afraid you are going totally against your manifesto.

I remember my consumer protection days. If there was a private company which said it was going to sell a particular product but sold an absolutely opposite product, you would know what would happen. I am not going to use any harsh words. … (*Interruptions*)

This country is the country of the *Mahabharata*; this country is the country of the *Ramayana*; this country is the country of the *Guru Granth Sahib*; this country is the country of the *Quran Sharief*. I would just take you to the days of the *Mahabharata*. When Pandavas asked Kauravas to give a little land as they did not want anything but their own land, Kauravs said "सुई की नोक तक की जमीन नहीं देंगे। आपको लड़ाई करनी है तो लड़ाई कर लीजिए। लड़ाई तो फारमर्स करेंगे।" That is the war. तैयारी आपकी होनी चाहिए। ...(व्यवधान) Let me just conclude. I am just going to conclude. I will just give you one example and I will be done. The example which I am going to give you, Sir, is about पूंजीपति, कॉर्पोरेट सैक्टर and all those stuff. I have nothing against them. Take the case of a very beautiful club in the heart of Delhi called

Delhi Golf Club. I also go there to play golf. That *zameen* belongs to the Government. यह सरकारी जमीन है। हमारे एक दोस्त हैं, जो मुझे कह रहे थे कि आप इस बिल का विरोध क्यों कर रहे हैं? मैंने अपने दोस्त को कहा कि एक काम करते हैं कि यह तो सरकारी जमीन है, कल उठ कर यदि सरकार कहती है कि इस दिल्ली गोल्फ क्लब में हम एम्स की एक बिल्डिंग बनाना चाहते हैं, गोल्फ को बंद करना चाहते हैं, फिर देखिए क्या मज़ा आता है। आप इसे एक टैस्ट केस ले लीजिए कि यह आप कर सकेंगे कि नहीं। यदि आप वह कर सकते हैं तो हम भी कहेंगे कि हमारी भी मंजूरी है। पूंजीपति अपनी जगह है। ...(व्यवधान) सर, मैं आखिर में एक शेयर कहना चाहता हूँ। I just want to read a *sher*. सर, यह क्या होता है कि जब हम यहां आ जाते हैं तो हम अपने आपको भगवान समझते हैं, खुदा समझते हैं, ईश्वर समझते हैं तो हम खुदा हैं, ...(व्यवधान) हम सबकी किताब लिखते हैं, मतलब हम सब यहां लॉ बनाते हैं। हम खुदा हैं, हम सबकी किताब लिखते हैं, तुम कौन हो, अपोजिशन को आप पूछेंगे कि तुम कौन हो कि हमसे पूछो हम अपना हिसाब कैसे लिखते हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया। ...(व्यवधान) आपको मैं यह कहूंगा कि मेहरबानी कर के send this Bill to the Standing Committee. It is in the interest of the farmers. It is in the interest of the country and I will not be wrong if I say it is in your own interest. Please send this Bill to the Standing Committee of Parliament. Thank you very much.

15.28 hrs (Shri Konakalla Narayana Rao *in the Chair*)

श्री चिराग पासवान (जमुई) : सभापति महोदय, आपने मुझे भूमि अधिग्रहण बिल पर जो चर्चा चल रही है, उस पर मुझे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राम विलास पासवान और हमारी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से अपने विचारों को रखने की अनुमति दी, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। उपाध्यक्ष जी, भूमि अधिग्रहण के इस बिल पर तमाम तरीके की चर्चाएं हुईं और चर्चा सिर्फ इस सदन में ही नहीं हुई, एनडीए के बीच में भी हुई है। हमारे तमाम गठबंधन साथियों के बीच भी यह चर्चा हुई है। यकीन मानिए कि यह इजाज़त, इतनी लिबर्टी हमें सिर्फ और सिर्फ इसी गठबंधन में मिली है, इस गठबंधन के नेतृत्व से मिली है, जहां पर हम जिनका प्रतिनिधित्व करते हैं, उनके सरोकारों को हम खुल कर सरकार के सामने रख सकें। हमने ऐसा किया भी है। उपाध्यक्ष जी, किसानों की भूमि का हमारे देश में क्या महत्व है, यह कोई बहस का विषय नहीं है, इस पर कोई चर्चा की जरूरत नहीं है, हम सब जानते हैं कि भारत हकीकत में गांवों में बसता है और किसान हमारे भारत की आत्मा है। किसान कोई वोट बैंक नहीं है। हमारे लिए किसान हमारा अन्नदाता है। जो चीज़ किसानों के पक्ष में नहीं है, वह हमारे पक्ष में नहीं है, वह सरकार के पक्ष में नहीं है, वह विपक्ष के पक्ष में नहीं है, वह किसी के पक्ष में नहीं है। इसीलिए हम लोगों की भी कुछ चिंताएं थीं, जिनको हमने खुल कर सरकार के सामने रखा। मुझे इस बात की खुशी है कि हमारी एक छोटी पार्टी होने के बावजूद, भले ही संख्या बल में हम लोग कम हैं, उसके बावजूद सरकार ने जो हमारे सुझावों को सम्मान दिया है, उसके लिए मैं इस सरकार का धन्यवाद करना चाहता हूँ। उसी के फलस्वरूप आज कुछ संशोधन सामने आए हैं। उन संशोधनों में यह वादा दिखता है कि चाहे कुछ भी हो किसान भाइयों के हितों की अनदेखी नहीं की जाएगी। स्वयं हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, जो कि खुद एक ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं, उन्होंने खुद उस दिन इस संसद में खड़े होकर सम्बोधित करते वक्त इस बात को बहुत स्पष्टता से रखा कि हमारा एनडीए का गठबन्धन, हमारी सरकार कोई भी ऐसा कार्य नहीं करेगी, जो किसानों के हित में न हो, जो गरीबों के हित में न हो। उनकी इस बात का मैं अपने दल की तरफ से पुरजोर तरीके से स्वागत करता हूँ।

महोदय, मेरा विश्वास, मेरा भरोसा हमारी सरकार पर है, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी पर है। यकीन मानिए जब हम लोग इस गठबन्धन का हिस्सा नहीं भी थे, इस गठबन्धन में आने की बहुत बड़ी वजह हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी रहे हैं। मैंने इस बात को खुलकर हर मंच पर स्वीकारा भी है। उनके प्रभावशाली व्यक्तित्व से जुड़ने की मेरी चाह हमेशा से रही है। जिस तरीके से वे विकास की राह पर हमारे देश को आगे लेकर जाना चाहते हैं, उस सोच के साथ जुड़ने की हमारी आशा शुरू से रही है। आज भी हमारा यह विश्वास हमारे प्रधानमंत्री जी पर है कि कोई भी ऐसा कार्य हमारी सरकार के द्वारा नहीं किया

जाएगा जिसमें किसानों की या गरीबों की अनदेखी हो और यह उम्मीद कभी नहीं टूटेगी, यह भी हमारा विश्वास है।

महोदय, उद्योग और कृषि विकास रथ के दो पहिये के समान हैं और इन दोनों का एक-साथ, एक जैसा विकास होना बहुत जरूरी है। कृषक हमारे देश के विकास के रथ को आज यहाँ तक खींचते हुए आगे लेकर आए हैं, लेकिन कहीं न कहीं आज के इस ग्लोबलाइजेशन के दौर में उद्योग भी हमारी जरूरतें हैं। औद्योगीकरण भी हमारी जरूरतों में से एक है। मैं युवा हूँ, मैं युवाओं से जुड़ी हुई सबसे गम्भीर समस्या को समझ सकता हूँ, जो कि रोजगार की समस्या है। अगर हम रोजगार के अवसर, जिसके बारे में हम लगातार चुनावी वादों में कहते रहे हैं, अगर हम युवाओं के साथ जुड़ी हुई इस समस्या पर एक अंकुश डालना चाहते हैं तो उद्योगीकरण को बढ़ावा मिलना बहुत जरूरी है, उद्योगों का खुलना बहुत जरूरी है। एक दुष्प्रचार चल रहा है और लगातार हमारे आदरणीय वित्त मंत्री जी भी इस बारे में कहते रहे हैं कि Industry is not a bad word. मैं इस बात का पूरी तरीके से समर्थन करता हूँ कि Industry is not a bad word पर हाँ, किन शर्तों पर यह उद्योगीकरण हो रहा है, किन बुनियादों पर हो रहा है, कहीं किसी का इसमें अहित तो नहीं हो रहा है, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए हम तमाम सदस्य, जो इस सदन के सदस्य हैं, हम यहाँ पर एकत्रित होकर बैठे हैं। यह हमारी जिम्मेदारी बनती है, हमें इस बात को सुनिश्चित करना है कि जब हम विकास की राह पर आगे बढ़ने की बात करते हैं, विकास के इस रथ के दोनों पहिओं को आगे लेकर चलने की बात करते हैं तो कहीं उनमें से कोई एक पहिआ पीछे तो नहीं छूट रहा है। कहीं किसी एक पहिए के विकास का प्रभाव हमारे दूसरे पहिए के विकास पर भारी तो नहीं पड़ रहा है। इस बात आश्वासन मुझे इस सरकार के द्वारा मिला है कि इस विकास की राह पर जितने प्रभावशाली तरीके से हम उद्योगीकरण को प्राथमिकता दे रहे हैं, उतनी ही हमारी प्राथमिकता किसान भाइयों के लिए भी रहेगी।

महोदय, मैं इस विश्वास के साथ कि आने वाले समय में हमारे किसान भाइयों का कोई अहित नहीं होगा और जिस तरीके से इस बिल के मूल ढ़ाँचे में संशोधन किए गए हैं, जिस तरीके से जो-जो

सुझाव हम लोगों ने अपने दल की तरफ से दिए थे, मैं दोबारा इस बात के लिए हमारी सरकार का धन्यवाद करना चाहूँगा कि जो हम लोगों की चिन्ताएं थीं, जिस तरीके से उन चिन्ताओं को, हमारे कन्सर्न को एड्रेस किया गया है और उसके बाद इन संशोधनों को सामने लाया गया है, उसका हम स्वागत करते हैं।

महोदय, अंत में, अपनी बातों को समाप्त करने से पहले इस उम्मीद के साथ कि प्रधानमंत्री जी जैसे सक्षम नेतृत्व में कभी किसानों के साथ, गरीबों के साथ कोई अहित नहीं होगा, इस बात पर विश्वास करते हुए मैं चिराग पासवान, लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से इस बिल का समर्थन करता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद।

कुँवर भारतेन्द्र सिंह (बिजनौर): महोदय, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2015 के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। अधिकतम बिन्दुओं पर इस सदन में योग्य सदस्यों और पूर्व वक्ताओं द्वारा चर्चा हो चुकी है। मैं केवल तीन बिन्दुओं पर चर्चा कर सरकार और आपका ध्यान आकृष्ट करवाना चाहता हूँ।

महोदय, यहाँ पर सभी उपस्थित सदस्य किसानों के अधिकारों के लिए चिन्तित हैं। हम किसान की बढ़ती हुई लागत और फसल के उचित मूल्य न मिल पाने की समस्या को भली-भाँति समझते हैं। मेरे क्षेत्र में मवाना चीनी मिल में पिछले तीन वर्ष से गन्ना भुगतान का बकाया है। ऐसी परिस्थिति में किसान के पास आज केवल अपनी भूमि ही है जिसकी कीमत और उसकी पूँजी बढ़ती जा रही है और उसे इसका सहारा है। यदि हम इस सदन में कठिन नियम बना दें जिससे किसान की भूमि का कोई खरीददार ही न बचे तो क्या यह किसान के हित में होगा? हमारे प्रतिपक्ष के साथियों ने भी अनेक चिन्ताएँ व्यक्त की हैं मगर केवल चिन्ताओं की बात करके और किसानों को दिग्भ्रमित करके क्या हम उनकी सहायता कर रहे हैं? क्या यह किसान के हित में है? जितना मौलिक ढाँचे का विकास होगा, जितना इनफ्रास्ट्रक्चरल डैवलपमैंट होगा, उतना ही किसान की भूमि के दाम बढ़ेंगे। बढ़ती हुई जनसंख्या और घटती हुई किसान की ज़मीन का एक ही उपाय है कि किसानों के बेटों को अच्छे वेतन का रोज़गार मिले। यह केवल औद्योगीकरण से ही संभव है। जितनी अधिक औद्योगिक ईकाइयाँ भूमि को खरीदना चाहेंगी, उतनी ही किसान की भूमि की कीमत बढ़ेगी। किसान का हित उसके ज़मीन के दाम बढ़ने में है। यदि हम ऐसे विधेयक पारित करें जिससे केवल भूमि-अर्जन नियमों के मकड़जाल में उलझकर केवल उन परिवारों का ही लाभ होगा जिनके हाथ और पाँवों की पहुँच कानून से भी लंबे हों या किसानों की भूमि सस्ते दामों पर किसी बड़े परिवार का दामाद खरीद ले, तो क्या इससे किसानों का लाभ होगा? पिछले दस वर्षों में हरियाणा में 18 हज़ार एकड़ भूमि का चेन्ज इन लैंड यूज़ हुआ है। इसमें हज़ारों लाख करोड़ों रुपये का घोटला है। मेरा आपके द्वारा सरकार से अनुरोध है कि इस घोटाले की जाँच की जाए। किसान को केवल उचित प्रतिकार और पारदर्शिता चाहिए जो इस संशोधन विधेयक में निहित है।

महोदय, प्रतिपक्ष के साथियों ने महत्वपूर्ण सुझाव दिये हैं जिन पर मैं माननीय मंत्री जी का पुनः ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। महाराष्ट्र में मगरपट्टा माडल है जिसमें किसानों को भूमि अधिग्रहण के पश्चात् हिस्सेदारी दी गई है। आंध्र प्रदेश के माडल में किसान, ज़मींदार और भूमि अर्जनकर्ता – तीनों के

लाभ पर ध्यान दिया है। मैं कहना चाहता हूँ कि इन दोनों माडल्स का अध्ययन कर माननीय मंत्री जी इन्हें सम्मिलित करें।

महोदय, पश्चिम उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट बैंच की सख्त आवश्यकता है और नए राष्ट्रीय राजमार्गों की ज़रूरत है। भीड़ और यातायात से सड़कों पर जाम लगा रहता है। रेलवे लाईन और नए रेलवे स्टेशनों की मांग है। हवाई अड्डे की ज़रूरत है और इन सब प्रोजैक्ट्स को पूर्ण होने में पाँच वर्ष से अधिक समय लगता है। यह पाँच वर्ष से अधिक सीमा की मांग जो बार-बार प्रतिपक्ष के योग्य साथी कर रहे हैं, क्या यह उचित है? सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन पर बहुत सदस्यों ने चिन्ता व्यक्त की है। भट्टा परसौल का उदाहरण दिया गया है। मैं अपने योग्य साथियों को जानकारी देना चाहता हूँ कि भट्टा परसौल में 5(क) किसान की आपत्ति सुनना, का प्रकाशन नहीं किया गया था। चेन्ज इन लैन्ड यूज़ औद्योगिक के लिए की गई थी, किन्तु बाद में उसे आवासीय बना दिया गया। किसानों से भूमि के लिए विकास का कर्ज़ पहले जमा करने को कहा गया था, तथा किसानों को ज़मीन उचित प्रतिकर नहीं दिया। विवाद इन दो बिन्दुओं को लेकर हुआ था। यह विवाद पुनः न उठे, इसकी चिन्ता उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार संशोधन में सम्मिलित की गई है। मैं सदन को बताना चाहता हूँ कि भट्टा परसौल के किसानों की समस्या के निराकरण हेतु सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों से किसानों का संवाद स्थापित है। आज शाम ही को हम माननीय मंत्री जी से भी मिल रहे हैं।

महोदय, कृषि योग्य भूमि और सिंचित भूमि अर्जन न होने की कुछ प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों ने सिफारिश की है। अभी-अभी दिनेश त्रिवेदी जी भी इसी बात को कह रहे थे। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या ये लोग हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश को विकास से वंचित रखना चाहते हैं? इस क्षेत्र की जनसंख्या अत्यधिक घनत्व में है, अतः रोज़गार की सबसे ज्यादा आवश्यकता पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जनप्रतिनिधि होने के नाते मैं इस सदन को बताना चाहूँगा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में घाटे में चल रही चीनी मिलों के अतिरिक्त कोई भी उद्योग नहीं है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का यह निश्चित मत है कि जनता को सरकारी तंत्र, गवर्नमेंट से अधिक सुशासन की, गुड गवर्नेंस की आवश्यकता है। भट्टा पारसौल और हरियाणा में एक प्रभावी परिवार के दामाद का भूमि घोटाला केवल कुशासन और भ्रष्टाचार का परम उदाहरण है।

मुझे पूर्ण आशा और विश्वास है कि एन.डी.ए. सरकार में इस भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (संशोधन), विधेयक, 2015 से इन सब घोटालों पर पूर्ण विराम लगेगा।

श्री दुष्यंत चौटाला (हिसार) : सभापति महोदय, आपने मुझे भूमि अधिग्रहण बिल पर बोलने का मौका दिया, धन्यवाद। जब चौधरी देवीलाल इस देश के कृषि मंत्री थे तो उन्होंने इस सदन में कहा था कि मैं किसान हूं, किसानों का दर्द समझता हूं। आज दिक्कत किसान को आ रही है और सांसें मेरी रुक रही हैं। आज इस सदन में बैठा हुआ हर किसान का बेटा या आज जो खेती करता है, वह बैठकर यही सोच रहा है कि किस तरह से इस बिल से निजात दिलाई जाये, पर कई साथियों की मजबूरी है कि वे सत्ता पक्ष में हैं, इसलिए वे इस बिल के विरोध में वोट नहीं डाल सकते।

मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब भूमि अधिग्रहण की बात की जाती है, आज जहां यह पार्लियामेंट है, जहां राष्ट्रपति भवन है, यहां पहले रायसीना गांव था। 1911 के अन्दर वायसराय ने एक ऊंची पहाड़ी देखी और वहां पर अपने लिए राष्ट्रपति भवन जैसे बड़े आलीशान बंगले को बनाने की शुरूआत की। उन किसानों को, जो रायसीना हिल पर रहते थे, उठाकर सोनीपत जिले में भेजा गया। आज यहां पर अरबों रुपये एकड़ की जमीन है और सोनीपत वाला किसान, जो यहां से 100 साल से भी पहले सोनीपत भेजा गया था, आज वह केवल लाखों रुपये एकड़ की जमीन का मालिक है। लैंड एक्वीजीशन किसानों की यह हालत कर देती है कि जब उनको डिस्प्लेस किया जाता है, उनको उठाकर भेजा जाता है तो उनको सोसायटी के अन्दर जगह बनाने में भी दोबारा दिक्कत आती है। सरकार कहती है, मेक इन इंडिया प्रोजैक्ट के लिए, स्पेशल कोरीडोर के लिए लैंड एक्वीजीशन बहुत जरूरी है, पर क्या वह लैंड एक्वीजीशन हमारे एन.सी.आर. के अन्दर आती है, क्या वह लैंड एक्वीजीशन हमारे मैट्रोज़ के पास ही आती है? लैंड एक्वीजीशन को सिर्फ यहीं रखा जाता है।

कल हमारे बड़े भाई साहब कीर्ति आजाद जी ने जब इस बिल का स्वागत किया तो वे कह रहे थे कि दरभंगा के अन्दर फैक्टरियां लगेंगी। माननीय मंत्री जी यहां बैठे हैं, अगर ये विश्वास दिलायें कि हरियाणा के सभी 21 जिलों के अन्दर बराबर इन्फ्रास्ट्रक्चर का डैवलपमेंट होगा, जब मैं 11 महीने का था तो चौधरी देवीलाल जी ने 21.5 एकड़ रेतीली जमीन मेरे नाम पर करवाई थी। आज मैं सरकार को यह विश्वास दिलाता हूं कि अगर इण्डस्ट्रियल डैवलपमेंट लम्बी के पास आएगी तो वहां रेलवे लाइन भी है, हाईवे भी है तो मैं सरकार को वह जमीन मुफ्त में देने को तैयार हूं, लेकिन सरकार हमारे लोगों को वहां पर एम्प्लायमेंट और इंडस्ट्रीज़ लाकर डैवलपमेंट का विश्वास दिलाने का काम करे।

जहां कल कीर्ति आजाद जी कह रहे थे कि लोगों को स्कूल बनाने के लिए, हॉस्पिटल बनाने के लिए सरकार को जमीन की जरूरत है। मैं हरियाणा का वाकया भी नहीं लेता, पिछले दिनों मुझे दिल्ली चुनाव में नजफगढ़ के रौशनपुरा गांव में जाने का मौका मिला। वहां पर ग्राम पंचायत के लोगों ने मुझे

बताया कि 17 एकड़ जमीन आज से 17 साल पहले, जब दिल्ली के अन्दर भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, ग्राम पंचायत ने दिल्ली सरकार के नाम पर रजिस्टर करवाई कि वहां पर स्कूल खोला जाये। 17 सालों में से 15 साल इनकी सरकार रही, दो साल इनकी सरकार रही, पर वहां पर आज तक लोगों को कालेज नसीब नहीं हुआ और वह 17 एकड़ जमीन आज भी बंजर पड़ी है।

आज सरकार कहती है कि एफोर्डेबल हाउसिंग हमने लेकर आना है, हम किस तरह के एफोर्डेबल हाउसिंग की बात करते हैं। आज गुड़गांव को उठाकर देखिये, यह दिसम्बर, 2013 की रिपोर्ट है कि अकेले गुड़गांव के अन्दर नौ लाख फ्लैट्स और घर खाली पड़े हैं। अगर आपने एफोर्डेबल हाउसिंग लेनी है तो उन पूंजीपतियों के फ्लैट्स पर जाकर कब्जा कीजिए, जिन्होंने अपने नाम पर 20-20 फ्लैट्स लेकर गुड़गांव में छोड़ रखे हैं और गरीबों को वे फ्लैट्स देने का काम कीजिए। मगर सरकार तो यह देखती है कि किस तरीके से, जहां मल्टी क्रॉप्स निकलती हैं, उस भूमि को लेकर हम आगे प्रोपर्टी डीलरों को बेचें। वहां चार एकड़ जमीन में से एक एकड़ में वह एफोर्डेबल हाउसिंग बनाएगा और तीन एकड़ में 50-50 लाख रुपये के फ्लैट्स बनाकर बेचने का काम करेगा।

माननीय सभापति महोदय, एक तरफ यह बिल लाया जाता है और बिल के अंदर सेक्शन-197 की बात की जाती है। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि आप इस देश का इतिहास उठा लें और देखें कि जब से सी.आर.पी.सी. बना है, उस समय से सेक्शन-197 के तहत एक भी अधिकारी के खिलाफ नोटिस सैंक्शन तक नहीं हुआ है, इंक्वायरी और इंवेस्टीगेशन तो बहुत दूर की बात है। गरीब किसानों की जमीनें छीनने का काम किया है।

श्री चौधरी बीरेन्द्र सिंह : अभी जो जेल में दो आई.ए.एस. पड़े हैं, वे आपकी ही स्टेट के हैं।

श्री दुष्यंत चौटाला : माननीय मंत्री जी, यहां लैण्ड एक्वीजीशन की बात की जा रही है। कल तथागत जी बोल रहे थे कि हरियाणा के अंदर दस सालों में 65,000 एकड़ जमीन एक्वायर की गयी। वे अभी यहां नहीं हैं। मैं उन्हें बताना चाहूंगा कि 65,000 एकड़ नहीं, बल्कि 70,000 एकड़ ज़मीन दस सालों में एक्वायर हुईं। माननीय मंत्री जी, आप भी उसी सरकार का हिस्सा थे। आपने भी विधान सभा में इसका समर्थन किया था और इसके संबंध में रूल पारित करके ज़मीन दिलाने का कार्य किया था। आज आप उस तरफ आकर इस बिल को दुबारा इस सदन में पेश करने का काम कर रहे हैं। वह 70,000 एकड़ ज़मीन तो दस सालों में एक्वायर की गईं, लेकिन अगर आपकी यह पॉलिसी आ गईं तो हरियाणा प्रदेश की अगली दो पीढ़ियों के बाद हरियाणा के अंदर ज़मीन नहीं बचेगी। आप पूरे हरियाणा को एक्वायर कर लेंगे।

मैं सर छोटू राम का एक वाकया इस सदन में लाना चाहूंगा। सर छोटू राम जी संभल गए थे। जब वे संभल गए तो उन्होंने देखा कि वहां महिलाएं मंच की ओर अपनी पीठ दिखा कर बैठी हैं। उन्होंने पूछा कि इन महिलाओं के ऊपर वस्त्र क्यों नहीं है, ये पीठ दिखा कर क्यों बैठीं हैं? सर छोटू राम जी को बताया गया कि इनके पास ज़मीन नहीं है। उन्होंने उनके अधिकारों की लड़ाई लड़ी और किसानों, गरीबों, मज़दूरों को ज़मीन का आधिकारिक मालिक बनाने का काम किया। आज उन्हीं के वंशज उनके अधिकारों को छीनने का काम कर रहे हैं।

मैं सरकार के समक्ष सर छोटू राम जी का एक वाकया लाना चाहूंगा और उन्हें कोट करूंगा कि "हिन्दुस्तान की सभी प्रकार की सरकारों को कहना चाहता हूं कि वे किसान को इस कदर तंग न करें कि वह उठ खड़ा हो। इस भोलेनाथ को इतना तंग न करो कि वह तांडव नृत्य पर उतर आए। दूसरे लोग जब सरकार का विरोध करते हैं तो कानून तोड़ते हैं, मगर जब किसान सरकार का विरोध करता है तो वह कानून नहीं, सरकार की पीठ तोड़ने का काम करता है।"

मैं आज सरकार को बोलना चाहूंगा कि किसान रूपी जो हमारी ज़मात है, यह किसी जाति विशेष से नहीं आती। आज 36 बिरादरी के लोग खेतों के अंदर काम करते हैं। आज आप उस किसान की पीठ तोड़ने का काम कर रहे हैं। मैं सदन के एक-एक साथी से अपील करूंगा कि उस किसान को आप बचाने का काम करें।

हमारी पार्टी इंडियन नेशनल लोक दल इस बिल का पूर्ण तौर पर विरोध करती है और सरकार से यह मांग करती है कि इस बिल को दुबारा स्टैण्डिंग कमेटी तक भेज कर फिर से किसानों के अधिकारों के बारे में सोचा जाए, उनकी सहमति के बारे में सोचा जाए, सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट के बारे में सोचा जाए। यह फिर से सोचा जाए कि किस तरीके से हम गरीबों को मकान दे पाएंगे, मगर उससे किसान को नुकसान न पहुंचे।

माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से इस बिल का विरोध करता हूं और सरकार से यही आग्रह करता हूं कि इस बिल को दुबारा स्टैण्डिंग कमेटी में भेज किसानों की समस्याओं पर विचार करने का काम करे।

श्रीमती अनुप्रिया पटेल (मिर्ज़ापुर): सभापति महोदय, भारत एक ऐसा देश है, जहां 70% लोग आज भी खेती-किसानी पर अपनी आजीविका चलाते हैं और इन 70% लोगों में बहुतायत रूप से देश के कमज़ोर, दलित, पिछड़े समुदाय के लोगों की आबादी शामिल है। ये वह तबका है, जिसकी निर्भरता जल, जंगल और ज़मीन पर सामान्य वर्ग के लोगों से सबसे ज्यादा है। शायद इसीलिए आज जब हमारी सरकार भूमि अधिग्रहण अध्यादेश लेकर आयी है तो यह पूरा सदन और पूरा देश तमाम सवालों, आशंकाओं और चिंताओं से घिर गया है। ऐसा माहौल बन रहा है कि लगता है कि जब एन.डी.ए. सरकार इस कानून को संशोधित करके लाई है, तभी ये तमाम चिंताएं पैदा हुईं हैं। लेकिन, यह सच नहीं है। वर्ष 2013 का जो कानून बना था, उसमें भी कमियां थीं। उन कमियों को भी दूर करने की जरूरत थी।

मैं सदन के संज्ञान में लाना चाहूंगी कि वर्ष 2011 में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी ने स्वयं तत्कालीन मंत्री श्री जयराम रमेश जी को इस कानून का विरोध करते हुए पत्र लिखा था। महाराष्ट्र की कांग्रेस सरकार ने ही मुआवजे की कीमत को 4 गुना से घटाकर 2.2 गुना करने का काम किया था। इतना ही नहीं केरल कांग्रेस की सरकार ने भी इस बात को पब्लिकली एडमिट किया था कि जो कानून यूपीए सरकार द्वारा बनाया गया है, उससे विकास असम्भव प्रतीत होता है। कमियां तब भी थीं, कमियां आज भी हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि हमारी सरकार ने, जो तमाम आपत्तियां विपक्ष के साथियों ने या सहयोगी दलों ने दर्ज कराई हैं, उस पर विचार किया है और तमाम संशोधन भी लाई है।

सबसे बड़ी आपत्ति या सबसे बड़ी चिन्ता बहुफसली जमीनों के अधिग्रहण को लेकर थी, जिस पर सरकार ने संशोधन किया है। हमारे तमाम साथियों ने कहा कि अगर कृषि प्रधान देश के अन्दर बहुफसली जमीनों का अधिग्रहण किया जाएगा तो इस देश की खाद्य सम्प्रभुता को खतरा पहुंचेगा। हमारे देश की बहुत सारी जमीनों का अधिग्रहण वर्ष 1894 से लेकर 2013 के बीच में हुआ। हमारे देश का किसान बधाई का पात्र है कि इतने अधिग्रहण के बावजूद भी देश के अन्दर किसी भी कीमत पर खाद्यान्न का संकट नहीं आने दिया। यह गौर करने लायक बात है कि ऐसा क्यों नहीं हुआ? ऐसा इसलिए नहीं हुआ, क्योंकि जो खाद्य का उत्पादन होता है, वह सिर्फ क्षेत्रफल पर नहीं, बल्कि हम खेती के कौन से तौर-तरीके इस्तेमाल करते हैं, इस पर भी निर्भर करता है। हमारी सरकार ने बहुफसली जमीनों के अधिग्रहण के प्रति जो चिंता व्यक्त की गई, उसको संज्ञान में लेते हुए दो अहम संशोधन किए हैं। पहला संशोधन यह किया गया कि जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है, वह किसी भी परियोजना के लिए एक सीमा तय करेगी कि कम से कम कितनी जमीन की आवश्यकता है और उतनी ही जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा। भविष्य में विस्तार के नाम पर एक्सेज जमीन का अधिग्रहण नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही जो तमाम सरकारें हैं, वे अनुपजाऊ भूमि का

सर्वेक्षण करेंगी और उसका रिकार्ड बनाएंगी। केवल ऐसी ही परिस्थितियों में बहुफसली जमीनों का अधिग्रहण होगा, जब किसी भी राज्य के अन्दर जो वेस्टेज लैंड है, जो अनुपजाऊ भूमि है, वह उपलब्ध नहीं है। निश्चित रूप से सरकार ने ये जो दो संशोधन किए हैं, इसके लिए सरकार बधाई की पात्र है।

जहां तक सोशल इंपैक्ट असेसमेंट का सवाल है, इसको लेकर भी सदन में बहुत सारे साथियों ने अपनी चिंता व्यक्त की है। इसमें दोनों के प्रति चिंता है। जो किसान जमीन मालिक है, उसके प्रति भी चिंता है। उस जमीन पर जो अन्य लोग निर्भर हैं, जैसे पशु चराने वाले, घास काटने वाले, मजदूर, बटाईदार, ये तमाम लोग हैं, उनकी भी चिंता है। मैं सरकार से यह जरूर कहना चाहती हूं कि आप किसानों को मुआवजा दे देते हैं, किसान परिवार को आप नौकरी भी देंगे, ये दोनों बातें अच्छी हैं। हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि हमारे किसानों को जमीन हैंडलिंग तो आती है, लेकिन मनी हैंडलिंग नहीं आती है। मुआवजे की जो राशि किसान को मिलती है, उसे उसका रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट करना नहीं आता है। इसलिए वह राशि एक-दो साल में खत्म हो जाती है और उसके बाद किसान का परिवार भूखा मरता है। सरकार को अपने प्रावधानों में यह व्यवस्था जरूर करनी होगी कि किसान को जो मुआवजा दिया जाता है, उस मुआवजे की कुछ राशि को जो परियोजनायें या उद्योग लगाए जा रहे हैं, उसको शेयर के रूप में लगाया जाए, किसान को शेयर होल्डर बनाया जाए। अगर किसान को मालिकाना हक मिलेगा, किसान शेयर होल्डर बनेगा, तो कहीं न कहीं अधिग्रहण के नाम पर जो तमाम लोकल ईश्यूज आते हैं, स्थानीय प्रोटेस्ट होते हैं, ऐसी समस्याओं का सामना किसान को नहीं करना पड़ेगा। जो तमाम अन्य लोग हैं, बटाईदार मजदूर हैं, उनके लिए सरकार ने संशोधन करके व्यवस्था की है कि ऐसे प्रभावित परिवारों के एक सदस्य को नौकरी दी जाएगी। इसके लिए मैं सरकार की सराहना करती हूं।

इस सदन में जो तीसरी चिंता रखी गई है, वह सरकार द्वारा बुनियादी सुविधाओं के नाम पर निजी अस्पतालों और निजी शिक्षण संस्थानों के लिए जमीन अधिग्रहण करने की है। इस संबंध में भी मुझे यह अवगत हुआ है कि सरकार ने इसमें संशोधन कर दिया है और निजी अस्पताल और निजी शिक्षण संस्थान के नाम पर सरकार किसी भी प्रकार का अधिग्रहण नहीं करेगी। हमारे विपक्ष के साथियों की इस चिंता का भी समाधान हुआ है। अधिनियम का उल्लंघन करने वाले अधिकारियों के खिलाफ किसी भी प्रकार की कार्रवाई न करने के संबंध में जो बात थी, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री देवगौड़ा जी भी इस बात को कह रहे थे कि सरकार ने संशोधन किया है कि सरकार के पूर्व सैंक्शन के बाद कोर्ट इसमें हस्तक्षेप कर सकती है, ऐसे मामलों का संज्ञान लेकर कार्रवाई कर सकती है। लेकिन अगर ऐसी परिस्थितियां हों कि जो हमारे अधिकारी हैं, वे राजनेताओं के साथ साठगांठ कर लें या जैसा कि हमारे भाई प्रहलाद पटेल जी ने कहा कि सिंचित

भूमि के आगे 'अ' लिखकर उसे असिंचित कर दें, लैंड यूज बदल दें तो इन प्रावधानों को और भी स्ट्रेंजेंट करने की जरूरत है। जिससे हमारे जो नौकरशाह हैं, जो ब्यूरोक्रैट्स हैं, वे किसानों के अधिकारों के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ न कर सकें। मैं सरकार से इसकी अपील करती हूं। किसानों के संबंध में जो शिकायतें हैं उनके निस्तारण की व्यवस्था, जो सरकार अध्यादेश लायी थी, उसमें नहीं थी, उसमें भी सरकार द्वारा संशोधन किया गया है। जिला स्तर पर जूडिशियल ट्रिब्यूनल की व्यवस्था दी गई है जिससे उन तमाम शिकायतों का निस्तारण किया जा सके। ये तमाम संशोधन जो सरकार ने किये हैं, उनके लिए मैं सरकार को बधाई देती हूं।...(व्यवधान) मैं एक और बात कह कर अपनी बात समाप्त करना चाहती हूं।

आज हमारे देश में एस.ई.जेड. के नाम पर, सेना, सिंचाई, पी.डब्ल्यू.डी. रेलवेज, वन विभाग, ग्राम सभा, नगरपालिका के पास पहले से ही बहुतायत जमीन खाली पड़ी हुयी है, पहले उसको उपयोग में लाने की जरूरत है। सरकार ने जो पांच श्रेणियां बतायी हैं कि उन पांच श्रेणियों की परियोजनाओं के लिए, जैसे - डिफेन्स, रूरल इन्फ्रास्ट्रक्चर, इन्डस्ट्रीयल कॉरिडोर्स हैं, उनके लिए जब आप जमीन का अधिग्रहण करेंगे तो पहले हमारे पास जो सरप्लस जमीन है उसका इस्तेमाल होना चाहिए और उसके बाद अन्य श्रेणियों के लिए जमीन का अधिग्रहण होना चाहिए। उसके लिए भी सरकार सोशल इमपैक्ट असेसमेन्ट और सरकार ने राज्य सरकारों को जो ऑप्शन दिया है तो यह राज्य सरकारों की जिम्मेदारी बनती है और राज्य सरकारें इस जिम्मेदारी का निर्वहन करें, इसकी व्यवस्था भी केन्द्र सरकार को करनी है।

मेरा सरकार से यही निवेदन है कि जो सुझाव दिये जा रहे हैं, क्योंकि आज भी इस बिल में उतनी कमियां हैं, जैसे वे पहले थीं, जैसे सरकार ने 9 संशोधन करके तमाम कमियों को दूर किया है, वैसे ही जो अन्य सुझाव दिये जा रहे हैं, जितना संभव हो उन्हें इसमें शामिल किया जाए। यह किसानों के हक और अधिकार की बात है। ...(व्यवधान) उनके लिए बहुत ही संवेदनशीलता दिखाने की जरूरत है।

श्री विजय कुमार हाँसदाक (राजमहल) : सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं अपनी पार्टी जे.एम.एम. की तरफ से इस लैण्ड बिल का पूरजोर तरीके से अपोज करता हूं क्योंकि यह कहीं न कहीं किसानों और आदिवासियों के हितों के खिलाफ जा रहा है। सरकार बहुत योजनाओं के लिए जो जमीन ली जानी है, उसका वर्ष 2013 के लैण्ड बिल में कोई विरोध नहीं हो रहा था। अगर देश के हित में जमीन का इस्तेमाल हो तो कहीं उसका विरोध नहीं है, लेकिन कितनी जमीन की जरूरत है? जिस तरह से इस लैण्ड बिल को लाया गया है, उससे सिर्फ उद्योगपतियों का भी फायदा होने वाला है। मैं क्लाउज बाई क्लाउज चर्चा नहीं करना चाहता हूं क्योंकि बहुत सारे माननीय सदस्य उन पर बोल चुके हैं। उन्होंने बहुत विस्तृत रूप से क्लाउज बाई क्लाउज और अमैण्डमेन्ट पर डिस्कशन किया है।

हमारे क्षेत्र के आदिवासियों और किसानों से बातें उठ कर आ रही हैं, मैं उन्हें सदन में रखना चाहता हूं। यह एक ऐसा मेजर बिल है जो कहीं न कहीं हर आदमी को अफेक्ट कर रहा है। यह किसानों को अफेक्ट कर रहा है, जो हमारे देश की रीढ़ है। इसे बहुत जल्दबाजी में लाया जा रहा है। वर्ष 2013 की बिल पर बहुत डिस्कशन हुयी थी और आज यह बिल बहुत तेजी से लाया जा रहा है, कौन-सी ताकतें हैं, जो इसे तेजी से लाना चाह रही हैं? जब देश हित की बात की जा रही है तो इसे पूरे सिस्टमैटिक ढंग से डिस्कशन के लिए फ्लोर पर क्यों नहीं लाया जा रहा है? यहां पर यह सवाल बहुत जरूरी है। मैं बाइबल के कुछ शब्दों को यहां पर कोट करना चाहूंगा - 'What benefit does it do to a man if he gains the whole world but loses his soul.' बी.जे.पी. का मूल मंत्र है - 'सबका साथ, सबका विकास।' मैंने जो बाइबल के शब्द कोट किये हैं उनसे मैं तुलना करना चाहता हूं कि जब 'सबका साथ, सबका विकास' की बात आप कर रहे हैं तो इस देश की आत्मा हमारे गांवों में बसती है। आज जब किसानों के हित की बात आ रही है तो हम इसे बहुत हड़बड़ी में क्यों कर रहे हैं, इसे चर्चा में क्यों नहीं ला रहे हैं? …(व्यवधान) चर्चा करने की बात जरूर हो रही है लेकिन यह हड़बड़ी में बहुत हो रही है। …(व्यवधान) इसे स्टैण्डिंग कमेटी में भी ले जाने की जरूरत है। …(व्यवधान) यह आप भी स्वीकार करेंगे।…(व्यवधान)

<u>16.00 hrs</u>

झारखंड में कुछ समय पहले इलैक्शन हुआ था। उस वक्त प्रधान मंत्री जी आए थे और उन्होंने अपना भाषण दिया था। उन्होंने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा था कि कोई माई का लाल आदिवासियों की जमीन नहीं ले सकता। मैं इस सदन द्वारा आज उन्हीं बातों को उन तक पहुंचाना चाहता हूं। आज इस

विधेयक को लेकर झारखंड और पूरे देश के किसान, आदिवासी जमीन पर उतरे हुए हैं। आप कृपया अपनी कही हुई बातों को फिर से जरूर याद कीजिए। शैडयूल एरियाज़ में मैक्सिमम मिनरल माइन्स हैं। इस कानून से आदिवासियों का अधिकार छीना जाएगा। आदिवासी या किसान बहुत शान्त प्रवृत्ति के होते हैं। जब उन्होंने अपने हक के लिए लड़ाई लड़ी तो ब्रिटिशर्स को भी अपने घुटनों पर लाकर खड़ा कर दिया था। वे सब जगह जीत पाए थे और आदिवासियों के सामने उन्हें घुटने टेकने पड़े थे। चाहे सिधु कानू हो, तिलका मांझी हों या बिरसा मुंडा हों, इन सबके सामने उन्हें घुटने टेकने पड़े थे। वही बातें आज फिर से हो रही हैं। हमारे देश के किसानों, आदिवासियों के हित को कुचलने का प्रयास किया जा रहा है। बहुत ही सीमित साधन और कम आय में आदिवासी लोग खुशी से रह सकते हैं। यहां जिस तरह लैंड बिल लाया जा रहा है, यह सीधे तौर पर पूंजीपतियों को फायदा देने वाला है, किसान और आदिवासियों को फायदा देने वाला नहीं है।

हम आतंकवादियों की बात करते हैं। उनकी बंदूक, गोलियों या बमों से कितने लोग मरते हैं, 10, 20, 50, 100, 500. यह करोड़ों आदिवासियों, किसानों की जिंदगी से जुड़ा हुआ मामला है। इसलिए इस बिल पर डिसकशन करने की जरूरत है, इसे जल्दबाजी में पारित करने की जरूरत नहीं है। आप भारतवासी हैं और यहां के लोगों के हितों के लिए सोचना आपका कर्म बनता है।

इसमें जो संशोधन लाए जा रहे हैं, वे आम आदमी और किसानों के विरुद्ध हैं। इसे स्टैंडिंग कमेटी में भेजने की जरूरत है। झारखंड में नक्सलवाद की समस्या है। इस तरह के कानून बनने से कहीं न कहीं नक्सलवाद को बढ़ावा मिलेगा। अगर इस तरह उन लोगों की लैंड ली गई तो आने वाले समय में हमारे यहां के लोग नक्सली बन जाएंगे। वे लोग नक्सली न बनें, इसके लिए जरूरत है कि लैंड बिल पर एक बार फिर से बढ़िया डिसकशन की जाए। यह पार्लियामैंट हमारे कौन्सटीट्यूशन का मंदिर है। अगर यहां हमारे लोगों के हितों की रक्षा नहीं की जा सकती तो हमें भी नक्सलियों के साथ खड़े होकर लोगों के दुख-दर्द और हक के लिए लड़ना पड़ेगा। इतना कहकर मैं धन्यवाद करना चाहता हूं।

श्री दिलीप सिंह भूरिया (रतलाम) : सभापति महोदय, मैं लैंड बिल के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। आजादी के 68 साल बाद हम देश के किसानों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। जब देश आजाद हुआ था, उस समय इसकी आबादी 36 करोड़ थी। उस वक्त हम बाहर से अनाज मंगवाते थे। आज भारत की आबादी 125 करोड़ है। हम 125 करोड़ लोगों को खिलाने के बाद दुनिया के बहुत से देशों में अपने देश का अनाज भेजते हैं और उनका पेट भरते हैं।

सभापति महोदय यह क्यों हुआ, विज्ञान डेवलप हुआ, किसान को क्या चाहिए, किसान को पानी और बिजली चाहिए। जब मैं सातवीं लोक सभा में चुन कर आया था उस समय पार्लियामेंट के सामने चार गाड़ी खड़ी रहती थी, हम उस समय सिटी बस में आते थे। आज हम साढ़े सात सौ एम.पीज के पास गाड़ियां हैं। गाड़ियों को रखने की जगह नहीं है। ...(व्यवधान) अगर आप गाड़ियों में घुमेगें और वोटरों से कहेंगे कि मेरे पास गाड़ियां नहीं हैं। क्या वह हमें पसंद करेंगे। आप बताइए कि हम गाड़ियां नहीं लेंगे, गाड़ियां नहीं रखेंगे। जब हमारी आबादी 36 करोड़ थी तब हमारा पेट नहीं भरता था, आज हम 125 करोड़ हैं। आप किसानों को भ्रमित मत कीजिए। आप खुद भ्रमित हैं, किसान भ्रमित नहीं है। मैं मध्य प्रदेश की बात बता रहा हूं। मध्य प्रदेश में 10 साल तक कांग्रेस का राज था। बिजली कहीं नहीं मिलती थी। आज मध्य प्रदेश में 24 घंटे बिजली मिल रही है। ...(व्यवधान) यहां कमल नाथ जी बैठे हुए हैं, 24 घंटे बिजली मिल रही है और मध्य प्रदेश का एग्रीकल्चरल ग्रोथ 25 प्रतिशत है जो हिन्दुस्तान में सबसे ज्यादा है। यह सब क्यों हुआ? आदरणीय कमल नाथ जी बैठे हुए हैं। जब नर्मदा की बात आई, हमने उस पर बांध बनाया, किसानों के खेतों में पानी गया, बिजली दी, यह विकास है। अगर आप किसानों को भ्रमित करके वोट लेना चाहते हैं तो आपको वोट मिलने वाला नहीं है। मध्य प्रदेश में नगर निगम का चुनाव हुआ, कमल नाथ जी बैठे हैं। 14 सीटों में से 14 जीत गए। किसान आप से भ्रमित नहीं है। यही स्थिति पंचायत चुनाव की भी है। आप स्टैंडिंग कमिटी की बात कर रहे हैं। हम यहां 550 एम.पीज बैठे हैं, आप चर्चा कीजिए, सरकार चाहती है कि हम अच्छे से अच्छा बिल लाएं, मोदी सरकार गरीब और किसानों का भला करने वाली सरकार है। ...(व्यवधान) आप क्या चाहते हैं।

माननीय सभापति: प्लीज बैठ जाइए। प्लीज कन्टीन्यू। अगर ऑब्जेक्शनेबल होगा, उसे डिलीट कर देंगे।

श्री दिलीप सिंह भूरिया: सभापति जी, अभी ये आदिवासी और ट्राइबल्स की बात कर रहे थे। वर्ष 1996 में आदिवासियों के लिए कानून बना है। मैं उस कमेटी का चेयरमैन था। पीसा कानून द्वारा आदिवासियों को यह हक दिया है कि जब तक ग्राम सभा द्वारा तय न हो आदिवासियों की जमीन न ली जाए। मगर ओडिशा में क्या हो रहा है? आप शिड्यूल एरिया की बात कर रहे हैं। वहां की सरकार और चीफ मिनिस्टर खदानों के

लिए जमीन मांग रही है। पहले आप गरीब के लिए कानून बनाइए, यह सरकार गरीबों की सरकार है। यह सरकार किसानों की सरकार है।

हम चाहते हैं कि भारत दुनिया में नम्बर वन देश बने। …(व्यवधान) भारत विकसित हो, तो वह कहां से विकसित बनेगा? हम सड़कें नहीं बनायेंगे, तो क्या वह विकसित होगा? जैसे मैंने पहले की पार्लियामेंट की बात कही कि हम पैदल आते थे। अब हम गाड़ी में आते हैं। हम फोर लेन्स बना रहे हैं, तो क्या उसके लिए जगह नहीं लेगी? …(व्यवधान) सिक्स लेन्स बना रहे हैं, तो क्या उसके लिए जगह नहीं लगेगी?…(व्यवधान) हमने बड़े-बड़े डैम्स बनाये हैं। अभी देवेगौडा जी कह रहे थे कि कावेरी और कृष्णा नहीं बनती, तो तमिलनाडु और कर्नाटक की क्या स्थिति होती, आंध्र प्रदेश की क्या स्थिति होती? …(व्यवधान) मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं।

16.11 hrs (Shri Arjun Charan Sethi *in the Chair*)

मैं सभापति महोदय से कहूंगा कि पूरा आपोजिशन भ्रमित है। ये देश का विकास नहीं चाहते। ये किसानों के खिलाफ हैं। …(व्यवधान) किसान अपने बच्चों को पढ़ाये। …(व्यवधान) किसान अपने बच्चों को डाक्टर, इंजीनियर, वकील या नेता बनाये, क्योंकि वह भी आजाद हिन्दुस्तान का नागरिक है। वह क्यों नहीं आगे बढ़ेगा? …(व्यवधान) मैं खुद आदिवासी हूं, किसान हूं। हम क्यों नहीं अपना विकास करेंगे? हम देश के साथ चलेंगे। …(व्यवधान) ये सारी चीजें हैं। आप भ्रमित न हों, किसान भ्रमित न हों। अगर किसान भ्रमित होगा तो वह खत्म हो जायेगा।

सभापति महोदय, मैं इस बिल का समर्थन करता हूं और आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

HON. CHAIRPERSON: Now, Shri Thota Narasimham.

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Please sit down.

Shri Thota Narasimham.

SHRI THOTA NARASIMHAM (KAKINADA): Hon. Chairperson, Sir, thank you very much for giving me this opportunity.

First of all, I rise to support the Bill on behalf of my Party, Telugu Desam Party. This Bill provides provisions for land acquisition as well as rehabilitation and resettlement. It replaces the Land Acquisition Act, 1894. Discussions to amend the colonial Land Acquisition Act, 1894 continued over nearly three decades under successive Governments. In parallel, there were conferences and debates in the civil society also. The result is the Land Acquisition Relief and Rehabilitation (Amendment) Bill.

One issue in India is that the records of land holding cannot be easily verified. This opens the possibility of disputes after purchase. Industrial enterprises use this fact to argue that the Government should acquire land on their behalf.

From the year 2008, the main reason for the failure of our economic policies targeted to achieve substantial growth rate is due to languishing corporate investment. Three main reasons for these are environmental laws and clearances, problems with land acquisition and to provide effective infrastructure on time. Because on these reasons, Land Acquisition Relief and Rehabilitation Act, 2013 came into limelight again. The present amendments are made to balance and recalibrate the Government laws and policies.

Hon. Chairperson, Sir, at the same time I would like to bring some important points to the notice of the Government.

Acquisition of land means not merely loss of land and home but also loss of livelihood, loss of a community and cultural continuities and loss of a way of life.

This is bound to be a traumatic experience. The Government has to keep this in mind while acquiring land.

In India, land is an emotionally attached factor for most of the farmers. Many farmers have small landholdings and they are mainly depending on those holdings to eke out their livelihood. These holdings have been transferred from their ancestors. Hence most of them are sentimentally attached to their lands. Any type of land acquisition should not affect their sentiments as well as their livelihood.

The policies of the Government should be to protect the interests of the farmers, small peasants and common man, and simultaneously giving thrust to economic growth of the country. The policies of the Government should be farmer-friendly, common man-friendly as well as growth-friendly. There is a thin line between them. So, a balance has to be maintained. Then only, comprehensive growth can be achieved. Growth should be appreciated. At the same time, cancer is also a growth. But cancerous growth is not desirable for any upcoming healthy society like India. The previous Government had neglected this point in the name of SEZs. I believe that this Government cannot go in that direction.

Sir, we have taken up land acquisition in Andhra Pradesh for our Capital through an innovative idea called ‘Land Pooling’. Our Chief Minister Shri Nara Chandrababu Naidugaru has prestigiously taken up this innovative initiative. This is a dual benefit programme for both farmer and the Government. Every farmer is happy with this system compared to land acquisition.

Sir, I want to caution the Government that land should not be used as a source for employment generation and job creation. When the acquisition of land is inevitable, farmers depending upon that land should not be left jobless. They should be involved in some kind of employment linked up with the land elsewhere.

The process for land acquisition involves a Social Impact Assessment Survey, preliminary notification stating the intent for acquisition, a declaration of

acquisition and compensation to be given by a certain timeframe. All acquisitions require rehabilitation and resettlement to be provided to the people affected by the acquisition. The requirement of a Social Impact Assessment for every acquisition without a minimum threshold may delay the implementation of certain Government programmes. So, a minimum threshold may be fixed for SIA.

Sir, certain safeguards are incorporated in the Bill for the benefit of the land owners. Compensation for the owners of the acquired land shall be four times the market value in case of rural areas and twice in case of the urban areas. In case of acquisition of land for use by private companies or public private partnerships, the consent of 80 per cent of the displaced people will be required. However no such consent is required in case of PSUs. Purchase of large pieces of land by private companies will require provision of rehabilitation and resettlement.

Farmers' right to their land on which they are earning their bread and butter, should not be compromised. Their interests have to be protected.

Sir, I sincerely thank the hon. Prime Minister, hon. Minister of Parliamentary Affairs and also hon. Minister of Rural Development, who came out with open minds to incorporate necessary Amendments to this Bill. It is a welcome step in the right direction. I would appeal to all my colleague MPs to suggest measures to make this Bill more effective for the prosperity of our motherland.

Sir, while referring to this issue yesterday, my learned friend from YCP made some remarks saying that our Andhra Pradesh Government is acquiring land forcibly from the farmers. I want to clarify to my learned friend that some politicians may not be happy but most of the farmers are happy. They voluntarily came forward and handed over their land passbooks to the revenue officials. No force or pressure is applied during acquisition. Gram Sabhas were conducted and farmers' consent was obtained. We are giving good package to the farmers. Hence most of the farmers voluntarily came forward. We completed more than 90 per cent of the first phase of land pooling with the willingness and consent of the

farmers. We sincerely hope and trust that we will complete cent per cent land pooling with the total willingness of the farmers. It is the biggest success of our Telugu Desam Party Government in our State.

Mr. Chairman Sir, my another learned friend from TRS Party pointed out yesterday that Y.S. Rajasekhara Reddy garu and also Chandrababu Naidu garu extensively acquired lands in Hyderabad. Everybody in the country knows what Chandrababu Naidu garu did to Hyderabad. Who brought IT to Hyderabad? Who initiated and made Hyderabad as an IT hub? Who had taken up construction of Hitech City at Madhapur and International Airport at Samshabad? Through acquired lands, Chandrababu Naidu garu developed Hyderabad in the united Andhra Pradesh. He brought a brand image to Hyderabad. Now, it went to Telangana. The people of Telangana are reaping the fruits sown by Chandrababu Naidu. Now, they are criticizing our leader. The world recognized him. Leaders are unable to digest the truth. I leave it to their wisdom.

Mr. Chairman Sir, we want to assure the Government that we will certainly stand with them to take this country ahead duly balancing the interests of economic growth and job creation which left the poor people with much poverty.

श्री संतोष कुमार (पूर्णिया) : माननीय सभापति महोदय, मैं अपनी पार्टी जनता दल (यू) की ओर से भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर पारदर्शिता अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2015 पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ।

पूरी एक सदी की लंबी जद्दोजहद के बाद जब देश में " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार विधेयक, 2013" कानून बना तो लगा कि इस कानून के अमल में आते ही देश भर में अब किसान से जबरन जमीन हथियाने के खेल पर रोक लगेगी। किसानों की जमीन उनसे बिना इजाजत के अब कोई नहीं छीन पाएगा। बहरहाल कानून ठीक ढंग से अमल में आ पाता उससे पहले ही केन्द्र की भाजपा सरकार ने इसमें बदलाव करने का फैसला कर लिया। एक अध्यादेश के जरिए भूमि अधिग्रहण कानून में व्यापक संशोधन कर दिया। अध्यादेश ने कानून के मूल सिद्धांत को ही बदल कर रख दिया।

दिसम्बर, 2013 में सर्वसम्मति के बाद हमारी संसद ने जो भूमि अधिग्रहण कानून पारित किया था उसमें सरकार और पूंजीपतियों से किसानों की जमीन बचाने के लिए कई क्रांतिकारी प्रावधान किए गए थे। सरकारी, गैर-सरकारी किसी भी परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण में संबंधित क्षेत्र के भू-स्वामियों की कुल आबादी के 70 फीसदी लोगों की सहमति को अनिवार्य बनाया गया था, लेकिन इस अध्यादेश में इस महत्वपूर्ण प्रावधान को खत्म कर दिया है। उस कानून में सिंचित कृषि भूमि के अधिग्रहण पर रोक लगाई गई थी। अध्यादेश में संशोधन के जरिए यह पाबंदी भी हटा दी गई है।

महोदय, मौजूदा सरकार ने, जो दिसम्बर, 2014 को भूमि अधिग्रहण से जुड़ा अध्यादेश पारित किया, जिसे कानूनी अमलीजामा पहनाने के लिए उसे इस सदन में लेकर आई है, उसके विरुद्ध देश भर में किसान संगठनों, विभिन्न संघों से लेकर सामाजिक संगठनों तथा राजनीतिक दल आन्दोलन कर रहे हैं। मैंने पूरे बिल का अध्ययन किया है, वास्तव में इसमें कई खामियां हैं, इसलिए इस तरह के आन्दोलन हो रहे हैं। अधिकांश राज्य सरकारें इस अध्यादेश के खिलाफ हैं।

माननीय प्रधानमंत्री जी ने लोक सभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा के जवाब के दौरान संसद में पहली बार भूमि अधिग्रहण पर विपक्ष के सहयोग की अपील की थी और यह भी कहा था कि किसानों के खिलाफ यदि एक भी चीज़ होगी तो मैं उसे बदलने के लिए तैयार हूँ।

मैं सरकार से कहना चाहूंगा कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ के लोगों का एक मात्र जीविकोपार्जन का मुख्य साधन खेती है। जो भूमि अधिग्रहण बिल लोक सभा में पेश किया गया है, उसमें बहुत सारी खामियां हैं। सरकार किसानों की कीमती भूमि का अधिग्रहण कर उन्हें बेदखल करना चाहती है,

जो गैर-कानूनी और असंवैधानिक भी है। भारत सरकार जब भी किसी परियोजना जैसे-पावर प्लांट, रक्षा उपकरण, एन.एच., रेलवे या किसी उद्योग-धंधे के लिए किसानों से जमीन का अधिग्रहण करती है, तो उसका उचित मुआवजा दिए जाने की बात करती है, किन्तु वास्तव में ऐसा नहीं हो पाता है और किसानों को उसके लिए कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाना पड़ता है और बड़ी मुश्किल से उन्हें न्याय मिलता है। लेकिन इस बिल में किसानों से वह अधिकार भी छीन लिया गया है। इस बिल में भूमि अधिग्रहण से पहले उसके सामाजिक प्रभाव का आकलन करना जरूरी नहीं बताया गया है जबकि इसके पूर्व के बिल में यह प्रावधान था कि भूमि अधिग्रहण से पहले उसके सामाजिक प्रभाव का आकलन करना आवश्यक है।

महोदय, वर्तमान बिल में राष्ट्रीय सुरक्षा, रक्षा और ग्रामीण क्षेत्र के प्रोजेक्ट के लिए उपजाऊ भूमि का भी अधिग्रहण किए जाने की बात कही गई है जबकि पुराने बिल में बहुफसली और उपजाऊ भूमि का किसी विशेष परिस्थिति में ही अधिग्रहण करने पर विचार किए जाने का प्रावधान किया गया था। पूर्व के बिल में यह प्रावधान था कि किसानों की अधिग्रहण की गई जमीन पर यदि पांच साल में प्रोजेक्ट शुरू नहीं हुए तो किसानों को जमीन वापस कर दी जाएगी। यह सरकार जो नया बिल ले कर आई है और उसे कानूनी अमलीजामा पहनाना चाहती है, उसमें अधिग्रहण की गई जमीन पर प्रोजेक्ट शुरू करने की कोई समय-सीमा तय नहीं की है। इससे प्राइवेट कंपनियों को अधिग्रहण की गई जमीन पर अपने प्लान के मुताबिक बड़े आराम से काम करने की सहूलियत होगी।

महोदय, सरकार ने तो सार्वजनिक उद्देश्य की परिभाषा को ही बदल दिया है जिसके तहत सरकार की ओर से ली गई जमीन के दायरे में प्राइवेट अस्पतालों, शैक्षणिक संस्थानों और प्राइवेट होटलों को शामिल किया गया है जबकि इस एक्ट के मूल प्रावधानों में प्राइवेट अस्पतालों, शैक्षणिक संस्थानों और प्राइवेट होटलों के लिए सरकार की तरफ से जमीन के अधिग्रहण पर रोक लगाई गई थी। इस बिल के मुताबिक सरकार सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के नाम पर प्राइवेट खिलाड़ियों के लिए जमीन का अधिग्रहण कर सकेगी। सरकार पूरी तरह से उद्योगपतियों के दबाव के आगे झुक गई है। अधिग्रहण की गई जमीन पर कोई निश्चित समय-सीमा तय नहीं किया जाना उद्योगपतियों को खुली छूट देना है।

इस बिल में भूमि अधिग्रहण के मामले से पीड़ित किसान, न्याय पाने हेतु बिना सरकार की अनुमति के कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटा सकता, उस पर कड़ा प्रतिबंध लगा दिया गया है।

महोदय, हमारी पार्टी इस बिल का पुरजोर विरोध करती है और मांग करती है कि इस बिल को लोकसभा की ग्रामीण विकास मंत्रालय की स्थायी समिति के पास पुनर्विचार के लिए भेजा जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री ओम बिरला (कोटा) : सभापति महोदय, आज एक महत्वपूर्ण बिल पर सदन में चर्चा हो रही है। भूसम्पत्ति कानून 1894 के बाद अब 120 साल बाद देश के अंदर किसानों के हित के लिए कानून बनाने की चर्चा हो रही है। हिंदुस्तान की असली आजादी तब मानी जाएगी, जब संसद के अंदर हम ब्रिटिश हुकूमत के सारे कानून समाप्त करके अपने देश के हित के लिए कानून बनाएंगे, तब हिंदुस्तान आजाद होगा। इस कानून को वर्ष 2013 में लाया गया था। 13 अलग-अलग अध्यादेशों से देश के अंदर भूमि अधिग्रहण की जा रही थी। 13 अध्यादेशों को मिलाकर एक कानून लाया गया, कानून को चाहे कोई भी दल की सरकार लाई हो क्योंकि कोई भी सरकार हो वह देश के किसान के हित में कानून लाती है, देश के विकास के हित में कानून लाती है। मेरे कांग्रेस के साथी चर्चा कर रहे थे कि हम तो किसान के हित में कानून लाए थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो संशोधन कानून ला रही है, वह पूंजीपति और भूमाफियाओं के पक्ष में कानून ला रही है। हमारे एक सम्मानित सदस्य ने कई माननीय सदस्यों की चर्चा की है कि उन्होंने संसद में यह बात कही थी। हमारे संसदीय कार्य मंत्री जी ने भी बताया था कि आपके राज्य के मुख्यमंत्रियों ने, आपके वरिष्ठ नेताओं ने संसद में और संसद के बाहर इस कानून के बारे में कहा था कि इस कानून से देश का विकास अवरुद्ध हो जाएगा।

जो लोग किसान हित की बात कर रहे हैं, अगर किसान हित के असली रखवाले होते तो क्या आज इस देश के किसान की ऐसी हालत होती? आज देश में किसान बदतर स्थिति में है। जो लोग सड़कों पर बात कर रहे हैं, हमसे कह रहे हैं कि भूमि के दलाल हो गए हैं, वे लोग इस कानून को ध्यान से पढ़ लें। यह कानून देश के विकास का कानून है। आज देश विकास मांग रहा है, आज देश नरेन्द्र मोदी के सपनों का देश मांग रहा है, जिसमें हर गांव के किसान को बिजली मिले, इंफ्रास्ट्रक्चर के आधार पर देश का चहुंमुखी विकास हो, देश के नौजवानों को रोजगार मिले। क्या आज हमें परेशानी नहीं होती है? गांवों में बिजली हो, सड़क हो, रेल हो, आज भी इन बुनियादी सवालों के लिए हम तड़पते रहते हैं। आज किसान चाहता है कि मेरे खेत में पानी पहुंचे, नहरें पहुंचें, बांध बनें, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो, देश का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा तो देश के विकास को आधार मिलेगा। इस कानून की चर्चा करते हुए माननीय सदस्यगण राजनीतिक दायरे में इसका विरोध जरूर कर लें, लेकिन इस कानून की एक-एक धारा और धारा के बाद इसमें लाए गए संशोधनों को देखें। हम देशहित में कानून बनाते हैं। यह कानून इस बात को साबित करता है कि जहां देश का किसान खुशहाल होगा, वहां इंफ्रास्ट्रक्चर के आधार पर हम देश के विकास की नई राह बनाना चाहते हैं। इस कानून में कहां लिखा है कि हम किसी होटलवाले को जमीन देंगे या निजी अस्पताल

को जमीन देंगे, इस कानून में कहां लिखा है कि हम भूमाफिया को जमीन देकर उसकी मल्टी-स्टोरी बिल्डिंग बनाएंगे। हमने जमीन की बात की है तो रेल के लिए की है, देश के अंदर आज भी मलिन बस्तियों में जो लोग रहते हैं, जिस तरह की वे जिन्दगी गुजार रहे हैं, उनके लिए अच्छे मकान बनाने के लिए जमीन की हमने बात की है। जिस गांव में सड़क नहीं पहुंची है, हमने वहां सड़क पहुंचाने की बात की है। जिस गांव के खेत में पानी नहीं पहुंचा, उस खेत में पानी पहुंचाने के लिए बांध बने, नहरें पहुंचें।

कई माननीय सदस्य सड़कों पर आन्दोलन करते हैं कि देश में बांध नहीं बनने चाहिए, नहरें नहीं बननी चाहिए। यहां बैठे लोग चाहते हैं कि अगर देश और किसान को खुशहाल बनाना है, खेत में पानी पहुंचाना है तो वह काम बांध और नहरों से ही किया जा सकता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जब यह कानून संसद के अंदर है, सारा देश सुन रहा है तो कानून की परिभाषा होनी चाहिए, हर सरकार चाहती है कि कानून बेहतर बने, लोगों की जिन्दगी को बेहतर बनाए। हमारे प्रधानमंत्री जी पांच साल के अंदर गांव के उस अंतिम व्यक्ति तक के जीवन को बेहतर बनाने के लिए यह कानून लाए हैं। यह कानून इसलिए नहीं लाया गया है कि चार-छः उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाया जाए। मेरा दूसरा तर्क यह है कि अगर कोई कारखाना या उद्योग देश में लगेगा तो हम इंफ्रास्ट्रक्चर के आधार पर विकास की कल्पना करेंगे। हम चीन की चर्चा करते हैं। हम मेक इन इंडिया बनाना चाहते हैं। मेक इन इंडिया बनाने के लिए उद्योगों को लाना पड़ेगा, उद्योगों को सुविधा देनी पड़ेगी। अगर एक गांव में कोई इंडस्ट्री आती है तो उसके आस-पास के गांवों में लोगों की जिन्दगी बेहतर हो जाती है। क्या उद्योगों का विरोध करके हम गांवों और शहरों के विकास को रोकना चाहते हैं, हम देश के विकास को अवरूद्ध करना चाहते हैं? संसद को इस कानून को पूरा पढ़ना चाहिए।

कई सम्मानित सदस्यों ने यहां तक चर्चा कर डाली कि यह कानून काला कानून है। सभापति महोदय, यह कानून देशहित का कानून है, इस कानून के आधार पर जहां देश का किसान खुशहाल होगा, समृद्ध होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास के नए रास्ते खुलेंगे। इसलिए मेरा इतना ही कहना है कि पूरी संसद को इस बिल को सर्वसम्मति से पारित करना चाहिए जिससे इस देश का किसान कह सके कि सारी संसद किसानों के हित में काम कर रही है। इतना ही मैं निवेदन करना चाहता हूं। धन्यवाद।

SHRI P.V. MIDHUN REDDY (RAJAMPET): Thank you, Sir. We, YSR Congress Party, would like to reiterate our stand on this Bill. First, we are opposed to multi-crop irrigable land being taken under the Land Acquisition Act. Second, we want the social impact assessment clause to be retained in the same condition.

Sir, apart from the concerns of food security, the farmers, who are losing their lands, will be affected the most. In addition to the farmers, even the labourers, who are dependent on this land, will also be affected very much.

In our State, Andhra Pradesh, it is justified to spend Rs. 3.5 lakh to Rs. 4 lakh per acre to irrigate dry lands through various lift irrigation schemes, including the Handri-Neeva scheme. One the one hand, the Government is spending lakhs and lakhs of rupees per acre to irrigate lands. At the same time, in our State, in the capital region, 50,000 acres of land is being acquired, of which 10,000 acres is multi-crop irrigated land. It is not justified that at one place, we are spending crores and crores of rupess to irrigate the lands and on the other side, we are acquiring rich fertilile lands. Every year in the Budget, we have the Central and State Governments putting in huge amounts of money to irrigate lands. This is a national waste.

Sir, the social impact assessment is very important. Without a proper social impact assessment clause, the whole Bill will be spineless and of no use, which it was intended to be.

Sir, we want to bring in one more issue. We want the whole country to come under a uniform land acquisition procedure. In our State, Andhra Pradesh, the Government is following land pooling scheme wherein the farmers' land is taken by the Government without even paying one rupee and they are given back 30 per cent of their land in the form of developed commercial land. There is a lot of ambiguity in this procedure because the farmers, whose land is worth Rs. 20 lakh and the farmers whose land is worth crores of rupees, are getting the same amount of compensation and they are not sure where they will be getting this piece of land from.

There is one more thing that the State is already in a financial crisis. There is a huge revenue deficit for the State and we are not sure where the money will come from to develop the capital. In the mean time, large tracts of fertile lands are being acquired by the Government without any clarity. To avoid ambiguity, all these things should be discussed further and there should be one Central Act on land acquisition.

If our concerns are not addressed properly, we will definitely oppose this Bill. Thank you.

SHRI ASADUDDIN OWAISI (HYDERABAD): Sir, I stand to oppose the Bill and agree with, at the outset, the views expressed by the hon. Members of different parties who have put forward their views in opposing this Bill.

Sir, I would like to know one thing from the Treasury Benches. After the parent Act, which was passed, came into existence, the Supreme Court had given various judgements upholding it. The Supreme Court had embraced the parent Act. The Supreme Court did not find it *ultra vires* or going against the principle of natural justice. The Supreme Court in Pune Municipal Corporation case upheld Section 24(2). In Radicap Finance case also, the Supreme Court upheld Section 24((2) and said that it is a statutory right. In Balaji Nagar, Shivraj, Velasan Kumar cases, the Supreme Court has given landmark judgements. The Government has no reason or rhyme whatsoever to bring an amendment. This is nothing but the dictatorial attitude of the Government that it brings such a legislation without a reason. These are based on nauseatingly vague assertions of the need for development.

A mention was made over here that the hon. Finance Minister had stated in his Press Conference that if SIA is asked for, then this will lead to sabotage by a neighbouring country. I would like to know what kind of arrogance and ignorance is this that you allow FDI and PPP in defence sector and it is not a threat to the national security, but when it comes to social impact assessment, the Finance Minister says that this can be sabotaged by a neighbouring country.

Sir, the Government has asked for suggestions. My request to the Government is to show me one democracy in the whole world which has such a legislation; show me one Government in the world which takes land from farmers and people, and resources of fishermen and give them to private individuals. We cannot give any example in any democracy wherein such a law was enacted.

If you want land development, then who is stopping it? Further, as regards this talk that industrial development has not taken place, we would like to educate the hon. Prime Minister that in 66 years, yes, development has happened. The development that has not happened, which you wanted, is the issue, but to say that it has not happened and I have an *allaudin's* lamp, which I rub and everything will happen is not going to happen.

Let me also put why cannot we ask the Government to go for private purchase. Kochin Airport is the biggest example of acquisition through consultation. IIM, Ahmedabad has done a study on it. Why cannot lease be given? This amendment is against Article 14 of Equality. Why do I say that? It is because what kind of favouritism is this that when it comes to industrial corridors land can be acquired, but what if I want land to be acquired for preservation of wildlife? What about preservation of wildlife? So, that is why this goes against Article 14. Your amendments are extra-Constitutional and they will not stand the test of law as the parent Act has withstood the test of law.

The Government's argument is about eminent domain. I agree that eminent domain is there, but eminent domain cannot go against Kameshwar Singh, Supreme Court judgement. Justice Mahajan found that even if the Constitution did not explicitly provide that a public purpose was required for employing eminent domain, such a condition is employed and that is what the Supreme Court has said. So, this argument of eminent domain has to go along with right to equality and argument of eminent domain has to go with public purpose.

Lastly, before I conclude, I think that and I might be wrong that we did a mistake, as hindsight, that why did we amend and why did we bring Article 44? What was the purpose behind bringing Article 44 of the Constitution? Why did we amend Article 31? Did we bring in the 44^{th} Constitutional amendment and did we bring Article 31 so that our resources can be given to the rich people?

I can give an example. The Telugu Desam people have just now said about Hyderabad. In the tenure of Telugu Desam and other Governments, 88,419 acres

was given to private individuals. The CAG Report said that 88,000 was given to 1,000 people and the CAG Report said that no public purpose was served. Is this the exploitation that you want wherein our resources will be taken away? Let me give a classic example of Maharashtra where at the Varasgaon dam 161 hectares of land was acquired. Now, what we see after Lavasa has come is that houses have been constructed around the dam. So, where is the public purpose?

This amendment and this Bill is nothing but a tool to exploit the people of India and to ensure that in this farce of development you want to ensure that all these corporates can take away all our resources. Hence, I oppose this Bill, and I oppose all the amendments that the Government is moving as this is extra-Constitutional.

Lastly, this Government stands by the theory of integral humanism of Pandit Deendayal Upadhyaya. I strictly oppose Pandit Deendayal Upadhyaya's theory, but in his theory he has said about land and about forest. Where is your ideologue theory? Why are you not standing by the theory of your ideologues? Thank you, Sir.

श्री पी.पी.चौधरी (पाली) : सभापति महोदय, मैं इस बिल का सपोर्ट करने के लिए खड़ा हुआ हूं। किसानों की बात करते हुए यह कहा गया है कि यह बिल किसानों के खिलाफ है। यह कहा गया है कि जो वर्ष 2013 का एक्ट है, वह किसानों के पक्ष में है। अभी जैसा कि माननीय सदस्य ने बताया कि पूरे विश्व में इस तरह से प्रॉपर्टी राइट लेने का कहीं अधिकार नहीं है।

<u>16.44 hrs</u> (Hon. Deputy Speaker *in the Chair*)

मैं सदन को यह बताना चाहता हूं कि जब संविधान बना था, तब राइट टू प्रॉपर्टी एक फण्डामेंटल राइट था। इस फण्डामेंटल राइट को हटा कर और जगह आप लोगों ने ही रखा है। अभी खड़गे साहब भी विराज रहे हैं, जहां तक वर्ष 2013 के एक्ट की बात है आप यह कह रहे हैं कि जो सोशल इम्पैक्ट का मामला है चैप्टर-2 और चैप्टर-3 वह अप्लायी होगा। आपने सैक्शन 2 में पब्लिक परपज़ दर्शाए हैं। आपने यह भी कहा है कि कंसेंट की जरूरत है। आपने यह भी कहा कि कंसेन्ट की जरूरत है। लेकिन चैप्टर 2 और सैक्शन 2 में जो आपने इस एक्ट की एप्लीकेबिलिटी बताई है, वह आपने कहीं नहीं लिखा है कि चैप्टर 2 और चैप्टर 3 सैक्शन 2 के लिए लागू होगा। आपने बहुत ही स्पेसिफिक लिखा है, जो सैक्शन 2ए कहता है, "The provisions of this Act relating to land acquisition, compensation, rehabilitation and resettlement shall apply." इसका मतलब यह है कि सैक्शन 2 के लिए जो भी पब्लिक परपज दर्शाये गये हैं, उनके लिए चैप्टर दो और तीन का कहीं हवाला नहीं है कि चैप्टर दो और तीन सोशल इम्पैक्ट और डिटरमिनेशन ऑफ पब्लिक परपज लागू होंगे। आपने स्पेसिफिक यह दर्शाया है कि सिर्फ पब्लिक परपज के लिए अगर लैंड ली जायेगी, तो चैप्टर 4, 5, 6, 7 और 8 भी लागू होगा, लेकिन चैप्टर 2 और 3 की बात कहीं नहीं कही है। मैं मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने सैक्शन 10ए लाकर इस पोजीशन को इस बिल के द्वारा क्लेरिफाई किया है। अगर यह होता तो इसका मतलब यह है कि जितने भी पब्लिक परपज सैक्शन दो में दर्शाये गये हैं, उन सभी के लिए चैप्टर 2 और चैप्टर 3 को इग्नोर किये बिना आप लैंड एक्वायर कर सकते हैं, यह आपने एक्ट बनाया है। यही नहीं आपने सैक्शन 7 जो लिखा है, सैक्शन 7 में सैक्शन 4,5,6 और 7 सारा का सारा सोशल इम्पैक्ट और डिटरमिनेशन ऑफ पब्लिक परपज के संबंध में हैं, उसके बारे में आपने एक प्रोवाइजो डालकर तीन लाइन में डाइल्यूट कर दिया, उसमें आपने प्रोवाइजो डाला कि अगर यह सारा होने के बाद में. सोशल इम्पैक्ट का डिटरमिनेशन होने के बाद में, पब्लिक परपज का डिटरमिनेशन होने के बाद में अगर एप्रोपरिएट गवर्नमैन्ट अगर यह चाहती हो कि यह जमीन हमें चाहिए

तो सारी रिपोर्ट को इग्नोर करके वह ले सकती हैं। यह आपने एक्ट बनाया है और आप कहते हैं कि यह हमने किसानों के फेवर में बनाया है।

सैक्शन 10 ए उन प्रोजैक्ट्स के लिए लाया गया है, जो प्रोजैक्ट्स नेशनल इम्पॉर्टेन्स के लिए हैं, जो प्रोजैक्ट्स किसानों के लिए हैं। आज किसान हमें कहता है कि नदियों से नदियों को जोड़ने का प्रोजैक्ट कब होगा, आज किसान कहता है कि मेरे खेत में पानी कब आयेगा, आज किसान कहता है कि मुझे 24 घंटे बिजली कब मिलेगी, आज किसान कहता है कि मेरे खेत के सामने रोड कब मिलेगी? ये सब कोई हवा में नहीं होता है, ये सब जमीन पर होता है। लेकिन इसके लिए आपने यह कहा कि अफैक्टिड फैमिलीज से पूछा जायेगा। चैप्टर 2 और 3 में आपने प्रावधान किया कि अगर हिमालय में बांध बनाना है और पानी राजस्थान, पंजाब, गुजरात, मध्य प्रदेश और दिल्ली में पहुंचाना है तो उन फैमिलीज को पूछा जायेगा कि वहां पानी देने के लिए या बिजली देने के लिए आप सहमति देते हैं या नहीं देते हैं, कौन सहमति देगा तो इस तरह के आपने प्रोविजन बनाये हैं। फिर आप कहते हैं कि यह किसानों के पक्ष में हैं, लेकिन यह किसानों के पक्ष में नहीं है, क्योंकि आप उन्हें पूछ रहे हैं। पब्लिक परपज यह है कि अगर पूरे देश में आज किसान चाहता है कि बांध बनने से जो हमारे प्रधान मंत्री जी और पूर्व प्रधान मंत्री, श्री वाजपेयी जी ने भी यह बीड़ा उठाया कि नदियों से नदियां जुड़ें और हर किसान के खेत में पानी पहुंचे, उसके लिए नदियों से नदियों को जोड़ने के लिए जमीन लेनी पड़ती है। जहां तक मुआवजे की बात है, मुआवजा चार गुणा है। जहां तक सैटलमैन्ट और रीहैबिलिटेशन की बात है, उसे कोई टच नहीं किया गया है।

इसमें यह भी कहा गया है कि जहां तक कम्पैनेसेशन की बात है, कई बार यह मुद्दा आया था कि कम्पैनसेशन क्या होगा, सर्किल रेट होगा या क्या होगा। एक्ट में हमने कोई टच नहीं किया है, वह अनअफैक्टिड हैं। कम्पैनसेशन के बारे में सैक्शन 26 में साफ लिखा हुआ है कि मार्कट वैल्यू होगी और उस मार्कट वैल्यू का डिटरमिनेशन या तो सर्किल रेट होगा या उस एरिया की जो सेल डीड होगी या निगोशिएशन प्राइज होगा और उसके बाद जो भी हायर होगा, वही उसका कम्पैनसेशन होगा।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

SHRI N.K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Mr. Deputy-Speaker, Sir, I thank you for giving me this opportunity. Yesterday also, I had given a notice regarding a statement which is misleading the entire House. So, kindly give me two more minutes.

First of all, I rise to oppose this Bill. I was wondering and hearing the speech of learned advocate Shri P.P. Chaudhary. Shri Chaudhary has just concluded his speech by saying that this legislation is in favour of farmers. I would like to ask the learned Member of this House Shri P.P. Chaudhary whether he would show any of the provisions of this amended Bill which is giving any additional benefit to the farmers than the Act of 2013. I am coming to the Bill.

The land issue is the core issue. It is the prime core issue as far as the social development, economic development and even the cultural development of our country or the society as a whole is concerned. From the days of Mahabharat Yudha, the land conflict has been there. We know about the Naxalite movement, Left Extremism, Left Wing Extremism as well as the Maoist movement. We know about Nandigram, Singur and the POSCO land issue. We very well know about all these issues. Now, when we go to the statistics of 2013-14, it is seen that 250 land conflicts took place in 161 districts. Keeping this in mind, the UPA Government has legislated the 2013 Act. According to me, that is the historic legislation in the parliamentary experience of our country. It is benefiting the poor farmers in the country. If we go through the Act also, it is giving fair compensation; it is providing just compensation. Resettlement is there; rehabilitation is there and also transparency in the land acquisition is also there in the Act of 2013. It is a wonderful legislation as far as the legislative process is concerned. There is no doubt about it. Yesterday Shrimati Supriya Sule also raised the same issue. I would like to know from the Government as to what prompted them to deviate from the original stand which they had taken in the year 2013. The whole-hearted support was given to this Bill by the BJP. Shrimati Sushmaji, Shri Rajnath Singh

as well as the present Speaker who was heading the panel of the Parliamentary Standing Committee vehemently insisted for the amendment and for the 2013 Bill. What prompted and what is the pressure now by which this new amendment is being brought to this House by means of an Ordinance?

Coming to the amendment, this amendment rolls back all the basic features and positive features of the 2013 Act. The heart and soul of the 2013 Act is taken away by means of these amendments. Shri Arun Jaitley, the hon. Finance Minister has stated that this amendment is to strike a balance between the industry and the farmer. What is the balance between the industry and the farmers? It is a significant step on the part of the Government. They are back-tracking from the movement of the country to have the land justice in the country by means of the 2013 legislation. Definitely, this is taking away the whole spirit of 2013 legislation. I strongly oppose the Bill.

Coming to the amendment number 1 relating to the consent and the social impact assessment, what do they mean by the consent? What is the consequence of taking away the term 'consent' from the existing Act? If the requirement of consent is being taken away from the original Act, it will be helping the forcible acquisition of land and also acquisition of excess land. That is the impact of taking away the consent. This is the bargaining power of the land owners. So, the consent is the heart of the Bill and the social impact assessment is the soul of the Bill. What is the social impact assessment? What is the valuation of the property? What is the loss and injury caused to the farmers by means of land acquisition? That means, social impact assessment is having a direct bearing on the determination of the price of compensation. Shri Chaudhary was saying that the price of compensation was protected in this amendment. No, it is not. The social impact assessment is the criteria so as to determine the price of compensation for the land owners whose land is acquired. So, the determination of the compensation is lost or it is coming down. Impact assessment is lost and the bargaining power of the farmers is also lost.

Another amendment relates to the return of land after five years. What is the harm in it? The Government has to understand that it is unnecessarily supporting the corporate houses. Why should it? If the land is not utilised for five years after taking possession, it should be returned. Utilised here does not mean completion of the project. After complying and completing all the formalities and taking possession of the land, if you are not doing anything on the land, if you are not commencing the project for five years, then that land will be returned. This is an amendment brought by the UPA Government at the insistence of Madam Sushma Swarajji. What is the opinion of Madam Sushmaji now and what pressure has prompted you in taking away this provision of five years? Instead of five years, the Bill says 'a period specified for setting up of a project or five years or whatever it may be'.

Coming to the third amendment, I am thankful to the hon. Minister that private educational institutions and private hospitals are taken away. Thank you very much, Mr. Minister and the Government, for accepting this amendment of the opposition.

The fourth one is regarding the words private company and private entity. You go through the definition of private entity. All the organisations under the sun will come within the purview of private entity. What does it mean? Private company is changed to private entity. Partnership will come, NGO will come, every thing will come under the purview of private entity. This has been done just to please the corporate and big business houses.

My next point relates to what the hon. Minister said yesterday during his intervention. Hon. Minister of Parliament Affairs Venkaiahji, we have high regards for him, was trying to explain yesterday that this Bill is giving an additional benefit to the farmers. How? Hon. Prime Minister also said outside the House that this is giving additional benefit to the farmers. Let us examine Section 105. The argument of Shri Venkaiah Naidu, the hon. Minister, was that 13 new Acts have been incorporated in Schedule IV of the Act by means of the Ordinance.

It is absolutely false. It is misleading the House. This is Schedule IV of the 2013 Act. All the 13 Acts are incorporated in that Schedule IV. It is not being done by the NDA Government but it is as a consequent effect of Section 105. Also you are deleting Clause (iii) of Section 105, and incorporating a new Clause in Section 105. Let us analyse and compare the two provisions, amended provision and the original provision. Since there is not much time I am not able to read the entire Section. But because it is legislative process I would like to highlight this.

Clause (iii) of Section 105 says: "The Central Government by notification within one year from the date of commencement of this Act direct that any of the provisions of this Act relating to determination of compensation, First Schedule, Second Schedule … and finally with exceptions and modifications that do not reduce the compensation or dilute the provisions of this Act relating to compensation, rehabilitation and resettlement as may be specified in the notification as the case may be".

That means, as per the existing provision of Section 105, Clause (iii), you can only increase the compensation, you can only increase the benefits of resettlement and rehabilitation, you can never reduce the compensation. The hon. Minister yesterday was arguing the case of the Government that this is an additional benefit which is being provided to the farmers by incorporating 13 Acts under Schedule IV and giving a substituted provision of Clause (iii). It is absolutely misleading the House. No additional benefit is being provided by means of this amendment.

Once again I would like to say that the entire spirit of the 2013 Act is compromised. I would like to appreciate and congratulate the then UPA Government for enacting such a historic legislation after such a long time.

17.00 hrs

It was a colonial legislation of 1894. We have changed it. A sovereign legislation has come to the Parliament. After making a sovereign legislation, you are again going back to the colonial legislation. This is just to appease the corporate and business houses. I strongly oppose this Bill.

डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक (हरिद्वार): उपाध्यक्ष महोदय, मैं भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्था में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 के संशोधन विधेयक 2015 के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ।

श्रीमन्, देखा जाए तो मुझे आश्चर्य होता है कि उधर से जो बात आ रही है, कई बार कहते हैं कि हज़ार असत्य बोलो तो वह भी सच में बदलने की कोशिश होती है। लगातार यह कहा जा रहा है कि यह विधेयक जैसे किसानों के विरोध में आ रहा है। केवल और केवल किसानों के विरोध की बात हो रही है। उसके सभी पक्षों पर विचार करके उसको ग्रहण करने की बात जहाँ होनी चाहिए थी, वह नहीं हो रही है। मैं कहता हूँ कि खंड 2 की उपधारा 3 जिसकी बड़ी चर्चा हो रही है कि सामाजिक प्रभाव का आकलन करने की बात होती है, राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय है। श्रीमन्, ढाँचागत विकास का है, रक्षा का है, विद्युतीकरण का है, गरीबों के लिए आवास का है। तो क्या आप यह कहना चाहते हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा, ढाँचागत विकास और गरीबों के लिए मकान और सड़क के पक्ष में आप नहीं हैं? आखिर भूमि का अधिग्रहण तो होगा। चर्चा हो रही थी कि पहले भी भूमि का अधिग्रहण होता था। अभी जब धारा में हमने पाँच वर्ष का प्रावधान किया कि पाँच वर्ष से बढ़कर हो, तो यह कहा जा रहा था कि पहले भी तो यह अधिग्रहण होता था। श्रीमन्, मैं कहना चाहता हूँ कि 2011-12 में देश में सबसे बड़ी 20 परियोजनाएँ आईं। उसमें आठ परियोजनाएँ आज तक भी अधिग्रहण के कारण लंबित पड़ी हुई हैं जिनकी लागत 1,65,000 करोड़ है। श्रीमन्, देश सफर कर रहा है। यह जो आर्थिक और सामाजिक विकास की बात की जाती है, मुझे अफसोस होता है कि केवल किसान की खेती जाएगी। मुझे लगता है कि मेरे एक सदस्य मित्र ने कहा कि शायद आप नहीं चाहते हैं कि किसान का बेटा भी पढ़े। यदि औद्योगिक क्षेत्र में हो तो वह गाड़ी ले, अपनी दुकान चलाए, अच्छा पढ़े। क्योंकि आज वे लोग किसानों के हितों की बात कर रहे हैं जिनके समय में किसान ने सबसे ज्यादा आत्महत्या की है। कब किसानों के बारे में चिन्ता की? एक विधेयक आया और वह भी सामूहिक रूप में विकास की दृष्टि से आया तो उसका ऐसा प्रचार करने की कोशिश हो रही है जैसे कि हम किसानों के विरोधी हों। श्रीमन्, मैं कहना चाहता हूँ कि यह सरकार ही किसानों की हितैषी है, उनके बच्चों की हितैषी है, उनके भविष्य की हितैषी है। यह एक्ट भी किसानों का परिवर्तन करने के लिए आया है। ये दोनों पक्ष जानने चाहिए। जहाँ बड़े औद्योगिक विकास हुए हैं, उसके इर्द-गिर्द देखिए 10-20 किलोमीटर तक वहाँ की आर्थिक स्थिति पहले क्या थी और अब क्या है, इसका आकलन और अध्ययन करें। यदि आप मुझे अनुमति देते तो मैं प्रमाणों के साथ आपको 50 ऐसे उदाहरण बता सकता हूँ जहाँ पहले औद्योगिक क्षेत्र

में विकास नहीं था, ऐसी भूमि थी जो बेकार भूमि थी और आज वह सोने की तरह लोगों को विकास की दिशा में आगे बढ़ा रही है।

श्रीमन्, मैं कहना चाहता हूँ कि खाद्य सुरक्षा की बार-बार बात आ रही है। ज़मीनों की स्थिति यह है कि झारखंड में केवल 4.5 प्रतिशत सिंचित भूमि है, छत्तीसगढ़ में 27.6 प्रतिशत, राजस्थान में 26.4 प्रतिशत, मध्य प्रदेश में 44 प्रतिशत, कर्नाटक में 28.5 प्रतिशत, ओडिशा में 33.6 प्रतिशत और महाराष्ट्र में केवल 16.8 प्रतिशत सिंचित भूमि है। क्या हमने कभी यह विचार किया कि जो बहुत बड़ी मात्रा में असिंचित भूमि है, उसको हम सिंचित करें। आज सिंचाई के अभाव में किसान दम तोड़ रहा है। क्या जहाँ सिंचाई की बड़ी परियोजनाएँ होंगी, वहाँ ज़मीन का अधिग्रहण नहीं होगा? श्रीमन्, ज़मीन का अधिग्रहण होगा, इस कानून के लिए मैं सरकार को और माननीय मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूँ कि समयबद्ध तरीके से जो मुआवज़ा वर्षो में नहीं मिलता था, व्यक्ति भटकता रहता था लेकिन उसको मुआवज़ा नहीं मिलता था, इस अधिनियम के तहत एक समय-सीमा के अंदर उसको मुआवज़ा मिलेगा, उसको प्रतिकर मिलेगा और उचित मिलेगा, चार गुना ज़्यादा मिलेगा, यह इस अधिनियम में आया है। मैं कहना चाहता हूं कि बार-बार यह कहा जा रहा है कि सहमति नहीं ली जायेगी और केवल औद्योगिक क्षेत्र को लेकर बड़ी बहस शुरू हो गई। मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि औद्योगिक गलियारा भी बनेगा तो सरकारी गलियारा बनेगा, संयुक्त उपक्रम का बनेगा, वह उद्योगपतियों के लिए नहीं बनेगा। यदि वह संयुक्त रूप में बनेगा तो इस बात का क्यों विरोध हो रहा है।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि कोर्ट की बात बार-बार आ रही है। इस अधिनियम में साफ है कि किसान न्यायालय में जा सकते हैं तो कृपा करके देश की जनता को गुमराह मत करें। इसमें सहमति का भी प्रावधान है, मुआवजे का भी प्रावधान है और पुनर्स्थापना का प्रावधान है। जो अधिकारी, जो दलाल इसमें गड़बड़ करेंगे, उनके लिए ऐसा कानून लाया गया है कि वे जेल के शिकंजों में रहेंगे। ...(व्यवधान) आपको क्यों परेशानी हो रही है? मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यह जो नोएडा है, ये नोएडा का उदाहरण दे रहे हैं, ये पचासों उदाहरण दें, मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूं, मैं नोएडा और अन्यों के उदाहरण में नहीं जाना चाहता हूं। वहां जिस तरीके से जमीनों का खुर्द-बुर्द हुआ है, उस खुर्द-बुर्द से किसानों को बचाने के लिए यह अध्यादेश लाया गया है और इसलिए मैं मंत्री जी को और सरकार को ढेर सारी बधाई देना चाहता हूं कि इससे सामाजिक उत्थान होगा, किसानों का हित होगा और देश प्रगति के शिखर पर जायेगा।

बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री राजू शेट्टी (हातकणंगले) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं दो दिन से बहस सुन रहा हूं। किसान जमीन देने के लिए तैयार नहीं हैं, विकास के नाम पर किसानों की जमीन अधिग्रहीत होनी चाहिए, इस तरह के विचार अनेक सदस्यों ने यहां रखे हैं।

मैं इस सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जब विनोबा जी ने भूमिहीन किसानों को जमीन दान करने के लिए किसानों से जमीन मांगी थी, तब इस देश के हजारों किसानों ने मुफ्त में उनको जमीन का दान दिया था। इस देश का यह इतिहास है। मैं महाराष्ट्र के कई समाज सुधारकों को जानता हूं, जिन्होंने गरीबों के बच्चों को स्कूल और अस्पताल बनवाने के लिए किसानों से मुफ्त में जमीन ले ली थी। किसान जमीन देने के लिए तैयार हैं, लेकिन किसान के पास से जमीन कौन मांग रहा है, यह सवाल है। अगर अपने निजी स्वार्थ के लिए कोई किसान की जमीन छीनना चाहेगा तो किसान हरगिज जमीन नहीं देगा।

मैं सदन से और सरकार से भी यह सवाल पूछना चाहता हूं कि आज तक जितनी भी जमीन किसानों से ली गई, उसका हिसाब कोई देगा? आप एक व्हाइट पेपर निकालिये कि किस मुद्दे पर, किस नाम पर आपने जमीन किसान से ले ली, उसका यूज़ चेंज हुआ कि नहीं, उस जमीन का क्या हुआ? होली के दिन मैं गांव गया था, तब कई किसान मेरे पास आये और उन्होंने कुछ सवाल मुझसे पूछे और उन्होंने कहा कि ये सवाल आप सदन में पूछो। सांगली जिले का सूर्यवंशी नाम का एक दलित किसान मेरे पास आया। उसने कहा कि 1994 में सिंचाई के नाम पर उसकी दो एकड़ जमीन सरकार ने अधिग्रहीत की और दस साल बाद वही जमीन सरकार ने नीलामी में बेच दी। उसको उस जमीन के 65 हजार रुपये दिये और दस साल के बाद वही जमीन सरकार ने 32 लाख रुपये में बेच दी। जिन छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम लेकर महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है, शिवाजी महाराज ने पुणे में सोने का हल हाथ में लेकर जमीन में चलाया था। उसी चांकन खेड़ एरिया में सात साल पहले सेज़ के नाम पर भारत फोर्ज ने सत्रह लाख रुपये प्रति हेक्टेयर के दाम पर ज़मीन खरीदा और आज भारत सरकार को वहां एयरपोर्ट बनाना है। वहां सेज़ तो नहीं बना, लेकिन वही ज़मीन वह चार करोड़ रुपये प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बेचने को तैयार हो गया। वहां किसानों के लिए जो पैकेज का एलान किया गया था, उसमें कुछ भी नहीं हुआ। मेरे पास एन.डी.टी.वी. की एक रिपोर्ट है कि महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में सेज़ के नाम पर जो 5,72,000 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण हुआ है, उसमें से 2,55,000 हेक्टेयर भूमि का इस्तेमाल नहीं हुआ। इसका मतलब 45% ज़मीन वैसी की वैसी पड़ी है। किसानों की ज़मीन जब अधिग्रहित होती है तो उसे सालों-साल उसके मुआवज़े के लिए दफ्तर के चक्कर काटने पड़ते हैं, अफसरों को रिश्वत

देनी पड़ती है। फिर भी उन्हें पैसा नहीं मिलता है। इसी तरह से, अगर उनके साथ विश्वासघात होता है तो किसान ज़मीन क्यों देगा? कोई सवाल पूछ रहा है कि अगर भूमि अधिग्रहण नहीं होगा तो सिंचाई के प्रोजेक्ट कैसे बनेंगे? मैं कहता हूं कि सिंचाई का प्रोजेक्ट करना है तो उसमें किसानों का हिस्सा रखें। बी.ओ.टी. के तहत आप सड़क बना रहे हैं। किसी निजी कंपनी को सड़क बनाने के लिए टेन्डर दे रहे हैं। उसे टॉल वसूलने के लिए परमिशन दे रहे हैं। उस टॉल में किसानों का हिस्सा रखिए। फिर किसान सड़क के लिए ज़मीन देगा। लेकिन, विकास के नाम पर हमारे किसानों की ज़मीनें छीनने की कोशिश की जा रही है। सरकार दलाल नहीं है, सरकार सब की है।

मैं सदन का और खासकर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जब चुनाव लड़ रहे थे तो सरकार के नेता ने वादा किया था कि लागत मूल्य से 50% अधिक का मुआवज़ा देकर हम समर्थन मूल्य देंगे। वह तो आपने नहीं दिया। फिर अगर किसानों की ज़मीन छीनने की कोशिश होगी तो मैं चेतावनी देता हूं कि खून की नदियां बहेंगी, लेकिन हम एक इंच भी ज़मीन नहीं देंगे।

मैं इस बिल का विरोध करता हूं।

श्री रत्न लाल कटारिया (अम्बाला) : डिप्टी स्पीकर सर, मैं 'द राइट टू फेयर कम्पेनसेशन एण्ड ट्रांसपैरेंसी इन लैण्ड एक्वीजीशन, रिहैबिलिटेशन एण्ड रिसेटलमेन्ट (अमेंडमेंट) बिल, 2015' के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।

महोदय, जब से इन नौ महीनों के अंदर भारत की अर्थव्यवस्था ने चीन की अर्थव्यवस्था को भी पछाड़ा है और हम अग्रणी देश बनने की ओर अग्रसर हुए हैं तो ये जो हमारे कांग्रेस के मित्र हैं, इनके पेट में तब से मरोड़ें उठने शुरू हो गए कि यह जो सरकार है, यह तो नौ महीने में ही बहुत तेजी से विकास के पथ पर चल पड़ी है। इसलिए इस बिल के बहाने आज इन्हें ऐसा लगता है कि जैसे 'अलादीन का चिराग़' इनके हाथ लग गया है और हम इसका उपयोग करके सरकार को घेर लेंगे। यह इनका भ्रम है। ये दुनिया को संदेश देना चाहते हैं कि हमारी सरकार विकास के मामले में कोई भी साहसिक कदम नहीं उठा सकती।

मैं बताना चाहता हूं कि मैं हरियाणा प्रदेश से आता हूं। हरियाणा प्रदेश में किसानों से 80,000 एकड़ से भी ज्यादा की बेशकीमती ज़मीनें छीन ली गयीं और जिन्हें वे दी गयीं, उन्हें भी सारा देश जानता है। मैंने यू.पी.ए. सेकेंड के शासन काल में वेलेंटाइन डे को एक बड़ा ही व्यंगात्मक जोक अखबार में पड़ा कि इन हरियाणा सी.एल.यू. इज मोर इंपोर्टेंट दैन आई.एल.यू., चेंज ऑफ लैंड यूज एंड आई लव यू। हरियाणा प्रदेश के अन्दर जिस तरह से किसानों के ऊपर जुल्म ढाए गए, आज वे किस तरह की बातें कर रहे हैं। नन्दीग्राम में, सिंगूर में, उत्तर प्रदेश के अन्दर मायावती जी ने जो किया, आज वे हमारे ऊपर इस तरह के इल्जाम लगा रहे हैं। मैं बड़ा हैरान हूँ। " हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वे कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता "। यू.पी.ए. शासनकाल में दस वर्षों के अन्दर 2.5 लाख किसानों ने आत्महत्याएं कीं, क्या वे इस बिल के कारण हुई थीं?

जब देश आजाद हुआ, हिन्दुस्तान की अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान 65 प्रतिशत था, लेकिन आज यह घटते-घटते 15 परसेंट पर आ गया। क्या इसके लिए भी मोदी सरकार जिम्मेदार है? तब किसानों का शोषण किसने किया? आजादी के बाद 67 वर्ष तक जितना शोषण इन लोगों ने किसानों का किया, इतना शोषण आज तक नहीं हुआ। आज इस बिल के माध्यम से मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि आज जब मोदी जी ने वर्ष 2022 तक हिन्दुस्तान के पाँच करोड़ गरीबों, दलितों और आदिवासियों के लिए घर बनाने की बात कही है तो इनको लगने लगा है कि कुछ तो सिंहासन वर्ष 2014 में खिसक गया और कहीं ऐसा न हो कि वर्ष 2019 आते-आते इस देश के अन्दर तुम्हारा नाम लेने वाला न हो। ...(व्यवधान) तुम गरीबों की बात कर रहे हो, तुम्हारा चेहरा तो बेनकाब हो चुका है। ...(व्यवधान)

महोदय, मैं यह कहना चाहता हूँ कि देश के रक्षा संस्थानों के लिए जो मेक इन इंडिया की बात हुई है, क्या यह आवश्यक नहीं है कि भारत अपने पैरों पर खड़ा हो, अपना जगुआर विमान बनाए, अपनी पनडुब्बियाँ बनाए? मैंने पहले भी सदन में कहा था कि हमें दूसरे देशों के ऊपर निर्भर नहीं रहना चाहिए। हमने अमेरिका से कम्प्यूटर चिप्स की बात कही थी, लेकिन उन्होंने हमारे हाथ में अंकल चिप्स पकड़ा दिया। आज जिन संस्थानों के लिए भूमि …(व्यवधान)

HON. DEPUTY SPEAKER: Your time is over. We have to pass this Bill. The Minister is going to reply at 5.30 p.m. Please conclude now.

श्री रत्न लाल कटारिया: महोदय, मैं आदरणीय मंत्री जी को बधाई देना चाहूँगा। मैं इनको पिछले 40 साल से जानता हूँ। सर छोटू राम जी, जिन्होंने किसानों के लिए इतनी बड़ी लड़ाई इनके नाना जी ने लड़ी, यह कैसे हो सकता है कि इस महान सदन के अन्दर ये कोई किसान विरोधी बात करें। मैं इनका पूरा-पूरा समर्थन करता हूँ, धन्यवाद।

ADV. JOICE GEORGE (IDUKKI): Thank you Mr. Deputy-Speaker, Sir. I rise to oppose this Bill.

The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013, was enacted for the purpose of addressing the historical injustice meted out by the provisions of the Land Acquisition Act, 1894. As far as a farmer is concerned, the land is not a tool for earning his livelihood alone. It is an asset. In rural India, land is everything. Your social status depends on land. One's financial freedom depends on the land; everything is depending on the land. Every attempt is being made, through the provisions of the Bill, to grab the land from the hands of the farmers. It will affect their livelihood options. Earlier, there was article 31 in the Constitution to protect the right to property. It was enshrined as a Fundamental Right. But that right has been taken away by the 44th Constitutional amendment. Now, we have article 300A to guarantee the right to property. This is a constitutional right. We also have article 21, the right to livelihood. We have the Constitution. That is our Bible; that is our Gita; that is our Quran. As per our Constitution, the right to livelihood is protected.

As far as the farmers are concerned, the right to life has been enshrined as a Fundamental Right in our Constitution and by this amendment the Government proposes to take away that Right. As per Chapter II of the 2013 Act, there is provision for consultation and provision for social impact assessment. But now the Government proposes to take away these two provisions in the Act. By taking these two provisions, the very purpose and purport of the 2013 Act is sought to be nullified. So, the proposed amendment being brought forward by the Government has to be defeated by the House if our hearts are beating for the poor farmers.

This amendment seeks to dilute Section 101 of the Act which empowers the States to return the land to the owners in the event of the land remaining unutilised for a period of five years after the acquisition. Here, after issuing the preliminary notification we have experiences of the land being kept idle. Once the preliminary notification is issued the right over the land has been freezed for ever and the land cannot be used for any other purpose. One cannot pledge it for getting loan from the financial institutions; one cannot use it for any other purposes; one cannot even construct or reconstruct a house on that land. In my constituency there is a case where a notification was issued in the year 2000 for laying a Angamali-Sabri railway line. As per that notification, lands of thousands of people were frozen and they are not in a position to exercise their rights over their property.

The farmers are acquiring the land with desire; the farmers are possessing the land with great hopes and they are cultivating the land with dreams. Is the Government is willing to have more grains or is the Government is willing to maul over the dreams of the poor farmers? I would like to caution the Government that if this Bill is passed then the Government could have a nation of their choice only over the graves of the poor farmers.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Deepender Hooda – The Minister will be replying at 5.30 p.m. So, please be brief.

श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा (रोहतक) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात को संक्षिप्त में बोलने का प्रयास करूंगा। आज मैं अपनी दल की ओर से सरकार द्वारा लाये गये इस बिल के विरोध में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। दो दिनों से बहुत से टी.वी. चैनलों पर और मीडिया में अलग-अलग तरह की चर्चायें चल रही हैं, यह भी बात सामने आ रही है कि शायद बातचीत चल रही है। मैं आपके माध्यम से, इस सभा के माध्यम से पूरे देश के किसानों से अपनी दल की ओर से कहना चाहता हूं कि इस बिल के मामले में हम सरकार से कोई भी समझौता करने लिए तैयार नहीं है। हम किसानों के साथ खड़े हैं। ...(व्यवधान) इस बिल की क्या पृष्ठभूमि है? मैं दो दिनों से सदन में चर्चा सुन रहा हूं। क्या कारण है कि सारे दल, सारे विपक्षी पार्टियां, जो अभी तक एक नहीं हो पायीं, इस बिल ने उन सबको एक कर दिया। क्या कारण है कि सत्ता पक्ष के दल में भी एक दरार दिखायी दे रही है? अभी राजीव शेट्टी जी बोल रहे थे। वह सत्ता पक्ष के सहयोगी हैं। वह इस बिल के विरोध में बोल रहे थे। शिवसेना ने खुलकर इस बिल का विरोध किया है। क्या कारण है कि ये दरारें उत्पन्न हुईं और क्या कारण है कि पूरा विपक्ष एक हुआ? इसके पीछे एक राजनीतिक पृष्ठभूमि है और कानून कैसे बना, उसकी भी पृष्ठभूमि है। राजनीतिक पृष्ठभूमि यह है कि जब से यह सरकार आई है, इसकी एक छवि बनती जा रही है। पूरे देश में एक हवा बनी थी और उसके आधार पर लोग इस सरकार को यहां लेकर आए थे। उसके बाद एक छवि बनती जा रही है कि यह सरकार किसानों के विरोध में चल रही है और बड़े उद्योगपतियों, कारपोरेट घरानों के हक में चल रही है। एक के बाद एक किसानों के लिए जो फैसले आए, जब किसान की फसल मंडियों में आई तो फसल पिटी, धान पिटा, कपास पिटा, सरसों पिटा। उसके बाद जब किसान यूरिया लेने गया तो वह खुद पिटा। संशय है कि अब किसानों की भूमि के अधिकार को पीटने का काम भी यह सरकार इस बिल के माध्यम से करने जा रही है। दूसरी ओर एक वातावरण यह भी बनता जा रहा है कि सरकार बड़े उद्योगपतियों, कारपोरेट को बड़ा फायदा पहुंचाना चाहती है।...(व्यवधान) बजट आया तो उसमें कारपोरेट टैक्स में कटौती की बात आई। रेलवे को प्राइवेट-पब्लिक पार्टनरशिप के माध्यम से बढ़ाने की बात आई। वैल्थ टैक्स की बात आई। अब इस बिल के माध्यम से एक वातावरण बन रहा है। मैं समझता हूं कि देश सर्वोपरि है। नई सरकार है। देश में इनकी सरकार कम से कम चार साल तक रहेगी। मैं समझता हूं कि ऐसा माहौल बनाकर यह प्रभावी रूप से सरकार की गाड़ी खींच पाएंगे, ऐसा संभव नहीं है। दिल्ली में जो हुआ, उससे आपको सबक लेना चाहिए। ...(व्यवधान) मैं आपका शुभचिंतक नहीं हूं, देश का शुभचिंतक हूं। मैं चाहता हूं कि आप प्रभावी तरीके से सरकार चलाएं। आपको लोगों ने जनादेश दिया है। देश को आगे ले जाने के लिए आपको काम करने होंगे।

जहां तक कानून की पृष्ठभूमि की बात है, जैसे बहुत से सदस्यों ने बताया, 120 साल के बाद वर्ष 2013 में इस कानून को बदला गया।

17.27 hrs (Hon. Speaker *in the Chair*)

120 साल पहले 1894 में ब्रितानिया सरकार इस कानून को लेकर आई थी। उसके बाद लगातार चाहे ब्रिटिश सरकार राज की बात हो, उसके बाद देश आजाद हुआ, प्रजातांत्रिक तरीके से विभिन्न सरकारें बनीं। इस कानून के आधार पर देश के विकास के नाम पर किसानों की जमीनें ली गईं। इसमें दो-तीन बार वर्ष 1962, 1967 और 1984 में अमैंडमेंट्स भी हुए, लेकिन हमेशा एक बात महसूस की गई कि यह किसानों के लिए बराबरी का कानून नहीं है।

आपके सदस्यों ने कई बार कहा कि 60 सालों से आपकी सरकार है। देश में 60 साल से हमारी सरकार नहीं है, इस देश के लोगों की सरकार है, लोकतंत्र की सरकार है। उसमें से 13 साल के करीब आपकी सरकार रही है और 49 साल हमारी सरकार रही है। हम 49 साल तक सत्ता में रहे हैं, लेकिन अपनी मर्जी से नहीं रहे, डंडे के जोर पर नहीं रहे, लोगों की मर्जी से रहे हैं, लोगों ने हमें यहां इतने साल तक रखा। आने वाले कुछ सालों के बाद आप भी यह कह पाएं, ऐसी शुभकामनाएं हैं, लेकिन उसके लिए आपको अच्छा काम करके दिखाना पड़ेगा, लोगों को विश्वास में रखना पड़ेगा। आपकी जो छवि बन रही है, उसके आधार पर आप इस देश में इतना लम्बा नहीं रह पाएंगे, मैं यह भी कहना चाहता हूं।

कानून एक बहुत लम्बी प्रक्रिया के बाद बदला गया। इस संसद में तकरीबन 15 घंटे उस पर बहस हुई। 65 सदस्यों ने उसमें हिस्सा लिया। तकरीबन साढ़े सात महीने तक स्थायी कमेटी ने इसका निरीक्षण किया। अध्यक्ष महोदया, आप स्वयं उसकी चेयरमैन थीं। स्टैंडिंग कमेटी के जितने सुझाव आए, उन्हें माना गया। आदरणीय राजनाथ सिंह जी, आदरणीय सुषमा जी भी यहां निराजमान हैं। इन्होंने भी उस बहस में हिस्सा लिया और उसका पूरा समर्थन किया। मैं उनको क्वोट नहीं करना चाहूंगा। 65 सदस्यों ने उस बहस में हिस्सा लिया था। अभी हमारा समय 10-15 मिनट बचा हुआ है। दूसरी बात, ये लोग अमेंडमेंट बहुत लेट लेकर आए हैं उस पर भी मुझे बोलना है। अमेंडमेंट पर बोलने का मौका नहीं मिला, इतनी जल्दबाजी में यह कानून बन रहा है। नौ अमेंडमेंट आज ही सुबह लेकर आए हैं। हमारे दल को उस पर विचार व्यक्त करने का मौका नहीं मिला है। मैं जल्दी से अपनी बात आगे बढ़ाता हूं। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि इतनी जल्दी इसको बदलने की आवश्यकता क्यों पड़ी। पिछले 10 महीने से जो सरकार है क्या उसने कहीं इसे लागू करके देखा है? क्या देश में सोशल इम्पैक्ट की स्टडी हुई? क्या इस कानून के आधार पर आपने किसानों से उनकी स्वीकृति लेकर भूमि अधिग्रहण करने का प्रयास किया? एक जगह भी नही किया। जैसे ही इनकी सरकार बनी, 27 जून को दिल्ली में एक मीटिंग बुलाई गई कि इस कानून में क्या बदलाव होना चाहिए।

इनका से बदलाव करने का मन था, यह ठीक नहीं है। तीन मुख्य बात इस कानून में है। कन्सेंट को लेकर देश में एक कन्फ्यूजन क्रियट किया गया है। क्या किसान से यह पूछना की आपकी धरती ली जाए या नहीं ली जाए, क्या यह किसान के हक में है या नहीं है? सभी ने कहा कि यह किसान के हक में है। मगर सरकारी कामों के लिए जैसे सड़क बनाने के लिए, नहर बनाने के लिए, बाध्यकारी है। सेक्शन 2 का फर्स्ट क्लॉज और सेंकड क्लॉज की तरफ सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए कन्सेंट की जरूरत नहीं है, अगर सरकार खुद इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्टस बनाती है, सड़क बनाती है, नहर बनाती है, पोर्ट बनाती है और एयरपोर्ट बनाती है तो किसान से सहमति की जरूरत नहीं है, यह हमारे कानून में प्रावधान था। रक्षा में भी सहमति की जरूरत नहीं है। सहमति की जरूरत दो चीजों में है, अगर सरकार प्राइवेट कंपनी के लिए जमीन लेती है, वहां सहमति की जरूरत है, सरकार पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के लिए जमीन लेती है वहां सहमति की जरूरत है।

माननीय अध्यक्ष : दीपेन्द्र जी अब खत्म कीजिए। आपने अच्छे से बोला।

श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा: यह कानून की आत्मा है, पहली बार इस देश में इस तरह का कानून बना। जिसमें किसान से पूछने का प्रावधान हुआ और सभी ने उसका समर्थन किया। आज आर्डिनेंस के माध्यम से बहुमत के घमंड में उसको बदलने की कोशिश कर रहे हैं। किसान से उसका अधिकार वापस लेने का प्रयास हो रहा है। देश देख रहा है, किसान को पहली बार 120 साल के बाद अपना विचार व्यक्त करने का मौका मिला था। उसे अपना अधिकार मिला था, उसे इस तरीके से खंडित किया गया और इसे खंडित किस चीज के लिए किया जा रहा है। प्राइवेट प्रोजेक्ट और पब्लिक प्राइवेट पार्टनशिप प्रोजेक्ट के लिए किए जा रहे हैं। आदरणीय मंत्री जी ने भी राज्य सभा में बहस में हिस्सा लिया था। उस बहस में यूपीए सरकार द्वारा लाए इस कानून की भूरी-भूरी प्रशंसा की थी। मगर मैं उनको क्वोट नहीं करना चाहता। एक चीज जरूर कहना चाहूंगा क्योंकि मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूं। आपने कहा था कि केवल 70 प्रतिशत कन्सेंट से काम नहीं चलेगा। I am quoting you verbatim. मंत्री जी ने राज्य सभा हिस्सा लेते हुए एक साल पहले कहा था So, what I want is, if those 80 per cent or 70 per cent families as well as those who have 70 per cent quantum of land agree for such thing, then it is all right. उन्होंने कहा था कि केवल परिवार के साथ काम नहीं चलेगा। जिनके पास 70-80 प्रतिशत भूमि है उनकी भी सहमति लेनी चाहिए, यह भी आपने एक सुझाव दिया था। ...(व्यवधान) आप हमारी बात को दबा नहीं पाएंगे, हमारा समय भी पूरा नहीं हुआ है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये आर्डिनेंस लेकर आए हैं, 120 साल के बाद सब की सहमति से कानून बदला था, संसद की पवित्रता होती है, संसद की सहमति से

कानून बना था। उस बारे में अब हमें अच्छी तरह से विचार भी व्यक्त नहीं करने दिया जा रहा है। मैडम, लोकतंत्र की रक्षा और सुरक्षा करना आपका दायित्व है। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं, राव इन्द्रजीत सिंह जी बैठे हैं। अभी पीछे भावल में, दिल्ली-मुम्बई इंडस्ट्रियल कोरीडोर में एक लोजेस्टिक्स हब्स बन रहा है। उसके लिए 3 हजार एकड़ जमीन एक्वायर हो रही थी। वहां के किसान आये। ...(व्यवधान) उन्होंने कहा कि हमें जमीन एक्वायर नहीं करनी है। आपने सिफारिश की कि इसे एक्वायर नहीं करनी चाहिए। ...(व्यवधान) सरकार ने फैसला लिया कि उसे एक्वायर नहीं करनी चाहिए। उसके 20 किलोमीटर दूर के किसानों ने आकर कहा कि हमारी जमीन एक्वायर कीजिए। ...(व्यवधान) 20 किलोमीटर दूर के किसान इसके लिए तैयार हैं। ...(व्यवधान) इसमें किसान की सहमति से काम हो सकता है। ...(व्यवधान) किसान की सहमति से विकास को आगे बढ़ाया जा सकता है। ...(व्यवधान) इस देश में किसान को विकास विरोधी बताया जा रहा है। यह इस देश का दुर्भाग्य है। ...(व्यवधान) इसका एक और सैक्शन 24 (बी) है। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : दीपेन्द्र जी, आप कितना समय और लेंगे? आपको कितना समय चाहिए?

...(व्यवधान)

श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा: सैक्शन 24(2) में, अभी पूनम म्युनिसिपल कार्पोरेशन वर्सेज हरचंद लाल सोलंकी केस को कोट किया गया। यह सही कोट किया गया। सुप्रीम कोर्ट की सात जजमेंट आयी हैं, जिसमें इस कानून के आधार पर हजारों एकड़ जमीन उन किसानों को वापस दी गयी, जिसमें रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन हुई है और पिछले पांच साल से जिस जमीन पर कोई काम नहीं हुआ। हजारों एकड़ जमीन उन किसानों को वापस देने का काम सुप्रीम कोर्ट ने किया है। ...(व्यवधान) सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून को सही माना है, मगर उस क्लाज को आज यह खत्म कर रहे हैं। ...(व्यवधान) जिस देश में पांच सौ केसेज सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं। जहां किसान इस कानून के तहत अपनी जमीन वापस लेना चाहते हैं, आज इस कानून के बाद उन किसानों को जमीन वापस नहीं मिलेगी, मैं यह भी बताना चाहता हूं। ...(व्यवधान)

इस कानून का दूसरा मूल सिद्धांत सोशल इम्पैक्ट स्टडी है। सोशल इम्पैक्ट स्टडी को पूरी तरह से ...(व्यवधान) मैं दो मिनट में अपनी बात खत्म कर रहा हूं। सोशल इम्पैक्ट स्टडी को पूरी तरह से नकारने का काम किया गया है। मैं समझता हूं कि सोशल इम्पैक्ट स्टडी इस कानून का एक मूल सिद्धांत है, इसलिए इस पर भी ध्यान दिया जाये। जहां तक कम्पेनसैशन की बात है, तो मैं समझता हूं कि पूरे सदन के दबाव में आकर जो चार गुना और दो गुना कम्पेनसैशन मार्केट रेट के आधार पर रखने का फैसला हुआ था, वह इन्होंने मान लिया है, मगर उसे प्रदेशों पर छोड़ने की बात हो रही है। यह बहुत खतरनाक बात है, क्योंकि प्रदेशों को यह अधिकार प्राप्त था, तभी हरियाणा में दिसम्बर में जो नोटीफिकेशन आया, उसमें चार

गुना और दो गुना के बजाय एक गुना मार्केट रेट जितना कम्पेनसैशन देने का फैसला सरकार ने किया। ...(व्यवधान) यह नोटीफिकेशन हरियाणा सरकार का है। यह प्रदेशों पर कतई न छोड़ा जाये, ऐसी हम मांग करते हैं। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया, अंत में, मैं दो सुझाव देकर अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा। एक यह है कि जिन किसानों ने पिछले 60 सालों से विभिन्न सरकारों में, प्रदेश सरकारों में अपनी जमीन देकर इस देश का निर्माण करने का काम किया है, उनके लिए केन्द्र सरकार की नौकरियों में कम से कम दो प्रतिशत का आरक्षण होना चाहिए, ताकि उनके परिवार ...(व्यवधान) जिन्होंने इस देश को बनाने में अपनी धरती मां का बलिदान दिया, उनके लिए नौकरियों में दो प्रतिशत का आरक्षण होना चाहिए। ...(व्यवधान) जनता इसे देख रही है। हम आज जो बात कह रहे हैं, उसे लोग देख रहे हैं। ...(व्यवधान) आप किसान की बात को कितना सुन रहे हैं, यह भी लोग देख रहे हैं। उसके साथ-साथ मैं समझता हूं। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया, मैं अंतिम बात कहकर अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। ...(व्यवधान) मेहनतकश जग वालों से ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : ठीक है, आप अपनी बात कम्पलीट कीजिए।

...(व्यवधान)

श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा: मैं किसान की बात को कनक्लूड कर रहा हूं। ...(व्यवधान)

हम मेहनतकश जगवालों से जब अपना हिस्सा मांगेंगे,
एक खेत नहीं, एक बाग नहीं, हम पूरी दुनिया मांगेंगे,
ये पर्वत-पर्वत हीरे हैं या सागर-सागर मोती हैं,
ये सारा माल हमारा है, हम पूरा खजाना मांगेंगे।

आप किसान का हक छीनने का काम न करें। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री नन्दकुमार सिंह चौहान (खंडवा) : अध्यक्ष महोदय, मैं उस क्षेत्र से आता हूं, जहां देश में सर्वाधिक भूमि अधिग्रहण हुआ है। इंदिरा सागर बांध, जिसमें 280 गांवों की जमीन, 280 डूबे हैं वहां सरकार ने जमीन अधिग्रहित की। ओंकारेश्वर बांध, जिसमें 37 गांव डूबे हैं, वहां के किसानों ने राष्ट्र, प्रदेश के हित में अपनी जमीनें दीं और सरकार ने जो मुआवजा दिया, वह मुआवजा लिया। आज मेरे खंडवा लोक सभा क्षेत्र की हालत बदल चुकी है। पहले हमारे यहां के किसानों के बच्चे शहरों में मजदूरी करने जाते थे, सिक्योरिटी गार्ड बनकर काम करते थे। आज लाखों एकड़ जमीन सिंचित हुई है और वे सब लौटकर आए हैं। वे सिंचित जमीन में अपने परिवार के साथ फसल पैदा करके राष्ट्र के लिए, अपने परिवार के लिए काम कर रहे हैं।

मध्य प्रदेश में साढ़े सात लाख हैक्टेयर जमीन सिंचित होती थी। जब शिवराज सिंह चौहान जी मुख्यमंत्री बने, प्रदेश में जमीन अधिग्रहित हुई तो किसानों ने खुशी-खुशी जमीन दी। आज मध्य प्रदेश में 30 लाख हैक्टेयर धरती सिंचित हो रही है। पंजाब और हरियाणा को भी मध्य प्रदेश ने उत्पादन में पीछे छोड़ दिया है। मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग बन रहे हैं, स्टेट हाईवेज़ बन रहे हैं। विकास के लिए धरती चाहिए। सूखे की धरती में एक किसान के सब बच्चे नहीं पल सकते हैं। इरीगेटिड लैंड के लिए सिचांई योजना लानी होगी। यदि सिंचाई योजना लानी है तो भूमि अधिग्रहण करना होगा तभी देश और समाज के व्यापक हित में काम आगे बढ़ेगा।...(व्यवधान)

महोदया, जिस तरह से पापुलेशन बढ़ रही है, अब धरती में सबको पालने की क्षमता नहीं रही है। महाराष्ट्र का उदाहरण हमारी आंखों के सामने है। विदर्भ में सबसे ज्यादा आत्महत्याएं हुई और इसके पीछे कारण यह है कि वहां इरीगेटिड लैंड नहीं है, सूखी जमीन है इसलिए विदर्भ के किसान खेती करने में घाटे में हैं। जहां इरीगेशन होता है वहां किसान की तरक्की होती है। ये उद्योगों की बात कह रहे हैं। आज पूरे हिंदुस्तान का आंकड़ा निकाल लें, तो पता चलेगा कि अभी तक हिंदुस्तान में जितनी जमीन अधिग्रहित हुई होगी, उसमें उद्योगों के लिए ज्यादा से ज्यादा दस परसेंट या बीस परसेंट हुई होगी, ज्यादातर जमीन इरीगेशन स्कीम्स, राष्ट्रीय राजमार्गों, बिजली के कारखानों के लिए हुई है। यदि बिजली नहीं बनेगी तो किसान सिंचाई कैसे करेगा? हम किसानों के हितों की बात कहने के लिए खड़े हुए हैं। किसानों के खेतों की सिंचाई बगैर बिजली के नहीं हो सकती है, बगैर बांध के जमीन सिंचित नहीं हो सकती है। इस बिल में यह कहा गया है कि सरकार जिन किसानों की जमीन लेगी, उन्हें बाजार भाव से चार गुना ज्यादा दाम देगी। अगर किसान को चार गुना ज्यादा दाम मिलेगा तो वह खुशी से सरकार को जमीन देगा। इसमें कोर्ट में जाने का भी प्रावधान रखा गया है। यदि किसान चाहे तो वह कोर्ट में जा सकता है, कहीं रुकावट नहीं है। इन्होंने प्राइवेट अस्पताल और प्राइवेट एजुकेशन संस्थाओं के बारे में शंका जताई है। इसमें जमीन का

अधिग्रहण नहीं किया जाएगा। रियल एस्टेट के लिए भी जमीन का अधिग्रहण नहीं किया जाएगा। इतनी स्पष्टता के साथ बिल में सारी बातें रखी गई हैं। ये किसानों का नाम ले रहे हैं लेकिन किसानों का सबसे बड़ा दुश्मन यदि यहां कोई है तो उधर बैठे हुए लोग हैं। ...(व्यवधान) ये नहीं चाहते हैं कि यहां नॉन इरीगेटिड लैंड सिंचित हों, किसानों के दरवाजे पर खुशहाली पहुंचे। ...(व्यवधान) किसान इरीगेटिड लैंड के भरोसे बहु फसलें उगा सके, ज्यादा से ज्यादा उत्पादन कर सके, कमर्शियल क्राप उगा सके, यदि यह सब किसान को चाहिए तो उसकी धरती को पानी चाहिए। धरती को पानी चाहिए तो सिंचाई योजनाओं के लिए जमीन भी चाहिए। यदि इन्फ्रास्ट्रक्चर डैवलप नहीं होगा तो दुनिया की दौड़ में हिंदुस्तान पिछड़ जाएगा।

महोदया, आज हम चीन से बराबरी की बात कह रहे हैं। क्या चीन से बराबरी ऐसे होगी? यदि हम चीन के बराबर खड़ा होना चाहते हैं तो राष्ट्र हित में रोड बनाने होंगे, रेलवे लाइनें बनानी होंगी, कारखाने भी खड़े करने होंगे। जो इंडस्ट्रीज़ लगेंगी, जिन प्रौजेक्ट के लिए जमीन ली जाएगी, यदि वहां का किसान भूमिहीन हो रहा है तो बिल में क्लॉज है उसके परिवार के एक व्यक्ति को उस प्रौजेक्ट में नौकरी दी जाएगी। यह किसानों के लिए सबसे बड़ा बेनिफिट है। आज यह जो बिल आया है, यह राष्ट्र के विकास का बिल है, यह राष्ट्र का रोड मैप तय करने वाला बिल है। दुनिया तेजी से आगे बढ़ रही है और यहाँ पर इस बिल को लेकर जो राजनीति कर रहे हैं, इससे किसका लाभ होगा और किसका नुकसान होगा? यदि सबसे अधिक नुकसान होगा, तो वह देश का नुकसान होगा और जिन किसानों की बात ये कह रहे हैं, उनका नुकसान होगा। आज निमाड़ में जितनी संपन्नता आयी है, उसके पीछे कारण यह है कि वहाँ पर किसानों की जो जमीनें ली गई हैं और जो इरिगेशन स्कीम्स बनें, मध्य प्रदेश में पहले साढ़े सात लाख हेक्टेयर जमीन सिंचित होती थी, आज वहाँ 30 लाख हेक्टेयर जमीन सिंचित हो रही है और कहीं से भी किसानों ने जमीन देने में विरोध नहीं किया। आज इस तरीके से इस बिल को लेकर यहाँ पर जो राजनीति हो रही है, वह राष्ट्र के लिए, देश के लिए ठीक नहीं है। यहाँ आज हम सब बैठे हैं, देश को दुनिया की एक ताकत बनाने का संकल्प लेकर बैठे हैं, दुनिया की एक शक्ति बनाने का संकल्प लेकर बैठे हैं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, बिजली के लिए, रेलवे के लिए जमीन जरूरी है और भरपूर पैसे देकर सरकार जमीन लेने का बिल लायी है, मैं इस बिल का पुरज़ोर समर्थन करता हूँ।

THE MINISTER OF RURAL DEVELOPMENT, MINISTER OF PANCHAYATI RAJ AND MINISTER OF DRINKING WATER AND SANITATION (SHRI CHAUDHARY BIRENDER SINGH): Madam Speaker, we have also moved nine amendments. It is because, now I am to reply and most of the Members have

already spoken on those amendments; but formally if I am to move them, I can move them just now and after that I can give my reply.

माननीय अध्यक्ष : आप पहले अपनी बात रखेंगे।

…(व्यवधान)

SHRI JYOTIRADITYA M. SCINDIA (GUNA): Madam, I have a point of order.

HON. SPEAKER: What is it?

… (*Interruptions*)

SHRI JYOTIRADITYA M. SCINDIA: It is under Rule 79 – notice of an amendment to clauses… (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : वे तो रिप्लाई दे रहे हैं। मैं उनको वही बता रही हूँ कि you have to reply first.

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आपको पहले रिप्लाई देना है, फिर आपको मूव करना है।

…(व्यवधान)

HON. SPEAKER: He was asking.

… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: You have to reply first.

… (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : वे रिप्लाई दे रहे हैं।

…(व्यवधान)

श्री चौधरी बीरेन्द्र सिंह : सांसद महोदय, हिंदी या अंग्रेजी में बोलने की बात नहीं है। आप चाहते हैं तो मैं हिंदुस्तानी में बोलूंगा, आपको इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए।

माननीय अध्यक्ष : कृपया दोनों तरफ शांति रखिए, आठ घंटे अच्छी चर्चा हुई है। अब मंत्री जी को रिप्लाई करने दीजिए। आपस में क्रास बातचीत मत कीजिएगा।

श्री चौधरी बीरेन्द्र सिंह : महोदया, भूमि अधिग्रहण बिल वर्ष 2013 में यू.पी.ए. सरकार ने पास किया था। उसके बाद हम 31 दिसम्बर, 2014 को आर्डिनेंस के माध्यम से उसमें कुछ अमेंडमेंड्स करके लाए थे और जब सत्र शुरू हुआ तो उन्हें ज्यों का त्यों सदन के सभा पटल पर रखना उचित समझा। आज इस बिल पर हो रही चर्चा में तीन दर्जन से ज्यादा सदस्यों ने भाग लिया। इस चर्चा में उत्तेजना भी थी, तर्क भी था और कई बातें ऐसी भी कही गईं, जो हमारे ध्यान में भी आईं तथा हमारे साथियों ने भी आपसे बहुत-सी बातें कहीं जो आपके भी ध्यान में आने योग्य थीं।

महोदया, मैं अपनी बात इस प्रकार से शुरू करता हूं कि आज जो पार्टी सबसे ज्यादा हंगामा इस बिल के संशोधनों के बारे में कर रही है, जैसा हमारे साथियों ने कहा कि 67 साल की स्वतंत्रता के इतिहास में अगर पांच दशक से ज्यादा कोई शासक दल के रूप में कोई राजनीतिक दल रहा है, तो मेरे सामने बैठे साथी हैं।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : वेणुगोपाल जी, कृपया बैठ जाएं।

...(व्यवधान)

श्री चौधरी बीरेन्द्र सिंह : महोदया, यही तो विडम्बना है कि आप में सही बात को सही कहने की हिम्मत नहीं है। गुलामी की बात को आप पसंद करते हैं, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूं।

महोदया, मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज किसान की वकालत करने वाले लोग पचास साल से सत्ता में बैठे थे। वर्ष 1972 के अंदर एक प्रस्ताव आया और उसमें यह कहा गया कि किसान की अपर लैंड सीलिंग निर्धारित की जाए। दिमाग में यह था कि देश में हजारों नहीं बल्कि लाखों ऐसे किसान हैं जिनको फ्यूडल का नाम दिया गया कि इनके पास हजारों एकड़ जमीन है। मुझे अच्छी तरह से याद है कि मैंने पहला चुनाव वर्ष 1972 में लड़ा था। शायद सदन में बहुत कम लोग होंगे जो वर्ष 1972 में चुनाव लड़े होंगे। खड़गे जी की बात मैं कह नहीं सकता, लेकिन अन्य सदस्यों के बारे में मैं यह बात कह सकता हूं। मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उन दिनों शिरोमणि अकाली दल ने एक प्रस्ताव पास किया था और उस प्रस्ताव का अभिप्राय यह था कि अगर किसान के लिए अपर लैंड सीलिंग तय करते हैं तो मेहरबानी करके लोअर लैंड सीलिंग भी फिक्स करो, ताकि जिस जमीन पर वह मेहनत करता है उसकी

मेहनत व्यर्थ न जाए और खेती उसके लिए घाटे का सौदा न हो। घाटे का सौदा बनने के बाद खेती के लिए किसान के मन में निराशा आएगी और वह गरीबी से नहीं निकल पाएगा। आपने और हमारे सदस्यों ने भी कहा कि आजादी प्राप्त करने के बाद जब पहला बजट आया था, तो उसमें 52 प्रतिशत से ज्यादा जीडीपी का शेयर कृषि पर आधारित था और आज हालत यह हो गई कि 52 परसेंट की बात छोड़िए 15 परसेंट से भी नीचे आ गया है। उस समय हम कहते थे कि 70 से 75 प्रतिशत लोगों के हाथ कृषि करते हैं, वे प्रतिशत आज 60 हो गया है। अगर आप इन बातों पर सोचेंगे तो आपको अंदाजा लगेगा कि कृषि का जी.डी.पी. 15 परसेंट आता है तो कृषि पर जो हाथ आधारित थे, वे भी 25 प्रतिशत आने चाहिए थे। यह विडम्बना है, लेकिन आपने यह कभी नहीं सोचा। आपने दो साल पहले कम्पनीज एक्ट पास किया। क्या आपने कभी यह सोचा कि हजारों एकड़ जमीन कारपोरेट कंपनी के नाम से खरीदी जाती है, कई जगह एक्वायर भी की गयी। आपने एसईजेड का जिक्र किया कि एसईजेड की जमीन का क्या होगा। मैं आपसे पूछता हूं कि क्या कांग्रेस के किसी भी सदस्य ने इस बात का विरोध किया कि किसान की साढ़े 18 एकड़ जमीन पर सीलिंग लगा दो और उद्योगपतियों को आप दो हजार एकड़ जमीन दीजिए और उसका कोई हिसाब भी न हो।...(व्यवधान) आप सुनिए। सिन्धिया जी, मैं आपको ही कह रहा हूं, आप कह रहे थे कि इस अमेंडमेंट ने इस एक्ट की आत्मा निकाल दी। आत्मा निकालने का काम आपने किया था, हम इसमें आत्मा डाल रहे हैं।...(व्यवधान) सुनिए, सुनने की हिम्मत होनी चाहिए।...(व्यवधान) मैं आपकी आत्मा की कांसेप्ट जानता हूं।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मंत्री जी, आप चेयर को एड्रेस करके बोलिए।

...(व्यवधान)

श्री चौधरी बीरेन्द्र सिंह: नहीं मैडम, मैं जवाब देता हूं। मैं किसी से घबराकर जवाब नहीं देता, सही जवाब दूंगा। मैं किसान का बेटा हूं।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप लोग बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

श्री चौधरी बीरेन्द्र सिंह: बैठिए, आपको एक-एक चीज का जवाब मिलेगा।...(व्यवधान) हां, बड़ी-बड़ी बातें करते हैं और अब सुनने को तैयार नहीं हैं।...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Please sit down. What is this?

… (*Interruptions*)… *

* Not recorded.

माननीय अध्यक्ष : ये दोनों तरफ से क्या हो रहा है? अनुराग जी, प्लीज बैठिए। आप सभी लोग बैठिए। पीछे आप लोग क्यों खड़े हैं?

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मंत्री जी सक्षम हैं, आप सब लोग सुनिए। मंत्री जी सक्षम हैं। कोई खड़ा नहीं होगा। प्लीज, आप सभी लोग बैठ जाइए।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : प्लीज, शांति से बात सुनिए। सिन्धिया जी, बैठ जाइए।

…(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Nothing will go on record except what the hon. Minister says.

… (*Interruptions*)… *

माननीय अध्यक्ष : यह क्या हो रहा है? मैं बोल रही हूं। आप लोग बैठ जाइए।

…(व्यवधान)

श्री चौधरी बीरेन्द्र सिंह: ये लोग ऐसे मेरी तरफ उंगली नहीं कर सकते।…(व्यवधान) Do not show your finger like this. I will not tolerate. … (*Interruptions*) यही तरीका है इनका।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप लोग बैठ जाइए।

शहरी विकास मंत्री, आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री एम. वैंकैय्या नायडू) : मैडम, वे लोग उंगली दिखा रहे हैं, यह अच्छा नहीं है।…(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Nothing will go on record except what the hon. Minister says.

… (*Interruptions*)… *

माननीय अध्यक्ष : इस तरीके से नहीं होता है।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप लोग बैठ जाइए।

…(व्यवधान)

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: Please do not gesticulate like that. … (*Interruptions*)

---

* Not recorded.

माननीय अध्यक्ष : यह क्या हो रहा है? आप लोग शान्ति से बैठिए। समझदारी दिखाइए।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : चुप रहिए। मैं देखूंगी। प्लीज, आप लोग बैठिए।

…(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Nothing will go on record except what the hon. Minister says.

… (*Interruptions*)… *

माननीय अध्यक्ष : प्लीज बैठिए। इतना गुस्सा नहीं करते। मैं बता रही हूं। प्लीज बैठिए।

…(व्यवधान)

18.00 hrs

माननीय अध्यक्ष: मंत्री जी आप चेयर को सम्बोधित करते हुए विषय से संदर्भित जितनी बात है, उतनी बात कहें।

SHRI CHAUDHARY BIRENDER SINGH: I am addressing the Chair only.

माननीय अध्यक्ष: आप भी गुस्सा न करें। आप तो समझदार हैं। Yes, Calm down.

… (*Interruptions*)

श्री चौधरी बीरेन्द्र सिंह: मैडम, अभी यह एक आम धारणा बनी कि जो संशोधन लाए गए हैं, वे विपक्ष को भी पसंद नहीं, कई साथियों ने ऐसा कहा। कइयों ने कहा कि हमारे साथियों को भी पसंद नहीं और कुछ ने यह कहा कि प्रेस को भी पसंद नहीं। मैं आज के "इंडियन एक्सप्रेस" में और अन्य अखबारों में जो छपा है, वह बताना चाहता हूं। मैं यह कहना चाहता हूं कि उन्होंने हमारे इस प्रयास की प्रशंसा की है कि ऐसी व्यवस्था में…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आप चेयर को सम्बोधित करके अपना भाषण रिकार्ड करवाएं।

श्री चौधरी बीरेन्द्र सिंह: भाषण तो तब दूंगा, जब ये मुझे डिस्टर्ब करना बंद करेंगे, वरना मैं कैसे दूंगा।…(व्यवधान) I cannot be cowed down by you… (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष: अधीर रंजन जी, आप बैठ जाएं। आप लोगों ने अपनी बात कह दी है।

… (*Interruptions*)

---

* Not recorded.

SHRI CHAUDHARY BIRENDER SINGH: Madam, it is *The Indian Express* of today. Heading is "**Whose land?** A citizen's guide to land acquisition" by Sanjoy Chakravorty. It says:

> "As best we know, every country has some sort of land acquisition law or process. The justification is to make public purpose override private interests… "

SHRI JYOTIRADITYA M. SCINDIA: Madam, why is he quoting a newspaper?

माननीय अध्यक्ष: बोलकर कोट कर रहे हैं। सबने बोलकर कोट किया है, आपने भी अपने भाषण में कोट किया है। अब आप बैठ जाएं।

…(व्यवधान)

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: He can quote… (*Interruptions*)

SHRI CHAUDHARY BIRENDER SINGH: Madam, it says:

> "As best we know, every country has some sort of land acquisition law or process. The justification is to make public purpose override private interests…so that 'unwilling sellers' cannot obstruct the creation of public good. In India, two other reasons are considered important. One, the land is very fragmented (three acres is the average landholding size, in contrast to hundreds acres in Europe and America). As a result, large projects can involve thousands of landowners, and individual negotiation with each is very difficult to coordinate, if not impossible. Two, many of these owners do not have clear title to the land they possess, which means that there are likely to be litigations and disputes later on. India's land acquisition law solves both problems: of fragmentation and unclear titles."

HON. SPEAKER: Mr. Minister, one minute, please.

Hon. Members, यह बिल पास होने तक सदन का समय बढ़ा दिया जाता है।

…(व्यवधान)

HON. SPEAKER: We will pass the Bill.

Yes, Mr. Minister, please continue.

… (*Interruptions*)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा) : मेरा पाइंट ऑफ ऑर्डर है।

माननीय अध्यक्ष: मंत्री जी के जवाब के समय कोई पाइंट ऑफ ऑर्डर नहीं है।

SHRI MALLIKARJUN KHARGE : I am raising a point of order. Now, 6 o'clock is already over. The House is continuing without raising the time of the House. You have to, first, take the permission of the House… (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष: मैंने अभी कहा है कि इस बिल के पास होने तक सदन का समय बढ़ाया जाता है। आप इतना शोर करते हैं कि आपको मेरी आवाज़ सुनाई नहीं दी। इसलिए कृपया शांत होकर बैठें।

SHRI CHAUDHARY BIRENDER SINGH: Madam Speaker, only yesterday, while speaking, Mr. Satpathy referred a very important factor, which should be brought to the notice of the entire House. He made a mention that in the last so many years, about seven lakh hectares of land have been acquired in different States of our country. Out of that, he made a mention that 65,000 acres of land have been acquired in Haryana. … (*Interruptions*) You cannot blow hot and cold in the same breath. That is what I am saying.

Madam, at one point of time, just to get the support of the farming community, they say that the *bhatta parsaul* issue is very important. When the *Kisan* is being looted in Haryana and 65,000 acres of land is being acquired, then there is no mention about that. This kind of politics will not serve. … (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : आप लोग बैठ जाइए। वेणुगोपाल जी, हर बात में खड़ा होना ठीक नहीं है।

…(व्यवधान)

SHRI CHAUDHARY BIRENDER SINGH: Out of 65,000 acres, and amount of 24,000 acres of land was given to the private owners. This is the state of affairs. … (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : इन्होंने ऐसी कोई बात नहीं बोली है कि आप खड़े हो रहे हैं।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : ऐसा नहीं होता है कि आप डिक्टेट करेंगे। जब आपने भाषण दिया था तो आपको पूरा समय दिया गया था। मंत्री जी तथागत जी के भाषण का जवाब दे रहे हैं। यही होता है और हर चीज पर खड़ा नहीं हुआ जाता है। आप थोड़ा तो समझिए। कोई भी माननीय सदस्य बीच में नहीं बोलेगा, जब तक मंत्री जी का भाषण समाप्त नहीं हो जाता है।

…(व्यवधान)

SHRI CHAUDHARY BIRENDER SINGH: Haryana's landmass, when compared to that of the total country, is less than 2 per cent. The then Government was acquiring more than 6 per cent of the land. What is this? … (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : आप सुनने की क्षमता रखिए, अभी आपको बहुत समय सदन में बिताना है।

SHRI CHAUDHARY BIRENDER SINGH: I am not of that type. I know what happened in Haryana. But on the floor of the House, I do not want to mention anything or any wrong which they have committed.

One thing I want to bring to your notice. Hon. Member of the CPI Party who brought this statutory resolution, said that there was a lot of delay while bringing this Ordinance.

Madam, the act came into existence in the year 2013. It became operational from 1st January, 2014 and in the month of February, 2014, during the time of UPA Government, a workshop took place. Most of the suggestions were that the Act which is now applicable, requires lot of rethinking, revisiting and it should be amended to a large extent. Then, Mr. Gadkari was looking after Rural Development. A meeting was convened on 27th June and out of 36 States and Union Territories, 32 participated. उन 32 राज्यों के सैक्रेटरीज़ ने और रैवेन्यु मिनिस्टर ने जो-जो कहा, अगर मैं उसे बताऊं तो हमारे साथी और मुलायम सिंह जी के भतीजे बहुत खुश होकर बोल रहे थे कि हमने बहुत स्मूथ किया है। I want to bring to the notice of this House that when he talked about acquiring of 3600 acre of land for that express highway, the land proceedings started on 31st December and finished on 31st December. That is how, it was done. … (*Interruptions*) किसानों का दम भरने वाले लोगों से मैं यह कहता हूं why I am saying this is because four times there was a mention about my grand father that he was a *kisan* leader and Birender Singh as such cannot tolerate anything which is going against the interest of the farmers. That is my commitment.

Madam, one more thing he used to say that ए भोले किसान, दो बात मेरी मान ले, एक बोलना ले सीख, एक दुश्मन को पहचान ले। He is still to recognise who is the enemy of

the *kisan* fraternity. What I want to say is that 27 जून की मीटिंग में उत्तर प्रदेश सरकार कहती है कि कंसेन्ट का क्लाज अच्छा नहीं है, खत्म कर दो।...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: He is not yielding, please.

श्री चौधरी बीरेन्द्र सिंह: और जब भट्टा पारसौल के लोगों ने यह कहा कि हमारे यहां जमीन का चार गुणा मुआवजा देंगे और जब उन्हें यह पता लगा कि रीसैटलमैन्ट और रीहैबिलिटेशन के लिए कुछ नहीं हो रहा है, now they are coming to us that the way the land was acquired, it was a cheating on the part of the Government and we do not want to part with our resettlement and rehabilitation advantage. That is the actual picture.

यह दीपेन्द्र नौजवान है और मैं यह चाहता हूं कि जो मैं कहूं, वह यह कम से कम सुन ले, बाकी अमल करना या न करना तुम्हारी मर्जी है। ...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: No, nothing will go on record. Only the Minister's statement will go on record.

… (*Interruptions*)*

माननीय अध्यक्ष : यह क्या हो रहा है? आपने यही चलाना है या बिल पास कराना है?

SHRI CHAUDHARY BIRENDER SINGH: Madam, a strong contingent of bureaucrats from Haryana was representing. The Haryana Government on behalf of the then hon. Chief Minister and they came out with this that if this consent clause continues and if this social impact clause continues, we will not be able to acquire even a single inch of land. … (*Interruptions*) It is on record. "Under PPP projects, the ownership of land vests with the Government. Therefore, the consent requirement should be done away with." This is what the Haryana Government had said.

SHRI DEEPENDER SINGH HOODA: The Chief Minister overruled them. What is the point? It is on the record.… (*Interruptions*)

श्री चौधरी बीरेन्द्र सिंह : मैं किसान का एक पक्ष और रखना चाहता हूं, उसको आप भी सोचें और हम भी सोचें...(व्यवधान) पप्पू साहब, आप मुझे बोलने दीजिए, अब आप पप्पू नहीं हो लट्टू हो।...(व्यवधान)

---

* Not recorded.

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया : महोदया, मंत्री जी को यह बात कहना शोभा नहीं देता, वह एक माननीय सदस्य के बारे में ऐसा कह रहे हैं।

श्री चौधरी बीरेन्द्र सिंह : वह मेरे मित्र हैं। आप तो अपनी आत्मा की बात करो, आपके पास और कुछ नहीं है।...(व्यवधान) मैं आपसे ही बात करूंगा, मैं दूसरी तरफ नज़र उठाऊंगा ही नहीं। ...(व्यवधान) मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि जो लोग आज किसान की वकालत करते हैं, कहते हैं कि उनकी जो भूमि है, उसके लिए हम कुर्बान हो जाएंगे, टच नहीं होने देंगे, इन्होंने एक मिथ्या प्रचार किया है कि बीजेपी की यह सरकार ऐसा कानून ले कर आ रही है कि इसके आते ही सब जमीनें एक्वायर हो जाएंगी। मैं यह जानना चाहता हूँ कि आप कब तक किसान को इस कदर रखोगे? आज मेरे किसान को रोज़गार की तलाश है। उसकी बहुत सी जमीनें, मैं यह कह सकता हूँ कि 70 प्रतिशत से अधिक किसान ऐसे हैं, जिनकी लैण्ड होल्डिंग आधा एकड़, पौना एकड़, एक एकड़, सवा एकड़ तक सीमित है और उसकी हालत यह है कि वह कहीं भी जाता है, तो कहता है कि मेरे बेटे को चपरासी लगवा दो, मेरे बेटे को कंडक्टर लगवा दो, मेरे बेटे को ड्राईवर लगवा दो, मेरे बेटे को पुलिस में भर्ती करवा दो। सेनाओं की रक्षा, देश की सीमाओं की रक्षा हम करें, लॉ एण्ड ऑर्डर को हम मेंटेन कर के रखें और जिस तरह से ये कौमा फ्लैज करते हैं कि किसान को इससे आगे मत बढ़ने दो, हमने इसमें प्रोविजन किया है कि किसान को आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। उसको भी वह अधिकार है। आप उनको आने वाले समय में इस बात के लिए मजबूर नहीं कर सकते हैं कि उनकी जमीनें अगर रहेंगी तो वे खुशहाल रहेंगे। आपने कहां खुशहाली छोड़ी है? आपने कॉरपोरेट सैक्टर को तो सब कुछ दे दिया है। कहा कि आपका कंपनी लॉ ठीक है। आपने कंपनी एक्ट में यह कहा है। यह प्रस्ताव आया है। ...(व्यवधान) आपने कंपनी एक्ट में यह कहा है कि किसी उद्योगपति को, किसी कॉरपोरेट को, किसी कंपनी को उसके शेयर तक की लाएबिलिटी तो है और किसान के बारे में जब बात आई, तो 50 साल राज़ करने के बाद भी इनको यह महसूस नहीं हुआ कि उनको भी आगे बढ़ने का मौका मिले। क्यों उसके लिए सारी लाएबिलिटी और कॉरपोरेट के लिए उनके शेयर तक लाएबिलिटी महफूज़ रखे? इस किस्म की व्यवस्था अगर रहेगी तो किसान क्या करेगा? एक माननीय सदस्य ने कहा, जब मैं बी.ए. में पढ़ता था तो मैंने भी अंग्रेज़ी में वह पोयम पढ़ी थी - 'The Man with the Hoe' वह यह कहती है कि इसको इतना मत सताओ, इसको इतना मजबूर न करो कि वह जिस दिन उठ खड़ा हुआ तो कोई उसको फिर आगे रोकने वाला नहीं मिलेगा। 50 साल के शासन में ...(व्यवधान) मैं कांग्रेस को अच्छी तरह जानता हूँ, इसलिए कह रहा हूँ। ...(व्यवधान) 50 साल के शासन में इन्होंने किसान को ऐसा

कर के रखा कि इनको टुकड़े तो डालते रहो, ताकि ये मरे न, लेकिन इनको आगे बढ़ने का मौका मत दो। यह इनकी नीति रही है। …(व्यवधान) ये बड़ी-बड़ी बातें करते हैं। …(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Only the Minister's statement will go in record.

… (*Interruptions*)

SHRI CHAUDHARY BIRENDER SINGH: I am not yielding … (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : सौगत राय जी, बैठ जाइए। He is not yielding

… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Nothing will go in record.

… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Yes Mr. Minister, you address the chair.

… (*Interruptions*)

SHRI CHAUDHARY BIRENDER SINGH: What I am saying, I do not think he would listen to my sane voice. … (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Only what the Hon. Minister is saying will go in record.

… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Please address the Chair.

… (*Interruptions*)

SHRI CHAUDHARY BIRENDER SINGH: That is my problem because I cannot speak in his way … (*Interruptions*)

Madam, let me tell you what we did. After the passing of this Act, naturally the State Governments were to make the rules and also the provision for compensation which is to be determined according to the length or the distance of a particular locality from the city or town. Up till now - it is more than 14 months' old Act - only six States have either framed rules or determined certain measurement for the fixation of compensation. One State is Andhra Pradesh where the notification was issued on 20.11.2014. Haryana issued it on 4.12.2014. It was issued on 13.07.2014 by Maharashtra. Madhya Pradesh issued it on 29.09.2014. Telangana issued it on 20.12.2014. Many States even did not inform. Rather they did not frame any rules.

In that situation, there was no other way. When we talk as a Chief Minister or a Minister in power, we have a different feeling. So, for those who were not framing the rules, the interest was that the existing Act should be amended, and we kept that thing and other problems also in mind. As I said, in the last six months – I have the data of last six months up to July – there was no acquisition done because there were no rules. If we are to progress, then for certain things, we have to do something.

When we talk of infrastructure, they straightaway jump to the conclusion that this is for the private things. Infrastructure does not mean only private things. Infrastructure means irrigation, infrastructure means roads. … (*Interruptions*)

मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि इन्फ्रास्ट्रक्चर के नाम पर कौन सी सड़क कितने दिन में बनेगी, यह आज के दिन आप बताएं, आपने 15 साल दिल्ली में राज किया, साफ हो गए, कहीं नजर ही नहीं आते, आप 9 परसेंट वोट पर आकर रूक गए।...(व्यवधान) One should be a large hearted man. … (*Interruptions*)

माननीय सदस्यों द्वारा जो कुछ ऐतराज उठाए गए, उनको लेकर मैं यह कहना चाहता हूँ कि हमने शुरू में वर्ष 2013 के एक्ट में आठ अमेंडमेंट्स रखीं और उनमें से चार पर किसी को कोई ऐतराज नहीं था। चार में ऐसा था, जैसे कहा गया कि आपने इंडस्ट्रियल कोरीडोर को परिभाषित नहीं किया है। हमने इसमें दूसरी अमेंडमेंट जो आज पेश की है, मैं माननीय सदस्यों को कहना चाहूँगा कि इसमें इंडस्ट्रियल कोरीडोर में एक्वीजिशन भी सरकार की तरफ से होगी या सरकार की कोई एजेंसी, कोई कॉरपोरेशन या कोई स्टेच्युट्री बॉडी या कोई बोर्ड करेगा और उसका एक-एक किलोमीटर दूरी तक ही उसको इंडस्ट्रियल कोरीडोर माना जाएगा। यह नहीं है कि उसको अंदर तक ले जाकर भी कहें कि यह भी इंडस्ट्रियल कोरीडोर है।...(व्यवधान) महोदय, एक तो यह है और इस पर बहुत से साथियों ने अपनी सहमति भी जताई है। ...(व्यवधान)

दूसरा, जैसे प्रेमचन्द्रन जी ने कहा कि I am happy that the clause relating to private hospitals and private educational institutions has been dropped. इसी तरीके का एक अमेंडमेंट हम लेकर आए हैं। मैं सदन में यह बात भी रखना चाहता हूँ कि कोई भी एक्वीज़ीशन इसलिए नहीं होगा कि हम किसी प्राइवेट आदमी को दे रहे हैं। सारी जितनी भी एक्वीज़ीशन है, वह सरकारी तौर पर हैं, सरकार का उससे ताल्लुक है। मैं सिंधिया जी को यह भी कहना चाहूँगा, ये मुझसे उम्र में बहुत छोटे हैं,

यदि इनको कोई अच्छा सुझाव याद आए, या दिमाग में आए, या किसी से पूछ लो, तो वह मुझे बता देना, उसको भी कर लेंगे। ...(व्यवधान) We will do it. … (*Interruptions*) It is in lighter vein. Do not get offended. … (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : आप सुझाव तो दे सकते हैं।

…(व्यवधान)

श्री चौधरी बीरेन्द्र सिंह : दूसरी बात यह है कि हमने जो पाँच चीज़ों को इनक्लूड किया है, उसमें डिफैन्स के लिए था, नेशनल सिक्यूरिटी के लिए था, हाउसेज़ फॉर पूअर थे, अफोर्डेबल हाउसेज़ थे, इनफ्रास्ट्रक्चर फॉर इलैक्ट्रिफिकेशन, इनफ्रास्ट्रक्चर फॉर रोड्ज़ भी था। ...(व्यवधान) एक चीज़ जो उसमें थी, वह इनफ्रास्ट्रक्चर, सोशल इनफ्रास्ट्रक्चर जो था, उसमें से 'सोशल इनफ्रास्ट्रक्चर' को हमने निकाल दिया है, यह सोचकर कि यह न समझा जाए कि सोशल में फिर वही प्राइवेट हास्पिटल या प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन आ सकते हैं। आज किसान के मन में यह बात गई है। मैं इसलिए नहीं कहता कि मैं यहाँ मिनिस्टर हूँ, मुझे उनकी psyche का पता है। वह कंपनसेशन की बात नहीं है। उनके मन में जो एक बात थी कि हमारे हितों को किसी दूसरे के पास गिरवी न रखा जाए, वह हमारी सरकार ने करके दिया है और आज उनको यह संदेश गया है। ...(व्यवधान)

हमने यह प्रावधान रखा था कि जो ज़मीन पाँच साल के बाद जिस काम के लिए रखी गई है, उस पर यदि काम नहीं होता तो उसको वापस किसान को दे दिया जाए।

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया: वह हमने रखा था, आपने नहीं रखा था। ...(व्यवधान)

श्री चौधरी बीरेन्द्र सिंह : अभी तो आप कह रहे थे कि मैं वहाँ था। तो मैंने रखा था, आपने नहीं रखा था, वह मेरा सुझाव था। ...(व्यवधान)

सैक्शन 24 में यह प्रावधान लाना ज़रूरी था कि अगर किसी कोर्ट के स्टे-आर्डर की वजह से या इंजंक्शन की वजह से अगर पाँच साल का पीरियड, सपोज़ 10 साल हो गए और प्रोजैक्ट शुरू नहीं हुआ तो उसमें छः साल इस बात के बीत गए कि कोर्ट से स्टे था, तो वह प्रोजैक्ट शुरू हो ही नहीं सकता था। इस सिचुएशन से निकलने के लिए यह तय किया गया कि अगर पाँच साल लिटिगेशन है तो बेशक कोर्ट में हो, लेकिन उसमें स्टे और इंजंक्शन नहीं है, तो पाँच साल कम्यूट होंगे और पाँच साल गिने जाएँगे। अदरवाइज़ अगर लंबा समय है तो उसमें से अगर वह समय निकाल दिया जाए और फिर पाँच साल बचते हैं तो वह ज़मीन वापस होगी, यह पुराने एक्ट के तहत मैं कह रहा हूँ।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूँ इसी के तहत एक अकाउंट की बात कही गई थी कि कुछ ट्रिब्यूनल के केसेज़ हैं, उनमें if the amount is deposited in any account, this we have changed. हमने कहा कि अकाउंट जो होगा वह डैज़िग्नेटेड अकाउंट होगा maintained for this purpose. If the account is designated and maintained for that purpose only, then the amount that is deposited would be treated as compensation has been paid.

हमने यह प्रावधान किया है। इसके साथ-साथ एक नया सैक्शन आज के बिल में हमने डाला है, वह सैक्शन 6(ए) है। इसमें यह था कि व्याख्या तो रिहैबिलिटेशन और रीसैटिलमेंट की थी, लेकिन उसमें जो इफैक्टिड फैमिलीज़ थीं, उनको और प्रीसाइज़ करने के लिए, ताकि इफैक्टिड फैमिलाज़ को दिक्कत न हो, मैं पढ़कर सुना देता हूं:

> "In the principal Act, in Section 31 of sub-section (2) and clause (h) after the words 'affected families', the words 'including compulsory employment to at least one member of such affected families of a farm labourer shall be inserted."

ताकि उस गरीब का जो बच्चा खेत में काम करता था, उसकी नौकरी पक्की हो। ...(व्यवधान)

SHRI K.C. VENUGOPAL (ALAPPUZHA): Is he moving an amendment?

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: Who said it? He said that he would only be reading it. … (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : अभी वह स्टेज आएगी, लेकिन बात नहीं कर सकते क्या?

एक माननीय सदस्य: वही तो पढ़कर सुनाया है।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : अभी तो वे एक्सप्लेन कर रहे हैं, बाद में मूव करेंगे। अभी वे मूव कहां कर रहे हैं? बात भी नहीं कर सकते क्या? अभी वे मूव नहीं कर रहे हैं, आप भी समझ रहे हैं। प्लीज़, बैठिये।

SHRI JYOTIRADITYA M. SCINDIA: Madam, if he his moving an amendment, then I have a point of order.

माननीय अध्यक्ष : अभी कुछ नहीं कर रहे हैं, मगर उसकी चर्चा भी नहीं कर सकते क्या? He is not moving anything.

… (*Interruptions*)

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: Madam, there are precedents. When you are going to move some amendment, हम एक एमेंडमेंट लाने वाले हैं, ऐसा बताने में कोई आपत्ति नहीं है, इतना क्रूशियल और कॉमनसेंस का पाइंट है। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : वे बोल सकते हैं। यह भी कोई बात है?

… (*Interruptions*)

SHRI MALLIKARJUN KHARGE: Madam, without moving the amendment, how can he explain it? He has to move the amendment and then he should explain. … (*Interruptions*)

SHRI JYOTIRADITYA M. SCINDIA: This is not fair. … (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: What he is saying is that they are going to move it. वह तो हो सकता है।

… (*Interruptions*)

SHRI CHAUDHARY BIRENDER SINGH: Actually, this is already provided in the Notification. … (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : आप थोड़ा हम पर भी विश्वास रखिये।

श्री चौधरी बीरेन्द्र सिंह: जो नोटिफिकेशन में है, उसको जो चेंज करने की बात है...(व्यवधान)

SHRI MALLIKARJUN KHARGE: What has not been included, how can he talk about that?

SHRI CHAUDHARY BIRENDER SINGH: You can find that from the List of Business and from your papers.

मैडम स्पीकर, एक हमने जो प्रावधान , वह सैक्शन 101 में है और उसमें जो 5 ईयर वर्ड है, उसको 'five years or the length of the project' किया है , but the length of the project would not be determined by the man who is submitting the proposal for the project. It would be submitted and it would be decided by the authority itself. क्योंकि, कुछ ऐसे प्रोजैक्ट्स हैं, जिनमें यह सम्भव हो ही नहीं सकता कि पांच साल में उसको खत्म करने की कोई बात हो, क्योंकि, हो सकता है कि उसमें सात साल लगें, दस साल लगें, इसलिए ऐसा प्रावधान हमने किया है और जिसमें लेंथ ऑफ प्रोजैक्ट पांच साल है, उसको रखा है, ताकि वह जमीन उसको वापस हो जाये।

इसी तरीके से सैक्शन 105 है, जिसके बारे में बहुत चर्चा हुई है। अगर मैं यह कहूं कि यह सबसे बड़ा प्रावधान है कि जो एक्ट 2013 में बना था, उसमें यह कमी थी कि 13 ऐसे सैण्ट्रल एक्ट्स, जिनको इस भरोसे छोड़ दिया गया था कि एक साल के बाद इनका क्रियान्वयन होगा, अगर कोई...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: पहले में यह प्रावधान था। नहीं था?...(व्यवधान)

श्री चौधरी बीरेन्द्र सिंह: नहीं है। Why anyone should wait for one year? Where is it written?

Madam Speaker, we have made this provision that all the 13 Acts which were not included in the Act of 2013 would be included and all the clauses relating to fair amount of compensation, that is, upto four times, and rehabilitation and resettlement would be applicable to all these 13 Acts. … (*Interruptions*)

SHRI JYOTIRADITYA M. SCINDIA: Madam, the Minister is misleading the House. यह प्रावधान उस बिल में रखा गया था कि एक साल की अवधि में...(व्यवधान)

SHRI CHAUDHARY BIRENDER SINGH: That is what I am saying. May I still repeat to all the hon. Members, including Prof. Saugata Roy and others, that if they still find that there is scope to do something better, we are ready to accept their proposal. We are ready to consider their proposal, but do not shut the door by saying that we have to oppose it or we have to support it. This should not be the

attitude of the hon. Members. We will ensure that everything which goes in favour of the farmers, we are willing to consider all such proposals.

हम आपको इंश्योर करते हैं कि किसान के हक़ में कोई भी बात होगी, हम आपकी बात मानने को तैयार होंगे, उसे कंसीडर करेंगे। मैंने यह सभी सदस्यों को कहा है। मैं इस बात को भी समझता हूं कि अगर हमें तरक्की करनी है, तरक्की का मतलब यह नहीं कि ज्यादा फैक्टरियां लग जाएं, बल्कि मैं तरक्की उस बात की कर रहा हूं जिसका मैंने ज़िक्र किया, अगर किसान को उस गरीबी से निकालना है और उसे भी अच्छी दुनिया का हक़दार बनाना है तो आपको दोनों चीज़ों में बैलेंस करना पड़ेगा।

धन्यवाद।

SHRI C.N. JAYADEVAN (THRISSUR): Madam, after the interesting speech of the hon. Minister, I still press for my Resolution and I would request the Minister to send the Bill to the Standing Committee for more discussion and amendments.

माननीय अध्यक्ष : यह नहीं होता है। आप अपनी बात कहिए।

SHRI C.N. JAYADEVAN : When I was talking about this Bill yesterday, as a Communist, I want to say specially that I am a Communist. I may be alone representing the Communist Party of India. But the BJP Members were only two in this corner at one time. They have to remember that. As a Communist, as has been mentioned, I want the hon. Minister to bring a basic Land Reforms Bill. Can he come with a basic Land Reforms Bill? It will allow the landlords to have only 15 acres of land with them. In Kerala, there were so many landlords, namely, Murikkan, Nilambur Kovilakam, Alathur Swamy, Mankumbil Pattaru, Parai Tharakkan etc. Now there are no landlords in Kerala. All are farmers. Can they take the lands of rich landlords, feudal lords and Kulaks in India? They are having acres and acres of land. Firstly, they have to capture those lands and distribute it to the poor, to the landless. They have to get land. The poor agriculture workers, the landless peasants have to get land at first.

The hon. Minister was speaking very humorously. I am saying this with respect that I was hearing 'His Master's Voice' -- the master's voice, the corporates of the world, the monopolists of India. It was the voice of the corporates. I am not a young man but I am young in this Sabha.

Shri Naidu is sitting here. I was listening to his speech yesterday. He was saying: "My Government, the Modi Government is with the poor, with the women, with the young men and with the peasants." It may be the truth. But if it is the truth, what action have they taken within nine months for the poor people, the peasants, for the women of India? It is not a long period. I agree that nine months is not a long period. But, is there any action taken for the poor, for the peasants, for the women in India in the last nine months?

HON. SPEAKER: Shri Jayadevan ji, are you withdrawing the Resolution?

SHRI C.N. JAYADEVAN : No, I am not withdrawing. I am moving.

HON. SPEAKER: The question is:

> "That this House disapproves of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement (Amendment) Ordinance, 2014 (No. 9 of 2014) promulgated by the President on 31st December, 2014".

SHRI C.N. JAYADEVAN: I want division.

HON. SPEAKER: Let the Lobbies be cleared.

ANNOUNCEMENT RE: AUTOMATIC VOTE RECORDING SYSTEM

HON. SPEAKER: Now, the lobbies have been cleared.

SECRETARY GENERAL: Kind attention of hon. Members is invited to the following points in the operation of Automatic Vote Recording System. Before a Division starts, every hon. Member should occupy his or her own seat and operate the system from that seat only. When the hon. Speaker says ‘Now Division’, the Secretary General will activate the voting button whereupon red bulbs above display boards on both sides of the hon. Speaker’s Chair will glow and a ‘gong’ sound will be heard simultaneously. For voting, hon. Members may please press the following two buttons simultaneously only after the sound of ‘gong’, I repeat, only after the sound of the ‘gong’- Red vote button in front of every hon. Member on the head of the phone plate and any one of the following buttons fixed on the top of the desk of the seat:

For ‘aye’, green colour button
For ‘no’, red colour button
For ‘abstention’, yellow colour button

It is essential to keep both the buttons pressed till the second ‘gong’ is heard and the red bulbs on the plasma display are off. The hon. Members may please note that the votes will not be registered if the buttons are kept pressed before the first ‘gong’ sound and if both the buttons are not simultaneously pressed till the second ‘gong’. The hon. Members can actually see their votes on display board installed on either side of the hon. Speaker’s Chair. In case the vote is not registered, they may call for voting through slips.

HON. SPEAKER: Shri C.N. Jayadevan, are you withdrawing your Statutory Resolution?

SHRI C.N. JAYADEVAN: Madam, I am not withdrawing my Statutory Resolution. I want a Division.

HON. SPEAKER: The lobbies have already been cleared.

The question is:

"That this House disapproves of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement (Amendment) Ordinance, 2014 (No. 9 of 2014) promulgated by the President on 31st December, 2014."

The Lok Sabha divided:

DIVISION **AYES** **18.41 hrs.**

@Adhikari, Shri Sisir Kumar

Adhikari, Shri Suvendu

Ahmed, Shri Sultan

Ali, Shri Idris

Anwar, Shri Tariq

Baite, Shri Thangso

Banerjee, Shri Abhishek

Banerjee, Shri Kalyan

Banerjee, Shri Prasun

Barman, Shri Bijoy Chandra

Bhonsale, Shri Chh. Udayanraje

Biju, Shri P. K.

Bose, Prof. Sugata

Chandrappa, Shri B. N.

Chaudhury, Shri Jitendra

Chautala, Shri Dushyant

@Chavan, Shri Ashok Shankarrao

Chowdhury, Shri A. H. khan

@Chowdhury, Shri Adhir Ranjan

Dastidar, Dr. Kakoli Ghosh

Datta, Shri Sankar Prasad

De(Nag), Dr. Ratna

Dev, Kumari Sushmita

Devegowda, Shri H.D.

Engti, Shri Biren Singh

@ Voted through slip.

Faizal, Mohammed

Geetha, Shrimati Kothapalli

George, Adv. Joice

Ghosh, Shrimati Arpita

Gogoi, Shri Gaurav

Gowda, Shri S.P. Muddahanume

Hansdak, Shri Vijay Kumar

Haque, Shri Mohd. Asrarul

Hazra, Dr. Anupam

@Hooda, Shri Deepender Singh

@Innocent, Shri

Jatua, Shri Choudhury Mohan

Jayadevan, Shri C. N

Karunakaran, Shri P.

@Khan, Shri Saumitra

Kharge, Shri Mallikarjun

Kumar, Shri Kaushalendra

Kumar, Shri Santosh

Kumar, Shri Shailesh

Mahato, Dr. Mriganka

Mandal, Dr. Tapas

Mann, Shri Bhagwant

Meinya, Dr. Thokchom

Moily, Shri M. Veerappa

Mondal, Shri Sunil Kumar

Mondal, Shrimati Pratima

Mukherjee, Shri Abhijit

Muniyappa, Shri K.H.

@ Voted through slip.

Naik, Prof. A.S.R.

Naik, Shri B.V.

Nath, Shri Kamal

Noor, Shrimati Mausam

Owaisi, Shri Asaduddin

Pala, Shri Vincent H.

Paswan, Shri Ram Chandra

Poddar, Shrimati Aparupa

Premachandran, Shri N.K.

Rajesh, Shri M. B.

@Raju, Shri C.S. Putta

Ramachandran, Shri Mullappally

Ranjan, Shri Rajesh

Ranjan, Shrimati Ranjeet

Reddy, Shri Gutha Sukender

Reddy, Shri Mekapati Raja Mohan

Reddy, Shri P. Srinivasa

Reddy, Shri P.V. Midhun

Reddy, Shri Y. V. Subba

Renuka, Shrimati Butta

Rori, Shri Charanjeet Singh

Roy, Prof. Saugata

Roy, Shrimati Sandhya

Ruala, Shri C.L.

Sahu, Shri Tamradhwaj

@Sampath, Dr. A.

Sanghamita, Dr. Mamtaz

Saren, Dr. Uma

@ Voted through slip.

Satav, Shri Rajeev

Scindia, Shri Jyotiraditya M.

Sharma, Shri Ram Kumar

Shetty, Shri Raju

Singh, Prof. Sadhu

Singh, Shri Ravneet

Sinha, Shrimati Renuka

Sule, Shrimati Supriya

Suresh, Shri D.K.

Suresh, Shri Kodikunnil

Teacher, Shrimati P.K. Shreemathi

Thakur, Shrimati Mamata

Tharoor, Dr. Shashi

@Thomas, Prof. K.V.

Tirkey, Shri Dasrath

Trivedi, Shri Dinesh

@Uddin, Shri Tasleem

Varma, Shrimati Dev

Velagapalli, Shri Varaprasad Rao

Venugopal, Shri K. C.

Yadav, Shri Akshay

Yadav, Shri Dharmendra

@Yadav, Shri Tej Pratap Singh

@Yadav, Shrimati Dimple

Yellaiah, Shri Nandi

@ Voted through slip.

NOES

[@]Adityanath, Yogi

Advani, Shri L.K.

Ahir, Shri Hansraj Gangaram

Ahlawat, Shrimati Santosh

Ahluwalia, Shri S.S.

Amarappa , Shri Karadi Sanganna

Ananthkumar, Shri

Angadi, Shri Suresh C.

Arunmozhithevan, Shri A.

Azad, Shri Kirti

Babu, Dr. Ravindra

Badal, Shrimati Harsimrat Kaur

Baheria, Shri Subhash Chandra

Bais, Shri Ramesh

Bala, Shrimati Anju

Balyan, Dr. Sanjeev

Bansode, Adv. Sharadkumar Maruti

Bhabhor, Shri Jasvantsinh Sumanbhai

Bhagat, Shri Sudarshan

Bhamre, Dr. Subhash Ramrao

Bharathi Mohan, Shri R.K.

Bharti, Sushri Uma

Bhatt, Shrimati Ranjanben

Bhole, Shri Devendra Singh

Bhuria, Shri Dileep Singh

@Bidhuri, Shri Ramesh

Birla, Shri Om

[@] Voted through slip.

Bohra, Shri Ramcharan

[@]Brahmpura, Shri Ranjit Singh

Chakravarty, Shrimati Bijoya

Chand, Shri Nihal

Chandel, Kunwar Pushpendra Singh

Chandrakasi, Shri M.

Chandumajra, Shri Prem Singh

Chaudhary, Shri C. R.

Chaudhary, Shri Haribhai

Chaudhary, Shri P.P.

Chaudhary, Shri Pankaj

Chaudhary, Shri Ram Tahal

Chauhan, Shri Devusinh

Chauhan, Shri P. P.

Chhewang, Shri Thupstan

[$]Chhotelal, Shri

Chinnaiyan, Shri S. Selvakumara

Choubey, Shri Ashwini Kumar

Choudhary, Col. Sonaram

$Choudhary, Shri Babulal

Choudhary, Shri Birendra Kumar

Chouhan, Shri Nandkumar Singh

Chudasama, Shri Rajeshbhai

Danve, Shri Raosaheb Patil

Dattatreya, Shri Bandaru

Deka, Shri Ramen

Devi, Shrimati Rama

[@] Voted through slip.
[$] Corrected through slip for Noes.

Dharambir, Shri

Dhotre, Shri Sanjay

Dhurve, Shrimati Jyoti

Diwakar, Shri Rajesh Kumar

Dubey, Shri Nishikant

Dubey, Shri Satish Chandra

Dwivedi, Shri Harishchandra alias Harish

Elumalai, Shri V.

Fatepara, Shri Devjibhai G.

Gaddigoudar, Shri P.C.

Gadkari, Shri Nitin

Gaikwad, Dr. Sunil Baliram

Galla, Shri Jayadev

Gandhi, Shri Dilipkumar Mansukhlal

Gandhi, Shrimati Maneka Sanjay

Gangwar, Shri Santosh Kumar

@Gautam, Shri Satish Kumar

Gavit, Dr. Heena Vijaykumar

Ghubaya, Shri Sher Singh

Giluwa, Shri Laxman

Girri, Shri Maheish

Gohain, Shri Rajen

Gopal, Dr. K.

@Gopalakrishnan, Shri C.

Gopalakrishnan, Shri R.

@Goud, Dr. Boora Narsaiah

Gowda, Shri D.V. Sadananda

Gupta, Shri Shyama Charan

@ Voted through slip.

Gurjar, Shri Krishanpal

Hari, Shri G.

Haribabu, Dr. Kambhampati

Hegde, Shri Anantkumar

Hemamalini, Shrimati

Jaiswal, Dr. Sanjay

Jardosh, Shrimati Darshana Vikram

Jat, Prof. Sanwar Lal

Jaunapuria, Shri Sukhbir Singh

Jigajinagi, Shri Ramesh

Joshi, Dr. Murli Manohar

Joshi, Shri Pralhad

Jyoti, Sadhvi Niranjan

Kachhadia, Shri Naranbhai

Kaiser, Choudhary Mehboob Ali

[@]Kalvakuntla, Shrimati kavitha

Kamaraj, Dr. K.

Karandlaje, Kumari Shobha

Kashyap, Shri Virender

Kaswan, Shri Rahul

Kataria, Shri Rattan Lal

Kateel, Shri Nalin Kumar

Katheria, Dr. Ramshankar

Kaushik, Shri Ramesh Chander

Khadse, Shrimati Rakshatai

Khanduri AVSM, Maj. Gen. (Retd.) B.C.

Khanna, Shri Vinod

Kher, Shrimati Kirron

[@] Voted through slip.

Khuba, Shri Bhagwanth

Kinjarapu, Shri Ram Mohan Naidu

Kishore, Shri Jugal

Kishore, Shri Kaushal

Koli, Shri Bahadur Singh

Koshyari, Shri Bhagat Singh

@Kristappa, Shri N.

@Kulaste, Shri Faggan Singh

Kumar, Dr. Arun

Kumar, Dr. Virendra

Kumar, Kunwar Sarvesh

$Kumar, Shri Ashwini

Kumar, Shri B. Vinod

Kumar, Shri Dharmendra

Kumar, Shri K. Ashok

Kumar, Shri P.

Kumar, Shri Shanta

Kundariya, Shri Mohanbhai Kalyanjibhai

Kushawaha, Shri Ravinder

Kushwaha, Shri Upendra

Lakhanpal, Shri Raghav

Lekhi, Shrimati Meenakashi

Maadam, Shrimati Poonamben

Maharaj, Dr. Swami Sakshiji

Mahato, Dr. Banshilal

Mahato, Shri Bidyut Baran

Mahendran, Shri C.

@ Voted through slip.
$ Corrected through slip for Noes.

Malviya, Prof. Chintamani

Manjhi, Shri Hari

Marabi, Shri Kamal Bhan Singh

Maragatham, Shrimati K.

@Marutharajaa, Shri R. P.

Maurya, Shri Keshav Prasad

Meena, Shri Arjun Lal

Meena, Shri Harish

Meghwal, Shri Arjun Ram

Mishra, Shri Anoop

Mishra, Shri Bhairon Prasad

Mishra, Shri Daddan

Mishra, Shri Janardan

Mishra, Shri Kalraj

Mohan, Shri M. Murli

Mohan, Shri P.C.

Munda, Shri Karia

Nagar, Shri Rodmal

@Nagarajan, Shri P.

Nagesh, Shri Godam

Narasimham, Shri Thota

Nath, Shri Chand

Natterjee, Shri J.J.T.

Nete, Shri Ashok Mahadeorao

Nishad, Shri Ajay

Nishad, Shri Ram Charitra

Nishank, Dr. Ramesh Pokhriyal

@ Voted through slip.

Oram, Shri Jual

Paatle, Shrimati Kamla

Pal, Shri Jagdambika

Pandey, Dr. Mahendra Nath

Pandey, Shri Hari Om

Pandey, Shri Rajesh

Pandey, Shri Ravindra Kumar

Panneerselvam, Shri V.

Parasuraman, Shri K.

Parthipan, Shri R.

Paswan, Shri Chhedi

Paswan, Shri Chirag

Paswan, Shri Ramvilas

Patel, Dr. K. C.

Patel, Shri Devji M.

Patel, Shri Dilip

Patel, Shri Lalubhai Babubhai

Patel, Shri Natubhai Gomanbhai

Patel, Shri Prahlad Singh

Patel, Shri Subhash

Patel, Shrimati Jayshreeben

Pathak, Shrimati Riti

Patil, Shri A.T. Nana

Patil, Shri C. R.

[@]Patil, Shri Kapil Moreshwar

Patil, Shri Sanjay Kaka

Patole, Shri Nana

Phule, Sadhvi Savitri Bai

[@] Voted through slip.

Prabakaran, Shri K. R. P.

Prasad, Dr. Bhagirath

Pratap, Shri Krishan

Radhakrishnan, Shri Pon

Radhakrishnan, Shri R.

@Radhakrishnan, Shri T.

Rai, Shri Nityanand

Raj, Dr. Udit

Raj, Shrimati Krishna

Raajhaa, Shri A. Anwhar

Rajbhar, Shri Harinarayan

Rajendran, Shri S.

Rajoria, Dr. Manoj

Rajput, Shri Mukesh

Raju, Shri Ashok Gajapathi

Raju, Shri Gokaraju Ganga

Ram, Shri Janak

Ram, Shri Vishnu Dayal

Ramachandran, Shri K. N.

Rao, Shri Konakalla Narayana

Rao (Avanthi), Shri Muthamsetti Srinivasa

Rao, Shri Rayapati Sambasiva

Rathod, Shri D.S.

Rathore, Col. Rajyavardhan

Rathore, Shri Hariom Singh

Rathwa, Shri Ramsinh

Raval, Shri Paresh

Rawat, Shrimati Priyanka Singh

@ Voted through slip.

Ray, Shri Bishnu Pada

Ray, Shri Ravindra Kumar

Reddy, Shri A.P. Jithender

[$]Reddy, Shri J.C. Divakar

Rijiju, Shri Kiren

Rudy, Shri Rajiv Pratap

Sahu, Shri Chandulal

Sahu, Shri Lakhan Lal

[@]Sai, Shri Vishnu Dev

Saini, Shri Rajkumar

Sampla, Shri Vijay

Sangma, Shri Purno Agitok

Sanjar, Shri Alok

Sarmah, Shri Ram Prasad

Sarswati, Shri Sumedhanand

Sathyabama, Shrimati V.

Sawaikar, Adv. Narendra Keshav

Senguttuvan, Shri B.

Senthilnathan, Shri P. R.

Shah, Shrimati Mala Rajyalakshmi

Sharma, Dr. Mahesh

Sharma, Shri Ram Swaroop

Shekhawat, Shri Gajendra Singh

Shetty, Shri Gopal

Shirole, Shri Anil

Shyal, Dr. Bhartiben D.

Siddeshwara, Shri G. M.

[$] Corrected through slip for Noes.
[@] Voted through slip.

Sigriwal, Shri Janardan Singh

Simha, Shri Pratap

Singh, Dr. Bhola

Singh, Dr. Jitendra

Singh, Dr. Nepal

Singh, Dr. Satya Pal

Singh, Dr. Yashwant

Singh, Gen. (Retd) Vijay Kumar

Singh, Kunwar Bharatendra

Singh, Rao Inderjit

Singh, Shri Abhishek

Singh, Shri Bharat

Singh, Shri Bhola

[@]Singh, Shri Brijbhushan Sharan

Singh, Shri Dushyant

Singh, Shri Giriraj

Singh, Shri Hukum

Singh, Shri Kirti Vardhan

Singh, Shri Lallu

Singh, Shri Nagendra

Singh, Shri Pashupati Nath

Singh, Shri R. K.

Singh, Shri Rajnath

Singh (Raju Bhaiya), Shri Rajveer

Singh, Shri Rakesh

Singh, Shri Satyapal

Singh, Shri Sunil Kumar

Singh, Shri Sushil Kumar

[@] Voted through slip.

Singh, Shri Uday Pratap

Singh, Shri Virendra

Sinha, Shri Jayant

Sinha, Shri Manoj

Solanki, Dr. Kirit P.

Somaiya, Dr. Kirit

Sonkar, Shri Vinod Kumar

Sonker, Shrimati Neelam

Sonowal, Shri Sarbananda

$Srinivas, Shri Kesineni

Sriramulu, Shri B.

Sundaram, Shri P. R.

Swaraj, Shrimati Sushma

Tadas, Shri Ramdas C.

Tamta, Shri Ajay

Tanwar, Shri Kanwar Singh

Tasa, Shri Kamakhya Prasad

Teli, Shri Rameshwar

Teni, Shri Ajay Misra

Thakur, Shri Anurag Singh

Thambidurai, Dr. M.

Tiwari, Shri Manoj

Tripathi, Shri Sharad

Udasi, Shri Shivkumar

Udhayakumar, Shri M.

Usendi, Shri Vikram

@Vanaroja, Shrimati R.

$ Corrected through slip for Noes.
@ Voted through slip.

Vardhan, Dr. Harsh

@Vasanthi, Shrimati M.

Vasava, Shri Parbhubhai Nagarbhai

Venugopal, Dr. P.

Verma, Dr. Anshul

Verma, Shri Bhanu Pratap Singh

@Verma, Shri Parvesh Sahib Singh

Verma, Shri Rajesh

Verma, Shrimati Rekha

Vijaya Kumar, Shri S. R.

@Wanga, Shri Chintaman Navasha

Yadav, Shri Hukmdeo Narayan

Yadav, Shri Laxmi Narayan

Yadav, Shri Om Prakash

Yadav, Shri Ram Kripal

Yediyurappa, Shri B.S.

@ Voted through slip.

ABSTAIN

Adsul, Shri Anandrao

Barne, Shri Shrirang Appa

[@]Gaikwad, Prof. Ravindra Vishwanath

Gawali, Shrimati Bhavana Pundalikrao

Geete, Shri Anant Gangaram

Godse, Shri Hemant Tukaram

Jadhav, Shri Prataprao

Jadhav, Shri Sanjay Haribhau

@Khaire, Shri Chandrakant

Kirtikar, Shri Gajanan

Lokhande, Shri Sadashiv

Raut, Shri Vinayak Bhaurao

Sawant, Shri Arvind

Shewale, Shri Rahul

Shinde, Dr. Shrikant Eknath

Shivajirao, Shri Adhalrao Patil

Vichare, Shri Rajan

[@] Voted through slip.

HON. SPEAKER: Subject to correction*, the result of the Division is:

Ayes: 99

Noes: 294

Abstain:15

The motion was negatived.

HON. SPEAKER: Now, the question is:

"That the Bill further to amend the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013, be taken into consideration."

The motion was adopted.

---

* The following Members also recorded/corrected their votes through slips:

Ayes: 099 + S/Shri Sisir Kumar Adhikari, Ashok Shankarrao Chavan, Adhir Ranjan Chowdhury, Deepender Singh Hooda, Innocent, Saumitra Khan, C.S. Putta Raju, Dr. A Sampath, Prof. K.V. Thomas, S/Shri Taslim Uddin, Tej Pratap Singh Yadav, Shrimati Dimple Yadav - S/Shri Chhotelal, Babulal Choudhary, Ashwini Kumar, J.C. Divakar Reddy, Kesineni Srinivas = **106**

Noes: 294 + Yogi Adityanath, S/Shri Ramesh Bidhuri, Ranjit Singh Brahmpura, Chhotelal, Babulal Choudhary, Satish Kumar Gautam, C. Gopalakrishnan, Dr. Boora Narsaiah Goud, Shrimati Kavitha Kalvakuntla, S/Shri Faggan Singh Kulaste, Ashwini Kumar, N. Kristappa, R.P. Marutharaja, P. Nagarajan, Kapil Moreshwar Patil, T. Radhakrishnan, J.C. Divakar Reddy, Vishnu Dev Sai, S/Shri Brijbhushan Sharan Singh, Kesineni Srinivas, Shrimati R. Vanaroja, Shrimati M. Vasanthi, S/Shri Pravesh Sahib Singh Verma, Chintaman Navasha Wanga = **318**

Abstain: 015 + Prof. Ravindra Vishwanath Gaikwad, Shri Chandrakant Khaire **=017**

HON. SPEAKER: Hon. Members, before we take up clause by clause consideration of the Bill, I would like to inform the House that Shri N.K. Premachandran has requested to allow him to raise objections to the moving of Government motion Nos. 61 and 62 for suspension of rule 80(i).

An amendment can be proposed only to some existing clause of a Bill. Government amendment Nos. 58 and 59 are not amending any clauses of the Bill. These two amendments seek to add new clauses 6A and 7A to the Bill which amounts to increasing the scope of the Bill. Therefore, amendment Nos. 58 and 59 can be moved only after suspension of rule 80(i).

In view of this, there is no point in raising objection to the moving of the motions by the hon. Minister.

HON. SPEAKER: Now we take up clause by clause consideration of the Bill. Now Clause 2.

Clause 2 Substitution of certain expression throughout Act

HON. SPEAKER: Shri Jai Prakash Narayan Yadav, are you moving your Amendment No. 7 to Clause 2?

… (*Interruptions*)

श्री जय प्रकाश नारायण यादव (बाँका) : हां, अध्यक्ष महोदया, जो बिल आया है और जिस पर मत विभाजन हो रहा है, सारा मुल्क जान रहा है कि यह बिल किसान विरोधी है, जन विरोधी है। किसान की आत्मा को निकाला जा रहा है। मैं प्रस्ताव करता हूं:

"पृष्ठ 2, पंक्ति 3,

शब्द 'प्राइवेट इकाई' के स्थान पर

शब्द 'सरकारी एकक' प्रतिस्थापित किया जाए।" (7)

The Amendment was put and negatived.

HON. SPEAKER: The question is:

"That clause 2 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 2 was added to the Bill.

Clause 3 Amendment of Section 2

HON. SPEAKER: Now, hon. Minister may move Amendment No. 52 to Clause 3.

… (*Interruptions*)

SHRI JYOTIRADITYA M. SCINDIA: Madam, I am on a point of order. … (*Interruptions*)

Rule 79 (1) very clearly says:

"If notice of an amendment to a clause or schedule of the Bill has not been given one day before that day on which the Bill is to be considered, any Member may object to the moving of such an

amendment, and such objection shall prevail, unless the Speaker allows the amendment to be moved:"

We will object to this amendment being moved. … (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: I have allowed.

… (*Interruptions*)

SHRI JYOTIRADITYA M. SCINDIA: Madam, no notice has been given. It has been circulated today. अध्यक्ष महोदया, अगर इस तरीके से प्रजातंत्र चलेगा तो किस आधार पर...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: I have allowed it. The Minister may now move Amendment No. 52 to Clause 3.

Amendment made:

"Page 1, *omit* lines 10 and 11." (52)

(Shri Chaudhary Birender Singh)

HON. SPEAKER: Professor Saugata Roy, are you moving your Amendment?

PROF. SAUGATA ROY (DUM DUM): Madam, my amendment relates to what is known as the consent clause. The Bill mentions it in sub-section 2 of section 2. After the second proviso, the following proviso shall be inserted, namely, provided also that the acquisition of land for the projects listed in section 10(a) and purposes specified thereon shall be exempted from the provisions of the first proviso … (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: You cannot speak now. Are you moving the amendment?

… (*Interruptions*)

PROF. SAUGATA ROY: Madam, I have not spoken on the Bill. Allow me to speak for one minute on this. This is the only amendment on which I will speak. Please allow me for two minutes. … (*Interruptions*)

This relates to the consent clause. Actually, in the 2013 Bill, for the first time in 112 years, the farmer was given respect in the sense that if the Government

acquired land for a private company. The consent of 80 percent of the farmers was needed; and if it was a PPP, 70 per cent of the consent was needed. Even at that time, we had objected to it because according to us in the Trinamool Congress, 100 per cent consent is required. … (*Interruptions*)

We fought on this issue in Singur where land was acquired for Tatas forcibly. We objected to it in Nandigram where 14 of our people were killed in police firing. Now, in one stroke, they are removing that consent clause. We are opposing with all our might. … (*Interruptions*) You are taking away the dignity of the farmer. How can you take the farmers' land without their consent?

Madam, he was asking for the suggestions. My suggestion is, do whatever you want but give respect and dignity to the farmers. Do not take away his land without his consent. Suddenly you decide that for such and such private company, Ambani or Adani, you will acquire land and then overnight that land will be taken away. The farmer will be left with nothing.… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: So, are you moving it?

प्रो. सौगत राय: आप लोग दिल्ली में हार गया तब भी शर्म नहीं आता है, मेरे साथ चिल्लाते हैं, ...(व्यवधान) मेरे साथ आओ लड़ो, किसान के खिलाफ किसी भी कदम का तृणमूल कांग्रेस विरोध करेगी। मैं चाहता हूं कि पूरा देश इस विरोध को देखे। ...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Prof. Saugata Roy ji, are you moving your Amendment No.3 to clause 3?

… (*Interruptions*)

PROF. SAUGATA ROY: Madam, I am moving my Amendment No.3 to clause 3.

I beg to move:

"Page 2, *omit* lines 1 to 5." (3)

HON. SPEAKER: I shall now put Amendment No.3 to clause 3 moved by Prof. Saugata Roy to the vote of the House.

PROF. SAUGATA ROY: Madam, I want Division.

HON. SPEAKER: The Lobbies have already been cleared. नियम भी सभी को मालूम है उसे बताने की जरूरत नहीं है।

The question is:

"Page 2, *omit* lines 1 to 5. "

The Lok Sabha divided:

DIVISION NO. 1 **AYES** **18.52 hrs.**

@Adhikari, Shri Sisir Kumar

Adhikari, Shri Suvendu

@Ahmed, Shri Sultan

@Antony, Shri Anto

Anwar, Shri Tariq

Baite, Shri Thangso

Banerjee, Shri Abhishek

Banerjee, Shri Kalyan

Banerjee, Shri Prasun

Barman, Shri Bijoy Chandra

Bhonsale, Shri Chh. Udayanraje

Biju, Shri P. K.

Bose, Prof. Sugata

Chandrappa, Shri B. N.

Chaudhury, Shri Jitendra

Chautala, Shri Dushyant

Chavan, Shri Ashok Shankarrao

Chowdhury, Shri A. H. khan

@Chowdhury, Shri Adhir Ranjan

Dastidar, Dr. Kakoli Ghosh

Datta, Shri Sankar Prasad

De(Nag), Dr. Ratna

Dev, Kumari Sushmita

@Devegowda, Shri H.D.

Engti, Shri Biren Singh

Faizal, Mohammed

@ Voted through slip.

[@]Geetha, Shrimati Kothapalli

George, Adv. Joice

Ghosh, Shrimati Arpita

Gogoi, Shri Gaurav

Gowda, Shri S.P. Muddahanume

Hansdak, Shri Vijay Kumar

Haque, Shri Mohd. Asrarul

Hazra, Dr. Anupam

Hooda, Shri Deepender Singh

@Innocent, Shri

Jatua, Shri Choudhury Mohan

Jayadevan, Shri C. N

Kalvakuntla, Shrimati kavitha

Karunakaran, Shri P.

Khan, Shri Saumitra

@Kharge, Shri Mallikarjun

Kumar, Shri Kaushalendra

Kumar, Shri Santosh

Kumar, Shri Shailesh

Mahato, Dr. Mriganka

Mandal, Dr. Tapas

Mann, Shri Bhagwant

Meinya, Dr. Thokchom

Moily, Shri M. Veerappa

Mondal, Shri Sunil Kumar

Mondal, Shrimati Pratima

Mukherjee, Shri Abhijit

Muniyappa, Shri K.H.

[@] Voted through slip.

[@]Nagesh, Shri Godam

Naik, Prof. A.S.R.

Naik, Shri B.V.

Nath, Shri Kamal

Noor, Shrimati Mausam

Owaisi, Shri Asaduddin

Pala, Shri Vincent H.

Poddar, Shrimati Aparupa

Premachandran, Shri N.K.

Rajesh, Shri M. B.

Raju, Shri C.S. Putta

Ramachandran, Shri Mullappally

Ranjan, Shri Rajesh

Ranjan, Shrimati Ranjeet

Reddy, Shri Gutha Sukender

Reddy, Shri Mekapati Raja Mohan

Reddy, Shri P. Srinivasa

Reddy, Shri Y. V. Subba

Renuka, Shrimati Butta

Roy, Prof. Saugata

Roy, Shrimati Sandhya

Ruala, Shri C.L.

Sahu, Shri Tamradhwaj

Sampath, Dr. A.

Sanghamita, Dr. Mamtaz

Saren, Dr. Uma

Satav, Shri Rajeev

Scindia, Shri Jyotiraditya M.

[@] Voted through slip.

Shetty, Shri Raju

@Singh, Kunwar Haribansh

@Singh, Prof. Sadhu

Singh, Shri Ravneet

Sinha, Shrimati Renuka

Sule, Shrimati Supriya

Suresh, Shri D.K.

Suresh, Shri Kodikunnil

Teacher, Shrimati P.K. Shreemathi

Thakur, Shrimati Mamata

Tharoor, Dr. Shashi

Thomas, Prof. K.V.

Tirkey, Shri Dasrath

Trivedi, Shri Dinesh

Uddin, Shri Tasleem

Varma, Shrimati Dev

Venugopal, Shri K. C.

Yadav, Shri Akshay

Yadav, Shri Dharmendra

Yadav, Shri Jai Prakash Narayan

Yadav, Shri Tej Pratap Singh

Yadav, Shrimati Dimple

Yellaiah, Shri Nandi

@ Voted through slip.

NOES

@Adityanath, Yogi

Advani, Shri L.K.

Ahir, Shri Hansraj Gangaram

Ahlawat, Shrimati Santosh

@Ahluwalia, Shri S.S.

Amarappa , Shri Karadi Sanganna

Ananthkumar, Shri

Angadi, Shri Suresh C.

Arunmozhithevan, Shri A.

Azad, Shri Kirti

Babu, Dr. Ravindra

Badal, Shrimati Harsimrat Kaur

Baheria, Shri Subhash Chandra

Bais, Shri Ramesh

Bala, Shrimati Anju

Balyan, Dr. Sanjeev

Bansode, Adv. Sharadkumar Maruti

Bhabhor, Shri Jasvantsinh Sumanbhai

Bhagat, Shri Sudarshan

Bhamre, Dr. Subhash Ramrao

Bharathi Mohan, Shri R.K.

Bharti, Sushri Uma

Bhatt, Shrimati Ranjanben

Bhole, Shri Devendra Singh

Bhuria, Shri Dileep Singh

Bidhuri, Shri Ramesh

Birla, Shri Om

@ Voted through slip.

Bohra, Shri Ramcharan

Brahmpura, Shri Ranjit Singh

Chakravarty, Shrimati Bijoya

Chand, Shri Nihal

Chandel, Kunwar Pushpendra Singh

Chandrakasi, Shri M.

Chandumajra, Shri Prem Singh

Chaudhary, Shri Haribhai

Chaudhary, Shri P.P.

Chaudhary, Shri Pankaj

Chaudhary, Shri Ram Tahal

Chauhan, Shri Devusinh

@Chauhan, Shri P. P.

Chhewang, Shri Thupstan

Chhotelal, Shri

Chinnaiyan, Shri S. Selvakumara

Choubey, Shri Ashwini Kumar

Choudhary, Col. Sonaram

Choudhary, Shri Babulal

Choudhary, Shri Birendra Kumar

Chouhan, Shri Nandkumar Singh

Chudasama, Shri Rajeshbhai

Danve, Shri Raosaheb Patil

Dattatreya, Shri Bandaru

Deka, Shri Ramen

Devi, Shrimati Rama

Dharambir, Shri

Dhotre, Shri Sanjay

@ Voted through slip.

Dhurve, Shrimati Jyoti

Diwakar, Shri Rajesh Kumar

Dubey, Shri Nishikant

Dubey, Shri Satish Chandra

Dwivedi, Shri Harishchandra alias Harish

Elumalai, Shri V.

Fatepara, Shri Devjibhai G.

Gaddigoudar, Shri P.C.

@Gadkari, Shri Nitin

Gaikwad, Dr. Sunil Baliram

Galla, Shri Jayadev

Gandhi, Shri Dilipkumar Mansukhlal

@Gandhi, Shrimati Maneka Sanjay

Gangwar, Shri Santosh Kumar

Gautam, Shri Satish Kumar

Gavit, Dr. Heena Vijaykumar

Giluwa, Shri Laxman

Girri, Shri Maheish

Gohain, Shri Rajen

Gopal, Dr. K.

Gopalakrishnan, Shri C.

Gopalakrishnan, Shri R.

@Goud, Dr. Boora Narsaiah

Gowda, Shri D.V. Sadananda

Gupta, Shri Shyama Charan

Gurjar, Shri Krishanpal

Hari, Shri G.

Haribabu, Dr. Kambhampati

@ Voted through slip.

Hegde, Shri Anantkumar

Hemamalini, Shrimati

Jaiswal, Dr. Sanjay

Jardosh, Shrimati Darshana Vikram

Jat, Prof. Sanwar Lal

Jaunapuria, Shri Sukhbir Singh

Jayavardhan, Dr. J.

Jigajinagi, Shri Ramesh

Joshi, Dr. Murli Manohar

Joshi, Shri Pralhad

Jyoti, Sadhvi Niranjan

Kachhadia, Shri Naranbhai

Kaiser, Choudhary Mehboob Ali

Kamaraj, Dr. K.

Karandlaje, Kumari Shobha

Kashyap, Shri Virender

Kaswan, Shri Rahul

Kataria, Shri Rattan Lal

Kateel, Shri Nalin Kumar

[$]Katheria, Dr. Ramshankar

Kaushik, Shri Ramesh Chander

Khadse, Shrimati Rakshatai

Khanduri AVSM, Maj. Gen. (Retd.) B.C.

Khanna, Shri Vinod

Kher, Shrimati Kirron

Khuba, Shri Bhagwanth

Kinjarapu, Shri Ram Mohan Naidu

Kishore, Shri Jugal

[$] Corrected through slip for Noes.

Kishore, Shri Kaushal

Koli, Shri Bahadur Singh

Koshyari, Shri Bhagat Singh

@Kristappa, Shri N.

Kulaste, Shri Faggan Singh

Kumar, Dr. Arun

Kumar, Dr. Virendra

Kumar, Kunwar Sarvesh

Kumar, Shri Ashwini

Kumar, Shri Dharmendra

Kumar, Shri K. Ashok

Kumar, Shri P.

Kumar, Shri Shanta

Kundariya, Shri Mohanbhai Kalyanjibhai

Kushawaha, Shri Ravinder

Kushwaha, Shri Upendra

Lakhanpal, Shri Raghav

Lekhi, Shrimati Meenakashi

Maadam, Shrimati Poonamben

Maharaj, Dr. Swami Sakshiji

Mahato, Dr. Banshilal

Mahato, Shri Bidyut Baran

@Mahendran, Shri C.

Malviya, Prof. Chintamani

Manjhi, Shri Hari

Marabi, Shri Kamal Bhan Singh

Maragatham, Shrimati K.

Marutharajaa, Shri R. P.

@ Voted through slip.

Maurya, Shri Keshav Prasad

Meena, Shri Arjun Lal

Meena, Shri Harish

Meghwal, Shri Arjun Ram

Mishra, Shri Anoop

Mishra, Shri Bhairon Prasad

@Mishra, Shri Daddan

Mishra, Shri Janardan

Mishra, Shri Kalraj

Mohan, Shri M. Murli

Mohan, Shri P.C.

Munda, Shri Karia

Nagar, Shri Rodmal

@Nagarajan, Shri P.

Narasimham, Shri Thota

Nath, Shri Chand

Natterjee, Shri J.J.T.

@Nete, Shri Ashok Mahadeorao

Nishad, Shri Ajay

Nishad, Shri Ram Charitra

Nishank, Dr. Ramesh Pokhriyal

@Oram, Shri Jual

Paatle, Shrimati Kamla

Pal, Shri Jagdambika

Pandey, Dr. Mahendra Nath

Pandey, Shri Hari Om

Pandey, Shri Rajesh

Pandey, Shri Ravindra Kumar

@ Voted through slip.

[@]Panneerselvam, Shri V.

Parasuraman, Shri K.

Parthipan, Shri R.

Paswan, Shri Chhedi

@Paswan, Shri Chirag

Paswan, Shri Ram Chandra

Paswan, Shri Ramvilas

Patel, Dr. K. C.

Patel, Shri Devji M.

Patel, Shri Dilip

Patel, Shri Lalubhai Babubhai

Patel, Shri Natubhai Gomanbhai

Patel, Shri Prahlad Singh

Patel, Shri Subhash

Patel, Shrimati Anupriya

Patel, Shrimati Jayshreeben

Pathak, Shrimati Riti

Patil, Shri A.T. Nana

Patil, Shri C. R.

Patil, Shri Kapil Moreshwar

@Patil, Shri Sanjay Kaka

Patole, Shri Nana

Phule, Sadhvi Savitri Bai

Prabakaran, Shri K. R. P.

Prasad, Dr. Bhagirath

Pratap, Shri Krishan

Radhakrishnan, Shri Pon

Radhakrishnan, Shri R.

[@] Voted through slip.

@Radhakrishnan, Shri T.

Rai, Shri Nityanand

Raj, Dr. Udit

Raj, Shrimati Krishna

Raajhaa, Shri A. Anwhar

@Rajbhar, Shri Harinarayan

Rajendran, Shri S.

Rajoria, Dr. Manoj

Rajput, Shri Mukesh

Raju, Shri Ashok Gajapathi

@Raju, Shri Gokaraju Ganga

Ram, Shri Janak

Ram, Shri Vishnu Dayal

Ramachandran, Shri K. N.

Rao, Shri Konakalla Narayana

Rao (Avanthi), Shri Muthamsetti Srinivasa

Rao, Shri Rayapati Sambasiva

Rathod, Shri D.S.

Rathore, Col. Rajyavardhan

Rathore, Shri Hariom Singh

Rathwa, Shri Ramsinh

Raval, Shri Paresh

Rawat, Shrimati Priyanka Singh

Ray, Shri Bishnu Pada

Ray, Shri Ravindra Kumar

Reddy, Shri J.C. Divakar

Rijiju, Shri Kiren

Rori, Shri Charanjeet Singh

@ Voted through slip.

Rudy, Shri Rajiv Pratap

Sahu, Shri Chandulal

Sahu, Shri Lakhan Lal

Sai, Shri Vishnu Dev

Saini, Shri Rajkumar

Sampla, Shri Vijay

Sangma, Shri Purno Agitok

Sanjar, Shri Alok

Sarmah, Shri Ram Prasad

Sarswati, Shri Sumedhanand

Sathyabama, Shrimati V.

Sawaikar, Adv. Narendra Keshav

Senguttuvan, Shri B.

Senthilnathan, Shri P. R.

Shah, Shrimati Mala Rajyalakshmi

[@]Sharma, Dr. Mahesh

Sharma, Shri Ram Swaroop

Shekhawat, Shri Gajendra Singh

Shetty, Shri Gopal

Shirole, Shri Anil

Shyal, Dr. Bhartiben D.

Siddeshwara, Shri G. M.

Sigriwal, Shri Janardan Singh

Simha, Shri Pratap

Singh, Dr. Bhola

Singh, Dr. Jitendra

Singh, Dr. Nepal

Singh, Dr. Satya Pal

[@] Voted through slip.

Singh, Dr. Yashwant

Singh, Gen. (Retd) Vijay Kumar

Singh, Kunwar Bharatendra

Singh, Rao Inderjit

Singh, Shri Abhishek

Singh, Shri Bharat

Singh, Shri Bhola

Singh, Shri Brijbhushan Sharan

Singh, Shri Dushyant

Singh, Shri Giriraj

Singh, Shri Hukum

Singh, Shri Kirti Vardhan

Singh, Shri Lallu

Singh, Shri Nagendra

Singh, Shri Pashupati Nath

Singh, Shri R. K.

Singh, Shri Rajnath

Singh (Raju Bhaiya), Shri Rajveer

Singh, Shri Rakesh

Singh, Shri Satyapal

Singh, Shri Sunil Kumar

Singh, Shri Sushil Kumar

Singh, Shri Uday Pratap

Singh, Shri Virendra

Sinha, Shri Jayant

Sinha, Shri Manoj

Solanki, Dr. Kirit P.

Somaiya, Dr. Kirit

Sonkar, Shri Vinod Kumar

Sonker, Shrimati Neelam

Sonowal, Shri Sarbananda

Srinivas, Shri Kesineni

Sriram, Shri Malyadri

@Sriramulu, Shri B.

Sundaram, Shri P. R.

Swaraj, Shrimati Sushma

Tadas, Shri Ramdas C.

Tamta, Shri Ajay

Tanwar, Shri Kanwar Singh

Tasa, Shri Kamakhya Prasad

Teli, Shri Rameshwar

Teni, Shri Ajay Misra

Thakur, Shri Anurag Singh

Thambidurai, Dr. M.

Tiwari, Shri Manoj

Tripathi, Shri Sharad

Udasi, Shri Shivkumar

Udhayakumar, Shri M.

Usendi, Shri Vikram

Vanaroja, Shrimati R.

Vardhan, Dr. Harsh

Vasanthi, Shrimati M.

Vasava, Shri Parbhubhai Nagarbhai

Venugopal, Dr. P.

Verma, Dr. Anshul

Verma, Shri Bhanu Pratap Singh

Verma, Shri Parvesh Sahib Singh

@ Voted through slip.

Verma, Shri Rajesh

Verma, Shrimati Rekha

Vijaya Kumar, Shri S. R.

Wanga, Shri Chintaman Navasha

Yadav, Shri Hukmdeo Narayan

Yadav, Shri Laxmi Narayan

Yadav, Shri Om Prakash

Yadav, Shri Ram Kripal

Yediyurappa, Shri B.S.

ABSTAIN

Adsul, Shri Anandrao

Barne, Shri Shrirang Appa

Gaikwad, Prof. Ravindra Vishwanath

Gawali, Shrimati Bhavana Pundalikrao

Geete, Shri Anant Gangaram

Godse, Shri Hemant Tukaram

Jadhav, Shri Prataprao

Jadhav, Shri Sanjay Haribhau

Khaire, Shri Chandrakant

Kirtikar, Shri Gajanan

Lokhande, Shri Sadashiv

Raut, Shri Vinayak Bhaurao

Sawant, Shri Arvind

Shewale, Shri Rahul

Shinde, Dr. Shrikant Eknath

Shivajirao, Shri Adhalrao Patil

Vichare, Shri Rajan

HON. SPEAKER: Subject to correction*, the result of the Division is:

Ayes: 094

Noes: 296

Abstain:17

The motion was negatived.

HON. SPEAKER: Shri N.K. Premachandran to move Amendment No.18 to clause 3.

SHRI N.K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Madam, I am here.

HON. SPEAKER: I know, every day you sit in a wrong seat.

SHRI N.K. PREMACHANDRAN: I sit with your permission, Madam.

Madam, my amendment is in respect of the consent as well as social impact assessment. The hon. Minister was very generous in replying that he is ready to accept those amendments given by the Members from opposition which are acceptable to him. From the Opposition side a number of Members have moved the first amendment but the Government has not accepted it and instead an official amendment has been brought. I am pressing this amendment because this is the heart and soul of the 2013 Act which is being taken away. So, I press for Amendment No.18 to Clause 3.

I beg to move:

---

* The following Members also recorded/corrected their votes through slips:

Ayes: 094+ S/Shri Sisir Adhikari, Anto Antony, Sultan Ahamed, Adhir Ranjan Chowdhury, H.D. Devegowda, Shrimati Kothapalli Geetha, S/Shri Innocent, Mallikarjun Kharge, Godam Nagesh, Kunwar Haribansh Singh, Prof. Sadhu Singh = **105**

Noes: 296 + Yogi Adityanath, S/Shri S.S. Ahluwalia, P.P. Chauhan, Nitin Gadkari, Shrimati Maneka Sanjay Gandhi, Dr. Boora Narsaiah Goud, Dr. Ramshankar Katheria, S/Shri N. Kristappa, C. Mahendran, Daddan Mishra, P. Nagarajan, Ashok Mahadeorao Nete, Jual Oram, V. Panneerselvan, Chirag Paswan, Sanjay Kaka Patil, T. Radhakrishnan, Harinarayan Rajbhar, Gokaraj Ganga Raju, Dr. Mahesh Sharma, Shri B. Sriramulu =**317**

Abstain: 017 + Chandrakant Khaire - Dr. Ramshankar Katheria **= 17**

"Page 1, *for* lines 10 and 11,—

substitute '(i) in sub-section (1), in clause (b) in sub-clause (i) for the words "private hospitals, private educational institutions and", the words "private hospitals, private educational institutions and such other activities of private companies and" shall be substituted.". (18)

HON. SPEAKER: I shall now put Amendment No.18 to clause 3 moved by Shri N.K. Premachandran to the vote of the House.

SHRI N.K. PREMACHANDRAN: Madam, I want Division.

HON. SPEAKER: The question is:

"Page 1, *for* lines 10 and 11,—

substitute '(i) in sub-section (1), in clause (b) in sub-clause (i) for the words "private hospitals, private educational institutions and", the words "private hospitals, private educational institutions and such other activities of private companies and" shall be substituted.'."

The Lok Sabha divided:

DIVISION NO. 2 **AYES** **18.55 hrs.**

Adhikari, Shri Suvendu

Ahmed, Shri Sultan

Ali, Shri Idris

Antony, Shri Anto

Anwar, Shri Tariq

Baite, Shri Thangso

Banerjee, Shri Abhishek

Banerjee, Shri Kalyan

@Banerjee, Shri Prasun

Barman, Shri Bijoy Chandra

Bhonsale, Shri Chh. Udayanraje

Biju, Shri P. K.

Bose, Prof. Sugata

@Chandrappa, Shri B. N.

Chaudhury, Shri Jitendra

Chavan, Shri Ashok Shankarrao

Chowdhury, Shri Adhir Ranjan

Dastidar, Dr. Kakoli Ghosh

Datta, Shri Sankar Prasad

De(Nag), Dr. Ratna

Dev, Kumari Sushmita

@Devegowda, Shri H.D.

Engti, Shri Biren Singh

Faizal, Mohammed

Geetha, Shrimati Kothapalli

George, Adv. Joice

@ Voted through slip.

Ghosh, Shrimati Arpita

Gogoi, Shri Gaurav

Gowda, Shri S.P. Muddahanume

Hansdak, Shri Vijay Kumar

Haque, Shri Mohd. Asrarul

Hazra, Dr. Anupam

Hooda, Shri Deepender Singh

[@]Innocent, Shri

Jatua, Shri Choudhury Mohan

Kalvakuntla, Shrimati kavitha

Karunakaran, Shri P.

Khan, Shri Saumitra

Kharge, Shri Mallikarjun

Kumar, Shri Kaushalendra

Kumar, Shri Santosh

Kumar, Shri Shailesh

Mahato, Dr. Mriganka

Mandal, Dr. Tapas

Mann, Shri Bhagwant

Meinya, Dr. Thokchom

Moily, Shri M. Veerappa

Mondal, Shrimati Pratima

Mukherjee, Shri Abhijit

Muniyappa, Shri K.H.

Nagesh, Shri Godam

Naik, Shri B.V.

Nath, Shri Kamal

[@] Voted through slip.

Owaisi, Shri Asaduddin

Pala, Shri Vincent H.

Poddar, Shrimati Aparupa

Premachandran, Shri N.K.

Rajesh, Shri M. B.

Ramachandran, Shri Mullappally

Ranjan, Shri Rajesh

Ranjan, Shrimati Ranjeet

Reddy, Shri Gutha Sukender

Reddy, Shri Mekapati Raja Mohan

Reddy, Shri P. Srinivasa

Renuka, Shrimati Butta

Roy, Shrimati Sandhya

Ruala, Shri C.L.

Sahu, Shri Tamradhwaj

Sampath, Dr. A.

Sanghamita, Dr. Mamtaz

Saren, Dr. Uma

Satav, Shri Rajeev

Scindia, Shri Jyotiraditya M.

Shetty, Shri Raju

Singh, Prof. Sadhu

Sinha, Shrimati Renuka

Sule, Shrimati Supriya

Suresh, Shri D.K.

Suresh, Shri Kodikunnil

Teacher, Shrimati P.K. Shreemathi

Thakur, Shrimati Mamata

Tharoor, Dr. Shashi

Thomas, Prof. K.V.

Tirkey, Shri Dasrath

Trivedi, Shri Dinesh

@Uddin, Shri Tasleem

Varma, Shrimati Dev

Venugopal, Shri K. C.

Yadav, Shri Akshay

Yadav, Shri Dharmendra

Yadav, Shri Jai Prakash Narayan

Yadav, Shri Tej Pratap Singh

@Yadav, Shrimati Dimple

Yellaiah, Shri Nandi

@ Voted through slip.

NOES

@Adityanath, Yogi

Advani, Shri L.K.

Ahir, Shri Hansraj Gangaram

Ahlawat, Shrimati Santosh

@Ahluwalia, Shri S.S.

Amarappa , Shri Karadi Sanganna

Ananthkumar, Shri

Angadi, Shri Suresh C.

Arunmozhithevan, Shri A.

Azad, Shri Kirti

Babu, Dr. Ravindra

Badal, Shrimati Harsimrat Kaur

Baheria, Shri Subhash Chandra

Bais, Shri Ramesh

Bala, Shrimati Anju

Balyan, Dr. Sanjeev

Bansode, Adv. Sharadkumar Maruti

Bhabhor, Shri Jasvantsinh Sumanbhai

Bhagat, Shri Sudarshan

Bhamre, Dr. Subhash Ramrao

Bharathi Mohan, Shri R.K.

Bharti, Sushri Uma

Bhatt, Shrimati Ranjanben

Bhole, Shri Devendra Singh

Bhuria, Shri Dileep Singh

Bidhuri, Shri Ramesh

Birla, Shri Om

@ Voted through slip.

Bohra, Shri Ramcharan

Brahmpura, Shri Ranjit Singh

Chakravarty, Shrimati Bijoya

Chand, Shri Nihal

Chandel, Kunwar Pushpendra Singh

Chandrakasi, Shri M.

Chandumajra, Shri Prem Singh

Chaudhary, Shri C.R.

Chaudhary, Shri Haribhai

Chaudhary, Shri P.P.

Chaudhary, Shri Pankaj

Chaudhary, Shri Ram Tahal

Chauhan, Shri Devusinh

[@]Chauhan, Shri P. P.

Chhewang, Shri Thupstan

@Chhotelal, Shri

Chinnaiyan, Shri S. Selvakumara

Choubey, Shri Ashwini Kumar

Choudhary, Col. Sonaram

Choudhary, Shri Babulal

Choudhary, Shri Birendra Kumar

Chouhan, Shri Nandkumar Singh

Chudasama, Shri Rajeshbhai

Danve, Shri Raosaheb Patil

Dattatreya, Shri Bandaru

Deka, Shri Ramen

Devi, Shrimati Rama

Dharambir, Shri

[@] Voted through slip.

Dhotre, Shri Sanjay

Dhurve, Shrimati Jyoti

Diwakar, Shri Rajesh Kumar

Dubey, Shri Nishikant

Dubey, Shri Satish Chandra

Dwivedi, Shri Harishchandra alias Harish

@Elumalai, Shri V.

Fatepara, Shri Devjibhai G.

Gaddigoudar, Shri P.C.

@Gadkari, Shri Nitin

Gaikwad, Dr. Sunil Baliram

Galla, Shri Jayadev

Gandhi, Shri Dilipkumar Mansukhlal

Gandhi, Shrimati Maneka Sanjay

Gangwar, Shri Santosh Kumar

Gautam, Shri Satish Kumar

Gavit, Dr. Heena Vijaykumar

Ghubaya, Shri Sher Singh

Giluwa, Shri Laxman

Girri, Shri Maheish

Gohain, Shri Rajen

Gopal, Dr. K.

Gopalakrishnan, Shri C.

Gopalakrishnan, Shri R.

Gowda, Shri D.V. Sadananda

Gupta, Shri Shyama Charan

Gurjar, Shri Krishanpal

Hari, Shri G.

@ Voted through slip.

Haribabu, Dr. Kambhampati

Hegde, Shri Anantkumar

Hemamalini, Shrimati

Jaiswal, Dr. Sanjay

Jardosh, Shrimati Darshana Vikram

Jat, Prof. Sanwar Lal

@Jaunapuria, Shri Sukhbir Singh

Jayavardhan, Dr. J.

Jigajinagi, Shri Ramesh

Joshi, Dr. Murli Manohar

Joshi, Shri Pralhad

Jyoti, Sadhvi Niranjan

Kachhadia, Shri Naranbhai

Kaiser, Choudhary Mehboob Ali

Kamaraj, Dr. K.

Karandlaje, Kumari Shobha

Kashyap, Shri Virender

@Kaswan, Shri Rahul

Kataria, Shri Rattan Lal

Kateel, Shri Nalin Kumar

@Katheria, Dr. Ramshankar

Kaushik, Shri Ramesh Chander

Khadse, Shrimati Rakshatai

Khanduri AVSM, Maj. Gen. (Retd.) B.C.

Khanna, Shri Vinod

Kher, Shrimati Kirron

Khuba, Shri Bhagwanth

Kinjarapu, Shri Ram Mohan Naidu

@ Voted through slip.

Kishore, Shri Jugal

Kishore, Shri Kaushal

Koli, Shri Bahadur Singh

Koshyari, Shri Bhagat Singh

Kristappa, Shri N.

@Kulaste, Shri Faggan Singh

Kumar, Dr. Arun

Kumar, Dr. Virendra

Kumar, Kunwar Sarvesh

Kumar, Shri Ashwini

Kumar, Shri Dharmendra

Kumar, Shri K. Ashok

Kumar, Shri P.

@Kumar, Shri Shanta

Kundariya, Shri Mohanbhai Kalyanjibhai

Kushawaha, Shri Ravinder

Kushwaha, Shri Upendra

Lakhanpal, Shri Raghav

Lekhi, Shrimati Meenakashi

Maadam, Shrimati Poonamben

Maharaj, Dr. Swami Sakshiji

Mahato, Dr. Banshilal

Mahato, Shri Bidyut Baran

Mahendran, Shri C.

Malviya, Prof. Chintamani

Manjhi, Shri Hari

Marabi, Shri Kamal Bhan Singh

Maragatham, Shrimati K.

@ Voted through slip.

Marutharajaa, Shri R. P.

Maurya, Shri Keshav Prasad

Meena, Shri Harish

Meghwal, Shri Arjun Ram

Mishra, Shri Anoop

Mishra, Shri Bhairon Prasad

Mishra, Shri Daddan

Mishra, Shri Janardan

Mishra, Shri Kalraj

Mohan, Shri M. Murli

Mohan, Shri P.C.

@Munda, Shri Karia

Nagar, Shri Rodmal

Nagarajan, Shri P.

Naik, Prof. A.S.R.

Narasimham, Shri Thota

Nath, Shri Chand

Natterjee, Shri J.J.T.

@Nete, Shri Ashok Mahadeorao

Nishad, Shri Ajay

Nishad, Shri Ram Charitra

Nishank, Dr. Ramesh Pokhriyal

Oram, Shri Jual

Paatle, Shrimati Kamla

Pal, Shri Jagdambika

Pandey, Dr. Mahendra Nath

Pandey, Shri Hari Om

Pandey, Shri Rajesh

@ Voted through slip.

Pandey, Shri Ravindra Kumar

Panneerselvam, Shri V.

Parasuraman, Shri K.

Parthipan, Shri R.

Paswan, Shri Chhedi

Paswan, Shri Chirag

Paswan, Shri Ram Chandra

Paswan, Shri Ramvilas

Patel, Dr. K. C.

Patel, Shri Devji M.

Patel, Shri Dilip

Patel, Shri Lalubhai Babubhai

Patel, Shri Natubhai Gomanbhai

Patel, Shri Prahlad Singh

Patel, Shri Subhash

Patel, Shrimati Anupriya

Patel, Shrimati Jayshreeben

Pathak, Shrimati Riti

Patil, Shri A.T. Nana

Patil, Shri C. R.

Patil, Shri Kapil Moreshwar

Patil, Shri Sanjay Kaka

Patole, Shri Nana

Phule, Sadhvi Savitri Bai

Prabakaran, Shri K. R. P.

Prasad, Dr. Bhagirath

Pratap, Shri Krishan

Radhakrishnan, Shri Pon

Radhakrishnan, Shri T.

Rai, Shri Nityanand

Raj, Dr. Udit

@Raj, Shrimati Krishna

Raajhaa, Shri A. Anwhar

Rajbhar, Shri Harinarayan

Rajendran, Shri S.

Rajoria, Dr. Manoj

Rajput, Shri Mukesh

Raju, Shri Ashok Gajapathi

@Raju, Shri Gokaraju Ganga

Ram, Shri Janak

Ram, Shri Vishnu Dayal

Ramachandran, Shri K. N.

Rao, Shri Konakalla Narayana

Rao (Avanthi), Shri Muthamsetti Srinivasa

Rao, Shri Rayapati Sambasiva

Rathod, Shri D.S.

Rathore, Col. Rajyavardhan

Rathore, Shri Hariom Singh

Rathwa, Shri Ramsinh

Raval, Shri Paresh

Rawat, Shrimati Priyanka Singh

$Ray, Shri Bishnu Pada

Ray, Shri Ravindra Kumar

Reddy, Shri J.C. Divakar

Rijiju, Shri Kiren

Rudy, Shri Rajiv Pratap

@ Voted through slip.

$ Corrected through slip for Noes.

Sahu, Shri Chandulal

Sahu, Shri Lakhan Lal

Sai, Shri Vishnu Dev

Saini, Shri Rajkumar

Sampla, Shri Vijay

Sangma, Shri Purno Agitok

Sanjar, Shri Alok

Sarmah, Shri Ram Prasad

Sarswati, Shri Sumedhanand

Sathyabama, Shrimati V.

Sawaikar, Adv. Narendra Keshav

Senguttuvan, Shri B.

Senthilnathan, Shri P. R.

Shah, Shrimati Mala Rajyalakshmi

Sharma, Dr. Mahesh

Sharma, Shri Ram Swaroop

Shekhawat, Shri Gajendra Singh

Shetty, Shri Gopal

Shirole, Shri Anil

Shyal, Dr. Bhartiben D.

Siddeshwara, Shri G. M.

Sigriwal, Shri Janardan Singh

Simha, Shri Pratap

Singh, Dr. Bhola

Singh, Dr. Jitendra

Singh, Dr. Nepal

Singh, Dr. Satya Pal

Singh, Dr. Yashwant

Singh, Gen. (Retd) Vijay Kumar

Singh, Kunwar Bharatendra

Singh, Rao Inderjit

Singh, Shri Abhishek

Singh, Shri Bharat

Singh, Shri Bhola

@Singh, Shri Brijbhushan Sharan

Singh, Shri Dushyant

Singh, Shri Giriraj

Singh, Shri Hukum

Singh, Shri Kirti Vardhan

@Singh, Shri Lallu

Singh, Shri Nagendra

Singh, Shri Pashupati Nath

Singh, Shri R. K.

Singh, Shri Rajnath

Singh (Raju Bhaiya), Shri Rajveer

Singh, Shri Rakesh

Singh, Shri Satyapal

Singh, Shri Sunil Kumar

Singh, Shri Sushil Kumar

Singh, Shri Uday Pratap

Singh, Shri Virendra

Sinha, Shri Jayant

Sinha, Shri Manoj

Solanki, Dr. Kirit P.

Somaiya, Dr. Kirit

Sonkar, Shri Vinod Kumar

Sonker, Shrimati Neelam

@ Voted through slip.

Sonowal, Shri Sarbananda

Srinivas, Shri Kesineni

Sriramulu, Shri B.

Sundaram, Shri P. R.

Swaraj, Shrimati Sushma

Tadas, Shri Ramdas C.

Tamta, Shri Ajay

Tanwar, Shri Kanwar Singh

Tasa, Shri Kamakhya Prasad

Teli, Shri Rameshwar

Teni, Shri Ajay Misra

Thakur, Shri Anurag Singh

Thambidurai, Dr. M.

Tiwari, Shri Manoj

Tripathi, Shri Sharad

Udasi, Shri Shivkumar

Udhayakumar, Shri M.

Usendi, Shri Vikram

Vanaroja, Shrimati R.

Vardhan, Dr. Harsh

Vasanthi, Shrimati M.

Vasava, Shri Parbhubhai Nagarbhai

Venugopal, Dr. P.

Verma, Dr. Anshul

Verma, Shri Bhanu Pratap Singh

Verma, Shri Parvesh Sahib Singh

Verma, Shrimati Rekha

Vijaya Kumar, Shri S. R.

Wanga, Shri Chintaman Navasha

Yadav, Shri Hukmdeo Narayan

Yadav, Shri Laxmi Narayan

Yadav, Shri Om Prakash

Yadav, Shri Ram Kripal

Yediyurappa, Shri B.S.

ABSTAIN

Adsul, Shri Anandrao

Barne, Shri Shrirang Appa

Gaikwad, Prof. Ravindra Vishwanath

Gawali, Shrimati Bhavana Pundalikrao

Geete, Shri Anant Gangaram

Godse, Shri Hemant Tukaram

Jadhav, Shri Prataprao

Jadhav, Shri Sanjay Haribhau

Khaire, Shri Chandrakant

Kirtikar, Shri Gajanan

Lokhande, Shri Sadashiv

Raut, Shri Vinayak Bhaurao

Sawant, Shri Arvind

Shewale, Shri Rahul

Shinde, Dr. Shrikant Eknath

Shivajirao, Shri Adhalrao Patil

Vichare, Shri Rajan

19.00 hrs

HON. SPEAKER: Subject to correction*, the result of the Division is:

Ayes: 088
Noes: 295
Abstain:17

The motion was negatived.

HON. SPEAKER: Shri B. Mahtabji, are you moving your Amendment No. 35 to Clause 3?

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Madam, I may be allowed to say a few words on this.

I welcome the amendment that has been moved by the Minister and especially the amendment relating to this Clause is a welcome step by the Government. We had impressed upon the Government that this is necessary. The private hospitals and private educational institutions should be deleted from the consent clause. The Biju Janata Dal is happy that the Government has accepted that suggestion and has moved the amendment today.

So, I am not pressing for the amendment that I have given.

HON. SPEAKER: Shri Deepender Singh Hoodaji, are you moving Amendment No. 45 to Clause 3?

---

* The following Members also recorded/corrected their votes through slips:

Ayes: 088 + S/Shri Prasun Banerjee, B.N. Chandrappa, H.D. Devegowda, Innocent, Taslim Uddin, Shrimati Dimple Yadav = **094**

Noes: 295 + Yogi Adityanath, S/Shri S.S. Ahluwalia, P.P. Chauhan, Chhotelal, V. Elumalai, Nitin Gadkari, Sukhbir Singh Jaunpuria, Rahul Kaswan, Dr. Ramshankar Katheria, S/Shri Faggan Singh Kulaste, Shanta Kumar, Karia Munda, Ashok Mahadeorao Nete, Shrimati Krishna Raj, S/Shri Gokaraju Ganga Raju, Bishnu Pada Ray, Brijbhushan Sharan Singh, Lallu Singh = **314**

Abstain: 017 + Shri Chandrakant Khaire - Shri Bishnu Pada Ray **= 17**

SHRI DEEPENDER SINGH HOODA (ROHTAK): I beg to move:

"Page 2, *for* lines 3 to 5, *substitute*,-

"Provided that every project under section 10A of Chapter IIIA shall compulsorily acquire consent of 80 per cent of affected persons in case of projects undertaken by private entities and consent of 70 per cent of affected persons in case of other projects including those undertaken through public private partnership, with such consent being obtained through a prior informed process as prescribed by the appropriate Government.". " (45)

यह इस एक्ट की आत्मा है और मैं सबसे आग्रह करूंगा कि वे आत्मा की आवाज पर इस पर वोटिंग करें कि किसान की सहमति अधिग्रहण से पहले होनी चाहिए या प्राइवेट लोगों के लिए आधिग्रहण होना चाहिए। ...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: I shall now put Amendment No.45 to Clause 3 moved by Shri Deepender Singh Hooda to the vote of the House.

SHRI DEEPENDER SINGH HOODA: Madam, I want Division.

HON. SPEAKER: The Lobbies have already been cleared.

The question is:

"Page 2, *for* lines 3 to 5, *substitute*,-

"Provided that every project under section 10A of Chapter IIIA shall compulsorily acquire consent of 80 per cent of affected persons in case of projects undertaken by private entities and consent of 70 per cent of affected persons in case of other projects including those undertaken through public private partnership, with such consent being obtained through a prior informed process as prescribed by the appropriate Government."

The Lok Sabha divided:

DIVISION NO. 3 **AYES** **18.59 hrs.**

@Adhikari, Shri Sisir Kumar

Adhikari, Shri Suvendu

Ahmed, Shri Sultan

Ali, Shri Idris

Antony, Shri Anto

Anwar, Shri Tariq

Baite, Shri Thangso

Banerjee, Shri Abhishek

Banerjee, Shri Kalyan

Banerjee, Shri Prasun

Barman, Shri Bijoy Chandra

Bhonsale, Shri Chh. Udayanraje

Biju, Shri P. K.

Bose, Prof. Sugata

Chandrappa, Shri B. N.

Chaudhury, Shri Jitendra

Chautala, Shri Dushyant

Chavan, Shri Ashok Shankarrao

Chowdhury, Shri A. H. khan

Chowdhury, Shri Adhir Ranjan

Dastidar, Dr. Kakoli Ghosh

Datta, Shri Sankar Prasad

De(Nag), Dr. Ratna

Dev, Kumari Sushmita

@Devegowda, Shri H.D.

Engti, Shri Biren Singh

@ Voted through slip.

Faizal, Mohammed

Geetha, Shrimati Kothapalli

George, Adv. Joice

Ghosh, Shrimati Arpita

Gogoi, Shri Gaurav

Gowda, Shri S.P. Muddahanume

Hansdak, Shri Vijay Kumar

Haque, Shri Mohd. Asrarul

Hazra, Dr. Anupam

Hooda, Shri Deepender Singh

@Innocent, Shri

Jadhav, Shri Prataprao

Jatua, Shri Choudhury Mohan

@Jayadevan, Shri C. N

Kalvakuntla, Shrimati kavitha

Karunakaran, Shri P.

Khan, Shri Saumitra

Kharge, Shri Mallikarjun

Kumar, Shri Kaushalendra

Kumar, Shri Santosh

Kumar, Shri Shailesh

Mahato, Dr. Mriganka

Mandal, Dr. Tapas

Mann, Shri Bhagwant

Meinya, Dr. Thokchom

@Moily, Shri M. Veerappa

Mondal, Shri Sunil Kumar

Mondal, Shrimati Pratima

@ Voted through slip.

Mukherjee, Shri Abhijit

Muniyappa, Shri K.H.

Nagesh, Shri Godam

Naik, Prof. A.S.R.

Naik, Shri B.V.

@Nath, Shri Kamal

Noor, Shrimati Mausam

Owaisi, Shri Asaduddin

Pala, Shri Vincent H.

Poddar, Shrimati Aparupa

Premachandran, Shri N.K.

Rajesh, Shri M. B.

Raju, Shri C.S. Putta

Ramachandran, Shri Mullappally

Ranjan, Shri Rajesh

Ranjan, Shrimati Ranjeet

Reddy, Shri Gutha Sukender

Reddy, Shri Mekapati Raja Mohan

Reddy, Shri P. Srinivasa

Reddy, Shri Y. V. Subba

Renuka, Shrimati Butta

@Rori, Shri Charanjeet Singh

Roy, Prof. Saugata

Roy, Shrimati Sandhya

Ruala, Shri C.L.

Sahu, Shri Tamradhwaj

Sampath, Dr. A.

Sanghamita, Dr. Mamtaz

@ Voted through slip.

Saren, Dr. Uma

Satav, Shri Rajeev

Scindia, Shri Jyotiraditya M.

Shetty, Shri Raju

Singh, Prof. Sadhu

Singh, Shri Ravneet

Sule, Shrimati Supriya

Suresh, Shri D.K.

Suresh, Shri Kodikunnil

Teacher, Shrimati P.K. Shreemathi

Thakur, Shrimati Mamata

Tharoor, Dr. Shashi

@Thomas, Prof. K.V.

Tirkey, Shri Dasrath

@Trivedi, Shri Dinesh

Uddin, Shri Tasleem

Varma, Shrimati Dev

Velagapalli, Shri Varaprasad Rao

Venugopal, Shri K. C.

Yadav, Shri Akshay

Yadav, Shri Dharmendra

Yadav, Shri Jai Prakash Narayan

Yadav, Shri Tej Pratap Singh

Yadav, Shrimati Dimple

Yellaiah, Shri Nandi

@ Voted through slip.

NOES

Adityanath, Yogi

Advani, Shri L.K.

Ahir, Shri Hansraj Gangaram

Ahlawat, Shrimati Santosh

@Ahluwalia, Shri S.S.

Amarappa , Shri Karadi Sanganna

Ananthkumar, Shri

Angadi, Shri Suresh C.

@Arunmozhithevan, Shri A.

Azad, Shri Kirti

Babu, Dr. Ravindra

Badal, Shrimati Harsimrat Kaur

Baheria, Shri Subhash Chandra

Bais, Shri Ramesh

Bala, Shrimati Anju

Balyan, Dr. Sanjeev

Bansode, Adv. Sharadkumar Maruti

Bhabhor, Shri Jasvantsinh Sumanbhai

Bhagat, Shri Sudarshan

Bhamre, Dr. Subhash Ramrao

Bharathi Mohan, Shri R.K.

Bharti, Sushri Uma

Bhatt, Shrimati Ranjanben

Bhole, Shri Devendra Singh

Bhuria, Shri Dileep Singh

Bidhuri, Shri Ramesh

Birla, Shri Om

@ Voted through slip.

Bohra, Shri Ramcharan

@Brahmpura, Shri Ranjit Singh

Chakravarty, Shrimati Bijoya

Chand, Shri Nihal

Chandel, Kunwar Pushpendra Singh

Chandrakasi, Shri M.

Chandumajra, Shri Prem Singh

Chaudhary, Shri C.R.

Chaudhary, Shri Haribhai

Chaudhary, Shri P.P.

Chaudhary, Shri Pankaj

Chaudhary, Shri Ram Tahal

Chauhan, Shri Devusinh

@Chauhan, Shri P. P.

Chhewang, Shri Thupstan

@Chhotelal, Shri

Chinnaiyan, Shri S. Selvakumara

Choubey, Shri Ashwini Kumar

Choudhary, Col. Sonaram

@Choudhary, Shri Babulal

@Choudhary, Shri Birendra Kumar

Chouhan, Shri Nandkumar Singh

Chudasama, Shri Rajeshbhai

Danve, Shri Raosaheb Patil

Dattatreya, Shri Bandaru

Deka, Shri Ramen

Devi, Shrimati Rama

@ Voted through slip.

@Devi, Shrimati Veena

Dharambir, Shri

Dhotre, Shri Sanjay

Dhurve, Shrimati Jyoti

Diwakar, Shri Rajesh Kumar

Dubey, Shri Nishikant

Dubey, Shri Satish Chandra

Dwivedi, Shri Harishchandra alias Harish

Elumalai, Shri V.

Fatepara, Shri Devjibhai G.

Gaddigoudar, Shri P.C.

Gadkari, Shri Nitin

Gaikwad, Dr. Sunil Baliram

Galla, Shri Jayadev

Gandhi, Shri Dilipkumar Mansukhlal

Gandhi, Shrimati Maneka Sanjay

Gangwar, Shri Santosh Kumar

Gautam, Shri Satish Kumar

Gavit, Dr. Heena Vijaykumar

Giluwa, Shri Laxman

Girri, Shri Maheish

Gohain, Shri Rajen

Gopal, Dr. K.

@Gopalakrishnan, Shri C.

Gopalakrishnan, Shri R.

Goud, Dr. Boora Narsaiah

@Gowda, Shri D.V. Sadananda

Gupta, Shri Shyama Charan

@ Voted through slip.

Gurjar, Shri Krishanpal

Hari, Shri G.

Haribabu, Dr. Kambhampati

Hegde, Shri Anantkumar

[@]Hemamalini, Shrimati

Jaiswal, Dr. Sanjay

Jardosh, Shrimati Darshana Vikram

Jat, Prof. Sanwar Lal

Jaunapuria, Shri Sukhbir Singh

Jayavardhan, Dr. J.

Jigajinagi, Shri Ramesh

Joshi, Dr. Murli Manohar

Joshi, Shri Pralhad

Jyoti, Sadhvi Niranjan

Kachhadia, Shri Naranbhai

Kaiser, Choudhary Mehboob Ali

Kamaraj, Dr. K.

Karandlaje, Kumari Shobha

Kashyap, Shri Virender

Kaswan, Shri Rahul

Kataria, Shri Rattan Lal

Kateel, Shri Nalin Kumar

Katheria, Dr. Ramshankar

Kaushik, Shri Ramesh Chander

[@]Khadse, Shrimati Rakshatai

Khanduri AVSM, Maj. Gen. (Retd.) B.C.

Khanna, Shri Vinod

[@] Voted through slip.

Kher, Shrimati Kirron

Khuba, Shri Bhagwanth

Kinjarapu, Shri Ram Mohan Naidu

Kishore, Shri Jugal

Kishore, Shri Kaushal

Koli, Shri Bahadur Singh

Koshyari, Shri Bhagat Singh

Kristappa, Shri N.

@Kulaste, Shri Faggan Singh

Kumar, Dr. Arun

Kumar, Dr. Virendra

Kumar, Kunwar Sarvesh

Kumar, Shri Ashwini

Kumar, Shri Dharmendra

Kumar, Shri K. Ashok

Kumar, Shri P.

Kumar, Shri Shanta

Kundariya, Shri Mohanbhai Kalyanjibhai

Kushawaha, Shri Ravinder

Kushwaha, Shri Upendra

Lakhanpal, Shri Raghav

Lekhi, Shrimati Meenakashi

Maadam, Shrimati Poonamben

Maharaj, Dr. Swami Sakshiji

Mahato, Dr. Banshilal

Mahato, Shri Bidyut Baran

Mahendran, Shri C.

Malviya, Prof. Chintamani

@ Voted through slip.

Manjhi, Shri Hari

Marabi, Shri Kamal Bhan Singh

Maragatham, Shrimati K.

Marutharajaa, Shri R. P.

Maurya, Shri Keshav Prasad

Meena, Shri Harish

Meghwal, Shri Arjun Ram

Mishra, Shri Anoop

Mishra, Shri Bhairon Prasad

Mishra, Shri Daddan

Mishra, Shri Janardan

@Mishra, Shri Kalraj

Mohan, Shri M. Murli

Mohan, Shri P.C.

Munda, Shri Karia

Nagar, Shri Rodmal

Nagarajan, Shri P.

Narasimham, Shri Thota

Nath, Shri Chand

Natterjee, Shri J.J.T.

[@]Nete, Shri Ashok Mahadeorao

Nishad, Shri Ajay

Nishad, Shri Ram Charitra

Nishank, Dr. Ramesh Pokhriyal

Oram, Shri Jual

Paatle, Shrimati Kamla

Pal, Shri Jagdambika

Pandey, Dr. Mahendra Nath

[@] Voted through slip.

Pandey, Shri Hari Om

Pandey, Shri Rajesh

Pandey, Shri Ravindra Kumar

Panneerselvam, Shri V.

Parasuraman, Shri K.

Parthipan, Shri R.

Paswan, Shri Chhedi

Paswan, Shri Chirag

Paswan, Shri Ram Chandra

Paswan, Shri Ramvilas

Patel, Dr. K. C.

Patel, Shri Devji M.

Patel, Shri Dilip

Patel, Shri Lalubhai Babubhai

Patel, Shri Natubhai Gomanbhai

Patel, Shri Prahlad Singh

Patel, Shri Subhash

Patel, Shrimati Anupriya

Patel, Shrimati Jayshreeben

Pathak, Shrimati Riti

Patil, Shri A.T. Nana

Patil, Shri C. R.

Patil, Shri Kapil Moreshwar

Patil, Shri Sanjay Kaka

Patole, Shri Nana

Phule, Sadhvi Savitri Bai

Prabakaran, Shri K. R. P.

Prasad, Dr. Bhagirath

Pratap, Shri Krishan

Radhakrishnan, Shri Pon

Radhakrishnan, Shri R.

Radhakrishnan, Shri T.

Rai, Shri Nityanand

Raj, Dr. Udit

Raj, Shrimati Krishna

Rajbhar, Shri Harinarayan

Rajendran, Shri S.

Rajoria, Dr. Manoj

Rajput, Shri Mukesh

Raju, Shri Ashok Gajapathi

Raju, Shri Gokaraju Ganga

Ram, Shri Janak

Ram, Shri Vishnu Dayal

Ramachandran, Shri K. N.

Rao, Shri Konakalla Narayana

Rao (Avanthi), Shri Muthamsetti Srinivasa

Rao, Shri Rayapati Sambasiva

Rathod, Shri D.S.

Rathore, Col. Rajyavardhan

Rathore, Shri Hariom Singh

[@]Rathwa, Shri Ramsinh

Raval, Shri Paresh

Rawat, Shrimati Priyanka Singh

Ray, Shri Bishnu Pada

Ray, Shri Ravindra Kumar

Reddy, Shri J.C. Divakar

Reddy, Shri P.V. Midhun

[@] Voted through slip.

Rijiju, Shri Kiren

Rudy, Shri Rajiv Pratap

Sahu, Shri Chandulal

Sahu, Shri Lakhan Lal

Sai, Shri Vishnu Dev

Saini, Shri Rajkumar

Sampla, Shri Vijay

Sangma, Shri Purno Agitok

Sanjar, Shri Alok

Sarmah, Shri Ram Prasad

Sarswati, Shri Sumedhanand

Sathyabama, Shrimati V.

Sawaikar, Adv. Narendra Keshav

Senguttuvan, Shri B.

Senthilnathan, Shri P. R.

Shah, Shrimati Mala Rajyalakshmi

Sharma, Dr. Mahesh

[@]Sharma, Shri Ram Kumar

Sharma, Shri Ram Swaroop

Shekhawat, Shri Gajendra Singh

Shetty, Shri Gopal

Shirole, Shri Anil

Shyal, Dr. Bhartiben D.

Siddeshwara, Shri G. M.

Sigriwal, Shri Janardan Singh

Simha, Shri Pratap

Singh, Dr. Bhola

Singh, Dr. Jitendra

[@] Voted through slip.

Singh, Dr. Nepal

Singh, Dr. Satya Pal

Singh, Dr. Yashwant

Singh, Gen. (Retd) Vijay Kumar

Singh, Kunwar Bharatendra

Singh, Kunwar Haribansh

Singh, Rao Inderjit

Singh, Shri Abhishek

[@]Singh, Shri Bharat

Singh, Shri Bhola

[@]Singh, Shri Brijbhushan Sharan

Singh, Shri Dushyant

Singh, Shri Giriraj

Singh, Shri Hukum

Singh, Shri Kirti Vardhan

Singh, Shri Lallu

Singh, Shri Nagendra

Singh, Shri Pashupati Nath

Singh, Shri R. K.

Singh, Shri Rajnath

Singh (Raju Bhaiya), Shri Rajveer

Singh, Shri Rakesh

Singh, Shri Satyapal

Singh, Shri Sunil Kumar

Singh, Shri Sushil Kumar

Singh, Shri Uday Pratap

Singh, Shri Virendra

[@] Voted through slip.

Sinha, Shri Jayant

Sinha, Shri Manoj

Solanki, Dr. Kirit P.

Somaiya, Dr. Kirit

Sonkar, Shri Vinod Kumar

Sonker, Shrimati Neelam

Sonowal, Shri Sarbananda

Srinivas, Shri Kesineni

Sriramulu, Shri B.

Sundaram, Shri P. R.

Swaraj, Shrimati Sushma

Tadas, Shri Ramdas C.

Tamta, Shri Ajay

Tanwar, Shri Kanwar Singh

Tasa, Shri Kamakhya Prasad

Teli, Shri Rameshwar

Teni, Shri Ajay Misra

Thakur, Shri Anurag Singh

Thambidurai, Dr. M.

Tiwari, Shri Manoj

Tripathi, Shri Sharad

Udasi, Shri Shivkumar

Udhayakumar, Shri M.

Usendi, Shri Vikram

Vanaroja, Shrimati R.

Vardhan, Dr. Harsh

Vasanthi, Shrimati M.

Vasava, Shri Parbhubhai Nagarbhai

Venugopal, Dr. P.

Verma, Dr. Anshul
Verma, Shri Bhanu Pratap Singh
Verma, Shri Parvesh Sahib Singh
Verma, Shri Rajesh
Verma, Shrimati Rekha
Vijaya Kumar, Shri S. R.
Wanga, Shri Chintaman Navasha
Yadav, Shri Hukmdeo Narayan
Yadav, Shri Laxmi Narayan
Yadav, Shri Om Prakash
Yadav, Shri Ram Kripal
Yediyurappa, Shri B.S.

ABSTAIN

Adsul, Shri Anandrao

Barne, Shri Shrirang Appa

Gaikwad, Prof. Ravindra Vishwanath

Gawali, Shrimati Bhavana Pundalikrao

Geete, Shri Anant Gangaram

Godse, Shri Hemant Tukaram

Jadhav, Shri Sanjay Haribhau

Khaire, Shri Chandrakant

Kirtikar, Shri Gajanan

Lokhande, Shri Sadashiv

Raut, Shri Vinayak Bhaurao

Sawant, Shri Arvind

Shewale, Shri Rahul

Shinde, Dr. Shrikant Eknath

Shivajirao, Shri Adhalrao Patil

Vichare, Shri Rajan

HON. SPEAKER: Subject to correction*, the result of the Division is:

Ayes: 098
Noes: 299
Abstain:16

The motion was negatived.

HON. SPEAKER: The question is:

"That clause 3, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 3, as amended, was added to the Bill.

* The following Members also recorded/corrected their votes through slips:

Ayes: 098 + S/Shri Sisir Kumar Adhikari, H.D. Devegowda, Innocent, C.N. Jayadevan, M. Veerappa Moily, Kamal Nath, Charanjeet Singh Rori, Prof. K.V. Thomas, S/Shri Dinesh Trivedi = **107**

Noes: 299 + S/Shri S.S. Ahluwalia, A. Arunmozhithevan, Ranjit Singh Brahmpura, P.P. Chauhan, Chhotelal, Babulal Choudhary, Birendra Kumar Choudhary, Shrimati Veena Devi, S/Shri C. Gopalakrishnan, D.V. Sadananda Gowda, Shrimati Hemamalini, Shrimati Rakshatai Khadse, S/Shri Faggan Singh Kulaste, Kalraj Mishra, Ashok Mahadeorao Nete, Ramsinh Rathwa, Ram Kumar Sharma, Bharat Singh, Brijbhushan Sharan Singh = **318**

Abstain: 016

Clause 4 Amendment of Section 3

माननीय अध्यक्ष : जय प्रकाश नारायण जी, आप खंड संख्या 4 की अमेंडमेंट संख्या 9 मूव कीजिए।

श्री जय प्रकाश नारायण यादव (बाँका) : मैं प्रस्ताव करता हूं:

'पृष्ठ 2, पंक्ति 16 से 21 का लोप किया जाए।" … (*Interruptions*)

मैं किसानों की बात कहना चाहता हूं।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : अमेंडमेंट के संदर्भ में बोलिए।

… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: I will now put Amendment No.9 to Clause 4 moved by Shri Jai Prakash Narayan Yadav to the vote of the House.

… (*Interruptions*)

श्री जय प्रकाश नारायण यादव: माननीय अध्यक्ष जी, मैं डिवीजन चाहता हूं।

HON. SPEAKER: The Lobbies have already been cleared.

The Lok Sabha divided:

DIVISION NO. 4 **AYES** **19.01 hrs.**

Adhikari, Shri Sisir Kumar

Adhikari, Shri Suvendu

[@]Ahmed, Shri Sultan

Antony, Shri Anto

Anwar, Shri Tariq

Baite, Shri Thangso

Banerjee, Shri Abhishek

Banerjee, Shri Kalyan

Banerjee, Shri Prasun

Barman, Shri Bijoy Chandra

Bhonsale, Shri Chh. Udayanraje

Biju, Shri P. K.

Bose, Prof. Sugata

[$]Chandrappa, Shri B. N.

Chaudhury, Shri Jitendra

Chautala, Shri Dushyant

Chavan, Shri Ashok Shankarrao

@Chowdhury, Shri A. H. khan

Chowdhury, Shri Adhir Ranjan

Dastidar, Dr. Kakoli Ghosh

Datta, Shri Sankar Prasad

De(Nag), Dr. Ratna

Dev, Kumari Sushmita

Devegowda, Shri H.D.

Engti, Shri Biren Singh

Faizal, Mohammed

[@] Voted through slip.
[$] Corrected through slip for Ayes.

Geetha, Shrimati Kothapalli

George, Adv. Joice

Ghosh, Shrimati Arpita

Gogoi, Shri Gaurav

Gowda, Shri S.P. Muddahanume

Hansdak, Shri Vijay Kumar

Haque, Shri Mohd. Asrarul

Hooda, Shri Deepender Singh

@Innocent, Shri

Jatua, Shri Choudhury Mohan

Jayadevan, Shri C. N

Kalvakuntla, Shrimati kavitha

Karunakaran, Shri P.

Khan, Shri Saumitra

Kharge, Shri Mallikarjun

Kumar, Shri Kaushalendra

Kumar, Shri Santosh

Kumar, Shri Shailesh

Mandal, Dr. Tapas

Mann, Shri Bhagwant

Meinya, Dr. Thokchom

Moily, Shri M. Veerappa

Mondal, Shri Sunil Kumar

Mondal, Shrimati Pratima

Mukherjee, Shri Abhijit

Muniyappa, Shri K.H.

Nagesh, Shri Godam

Naik, Shri B.V.

@ Voted through slip.

Nath, Shri Kamal

Noor, Shrimati Mausam

Owaisi, Shri Asaduddin

Pala, Shri Vincent H.

Poddar, Shrimati Aparupa

Premachandran, Shri N.K.

Rajesh, Shri M. B.

Raju, Shri C.S. Putta

Ramachandran, Shri Mullappally

Ranjan, Shri Rajesh

Ranjan, Shrimati Ranjeet

Reddy, Shri Gutha Sukender

Reddy, Shri Mekapati Raja Mohan

Reddy, Shri P. Srinivasa

Reddy, Shri Y. V. Subba

Renuka, Shrimati Butta

Rori, Shri Charanjeet Singh

Roy, Prof. Saugata

Roy, Shrimati Sandhya

Ruala, Shri C.L.

[@]Sahu, Shri Tamradhwaj

Sampath, Dr. A.

Sanghamita, Dr. Mamtaz

Saren, Dr. Uma

Satav, Shri Rajeev

Scindia, Shri Jyotiraditya M.

Shetty, Shri Raju

Singh, Prof. Sadhu

[@] Voted through slip.

Singh, Shri Ravneet

Sinha, Shrimati Renuka

Sule, Shrimati Supriya

Suresh, Shri D.K.

@Suresh, Shri Kodikunnil

Teacher, Shrimati P.K. Shreemathi

Thakur, Shrimati Mamata

Tharoor, Dr. Shashi

Thomas, Prof. K.V.

Tirkey, Shri Dasrath

@Trivedi, Shri Dinesh

Uddin, Shri Tasleem

Varma, Shrimati Dev

Velagapalli, Shri Varaprasad Rao

@Venugopal, Shri K. C.

Yadav, Shri Akshay

Yadav, Shri Dharmendra

Yadav, Shri Jai Prakash Narayan

Yadav, Shri Tej Pratap Singh

Yadav, Shrimati Dimple

Yellaiah, Shri Nandi

@ Voted through slip.

NOES

Adityanath, Yogi

Advani, Shri L.K.

Ahir, Shri Hansraj Gangaram

Ahlawat, Shrimati Santosh

@Ahluwalia, Shri S.S.

Amarappa , Shri Karadi Sanganna

Ananthkumar, Shri

Angadi, Shri Suresh C.

Arunmozhithevan, Shri A.

Azad, Shri Kirti

Babu, Dr. Ravindra

Badal, Shrimati Harsimrat Kaur

Baheria, Shri Subhash Chandra

Bais, Shri Ramesh

Bala, Shrimati Anju

Balyan, Dr. Sanjeev

Bansode, Adv. Sharadkumar Maruti

Bhabhor, Shri Jasvantsinh Sumanbhai

Bhagat, Shri Sudarshan

Bhamre, Dr. Subhash Ramrao

Bharathi Mohan, Shri R.K.

Bharti, Sushri Uma

Bhatt, Shrimati Ranjanben

Bhole, Shri Devendra Singh

Bhuria, Shri Dileep Singh

Bidhuri, Shri Ramesh

@ Voted through slip.

Birla, Shri Om

Bohra, Shri Ramcharan

Brahmpura, Shri Ranjit Singh

@Chakravarty, Shrimati Bijoya

Chand, Shri Nihal

Chandel, Kunwar Pushpendra Singh

Chandrakasi, Shri M.

Chandumajra, Shri Prem Singh

@Chaudhary, Shri C. R.

Chaudhary, Shri Haribhai

Chaudhary, Shri P.P.

Chaudhary, Shri Pankaj

Chaudhary, Shri Ram Tahal

Chauhan, Shri Devusinh

Chauhan, Shri P. P.

Chhewang, Shri Thupstan

Chhotelal, Shri

Chinnaiyan, Shri S. Selvakumara

Choubey, Shri Ashwini Kumar

Choudhary, Col. Sonaram

Choudhary, Shri Babulal

Choudhary, Shri Birendra Kumar

Chouhan, Shri Nandkumar Singh

Chudasama, Shri Rajeshbhai

Danve, Shri Raosaheb Patil

Dattatreya, Shri Bandaru

$Deka, Shri Ramen

@ Voted through slip.
$ Corrected through slip for Noes.

@Devi, Shrimati Rama

Devi, Shrimati Veena

@Dharambir, Shri

Dhotre, Shri Sanjay

Dhurve, Shrimati Jyoti

Diwakar, Shri Rajesh Kumar

Dubey, Shri Nishikant

Dubey, Shri Satish Chandra

Dwivedi, Shri Harishchandra alias Harish

Elumalai, Shri V.

Fatepara, Shri Devjibhai G.

Gaddigoudar, Shri P.C.

Gadkari, Shri Nitin

Gaikwad, Dr. Sunil Baliram

Galla, Shri Jayadev

Gandhi, Shri Dilipkumar Mansukhlal

Gandhi, Shrimati Maneka Sanjay

Gangwar, Shri Santosh Kumar

Gautam, Shri Satish Kumar

Gavit, Dr. Heena Vijaykumar

Ghubaya, Shri Sher Singh

Giluwa, Shri Laxman

Girri, Shri Maheish

Gohain, Shri Rajen

Gopal, Dr. K.

@Gopalakrishnan, Shri C.

Gopalakrishnan, Shri R.

Goud, Dr. Boora Narsaiah

@ Voted through slip.

Gowda, Shri D.V. Sadananda

Gupta, Shri Shyama Charan

Gurjar, Shri Krishanpal

@Hari, Shri G.

Haribabu, Dr. Kambhampati

Hegde, Shri Anantkumar

@Hemamalini, Shrimati

Jaiswal, Dr. Sanjay

Jardosh, Shrimati Darshana Vikram

Jat, Prof. Sanwar Lal

@Jaunapuria, Shri Sukhbir Singh

Jayavardhan, Dr. J.

Jigajinagi, Shri Ramesh

Joshi, Dr. Murli Manohar

Joshi, Shri Pralhad

Jyoti, Sadhvi Niranjan

Kachhadia, Shri Naranbhai

Kaiser, Choudhary Mehboob Ali

Kamaraj, Dr. K.

Karandlaje, Kumari Shobha

Kashyap, Shri Virender

Kaswan, Shri Rahul

Kataria, Shri Rattan Lal

Kateel, Shri Nalin Kumar

@Katheria, Dr. Ramshankar

Kaushik, Shri Ramesh Chander

Khadse, Shrimati Rakshatai

Khanduri AVSM, Maj. Gen. (Retd.) B.C.

@ Voted through slip.

[$]Khanna, Shri Vinod

Kher, Shrimati Kirron

Khuba, Shri Bhagwanth

Kinjarapu, Shri Ram Mohan Naidu

Kishore, Shri Jugal

Kishore, Shri Kaushal

[@]Koli, Shri Bahadur Singh

Koshyari, Shri Bhagat Singh

Kristappa, Shri N.

Kulaste, Shri Faggan Singh

Kumar, Dr. Arun

Kumar, Dr. Virendra

Kumar, Kunwar Sarvesh

@Kumar, Shri Ashwini

Kumar, Shri Dharmendra

Kumar, Shri K. Ashok

Kumar, Shri P.

Kumar, Shri Shanta

Kundariya, Shri Mohanbhai Kalyanjibhai

Kushawaha, Shri Ravinder

Kushwaha, Shri Upendra

Lakhanpal, Shri Raghav

Lekhi, Shrimati Meenakashi

Maadam, Shrimati Poonamben

Maharaj, Dr. Swami Sakshiji

Mahato, Dr. Banshilal

[$] Corrected through slip for Noes.
[@] Voted through slip.

@Mahato, Shri Bidyut Baran

Mahendran, Shri C.

Malviya, Prof. Chintamani

Manjhi, Shri Hari

@Marabi, Shri Kamal Bhan Singh

Maragatham, Shrimati K.

Marutharajaa, Shri R. P.

Maurya, Shri Keshav Prasad

Meena, Shri Harish

Meghwal, Shri Arjun Ram

Mishra, Shri Anoop

Mishra, Shri Bhairon Prasad

Mishra, Shri Daddan

Mishra, Shri Janardan

Mishra, Shri Kalraj

Mohan, Shri M. Murli

Mohan, Shri P.C.

Munda, Shri Karia

Nagar, Shri Rodmal

Nagarajan, Shri P.

Naik, Prof. A.S.R.

Narasimham, Shri Thota

Nath, Shri Chand

Natterjee, Shri J.J.T.

Nete, Shri Ashok Mahadeorao

Nishad, Shri Ajay

Nishad, Shri Ram Charitra

Nishank, Dr. Ramesh Pokhriyal

@ Voted through slip.

Oram, Shri Jual

Paatle, Shrimati Kamla

Pal, Shri Jagdambika

Pandey, Dr. Mahendra Nath

Pandey, Shri Hari Om

Pandey, Shri Rajesh

Pandey, Shri Ravindra Kumar

@Panneerselvam, Shri V.

@Parasuraman, Shri K.

Parthipan, Shri R.

Paswan, Shri Chhedi

@Paswan, Shri Chirag

Paswan, Shri Ram Chandra

Paswan, Shri Ramvilas

Patel, Dr. K. C.

Patel, Shri Devji M.

Patel, Shri Dilip

Patel, Shri Lalubhai Babubhai

Patel, Shri Natubhai Gomanbhai

Patel, Shri Prahlad Singh

Patel, Shri Subhash

Patel, Shrimati Anupriya

Patel, Shrimati Jayshreeben

Pathak, Shrimati Riti

Patil, Shri A.T. Nana

Patil, Shri C. R.

Patil, Shri Kapil Moreshwar

Patil, Shri Sanjay Kaka

@ Voted through slip.

Patole, Shri Nana

Phule, Sadhvi Savitri Bai

Prabakaran, Shri K. R. P.

Prasad, Dr. Bhagirath

Pratap, Shri Krishan

Radhakrishnan, Shri Pon

Radhakrishnan, Shri R.

Radhakrishnan, Shri T.

Rai, Shri Nityanand

Raj, Dr. Udit

Raj, Shrimati Krishna

Rajbhar, Shri Harinarayan

Rajendran, Shri S.

Rajoria, Dr. Manoj

Rajput, Shri Mukesh

Raju, Shri Ashok Gajapathi

Raju, Shri Gokaraju Ganga

Ram, Shri Janak

Ram, Shri Vishnu Dayal

Ramachandran, Shri K. N.

Rao, Shri Konakalla Narayana

Rao (Avanthi), Shri Muthamsetti Srinivasa

Rao, Shri Rayapati Sambasiva

Rathod, Shri D.S.

Rathore, Col. Rajyavardhan

Rathore, Shri Hariom Singh

Rathwa, Shri Ramsinh

Raval, Shri Paresh

Rawat, Shrimati Priyanka Singh

Ray, Shri Bishnu Pada

Ray, Shri Ravindra Kumar

@Reddy, Shri Ch. Malla

Reddy, Shri J.C. Divakar

Reddy, Shri P.V. Midhun

Rijiju, Shri Kiren

Rudy, Shri Rajiv Pratap

Sahu, Shri Chandulal

Sahu, Shri Lakhan Lal

Sai, Shri Vishnu Dev

@Saini, Shri Rajkumar

Sampla, Shri Vijay

Sangma, Shri Purno Agitok

Sanjar, Shri Alok

Sarmah, Shri Ram Prasad

Sarswati, Shri Sumedhanand

Sathyabama, Shrimati V.

Sawaikar, Adv. Narendra Keshav

Senguttuvan, Shri B.

Senthilnathan, Shri P. R.

Shah, Shrimati Mala Rajyalakshmi

Sharma, Dr. Mahesh

Sharma, Shri Ram Kumar

Sharma, Shri Ram Swaroop

Shekhawat, Shri Gajendra Singh

@Shetty, Shri Gopal

Shirole, Shri Anil

Shyal, Dr. Bhartiben D.

@ Voted through slip.

Siddeshwara, Shri G. M.

Sigriwal, Shri Janardan Singh

Simha, Shri Pratap

Singh, Dr. Bhola

Singh, Dr. Jitendra

@Singh, Dr. Nepal

Singh, Dr. Satya Pal

Singh, Dr. Yashwant

Singh, Gen. (Retd) Vijay Kumar

Singh, Kunwar Bharatendra

Singh, Kunwar Haribansh

Singh, Rao Inderjit

Singh, Shri Abhishek

Singh, Shri Bharat

Singh, Shri Bhola

Singh, Shri Brijbhushan Sharan

Singh, Shri Dushyant

Singh, Shri Giriraj

Singh, Shri Hukum

Singh, Shri Kirti Vardhan

Singh, Shri Lallu

Singh, Shri Nagendra

Singh, Shri Pashupati Nath

Singh, Shri R. K.

Singh, Shri Rajnath

Singh (Raju Bhaiya), Shri Rajveer

Singh, Shri Rakesh

Singh, Shri Satyapal

@ Voted through slip.

Singh, Shri Sunil Kumar

Singh, Shri Sushil Kumar

Singh, Shri Uday Pratap

Singh, Shri Virendra

Sinha, Shri Jayant

Sinha, Shri Manoj

Solanki, Dr. Kirit P.

Somaiya, Dr. Kirit

Sonkar, Shri Vinod Kumar

Sonker, Shrimati Neelam

Sonowal, Shri Sarbananda

Srinivas, Shri Kesineni

Sriramulu, Shri B.

Sundaram, Shri P. R.

Swaraj, Shrimati Sushma

Tadas, Shri Ramdas C.

Tamta, Shri Ajay

Tanwar, Shri Kanwar Singh

Tasa, Shri Kamakhya Prasad

Teli, Shri Rameshwar

Teni, Shri Ajay Misra

Thakur, Shri Anurag Singh

Thambidurai, Dr. M.

Tiwari, Shri Manoj

Tripathi, Shri Sharad

Udasi, Shri Shivkumar

Udhayakumar, Shri M.

Usendi, Shri Vikram

Vanaroja, Shrimati R.

Vardhan, Dr. Harsh

Vasanthi, Shrimati M.

Vasava, Shri Parbhubhai Nagarbhai

Venugopal, Dr.   P.

Verma, Dr. Anshul

Verma, Shri Bhanu Pratap Singh

Verma, Shri Parvesh Sahib Singh

Verma, Shri Rajesh

Verma, Shrimati Rekha

Vijaya Kumar, Shri S. R.

Wanga, Shri Chintaman Navasha

Yadav, Shri Hukmdeo Narayan

Yadav, Shri Laxmi Narayan

Yadav, Shri Om Prakash

[@]Yadav, Shri Ram Kripal

Yediyurappa, Shri B.S.

[@] Voted through slip.

ABSTAIN

Anant Gangaram Geete

Barne, Shri Shrirang Appa

Gaikwad, Prof. Ravindra Vishwanath

Gawali, Shrimati Bhavana Pundalikrao

Godse, Shri Hemant Tukaram

Jadhav, Shri Prataprao

Jadhav, Shri Sanjay Haribhau

Khaire, Shri Chandrakant

Kirtikar, Shri Gajanan

Lokhande, Shri Sadashiv

Raut, Shri Vinayak Bhaurao

Sawant, Shri Arvind

Shewale, Shri Rahul

Shinde, Dr. Shrikant Eknath

Shivajirao, Shri Adhalrao Patil

Vichare, Shri Rajan

HON. SPEAKER: Subject to correction*, the result of the Division is:

Ayes: 096

Noes: 298

Abstain:17

The motion was negatived.

HON. SPEAKER: Amendment No. 37 to Clause 4, Shri Bhartruhari Mahtab.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Madam, I am not pressing Amendment No. 37 to Clause 4..

HON. SPEAKER: The question is:

"That clause 4 stand part of the Bill. "

The motion was adopted.

Clause 4 was added to the Bill.

Clause 5 Insertion of new chapter IIIA

HON. SPEAKER: Now, Government amendments. Hon. Minister.

Amendments moved:

Page 2, line 17, --*for* "10A" *substitute* "10A(1)" (53)

Page 2, *for* line 24, *substitute* –

"(d) industrial corridors set up by the appropriate Government and its undertakings (in which case the land shall be acquired up to one kilometer on both sides of designated railway line or roads for such industrial corridor) and". (54)

---

* The following Members also recorded/corrected their votes through slips.

Ayes: 096 + S/Shri Sultan Ahamed, B.N. Chandrappa, A.H. Khan Chowdhury, Innocent, Tamradhwaj Sahu, Kodikunnil Suresh, Dinesh Trivedi, K.C. Venugopal - Ramen Deka = **103**

Noes: 298 + Shri S.S. Ahluwalia, Shrimati Bijoy Chakravarty, S/Shri C.R. Chaudhary, Ramen Deka , Shrimati Rama Devi, S/Shri Dharambir, C. Gopalakrishnan, G. Hari, Shrimati Hemamalini, Shri Sukhbir Singh Jaunapuria, Dr. Ramshankar Katheria, S/Shri Vinod Khanna, Bahadur Singh Koli, Ashwini Kumar, Bidyut Baran Mahato, Kamal Bhan Singh Marabi, V. Panneerselvam, K. Parasuraman, Chirag Paswan, Ch. Mala Reddy, Raj Kumar Saini, Gopal Shetty, Dr. Nepal Singh, Shri Ram Kripal Yadav - Shri B.N. Chandrappa = **321**

Abstain: 017 - Shri Vinod Khanna **= 16**

Page 2, line 25, *omit* "and social infrastructure". (55)

Page 2, *after* line 27, *insert* –

"Provided that the appropriate Government shall, before the issue of notification, ensure the extent of land for the proposed acquisition keeping in view the bare minimum land required for such project.

(2) The appropriate Government shall, undertake a survey of its wasteland including arid land and, maintain a record containing details of such land, in such manner as may be prescribed by the appropriate Government.". (56)

(Shri Chaudhary Birender Singh)

HON. SPEAKER: Amendment No. 4 to Clause 5, Prof. Saugata Roy.

… (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : कुछ भी रिकॉर्ड में नहीं जाएगा, सिर्फ अमेंडमेंट की बात रिकॉर्ड में जाएगी।

...(व्यवधान) *

PROF. SAUGATA ROY (DUM DUM): I beg to move:

"Page 2, line 19,--
omit "and Chapter III" (4)

It says to omit Chapter II from that line because by the amendment, they are taking away Chapter III from the ambit of the Act. What is Chapter III? It is regarding the special provision to safeguard food security. What is the first clause? It says: "Save as otherwise provided in sub-section 2, no irrigated multi-crop land shall be acquired under the Act." The Minister was asking how the Government will be able to build railway corridors. The Act has provided for that. It provided that the provisions of the Section shall not apply in the case of projects that are linear in nature, such as those relating to railways, highways, major district roads, irrigation canals, power lines and the like. So, there is no problem in having

* Not recorded.

irrigation canals, there is no problem in having railway lines. But we wanted to protect the multi-crop land. That was our fight in Singur. … (*Interruptions*)

Madam Speaker, you must remember that similar is the case in the whole country. Tatas were cutting rice crops and Kumari Mamata Banerjee was sitting in *dharna* there. That is why this Chapter III is very important. Now, Shri Chaudhary Birender Singh says that he is a *kisan* himself and he wants to take away this Chapter relating to food security. … (*Interruptions*) He wants to take away the multi-crop land whereas he does not need it. … (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Are you moving or not moving your amendment?

… (*Interruptions*)

प्रो. सौगत राय: यह बड़ी दुखद बात है, इसलिए मैं अमेंडमेंट को मूव करता हूँ। That is why I have moved my Amendment No. 4 to Clause 5. ...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: I shall now put Amendment No. 4 to Clause 5 to the vote of the House.

The Amendment was put and negatived.

HON. SPEAKER: Now, Amendment No. 5 to Clause 5 to be moved by Prof. Saugata Roy.

… (*Interruptions*)

PROF. SAUGATA ROY: We want Division on Amendment No. 4 to Clause 5. … (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: We have already come to Amendment No. 5 to Clause 5.

प्रो. सौगत राय : पहले जिस अमेंडमेंट पर मैंने बोला, ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : वह हो गया, आप ध्यान नहीं देते हैं।

…(व्यवधान)

PROF. SAUGATA ROY : We want a Division. We want to register our protest for posterity. Please allow us. … (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Prof. Saugata Roy, we have already come to Amendment No. 5.

… (*Interruptions*)

PROF. SAUGATA ROY: We want a Division for Amendment No. 4 to Clause 5. … (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Amendment No. 4 to Clause 5 is over.

… (*Interruptions*)

PROF. SAUGATA ROY: We want a Division. It is our fundamental right to ask for a Division. We want to register our protest. … (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: I am sorry. You have not asked for the Division at the appropriate time.

… (*Interruptions*)

PROF. SAUGATA ROY: If you can allow the Minister to move 20 Amendments one day ahead of the consideration, can you not allow me one Division just because you have said that? Where is justice if I do not get it from you? I want a Division on Amendment No.4 to Clause 5. … (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: You have not asked for Division at the appropriate time.

… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: No, we have already come to Amendment No. 5 to Clause 5.

… (*Interruptions*)

PROF. SAUGATA ROY: I am not talking about Amendment No. 5 to Clause 5. I do not want to move Amendment No. 5 to Clause 5. I want Division on Amendment No. 4 to Clause 5. … (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: I am asking about Amendment No. 5 to Clause 5. Voting for Amendment No. 4 is already over.

… (*Interruptions*)

PROF. SAUGATA ROY: No, I want Division on Amendment No. 4 to Clause 5. … (*Interruptions*) जो मेरा अमेंडमेंट नम्बर चार है, उस पर मैं डिवीज़न मांगता हूँ।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आपने उस समय तो नहीं मांगा, ऐसा थोड़े ही होता है।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : उन्होंने नहीं बोला था, आपने बोला था।

…(व्यवधान)

HON. SPEAKER: We cannot go back.

… (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : मैं बोलूँगी कि आगे से सभी इसका ध्यान रखें, ऐसा बार-बार न हो। सौगत राय जी, मैं अलाऊ कर रही हूँ।

…(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Please listen to me. I am allowing this time, but it should not happen again. You have not asked for Division at the appropriate time. He was asking, but you must have asked for it. That was the question. Hereafter, do not do that. It should not be repeated.

I shall now put Amendment No. 4 to Clause 5 moved by Prof. Saugata Roy to the vote of the House. The question is:

"Page 2, line 19,--
omit "and Chapter III" (4)

PROF. SAUGATA ROY: Madam Speaker, I want Division.

HON. SPEAKER: The Lobbies are already cleared.

आप सभी लोग यह ध्यान में रखें कि मैं ऐसा दोबारा नहीं होने दूंगी।

…(व्यवधान)

HON. SPEAKER: You have to stand up and then say.

… (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : यह बैठे-बैठे नहीं होता है।

…(व्यवधान)

The Lok Sabha divided:

DIVISION NO.5 **AYES** **19.10 hrs.**

Adhikari, Shri Sisir Kumar

Adhikari, Shri Suvendu

Ahmed, Shri Sultan

Antony, Shri Anto

Anwar, Shri Tariq

Baite, Shri Thangso

Banerjee, Shri Abhishek

Banerjee, Shri Kalyan

Banerjee, Shri Prasun

Barman, Shri Bijoy Chandra

Bhonsale, Shri Chh. Udayanraje

Biju, Shri P. K.

Bose, Prof. Sugata

Chandrappa, Shri B. N.

Chaudhury, Shri Jitendra

Chautala, Shri Dushyant

Chavan, Shri Ashok Shankarrao

Chowdhury, Shri Adhir Ranjan

Dastidar, Dr. Kakoli Ghosh

Datta, Shri Sankar Prasad

De(Nag), Dr. Ratna

Dev, Kumari Sushmita

[@]Devegowda, Shri H.D.

Devi, Shrimati Veena

Engti, Shri Biren Singh

Faizal, Mohammed

Geetha, Shrimati Kothapalli

[@] Voted through slip.

George, Adv. Joice

Ghosh, Shrimati Arpita

Gowda, Shri S.P. Muddahanume

Hansdak, Shri Vijay Kumar

Haque, Shri Mohd. Asrarul

Hazra, Dr. Anupam

Hooda, Shri Deepender Singh

@Innocent, Shri

Jatua, Shri Choudhury Mohan

@Jayadevan, Shri C. N

Kalvakuntla, Shrimati kavitha

Karunakaran, Shri P.

Khan, Shri Saumitra

Kharge, Shri Mallikarjun

Kumar, Shri Kaushalendra

Kumar, Shri Santosh

Kumar, Shri Shailesh

Mahato, Dr. Mriganka

Mandal, Dr. Tapas

Mann, Shri Bhagwant

Meinya, Dr. Thokchom

Moily, Shri M. Veerappa

Mondal, Shri Sunil Kumar

Mondal, Shrimati Pratima

Mukherjee, Shri Abhijit

Muniyappa, Shri K.H.

Nagesh, Shri Godam

Naik, Prof. A.S.R.

@ Voted through slip.

Naik, Shri B.V.

Nath, Shri Kamal

Noor, Shrimati Mausam

Owaisi, Shri Asaduddin

Pala, Shri Vincent H.

Poddar, Shrimati Aparupa

Premachandran, Shri N.K.

Rajesh, Shri M. B.

Raju, Shri C.S. Putta

Ramachandran, Shri Mullappally

Ranjan, Shri Rajesh

Ranjan, Shrimati Ranjeet

Reddy, Shri Gutha Sukender

Reddy, Shri Mekapati Raja Mohan

Reddy, Shri P. Srinivasa

Reddy, Shri P.V. Midhun

Reddy, Shri Y. V. Subba

Renuka, Shrimati Butta

Rori, Shri Charanjeet Singh

@Roy, Prof. Saugata

Roy, Shrimati Sandhya

Ruala, Shri C.L.

@Sahu, Shri Tamradhwaj

Sampath, Dr. A.

Sanghamita, Dr. Mamtaz

Saren, Dr. Uma

Satav, Shri Rajeev

Scindia, Shri Jyotiraditya M.

@ Voted through slip.

Shetty, Shri Raju

Singh, Prof. Sadhu

Singh, Shri Ravneet

Sinha, Shrimati Renuka

Sule, Shrimati Supriya

Suresh, Shri D.K.

Suresh, Shri Kodikunnil

Teacher, Shrimati P.K. Shreemathi

Thakur, Shrimati Mamata

Tharoor, Dr. Shashi

Thomas, Prof. K.V.

Tirkey, Shri Dasrath

Trivedi, Shri Dinesh

Uddin, Shri Tasleem

Varma, Shrimati Dev

Velagapalli, Shri Varaprasad Rao

Venugopal, Shri K. C.

Yadav, Shri Akshay

Yadav, Shri Dharmendra

Yadav, Shri Jai Prakash Narayan

Yadav, Shri Tej Pratap Singh

Yadav, Shrimati Dimple

Yellaiah, Shri Nandi

NOES

Adityanath, Yogi

Advani, Shri L.K.

Ahir, Shri Hansraj Gangaram

Ahlawat, Shrimati Santosh

Ahluwalia, Shri S.S.

Ali, Shri Idris

Amarappa , Shri Karadi Sanganna

Ananthkumar, Shri

Angadi, Shri Suresh C.

Arunmozhithevan, Shri A.

Azad, Shri Kirti

Babu, Dr. Ravindra

Badal, Shrimati Harsimrat Kaur

Baheria, Shri Subhash Chandra

Bais, Shri Ramesh

Bala, Shrimati Anju

Balyan, Dr. Sanjeev

Bansode, Adv. Sharadkumar Maruti

Bhabhor, Shri Jasvantsinh Sumanbhai

Bhagat, Shri Sudarshan

Bhamre, Dr. Subhash Ramrao

Bharathi Mohan, Shri R.K.

Bharti, Sushri Uma

Bhatt, Shrimati Ranjanben

Bhole, Shri Devendra Singh

Bhuria, Shri Dileep Singh

Bidhuri, Shri Ramesh

@Birla, Shri Om

Bohra, Shri Ramcharan

Brahmpura, Shri Ranjit Singh

Chakravarty, Shrimati Bijoya

Chand, Shri Nihal

Chandel, Kunwar Pushpendra Singh

Chandrakasi, Shri M.

Chandumajra, Shri Prem Singh

Chaudhary, Shri C. R.

Chaudhary, Shri Haribhai

Chaudhary, Shri P.P.

Chaudhary, Shri Pankaj

Chaudhary, Shri Ram Tahal

Chauhan, Shri Devusinh

Chauhan, Shri P. P.

Chhewang, Shri Thupstan

Chhotelal, Shri

Chinnaiyan, Shri S. Selvakumara

Choubey, Shri Ashwini Kumar

Choudhary, Col. Sonaram

Choudhary, Shri Babulal

Choudhary, Shri Birendra Kumar

Chouhan, Shri Nandkumar Singh

Chudasama, Shri Rajeshbhai

Danve, Shri Raosaheb Patil

Dattatreya, Shri Bandaru

Deka, Shri Ramen

Devi, Shrimati Rama

@ Voted through slip.

[@]Dharambir, Shri

Dhotre, Shri Sanjay

Dhurve, Shrimati Jyoti

Diwakar, Shri Rajesh Kumar

Dubey, Shri Nishikant

Dubey, Shri Satish Chandra

Dwivedi, Shri Harishchandra alias Harish

Elumalai, Shri V.

Fatepara, Shri Devjibhai G.

Gaddigoudar, Shri P.C.

Gadkari, Shri Nitin

Gaikwad, Dr. Sunil Baliram

Galla, Shri Jayadev

Gandhi, Shri Dilipkumar Mansukhlal

Gandhi, Shrimati Maneka Sanjay

Gangwar, Shri Santosh Kumar

Gautam, Shri Satish Kumar

Gavit, Dr. Heena Vijaykumar

@Ghubaya, Shri Sher Singh

Giluwa, Shri Laxman

Girri, Shri Maheish

Gohain, Shri Rajen

Gopal, Dr. K.

Gopalakrishnan, Shri C.

Gopalakrishnan, Shri R.

Gowda, Shri D.V. Sadananda

Gupta, Shri Shyama Charan

Gurjar, Shri Krishanpal

[@] Voted through slip.

Hari, Shri G.

Haribabu, Dr. Kambhampati

Hegde, Shri Anantkumar

Hemamalini, Shrimati

@Jaiswal, Dr. Sanjay

Jardosh, Shrimati Darshana Vikram

Jat, Prof. Sanwar Lal

@Jaunapuria, Shri Sukhbir Singh

Jayavardhan, Dr. J.

Jigajinagi, Shri Ramesh

Joshi, Dr. Murli Manohar

Joshi, Shri Pralhad

Jyoti, Sadhvi Niranjan

Kachhadia, Shri Naranbhai

Kaiser, Choudhary Mehboob Ali

Kamaraj, Dr. K.

Karandlaje, Kumari Shobha

Kashyap, Shri Virender

Kaswan, Shri Rahul

Kataria, Shri Rattan Lal

Kateel, Shri Nalin Kumar

Katheria, Dr. Ramshankar

Kaushik, Shri Ramesh Chander

Khadse, Shrimati Rakshatai

Khanduri AVSM, Maj. Gen. (Retd.) B.C.

Khanna, Shri Vinod

Kher, Shrimati Kirron

Khuba, Shri Bhagwanth

@ Voted through slip.

Kinjarapu, Shri Ram Mohan Naidu

Kishore, Shri Jugal

Kishore, Shri Kaushal

Koli, Shri Bahadur Singh

Koshyari, Shri Bhagat Singh

Kristappa, Shri N.

Kulaste, Shri Faggan Singh

Kumar, Dr. Arun

Kumar, Dr. Virendra

Kumar, Kunwar Sarvesh

Kumar, Shri Ashwini

Kumar, Shri Dharmendra

Kumar, Shri K. Ashok

Kumar, Shri P.

Kumar, Shri Shanta

Kundariya, Shri Mohanbhai Kalyanjibhai

Kushawaha, Shri Ravinder

Kushwaha, Shri Upendra

Lakhanpal, Shri Raghav

[@]Lekhi, Shrimati Meenakashi

Maadam, Shrimati Poonamben

Maharaj, Dr. Swami Sakshiji

Mahato, Dr. Banshilal

Mahato, Shri Bidyut Baran

Mahendran, Shri C.

Malviya, Prof. Chintamani

Manjhi, Shri Hari

Marabi, Shri Kamal Bhan Singh

[@] Voted through slip.

Maragatham, Shrimati K.

Marutharajaa, Shri R. P.

Maurya, Shri Keshav Prasad

Meena, Shri Arjun Lal

Meena, Shri Harish

Meghwal, Shri Arjun Ram

Mishra, Shri Anoop

Mishra, Shri Bhairon Prasad

Mishra, Shri Daddan

Mishra, Shri Janardan

@Mishra, Shri Kalraj

Mohan, Shri M. Murli

Mohan, Shri P.C.

Munda, Shri Karia

Nagar, Shri Rodmal

Nagarajan, Shri P.

Narasimham, Shri Thota

Nath, Shri Chand

Natterjee, Shri J.J.T.

Nete, Shri Ashok Mahadeorao

Nishad, Shri Ajay

Nishad, Shri Ram Charitra

Nishank, Dr. Ramesh Pokhriyal

@Oram, Shri Jual

Paatle, Shrimati Kamla

Pal, Shri Jagdambika

Pandey, Dr. Mahendra Nath

Pandey, Shri Hari Om

@ Voted through slip.

Pandey, Shri Rajesh

Pandey, Shri Ravindra Kumar

Panneerselvam, Shri V.

Parasuraman, Shri K.

Parthipan, Shri R.

Paswan, Shri Chhedi

Paswan, Shri Chirag

Paswan, Shri Ram Chandra

Paswan, Shri Ramvilas

Patel, Dr. K. C.

Patel, Shri Devji M.

Patel, Shri Dilip

Patel, Shri Lalubhai Babubhai

Patel, Shri Natubhai Gomanbhai

Patel, Shri Prahlad Singh

Patel, Shri Subhash

Patel, Shrimati Anupriya

Patel, Shrimati Jayshreeben

Pathak, Shrimati Riti

Patil, Shri A.T. Nana

Patil, Shri C. R.

Patil, Shri Kapil Moreshwar

Patil, Shri Sanjay Kaka

Patole, Shri Nana

Phule, Sadhvi Savitri Bai

Prabakaran, Shri K. R. P.

Prasad, Dr. Bhagirath

Pratap, Shri Krishan

Radhakrishnan, Shri Pon

Radhakrishnan, Shri T.

Rai, Shri Nityanand

Raj, Dr. Udit

Raj, Shrimati Krishna

Raajhaa, Shri A. Anwhar

Rajbhar, Shri Harinarayan

Rajendran, Shri S.

Rajoria, Dr. Manoj

Rajput, Shri Mukesh

Raju, Shri Ashok Gajapathi

Raju, Shri Gokaraju Ganga

Ram, Shri Janak

Ram, Shri Vishnu Dayal

Ramachandran, Shri K. N.

Rao, Shri Konakalla Narayana

Rao (Avanthi), Shri Muthamsetti Srinivasa

Rao, Shri Rayapati Sambasiva

Rathod, Shri D.S.

Rathore, Col. Rajyavardhan

Rathore, Shri Hariom Singh

Rathwa, Shri Ramsinh

Raval, Shri Paresh

Rawat, Shrimati Priyanka Singh

Ray, Shri Bishnu Pada

Ray, Shri Ravindra Kumar

[@]Reddy, Shri Ch. Malla

Reddy, Shri J.C. Divakar

Rijiju, Shri Kiren

[@] Voted through slip.

Rudy, Shri Rajiv Pratap

@Sahu, Shri Chandulal

Sahu, Shri Lakhan Lal

Sai, Shri Vishnu Dev

Saini, Shri Rajkumar

Sampla, Shri Vijay

Sangma, Shri Purno Agitok

Sanjar, Shri Alok

Sarmah, Shri Ram Prasad

Sarswati, Shri Sumedhanand

Sathyabama, Shrimati V.

Sawaikar, Adv. Narendra Keshav

Senguttuvan, Shri B.

Senthilnathan, Shri P. R.

Shah, Shrimati Mala Rajyalakshmi

Sharma, Dr. Mahesh

Sharma, Shri Ram Kumar

Sharma, Shri Ram Swaroop

Shekhawat, Shri Gajendra Singh

Shetty, Shri Gopal

Shirole, Shri Anil

Shyal, Dr. Bhartiben D.

Siddeshwara, Shri G. M.

Sigriwal, Shri Janardan Singh

Simha, Shri Pratap

Singh, Dr. Bhola

@Singh, Dr. Jitendra

Singh, Dr. Nepal

@ Voted through slip.

Singh, Dr. Satya Pal

Singh, Dr. Yashwant

Singh, Gen. (Retd) Vijay Kumar

Singh, Kunwar Bharatendra

Singh, Kunwar Haribansh

Singh, Rao Inderjit

Singh, Shri Abhishek

Singh, Shri Bharat

Singh, Shri Bhola

Singh, Shri Brijbhushan Sharan

Singh, Shri Dushyant

Singh, Shri Giriraj

Singh, Shri Hukum

Singh, Shri Kirti Vardhan

Singh, Shri Lallu

Singh, Shri Nagendra

Singh, Shri Pashupati Nath

Singh, Shri R. K.

Singh, Shri Rajnath

Singh (Raju Bhaiya), Shri Rajveer

Singh, Shri Rakesh

Singh, Shri Satyapal

Singh, Shri Sunil Kumar

Singh, Shri Sushil Kumar

Singh, Shri Uday Pratap

Singh, Shri Virendra

Sinha, Shri Jayant

Sinha, Shri Manoj

Solanki, Dr. Kirit P.

Somaiya, Dr. Kirit

Sonkar, Shri Vinod Kumar

Sonker, Shrimati Neelam

Sonowal, Shri Sarbananda

Srinivas, Shri Kesineni

Sriramulu, Shri B.

Sundaram, Shri P. R.

Swaraj, Shrimati Sushma

[@]Tadas, Shri Ramdas C.

Tamta, Shri Ajay

Tanwar, Shri Kanwar Singh

Tasa, Shri Kamakhya Prasad

Teli, Shri Rameshwar

Teni, Shri Ajay Misra

Thakur, Shri Anurag Singh

Thambidurai, Dr. M.

Tiwari, Shri Manoj

Tripathi, Shri Sharad

Udasi, Shri Shivkumar

Udhayakumar, Shri M.

@Usendi, Shri Vikram

@Vanaroja, Shrimati R.

Vardhan, Dr. Harsh

Vasanthi, Shrimati M.

Vasava, Shri Parbhubhai Nagarbhai

Venugopal, Dr. P.

Verma, Dr. Anshul

Verma, Shri Bhanu Pratap Singh

[@] Voted through slip.

Verma, Shri Parvesh Sahib Singh

Verma, Shri Rajesh

Verma, Shrimati Rekha

Vijaya Kumar, Shri S. R.

Wanga, Shri Chintaman Navasha

Yadav, Shri Hukmdeo Narayan

Yadav, Shri Laxmi Narayan

Yadav, Shri Om Prakash

Yadav, Shri Ram Kripal

Yediyurappa, Shri B.S.

ABSTAIN

Adsul, Shri Anandrao

Barne, Shri Shrirang Appa

Gaikwad, Prof. Ravindra Vishwanath

Gawali, Shrimati Bhavana Pundalikrao

Geete, Shri Anant Gangaram

Godse, Shri Hemant Tukaram

Jadhav, Shri Prataprao

Jadhav, Shri Sanjay Haribhau

Khaire, Shri Chandrakant

Kirtikar, Shri Gajanan

Lokhande, Shri Sadashiv

Raut, Shri Vinayak Bhaurao

Sawant, Shri Arvind

Shewale, Shri Rahul

Shinde, Dr. Shrikant Eknath

Shivajirao, Shri Adhalrao Patil

Vichare, Shri Rajan

HON. SPEAKER: Subject to correction*, the result of the Division is:

Ayes: 101

Noes: 304

Abstain:17

The motion was negatived.

HON. SPEAKER: Prof. Saugata Roy, are you moving your Amendment No.5 to Clause 5?

PROF. SAUGATA ROY: I am not moving my Amendment No.5 to Clause 5.

HON. SPEAKER: Shri Jai Prakash Narayan Yadav, are you moving your Amendment No.10 to Clause 5?

श्री जय प्रकाश नारायण यादव (बाँका) : अध्यक्ष जी, यह बोलें कि अच्छे दिना लायेंगे,...(व्यवधान) अच्छे दिन तो आये नहीं,...(व्यवधान) लेकिन बुरा दिन आ गया।...(व्यवधान)।

मैं प्रस्ताव करता हूं

पृष्ठ 3, पंक्ति 4 के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाए, -

'परंतु यह कि निजी परियोजनाओं और सरकारी निजी भागीदारी के अंतर्गत परियोजनाओं के मामले में प्रभावित व्यक्तियों के कम से कम अस्सी प्रतिशत और सत्तर प्रतिशत की सहमति अनिवार्य होगी' (10)

---

* The following Members also recorded/corrected their votes through slips:

Ayes: 101 + S/Shri H.D. Devegowda, Innocent, C.N. Jayadevan, Prof. Saugat Roy, S/Shri Tamradhwaj Sahu = **106**

Noes: 304 + S/Shri Om Birla, Dharambir, Sher Singh Ghubaya, Dr. Sajnay Jaiswal, Shri Sukhbir Singh Jaunapurua, Shri Virender Kashyap, Shrimati Meenakshi Lekhi, S/Shri Kalraj Mishra, Jual Oram, Ch. Mala Reddy, Chandulal Sahu, Dr. Jitendra Singh, S/Shri Ramdas C. Tadas, Vikram Usendi, Shrimati R. Vanaroja = **319**

Abstain: 017

HON. SPEAKER: I shall now put Amendment No.10 to Clause 5 to the vote of the House. The Lobbies have already been cleared.

The question is:

'पृष्ठ 3, पंक्ति 4 के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाए, -

'परंतु यह कि निजी परियोजनाओं और सरकारी निजी भागीदारी के अंतर्गत परियोजनाओं के मामले में प्रभावित व्यक्तियों के कम से कम अस्सी प्रतिशत और सत्तर प्रतिशत की सहमति अनिवार्य होगी' (10)'

The Lok Sabha divided:

DIVISION NO. 6 **AYES** **19.13 hrs.**

Adhikari, Shri Sisir Kumar

Adhikari, Shri Suvendu

Ahmed, Shri Sultan

Ali, Shri Idris

Antony, Shri Anto

Anwar, Shri Tariq

Baite, Shri Thangso

Banerjee, Shri Abhishek

Banerjee, Shri Kalyan

Banerjee, Shri Prasun

Barman, Shri Bijoy Chandra

Bhonsale, Shri Chh. Udayanraje

Biju, Shri P. K.

Bose, Prof. Sugata

Chandrappa, Shri B. N.

Chaudhury, Shri Jitendra

Chavan, Shri Ashok Shankarrao

@Chowdhury, Shri A. H. khan

@Chowdhury, Shri Adhir Ranjan

Dastidar, Dr. Kakoli Ghosh

Datta, Shri Sankar Prasad

De(Nag), Dr. Ratna

Dev, Kumari Sushmita

@Devegowda, Shri H.D.

Engti, Shri Biren Singh

Faizal, Mohammed

@ Voted through slip.

Geetha, Shrimati Kothapalli

George, Adv. Joice

Ghosh, Shrimati Arpita

Gogoi, Shri Gaurav

Gowda, Shri S.P. Muddahanume

Hansdak, Shri Vijay Kumar

Haque, Shri Mohd. Asrarul

Hazra, Dr. Anupam

Hooda, Shri Deepender Singh

@Innocent, Shri

Jatua, Shri Choudhury Mohan

@Jayadevan, Shri C. N

Kalvakuntla, Shrimati kavitha

Karunakaran, Shri P.

Kharge, Shri Mallikarjun

Kumar, Shri Kaushalendra

Kumar, Shri Santosh

Kumar, Shri Shailesh

@Mahato, Dr. Mriganka

Mandal, Dr. Tapas

Mann, Shri Bhagwant

Meinya, Dr. Thokchom

Mondal, Shri Sunil Kumar

Mondal, Shrimati Pratima

Mukherjee, Shri Abhijit

Muniyappa, Shri K.H.

Nagesh, Shri Godam

@ Voted through slip.

Naik, Shri B.V.

Nath, Shri Kamal

Noor, Shrimati Mausam

Pala, Shri Vincent H.

Poddar, Shrimati Aparupa

Premachandran, Shri N.K.

Rajesh, Shri M. B.

Raju, Shri C.S. Putta

Ramachandran, Shri Mullappally

Ranjan, Shri Rajesh

Ranjan, Shrimati Ranjeet

[@]Reddy, Shri Gutha Sukender

Reddy, Shri Mekapati Raja Mohan

Reddy, Shri P. Srinivasa

Reddy, Shri Y. V. Subba

Renuka, Shrimati Butta

Roy, Prof. Saugata

Roy, Shrimati Sandhya

Ruala, Shri C.L.

Sahu, Shri Tamradhwaj

Sampath, Dr. A.

Sanghamita, Dr. Mamtaz

Saren, Dr. Uma

Satav, Shri Rajeev

Scindia, Shri Jyotiraditya M.

Shetty, Shri Raju

Singh, Prof. Sadhu

[@] Voted through slip.

Singh, Shri Ravneet

Sinha, Shrimati Renuka

Sule, Shrimati Supriya

Suresh, Shri D.K.

Suresh, Shri Kodikunnil

Teacher, Shrimati P.K. Shreemathi

Thakur, Shrimati Mamata

Tharoor, Dr. Shashi

Thomas, Prof. K.V.

[@]Tirkey, Shri Dasrath

Trivedi, Shri Dinesh

Uddin, Shri Tasleem

Varma, Shrimati Dev

Velagapalli, Shri Varaprasad Rao

Venugopal, Shri K. C.

Yadav, Shri Akshay

Yadav, Shri Dharmendra

Yadav, Shri Jai Prakash Narayan

Yadav, Shri Tej Pratap Singh

Yadav, Shrimati Dimple

Yellaiah, Shri Nandi

[@] Voted through slip.

NOES

Adityanath, Yogi

Advani, Shri L.K.

Ahir, Shri Hansraj Gangaram

Ahlawat, Shrimati Santosh

@Ahluwalia, Shri S.S.

Amarappa , Shri Karadi Sanganna

Ananthkumar, Shri

Angadi, Shri Suresh C.

Arunmozhithevan, Shri A.

Azad, Shri Kirti

Babu, Dr. Ravindra

Badal, Shrimati Harsimrat Kaur

Baheria, Shri Subhash Chandra

Bais, Shri Ramesh

Bala, Shrimati Anju

Balyan, Dr. Sanjeev

Bansode, Adv. Sharadkumar Maruti

Bhabhor, Shri Jasvantsinh Sumanbhai

Bhagat, Shri Sudarshan

Bhamre, Dr. Subhash Ramrao

Bharathi Mohan, Shri R.K.

Bharti, Sushri Uma

Bhatt, Shrimati Ranjanben

Bhole, Shri Devendra Singh

Bhuria, Shri Dileep Singh

Bidhuri, Shri Ramesh

Birla, Shri Om

@ Voted through slip.

Bohra, Shri Ramcharan

Brahmpura, Shri Ranjit Singh

Chakravarty, Shrimati Bijoya

Chand, Shri Nihal

Chandel, Kunwar Pushpendra Singh

Chandrakasi, Shri M.

Chandumajra, Shri Prem Singh

Chaudhary, Shri C. R.

Chaudhary, Shri Haribhai

Chaudhary, Shri P.P.

Chaudhary, Shri Pankaj

Chaudhary, Shri Ram Tahal

Chauhan, Shri Devusinh

@Chauhan, Shri P. P.

Chhewang, Shri Thupstan

Chhotelal, Shri

Chinnaiyan, Shri S. Selvakumara

@Choubey, Shri Ashwini Kumar

Choudhary, Col. Sonaram

@Choudhary, Shri Babulal

Choudhary, Shri Birendra Kumar

Chouhan, Shri Nandkumar Singh

Chudasama, Shri Rajeshbhai

Danve, Shri Raosaheb Patil

Dattatreya, Shri Bandaru

Deka, Shri Ramen

Devi, Shrimati Rama

Devi, Shrimati Veena

@ Voted through slip.

@Dharambir, Shri

Dhotre, Shri Sanjay

Dhurve, Shrimati Jyoti

Diwakar, Shri Rajesh Kumar

Dubey, Shri Nishikant

Dubey, Shri Satish Chandra

Dwivedi, Shri Harishchandra alias Harish

Elumalai, Shri V.

Fatepara, Shri Devjibhai G.

Gaddigoudar, Shri P.C.

Gadkari, Shri Nitin

Gaikwad, Dr. Sunil Baliram

Galla, Shri Jayadev

Gandhi, Shri Dilipkumar Mansukhlal

Gandhi, Shrimati Maneka Sanjay

Gangwar, Shri Santosh Kumar

Gautam, Shri Satish Kumar

Gavit, Dr. Heena Vijaykumar

@Ghubaya, Shri Sher Singh

Giluwa, Shri Laxman

Girri, Shri Maheish

Gohain, Shri Rajen

Gopal, Dr. K.

Gopalakrishnan, Shri C.

Gopalakrishnan, Shri R.

Goud, Dr. Boora Narsaiah

Gowda, Shri D.V. Sadananda

@ Voted through slip.

Gupta, Shri Shyama Charan

Gurjar, Shri Krishanpal

Hari, Shri G.

Haribabu, Dr. Kambhampati

Hegde, Shri Anantkumar

Hemamalini, Shrimati)

Jardosh, Shrimati Darshana Vikram

Jat, Prof. Sanwar Lal

Jaunapuria, Shri Sukhbir Singh

Jayavardhan, Dr. J.

Jigajinagi, Shri Ramesh

Joshi, Dr. Murli Manohar

Joshi, Shri Pralhad

Jyoti, Sadhvi Niranjan

Kachhadia, Shri Naranbhai

Kaiser, Choudhary Mehboob Ali

Kamaraj, Dr. K.

Karandlaje, Kumari Shobha

Kashyap, Shri Virender

Kaswan, Shri Rahul

Kataria, Shri Rattan Lal

Kateel, Shri Nalin Kumar

Katheria, Dr. Ramshankar

Kaushik, Shri Ramesh Chander

Khadse, Shrimati Rakshatai

Khanduri AVSM, Maj. Gen. (Retd.) B.C.

Khanna, Shri Vinod

Kher, Shrimati Kirron

Khuba, Shri Bhagwanth

Kinjarapu, Shri Ram Mohan Naidu

Kishore, Shri Jugal

Kishore, Shri Kaushal

Koli, Shri Bahadur Singh

Koshyari, Shri Bhagat Singh

Kristappa, Shri N.

Kulaste, Shri Faggan Singh

Kumar, Dr. Arun

Kumar, Dr. Virendra

Kumar, Kunwar Sarvesh

Kumar, Shri Ashwini

Kumar, Shri Dharmendra

Kumar, Shri K. Ashok

Kumar, Shri P.

Kumar, Shri Shanta

Kundariya, Shri Mohanbhai Kalyanjibhai

Kushawaha, Shri Ravinder

Kushwaha, Shri Upendra

Lakhanpal, Shri Raghav

Lekhi, Shrimati Meenakashi

Maadam, Shrimati Poonamben

Maharaj, Dr. Swami Sakshiji

Mahato, Dr. Banshilal

[$]Mahato, Shri Bidyut Baran

Mahendran, Shri C.

Malviya, Prof. Chintamani

Manjhi, Shri Hari

Marabi, Shri Kamal Bhan Singh

[$] Corrected through slip for Noes.

Maragatham, Shrimati K.

Marutharajaa, Shri R. P.

Maurya, Shri Keshav Prasad

Meena, Shri Arjun Lal

Meena, Shri Harish

Meghwal, Shri Arjun Ram

Mishra, Shri Anoop

Mishra, Shri Bhairon Prasad

Mishra, Shri Daddan

Mishra, Shri Janardan

@Mishra, Shri Kalraj

Mohan, Shri M. Murli

Mohan, Shri P.C.

Munda, Shri Karia

Nagar, Shri Rodmal

Nagarajan, Shri P.

Naik, Prof. A.S.R.

Narasimham, Shri Thota

Nath, Shri Chand

Natterjee, Shri J.J.T.

Nete, Shri Ashok Mahadeorao

Nishad, Shri Ajay

Nishad, Shri Ram Charitra

Nishank, Dr. Ramesh Pokhriyal

Oram, Shri Jual

Paatle, Shrimati Kamla

Pal, Shri Jagdambika

Pandey, Dr. Mahendra Nath

@ Voted through slip.

Pandey, Shri Hari Om

Pandey, Shri Rajesh

Pandey, Shri Ravindra Kumar

Panneerselvam, Shri V.

Parasuraman, Shri K.

Parthipan, Shri R.

Paswan, Shri Chhedi

Paswan, Shri Chirag

Paswan, Shri Ram Chandra

Paswan, Shri Ramvilas

Patel, Dr. K. C.

Patel, Shri Devji M.

Patel, Shri Dilip

Patel, Shri Lalubhai Babubhai

Patel, Shri Natubhai Gomanbhai

Patel, Shri Prahlad Singh

Patel, Shri Subhash

Patel, Shrimati Anupriya

Patel, Shrimati Jayshreeben

Pathak, Shrimati Riti

[@]Patil, Shri A.T. Nana

Patil, Shri C. R.

Patil, Shri Kapil Moreshwar

Patil, Shri Sanjay Kaka

Patole, Shri Nana

Phule, Sadhvi Savitri Bai

Prabakaran, Shri K. R. P.

Prasad, Dr. Bhagirath

[@] Voted through slip.

Pratap, Shri Krishan

Radhakrishnan, Shri Pon

Radhakrishnan, Shri T.

Rai, Shri Nityanand

Raj, Dr. Udit

Raj, Shrimati Krishna

Raajhaa, Shri A. Anwhar

Rajbhar, Shri Harinarayan

Rajendran, Shri S.

Rajoria, Dr. Manoj

Rajput, Shri Mukesh

Raju, Shri Ashok Gajapathi

Raju, Shri Gokaraju Ganga

Ram, Shri Janak

Ram, Shri Vishnu Dayal

Ramachandran, Shri K. N.

Rao, Shri Konakalla Narayana

Rao (Avanthi), Shri Muthamsetti Srinivasa

Rao, Shri Rayapati Sambasiva

Rathod, Shri D.S.

Rathore, Col. Rajyavardhan

Rathore, Shri Hariom Singh

Rathwa, Shri Ramsinh

Raval, Shri Paresh

Rawat, Shrimati Priyanka Singh

Ray, Shri Bishnu Pada

Ray, Shri Ravindra Kumar

@Reddy, Shri Ch. Malla

Reddy, Shri J.C. Divakar

Reddy, Shri P.V. Midhun

Rijiju, Shri Kiren

Rudy, Shri Rajiv Pratap

Sahu, Shri Chandulal

Sahu, Shri Lakhan Lal

@Sai, Shri Vishnu Dev

Saini, Shri Rajkumar

Sampla, Shri Vijay

Sangma, Shri Purno Agitok

Sanjar, Shri Alok

Sarmah, Shri Ram Prasad

Sarswati, Shri Sumedhanand

Sathyabama, Shrimati V.

Sawaikar, Adv. Narendra Keshav

Senguttuvan, Shri B.

Senthilnathan, Shri P. R.

Shah, Shrimati Mala Rajyalakshmi

Sharma, Dr. Mahesh

Sharma, Shri Ram Kumar

Sharma, Shri Ram Swaroop

Shekhawat, Shri Gajendra Singh

Shetty, Shri Gopal

Shirole, Shri Anil

Shyal, Dr. Bhartiben D.

Siddeshwara, Shri G. M.

Sigriwal, Shri Janardan Singh

@ Votes through slip.

Simha, Shri Pratap

Singh, Dr. Bhola

Singh, Dr. Jitendra

Singh, Dr. Nepal

@Singh, Dr. Satya Pal

Singh, Dr. Yashwant

Singh, Gen. (Retd) Vijay Kumar

Singh, Kunwar Bharatendra

Singh, Kunwar Haribansh

Singh, Rao Inderjit

Singh, Shri Abhishek

Singh, Shri Bharat

Singh, Shri Bhola

Singh, Shri Brijbhushan Sharan

Singh, Shri Dushyant

Singh, Shri Giriraj

Singh, Shri Hukum

Singh, Shri Kirti Vardhan

Singh, Shri Lallu

Singh, Shri Nagendra

Singh, Shri Pashupati Nath

Singh, Shri R. K.

Singh, Shri Rajnath

Singh (Raju Bhaiya), Shri Rajveer

Singh, Shri Rakesh

Singh, Shri Satyapal

Singh, Shri Sunil Kumar

Singh, Shri Sushil Kumar

@ Voted through slip.

Singh, Shri Uday Pratap

Singh, Shri Virendra

Sinha, Shri Jayant

Sinha, Shri Manoj

Solanki, Dr. Kirit P.

Somaiya, Dr. Kirit

Sonkar, Shri Vinod Kumar

Sonker, Shrimati Neelam

Sonowal, Shri Sarbananda

Srinivas, Shri Kesineni

@Sriram, Shri Malyadri

Sriramulu, Shri B.

Sundaram, Shri P. R.

Swaraj, Shrimati Sushma

Tadas, Shri Ramdas C.

Tamta, Shri Ajay

Tanwar, Shri Kanwar Singh

Tasa, Shri Kamakhya Prasad

Teli, Shri Rameshwar

Teni, Shri Ajay Misra

Thakur, Shri Anurag Singh

Thambidurai, Dr. M.

Tiwari, Shri Manoj

Tripathi, Shri Sharad

Udasi, Shri Shivkumar

Udhayakumar, Shri M.

Usendi, Shri Vikram

Vanaroja, Shrimati R.

@ Voted through slip.

Vardhan, Dr. Harsh

Vasanthi, Shrimati M.

Vasava, Shri Parbhubhai Nagarbhai

Venugopal, Dr. P.

Verma, Dr. Anshul

Verma, Shri Bhanu Pratap Singh

Verma, Shri Parvesh Sahib Singh

Verma, Shri Rajesh

Verma, Shrimati Rekha

Vijaya Kumar, Shri S. R.

Wanga, Shri Chintaman Navasha

Yadav, Shri Hukmdeo Narayan

Yadav, Shri Laxmi Narayan

Yadav, Shri Om Prakash

Yadav, Shri Ram Kripal

Yediyurappa, Shri B.S.

ABSTAIN

Barne, Shri Shrirang Appa

Gaikwad, Prof. Ravindra Vishwanath

Gawali, Shrimati Bhavana Pundalikrao

Geete, Shri Anant Gangaram

Godse, Shri Hemant Tukaram

Jadhav, Shri Prataprao

Jadhav, Shri Sanjay Haribhau

Khaire, Shri Chandrakant

Kirtikar, Shri Gajanan

Lokhande, Shri Sadashiv

Raut, Shri Vinayak Bhaurao

Sawant, Shri Arvind

Shewale, Shri Rahul

Shinde, Dr. Shrikant Eknath

Shivajirao, Shri Adhalrao Patil

Vichare, Shri Rajan

HON. SPEAKER: Subject to correction*, the result of the Division is:

Ayes: 094

Noes: 309

Abstain:16

The motion was negatived.

HON. SPEAKER: Shri H.D. Deve Gowda, are you moving your Amendment No.11 to Clause 5?

SHRI H.D. DEVEGOWDA (HASSAN): I beg to move:

Page 2, *after* line 27, *add*--

"Provided that the projects exempted from the application of the provisions of Chapter II and Chapter III shall be compulsorily audited by the Comptroller and Auditor General of India.". (11)

HON. SPEAKER: The question is:

Page 2, *after* line 27, *add*--

"Provided that the projects exempted from the application of the provisions of Chapter II and Chapter III shall be compulsorily audited by the Comptroller and Auditor General of India.". (11)

The Amendment was put and negatived.

---

* The following Members also recorded/corrected their votes through slips:

Ayes: 094 + S/Shri A.H. Khan Chowdhury, Adhir Ranjan Chowdhury, H.D. Devegowda, Innocent, C.N. Jayadevan, Dr. Mriganka Mahato, Gutha Sukender Reddy, Dasrath Tirkey - Shri Bidyut Baran Mahato = **101**

Noes: 309 +S/ Shri S.S. Ahluwalia, P.P. Chauhan, Ashwini Kumar Choubey, Babulal Choudhary, Dharambir, Sher Singh Ghubaya, Bidyut Baran Mahato, Kalraj Mishra, A.T. Nana Patil, Ch. Malla Reddy, Vishnu Dev Sai, Dr. Satya Pal Singh, Shri Malyadri Sriram = **322**

Abstain: 016

HON. SPEAKER: Shri N.K. Premachandran, are you moving your Amendment No.14 to Clause 5?

SHRI N.K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): I beg to move:

Page 2, line 18,--

for "the following projects from the application",

substitute "the following projects of the Government from the application".

(14)

My amendment is in respect of Clause 5. I would say that the appropriate Government may, in the public interest, by Notification, exempt any of the following projects:

I would like to add `the following projects of the Government'. That means, `only for the Government projects' these five categories exemptions is there; for private, `no'. That is my amendment. It can be accepted because in the amendment, which is moved by the hon. Minister also, `appropriate Government is there'. So, if the hon. Minister is so generous to accept the constructive proposals of the Opposition, kindly accept this amendment proposal.

HON. SPEAKER: I shall now put the Amendment No. 14 to Clause 5 moved by Shri N..K. Premachandran to the vote of the House.

The amendment was put and negatived.

HON. SPEAKER: Now, Amendment No.15 to Clause 5. Shri Premachandran, are you moving?

SHRI N.K. PREMACHANDRAN: I beg to move:

"Page 2, *omit* lines 25 to 27"

My amendment No.15 is in Page 2, which omits lines 25 to 27. I am pressing for this amendment because `lines 25 to 27' are infrastructure and social infrastructure projects including projects under Public Private Partnership where the ownership of land continues vests with the Government. My proposed amendment is for deletion of this clause which deals with Private Partnership infrastructure. I press for the amendment.

HON. SPEAKER: I shall now put the Amendment No.15 to Clause 5 moved by Shri N..K. Premachandran to the vote of the House.

SHRI N.K. PREMACHANDRAN: I want division.

HON. SPEAKER: The Lobbies have already been cleared.

The question is:

"Page 2, *omit* lines 25 to 27"

The Lok Sabha divided:

DIVISION NO. 7. **AYES** **19.17 hrs.**

Adhikari, Shri Sisir Kumar

Adhikari, Shri Suvendu

Ahmed, Shri Sultan

Antony, Shri Anto

Anwar, Shri Tariq

Baite, Shri Thangso

Banerjee, Shri Abhishek

Banerjee, Shri Kalyan

Banerjee, Shri Prasun

Barman, Shri Bijoy Chandra

Bhonsale, Shri Chh. Udayanraje

Biju, Shri P. K.

Bose, Prof. Sugata

Chandrappa, Shri B. N.

Chaudhury, Shri Jitendra

Chavan, Shri Ashok Shankarrao

@Chowdhury, Shri A. H. khan

Chowdhury, Shri Adhir Ranjan

Dastidar, Dr. Kakoli Ghosh

Datta, Shri Sankar Prasad

De(Nag), Dr. Ratna

Dev, Kumari Sushmita

@Devegowda, Shri H.D.

Engti, Shri Biren Singh

Faizal, Mohammed

@ Voted through slip.

Geetha, Shrimati Kothapalli

George, Adv. Joice

Ghosh, Shrimati Arpita

Gogoi, Shri Gaurav

Gowda, Shri S.P. Muddahanume

Hansdak, Shri Vijay Kumar

@Haque, Shri Mohd. Asrarul

@Hazra, Dr. Anupam

Hooda, Shri Deepender Singh

@Innocent, Shri

Jatua, Shri Choudhury Mohan

@Jayadevan, Shri C. N

Kalvakuntla, Shrimati kavitha

Karunakaran, Shri P.

Khan, Shri Saumitra

Kharge, Shri Mallikarjun

Kumar, Shri Kaushalendra

Kumar, Shri Santosh

Kumar, Shri Shailesh

@Mann, Shri Bhagwant

Meinya, Dr. Thokchom

Moily, Shri M. Veerappa

Mukherjee, Shri Abhijit

Muniyappa, Shri K.H.

Nagesh, Shri Godam

Naik, Prof. A.S.R.

Naik, Shri B.V.

Nath, Shri Kamal

@ Voted through slip.

Noor, Shrimati Mausam

Pala, Shri Vincent H.

Poddar, Shrimati Aparupa

Premachandran, Shri N.K.

Rajesh, Shri M. B.

Raju, Shri C.S. Putta

Ramachandran, Shri Mullappally

Ranjan, Shri Rajesh

Ranjan, Shrimati Ranjeet

Reddy, Shri Gutha Sukender

Reddy, Shri Mekapati Raja Mohan

Reddy, Shri P. Srinivasa

Reddy, Shri Y. V. Subba

Renuka, Shrimati Butta

Roy, Prof. Saugata

Roy, Shrimati Sandhya

Sahu, Shri Tamradhwaj

Sampath, Dr. A.

Sanghamita, Dr. Mamtaz

Saren, Dr. Uma

Satav, Shri Rajeev

Scindia, Shri Jyotiraditya M.

Shetty, Shri Raju

Singh, Prof. Sadhu

Singh, Shri Ravneet

Sinha, Shrimati Renuka

Sule, Shrimati Supriya

Suresh, Shri D.K.

Suresh, Shri Kodikunnil

Teacher, Shrimati P.K. Shreemathi

Thakur, Shrimati Mamata

Tharoor, Dr. Shashi

Thomas, Prof. K.V.

Trivedi, Shri Dinesh

Uddin, Shri Tasleem

Varma, Shrimati Dev

Velagapalli, Shri Varaprasad Rao

Venugopal, Shri K. C.

Yadav, Shri Akshay

Yadav, Shri Dharmendra

Yadav, Shri Jai Prakash Narayan

Yadav, Shri Tej Pratap Singh

Yadav, Shrimati Dimple

Yellaiah, Shri Nandi

NOES

Adityanath, Yogi

Advani, Shri L.K.

Ahir, Shri Hansraj Gangaram

Ahlawat, Shrimati Santosh

Ahluwalia, Shri S.S.

Amarappa , Shri Karadi Sanganna

Ananthkumar, Shri

Angadi, Shri Suresh C.

Arunmozhithevan, Shri A.

[@]Azad, Shri Kirti

Babu, Dr. Ravindra

Badal, Shrimati Harsimrat Kaur

Baheria, Shri Subhash Chandra

Bais, Shri Ramesh

Bala, Shrimati Anju

Balyan, Dr. Sanjeev

Bansode, Adv. Sharadkumar Maruti

Bhabhor, Shri Jasvantsinh Sumanbhai

Bhagat, Shri Sudarshan

Bhamre, Dr. Subhash Ramrao

Bharathi Mohan, Shri R.K.

Bharti, Sushri Uma

Bhatt, Shrimati Ranjanben

Bhole, Shri Devendra Singh

Bhuria, Shri Dileep Singh

Bidhuri, Shri Ramesh

Birla, Shri Om

[@] Voted through slip.

Bohra, Shri Ramcharan

Brahmpura, Shri Ranjit Singh

Chakravarty, Shrimati Bijoya

Chand, Shri Nihal

Chandel, Kunwar Pushpendra Singh

Chandrakasi, Shri M.

Chandumajra, Shri Prem Singh

Chaudhary, Shri C. R.

Chaudhary, Shri Haribhai

Chaudhary, Shri P.P.

Chaudhary, Shri Pankaj

Chaudhary, Shri Ram Tahal

Chauhan, Shri Devusinh

Chauhan, Shri P. P.

Chhewang, Shri Thupstan

Chhotelal, Shri

Chinnaiyan, Shri S. Selvakumara

Choubey, Shri Ashwini Kumar

Choudhary, Col. Sonaram

Choudhary, Shri Babulal

Choudhary, Shri Birendra Kumar

Chouhan, Shri Nandkumar Singh

Chudasama, Shri Rajeshbhai

Danve, Shri Raosaheb Patil

Dattatreya, Shri Bandaru

Deka, Shri Ramen

Devi, Shrimati Rama

Devi, Shrimati Veena

Dharambir, Shri

Dhotre, Shri Sanjay

Dhurve, Shrimati Jyoti

Diwakar, Shri Rajesh Kumar

Dubey, Shri Nishikant

Dubey, Shri Satish Chandra

Dwivedi, Shri Harishchandra alias Harish

Elumalai, Shri V.

Fatepara, Shri Devjibhai G.

Gaddigoudar, Shri P.C.

[@]Gadkari, Shri Nitin

Gaikwad, Dr. Sunil Baliram

Galla, Shri Jayadev

Gandhi, Shri Dilipkumar Mansukhlal

Gandhi, Shrimati Maneka Sanjay

Gangwar, Shri Santosh Kumar

Gautam, Shri Satish Kumar

Gavit, Dr. Heena Vijaykumar

Ghubaya, Shri Sher Singh

Giluwa, Shri Laxman

Girri, Shri Maheish

Gohain, Shri Rajen

Gopal, Dr. K.

Gopalakrishnan, Shri C.

Gopalakrishnan, Shri R.

Goud, Dr. Boora Narsaiah

Gowda, Shri D.V. Sadananda

Gupta, Shri Shyama Charan

Gurjar, Shri Krishanpal

[@] Voted through slip.

Hari, Shri G.

Haribabu, Dr. Kambhampati

Hegde, Shri Anantkumar

Hemamalini, Shrimati)

Jaiswal, Dr. Sanjay Haribhau

Jardosh, Shrimati Darshana Vikram

Jat, Prof. Sanwar Lal

Jaunapuria, Shri Sukhbir Singh

Jayavardhan, Dr. J.

Jigajinagi, Shri Ramesh

Joshi, Dr. Murli Manohar

Joshi, Shri Pralhad

Jyoti, Sadhvi Niranjan

Kachhadia, Shri Naranbhai

Kaiser, Choudhary Mehboob Ali

Kamaraj, Dr. K.

Karandlaje, Kumari Shobha

Kashyap, Shri Virender

Kaswan, Shri Rahul

Kataria, Shri Rattan Lal

Kateel, Shri Nalin Kumar

Katheria, Dr. Ramshankar

Kaushik, Shri Ramesh Chander

Khadse, Shrimati Rakshatai

Khanduri AVSM, Maj. Gen. (Retd.) B.C.

Khanna, Shri Vinod

Kher, Shrimati Kirron

Khuba, Shri Bhagwanth

Kinjarapu, Shri Ram Mohan Naidu

Kishore, Shri Jugal

Kishore, Shri Kaushal

Koli, Shri Bahadur Singh

Koshyari, Shri Bhagat Singh

Kristappa, Shri N.

Kulaste, Shri Faggan Singh

Kumar, Dr. Arun

Kumar, Dr. Virendra

Kumar, Kunwar Sarvesh

Kumar, Shri Ashwini

Kumar, Shri Dharmendra

Kumar, Shri K. Ashok

Kumar, Shri P.

Kumar, Shri Shanta

[@]Kundariya, Shri Mohanbhai Kalyanjibhai

Kushawaha, Shri Ravinder

Kushwaha, Shri Upendra

Lakhanpal, Shri Raghav

Lekhi, Shrimati Meenakashi

Maadam, Shrimati Poonamben

Maharaj, Dr. Swami Sakshiji

Mahato, Dr. Banshilal

Mahato, Shri Bidyut Baran

Mahendran, Shri C.

Malviya, Prof. Chintamani

Manjhi, Shri Hari

Marabi, Shri Kamal Bhan Singh

Maragatham, Shrimati K.

[@] Voted through slip.

Marutharajaa, Shri R. P.

Maurya, Shri Keshav Prasad

Meena, Shri Harish

Meghwal, Shri Arjun Ram

Mishra, Shri Anoop

Mishra, Shri Bhairon Prasad

Mishra, Shri Daddan

Mishra, Shri Janardan

Mishra, Shri Kalraj

Mohan, Shri M. Murli

Mohan, Shri P.C.

[$]Munda, Shri Karia

Nagar, Shri Rodmal

Nagarajan, Shri P.

Narasimham, Shri Thota

Nath, Shri Chand

Natterjee, Shri J.J.T.

Nete, Shri Ashok Mahadeorao

Nishad, Shri Ajay

Nishad, Shri Ram Charitra

Nishank, Dr. Ramesh Pokhriyal

Oram, Shri Jual

Paatle, Shrimati Kamla

Pal, Shri Jagdambika

Pandey, Dr. Mahendra Nath

Pandey, Shri Hari Om

Pandey, Shri Rajesh

Pandey, Shri Ravindra Kumar

[$] Corrected through slip for Noes.

Panneerselvam, Shri V.

Parasuraman, Shri K.

Parthipan, Shri R.

Paswan, Shri Chhedi

Paswan, Shri Chirag

@Paswan, Shri Ram Chandra

Paswan, Shri Ramvilas

Patel, Dr. K. C.

Patel, Shri Devji M.

Patel, Shri Dilip

Patel, Shri Lalubhai Babubhai

Patel, Shri Natubhai Gomanbhai

Patel, Shri Prahlad Singh

Patel, Shri Subhash

Patel, Shrimati Anupriya

Patel, Shrimati Jayshreeben

Pathak, Shrimati Riti

Patil, Shri A.T. Nana

Patil, Shri C. R.

Patil, Shri Kapil Moreshwar

Patil, Shri Sanjay Kaka

Patole, Shri Nana

Phule, Sadhvi Savitri Bai

Prabakaran, Shri K. R. P.

@Prasad, Dr. Bhagirath

Pratap, Shri Krishan

Radhakrishnan, Shri Pon

Radhakrishnan, Shri R.

@ Voted through slip.

Radhakrishnan, Shri T.

Rai, Shri Nityanand

Raj, Dr. Udit

Raj, Shrimati Krishna

Raajhaa, Shri A. Anwhar

Rajbhar, Shri Harinarayan

Rajendran, Shri S.

Rajoria, Dr. Manoj

Rajput, Shri Mukesh

Raju, Shri Ashok Gajapathi

Raju, Shri Gokaraju Ganga

Ram, Shri Janak

Ram, Shri Vishnu Dayal

Ramachandran, Shri K. N.

Rao, Shri Konakalla Narayana

Rao (Avanthi), Shri Muthamsetti Srinivasa

Rao, Shri Rayapati Sambasiva

Rathod, Shri D.S.

Rathore, Col. Rajyavardhan

Rathore, Shri Hariom Singh

Rathwa, Shri Ramsinh

Raval, Shri Paresh

Rawat, Shrimati Priyanka Singh

Ray, Shri Bishnu Pada

Ray, Shri Ravindra Kumar

Reddy, Shri Ch. Malla

Reddy, Shri J.C. Divakar

Reddy, Shri P.V. Midhun

Rijiju, Shri Kiren

Rudy, Shri Rajiv Pratap

Sahu, Shri Chandulal

Sahu, Shri Lakhan Lal

Sai, Shri Vishnu Dev

Saini, Shri Rajkumar

Sampla, Shri Vijay

Sangma, Shri Purno Agitok

Sanjar, Shri Alok

Sarmah, Shri Ram Prasad

Sarswati, Shri Sumedhanand

Sathyabama, Shrimati V.

Sawaikar, Adv. Narendra Keshav

Senguttuvan, Shri B.

Senthilnathan, Shri P. R.

Shah, Shrimati Mala Rajyalakshmi

Sharma, Dr. Mahesh

Sharma, Shri Ram Kumar

Sharma, Shri Ram Swaroop

Shekhawat, Shri Gajendra Singh

Shetty, Shri Gopal

Shirole, Shri Anil

Shyal, Dr. Bhartiben D.

Siddeshwara, Shri G. M.

Sigriwal, Shri Janardan Singh

Simha, Shri Pratap

Singh, Dr. Bhola

Singh, Dr. Jitendra

Singh, Dr. Nepal

Singh, Dr. Satya Pal

Singh, Dr. Yashwant

Singh, Gen. (Retd) Vijay Kumar

Singh, Kunwar Bharatendra

Singh, Kunwar Haribansh

Singh, Rao Inderjit

Singh, Shri Abhishek

Singh, Shri Bharat

Singh, Shri Bhola

@Singh, Shri Brijbhushan Sharan

Singh, Shri Dushyant

Singh, Shri Giriraj

Singh, Shri Hukum

Singh, Shri Kirti Vardhan

Singh, Shri Lallu

Singh, Shri Nagendra

Singh, Shri Pashupati Nath

Singh, Shri R. K.

Singh, Shri Rajnath

Singh (Raju Bhaiya), Shri Rajveer

Singh, Shri Rakesh

Singh, Shri Satyapal

Singh, Shri Sunil Kumar

Singh, Shri Sushil Kumar

Singh, Shri Uday Pratap

Singh, Shri Virendra

Sinha, Shri Jayant

Sinha, Shri Manoj

Solanki, Dr. Kirit P.

@ Voted through slip.

Somaiya, Dr. Kirit

Sonkar, Shri Vinod Kumar

Sonker, Shrimati Neelam

Sonowal, Shri Sarbananda

Srinivas, Shri Kesineni

Sriram, Shri Malyadri

Sriramulu, Shri B.

Sundaram, Shri P. R.

Swaraj, Shrimati Sushma

Tadas, Shri Ramdas C.

Tamta, Shri Ajay

Tanwar, Shri Kanwar Singh

@Tasa, Shri Kamakhya Prasad

Teli, Shri Rameshwar

Teni, Shri Ajay Misra

Thakur, Shri Anurag Singh

Thambidurai, Dr. M.

Tiwari, Shri Manoj

Tripathi, Shri Sharad

Udasi, Shri Shivkumar

Udhayakumar, Shri M.

Usendi, Shri Vikram

Vanaroja, Shrimati R.

Vardhan, Dr. Harsh

@Vasanthi, Shrimati M.

Vasava, Shri Parbhubhai Nagarbhai

Venugopal, Dr. P.

Verma, Dr. Anshul

@ Voted through slip.

Verma, Shri Bhanu Pratap Singh

Verma, Shri Parvesh Sahib Singh

Verma, Shri Rajesh

Verma, Shrimati Rekha

Vijaya Kumar, Shri S. R.

Wanga, Shri Chintaman Navasha

Yadav, Shri Hukmdeo Narayan

Yadav, Shri Laxmi Narayan

Yadav, Shri Om Prakash

Yadav, Shri Ram Kripal

Yediyurappa, Shri B.S.

ABSTAIN

Adsul, Shri Anandrao

Barne, Shri Shrirang Appa

Gaikwad, Prof. Ravindra Vishwanath

Gawali, Shrimati Bhavana Pundalikrao

Geete, Shri Anant Gangaram

Godse, Shri Hemant Tukaram

Jadhav, Shri Prataprao

Jadhav, Shri Sanjay Haribhau

Khaire, Shri Chandrakant

Kirtikar, Shri Gajanan

Lokhande, Shri Sadashiv

Owaisi, Shri Asaduddin

Raut, Shri Vinayak Bhaurao

Sawant, Shri Arvind

Shewale, Shri Rahul

Shinde, Dr. Shrikant Eknath

Shivajirao, Shri Adhalrao Patil

Vichare, Shri Rajan

HON. SPEAKER: Subject to correction*, the result of the Division is:

Ayes: 090

Noes: 313

Abstain:19

The motion was negatived.

HON. SPEAKER: Now, Shri Raju Shetty – are you moving Amendment No.21 to Clause 21?

श्री राजू शेट्टी (हातकणंगले) : अध्यक्ष महोदया, किसानों की सहमति लिए बिना उनकी जमीन अधिग्रहण करना अन्याय है, इसलिए मैं संशोधन मूव कर रहा हूं।

मैं प्रस्ताव करता हूं:

पृष्ठ 2, पंक्ति 33 से 35 का और
पृष्ठ 3, पंक्ति 1 से 4 का
लोप किया जाए। (21)

The Amendment was put and negatived.

HON. SPEAKER: Shri Tathagata Satpathy – are you moving your Amendment No.25 to Clause 5?.

SHRI TATHAGATA SATPATHY (DHENKANAL): My amendments have more or less been met by the Minister, and very grudgingly, I have decided not to move them.

HON. SPEAKER: Now, we take up Amendment Nos. 39 and 40 to Clause 5. Shri B. Mahtab.

---

* The following Members also recorded/corrected their votes through slips.

Ayes: 090 + S/Shri A.H. Khan Chowdhury, H.D. Devegowda, Mohd. Asrarul Haque, Dr. Anupam Hazra, S/Shri Innocent, C.N. Jayadevan, Bhagwant Mann = **097**

Noes: 313 + S/Shri Kirti Azad, Nitin Gadkari, Mohanbhai Kalyanjibhai Kundariya, Karia Munda, Ram Chandra Paswan, Dr. Bhagirath Prasad, S/Shri Brijbhushan Sharan Singh, Kamakhya Prasad Tasa, Shrimati M. Vasanthi = **322**

Abstain: 019 - Shri Karia Munda = **018**

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): I may be allowed to speak a few words. This deals with deletion of Chapter III; this deals with the concerned clause; this deals with the right of citizen of this country; this deals with the dignity of farmers. So, in that respect, I would say that the suggestions that Biju Janata Dal had given, some aspects have been met by the Government.

There were five specific issues which were supposed to be added to the 13 issues. That was done by the UPA Government in 2013. Those five issues were: national security and defence, rural infrastructure, affordable housing or housing for the poor, industrial corridors, and social infrastructure projects including public-private partnership. Of these five, we have no issue as regards defence and national security. As regards the industrial corridors, the suggestion given is that you define and that has already been defined in the amendment that has been moved by the Minister. As regards public-private partnerships, the thing is still hazy. As regards rural infrastructure including electrification we have an issue because supplying electricity is no more a service sector activity. It is more like an economic activity.

In our manifesto, on page 43, Biju Janata Dal had categorically stated that wherever land is to be acquired for economic activity, the land loser should become a partner in that activity. … (*Interruptions*) I have to explain my party's position here, Madam. I am not giving a speech. Our party's viewpoint has been given by our leader Mr. Tathagat Satpathy.

We welcome certain steps the Government has taken, but some more steps need to be taken. When the Minister has stated that in future some more amendments may be done, … (*Interruptions*) I would say that in Chapter 3 you are withdrawing the power of the citizen which was given in the previous Act. That power of the citizen is being withdrawn by this amendment. I can only mention here that when the all-party meeting had taken place in 2013, this was agreed upon by all parties. It was a unanimous decision that consent clause should be there, and

that while taking away the right of the landowner or farmer he should be given voice to speak. I would say that because that is not happening and because on all the five issues only two have been addressed, Biju Janata Dal is walking out and is not participating in this voting. Thank you.

<u>19.29 hrs</u>

At this stage, Shri Bhartruhari Mahtab and some other hon. Members left the House.

HON. SPEAKER: Amendment No.43 to Clause 5. Shri K.C. Venugopal, are you moving?

SHRI K.C. VENUGOPAL (ALAPPUZHA): Madam, actually this legislation opens doors for forcible acquisition and that is why we are opposing it. Also, we are referring to your Standing Committee reports. As per your Standing Committee report, no government land can be acquired for PPP projects. I insist on that. There are two major pillars of this Bill – one is consent and the other is social impact assessment – and both are destroyed by the government. Therefore, I am moving my amendment.

HON. SPEAKER: I now put Amendment No.43 to Clause 5 moved by Shri K.C. Venogopal to the vote of the House.

SHRI K.C. VENUGOPAL: I want Division, Madam.

HON. SPEAKER: The Lobbies have already been cleared.

The question is:

"Page 2, *omit* lines 24 to 27."

The Lok Sabha divided:

DIVISION NO. 8 **AYES** **19.25 hrs.**

Adhikari, Shri Sisir Kumar
Adhikari, Shri Suvendu
Ahmed, Shri Sultan
Ali, Shri Idris
Antony, Shri Anto
Anwar, Shri Tariq
Baite, Shri Thangso
Banerjee, Shri Abhishek
Banerjee, Shri Kalyan
Banerjee, Shri Prasun
Barman, Shri Bijoy Chandra
Bhonsale, Shri Chh. Udayanraje
Biju, Shri P. K.
Bose, Prof. Sugata
Chandrappa, Shri B. N.
Chaudhury, Shri Jitendra
Chavan, Shri Ashok Shankarrao
Chowdhury, Shri A. H. khan
Chowdhury, Shri Adhir Ranjan
Dastidar, Dr. Kakoli Ghosh
[@]Datta, Shri Sankar Prasad
Dev, Kumari Sushmita
Devegowda, Shri H.D.
Engti, Shri Biren Singh
Faizal, Mohammed
Geetha, Shrimati Kothapalli

[@] Voted through slip.

George, Adv. Joice

Ghosh, Shrimati Arpita

Gogoi, Shri Gaurav

Gowda, Shri S.P. Muddahanume

Hansdak, Shri Vijay Kumar

Haque, Shri Mohd. Asrarul

Hazra, Dr. Anupam

Hooda, Shri Deepender Singh

Innocent, Shri

Jatua, Shri Choudhury Mohan

[Ø]Jayadevan, Shri C. N

Kalvakuntla, Shrimati kavitha

Karunakaran, Shri P.

Khan, Shri Saumitra

Kharge, Shri Mallikarjun

Kumar, Shri Kaushalendra

Kumar, Shri Santosh

Kumar, Shri Shailesh

Mandal, Dr. Tapas

Mann, Shri Bhagwant

Meinya, Dr. Thokchom

Moily, Shri M. Veerappa

Mondal, Shri Sunil Kumar

Mondal, Shrimati Pratima

Mukherjee, Shri Abhijit

Muniyappa, Shri K.H.

Naik, Prof. A.S.R.

Naik, Shri B.V.

[Ø] Corrected through slip for Ayes.

Nath, Shri Kamal

Owaisi, Shri Asaduddin

Pala, Shri Vincent H.

Poddar, Shrimati Aparupa

Premachandran, Shri N.K.

Rajesh, Shri M. B.

Raju, Shri C.S. Putta

Ramachandran, Shri Mullappally

Ranjan, Shri Rajesh

Ranjan, Shrimati Ranjeet

Reddy, Shri Gutha Sukender

Reddy, Shri Mekapati Raja Mohan

Reddy, Shri P. Srinivasa

Reddy, Shri Y. V. Subba

Renuka, Shrimati Butta

Roy, Prof. Saugata

Roy, Shrimati Sandhya

Ruala, Shri C.L.

Sahu, Shri Tamradhwaj

Sampath, Dr. A.

Sanghamita, Dr. Mamtaz

Saren, Dr. Uma

Satav, Shri Rajeev

Scindia, Shri Jyotiraditya M.

Shetty, Shri Raju

Singh, Prof. Sadhu

Singh, Shri Ravneet

[@]Sinha, Shrimati Renuka

Sule, Shrimati Supriya

Suresh, Shri D.K.

Suresh, Shri Kodikunnil

Teacher, Shrimati P.K. Shreemathi

Thakur, Shrimati Mamata

Tharoor, Dr. Shashi

Thomas, Prof. K.V.

Tirkey, Shri Dasrath

Trivedi, Shri Dinesh

Uddin, Shri Tasleem

Varma, Shrimati Dev

Velagapalli, Shri Varaprasad Rao

Venugopal, Shri K. C.

Yadav, Shri Akshay

Yadav, Shri Dharmendra

Yadav, Shri Jai Prakash Narayan

Yadav, Shri Tej Pratap Singh

Yadav, Shrimati Dimple

Yellaiah, Shri Nandi

[@] Voted through slip.

NOES

Adityanath, Yogi

[@]Advani, Shri L.K.

Ahir, Shri Hansraj Gangaram

Ahlawat, Shrimati Santosh

Ahluwalia, Shri S.S.

Amarappa , Shri Karadi Sanganna

Ananthkumar, Shri

Angadi, Shri Suresh C.

Arunmozhithevan, Shri A.

Azad, Shri Kirti

Babu, Dr. Ravindra

Badal, Shrimati Harsimrat Kaur

Baheria, Shri Subhash Chandra

Bais, Shri Ramesh

Bala, Shrimati Anju

Balyan, Dr. Sanjeev

Bansode, Adv. Sharadkumar Maruti

Bhabhor, Shri Jasvantsinh Sumanbhai

Bhagat, Shri Sudarshan

Bhamre, Dr. Subhash Ramrao

Bharathi Mohan, Shri R.K.

Bharti, Sushri Uma

Bhatt, Shrimati Ranjanben

Bhole, Shri Devendra Singh

Bhuria, Shri Dileep Singh

[@] Voted through slip.

Bidhuri, Shri Ramesh

Birla, Shri Om

Bohra, Shri Ramcharan

Brahmpura, Shri Ranjit Singh

Chakravarty, Shrimati Bijoya

Chand, Shri Nihal

Chandel, Kunwar Pushpendra Singh

Chandrakasi, Shri M.

Chandumajra, Shri Prem Singh

Chaudhary, Shri C. R.

Chaudhary, Shri Haribhai

Chaudhary, Shri P.P.

Chaudhary, Shri Pankaj

Chaudhary, Shri Ram Tahal

Chauhan, Shri Devusinh

Chauhan, Shri P. P.

Chhewang, Shri Thupstan

[@]Chhotelal, Shri

Chinnaiyan, Shri S. Selvakumara

Choudhary, Col. Sonaram

Choudhary, Shri Babulal

Choudhary, Shri Birendra Kumar

Chouhan, Shri Nandkumar Singh

Chudasama, Shri Rajeshbhai

Danve, Shri Raosaheb Patil

Dattatreya, Shri Bandaru

Deka, Shri Ramen

Devi, Shrimati Rama

[@] Voted through slip.

Devi, Shrimati Veena

@Dharambir, Shri

Dhotre, Shri Sanjay

Dhurve, Shrimati Jyoti

Diwakar, Shri Rajesh Kumar

Dubey, Shri Nishikant

Dubey, Shri Satish Chandra

Dwivedi, Shri Harishchandra alias Harish

Elumalai, Shri V.

Fatepara, Shri Devjibhai G.

Gaddigoudar, Shri P.C.

Gadkari, Shri Nitin

Gaikwad, Dr. Sunil Baliram

Galla, Shri Jayadev

Gandhi, Shri Dilipkumar Mansukhlal

Gandhi, Shrimati Maneka Sanjay

Gangwar, Shri Santosh Kumar

Gautam, Shri Satish Kumar

Gavit, Dr. Heena Vijaykumar

Ghubaya, Shri Sher Singh

Giluwa, Shri Laxman

Girri, Shri Maheish

Gohain, Shri Rajen

@Gopal, Dr. K.

Gopalakrishnan, Shri C.

Gopalakrishnan, Shri R.

Gowda, Shri D.V. Sadananda

Gupta, Shri Shyama Charan

@ Voted through slip.

Gurjar, Shri Krishanpal

Hari, Shri G.

Haribabu, Dr. Kambhampati

Hegde, Shri Anantkumar

Hemamalini, Shrimati)

Jaiswal, Dr. Sanjay

Jardosh, Shrimati Darshana Vikram

Jat, Prof. Sanwar Lal

Jaunapuria, Shri Sukhbir Singh

Jayavardhan, Dr. J.

Jigajinagi, Shri Ramesh

Joshi, Dr. Murli Manohar

Joshi, Shri Pralhad

Jyoti, Sadhvi Niranjan

Kachhadia, Shri Naranbhai

Kaiser, Choudhary Mehboob Ali

Kamaraj, Dr. K.

Karandlaje, Kumari Shobha

Karunakaran, Shri P.

Kashyap, Shri Virender

Kaswan, Shri Rahul

Kataria, Shri Rattan Lal

Kateel, Shri Nalin Kumar

Katheria, Dr. Ramshankar

Kaushik, Shri Ramesh Chander

Khadse, Shrimati Rakshatai

Khanduri AVSM, Maj. Gen. (Retd.) B.C.

Khanna, Shri Vinod

Kher, Shrimati Kirron

Khuba, Shri Bhagwanth

Kinjarapu, Shri Ram Mohan Naidu

Kishore, Shri Jugal

Kishore, Shri Kaushal

Koli, Shri Bahadur Singh

Koshyari, Shri Bhagat Singh

Kristappa, Shri N.

Kulaste, Shri Faggan Singh

Kumar, Dr. Arun

Kumar, Dr. Virendra

Kumar, Kunwar Sarvesh

Kumar, Shri Ashwini

Kumar, Shri Dharmendra

Kumar, Shri K. Ashok

Kumar, Shri P.

Kumar, Shri Shanta

Kundariya, Shri Mohanbhai Kalyanjibhai

Kushawaha, Shri Ravinder

Kushwaha, Shri Upendra

Lakhanpal, Shri Raghav

Lekhi, Shrimati Meenakashi

Maadam, Shrimati Poonamben

Maharaj, Dr. Swami Sakshiji

Mahato, Dr. Banshilal

Mahato, Shri Bidyut Baran

Mahendran, Shri C.

Malviya, Prof. Chintamani

Manjhi, Shri Hari

Marabi, Shri Kamal Bhan Singh

Maragatham, Shrimati K.

Marutharajaa, Shri R. P.

Maurya, Shri Keshav Prasad

Meena, Shri Arjun Lal

Meena, Shri Harish

Meghwal, Shri Arjun Ram

Mishra, Shri Anoop

Mishra, Shri Bhairon Prasad

Mishra, Shri Daddan

Mishra, Shri Janardan

Mishra, Shri Kalraj

Mohan, Shri M. Murli

Mohan, Shri P.C.

Munda, Shri Karia

Nagar, Shri Rodmal

Nagarajan, Shri P.

Narasimham, Shri Thota

Nath, Shri Chand

Natterjee, Shri J.J.T.

Nete, Shri Ashok Mahadeorao

Nishad, Shri Ajay

Nishad, Shri Ram Charitra

Nishank, Dr. Ramesh Pokhriyal

Oram, Shri Jual

Paatle, Shrimati Kamla

Pal, Shri Jagdambika

Pandey, Dr. Mahendra Nath

Pandey, Shri Hari Om

Pandey, Shri Rajesh

Pandey, Shri Ravindra Kumar

Panneerselvam, Shri V.

Parasuraman, Shri K.

Parthipan, Shri R.

Paswan, Shri Chhedi

Paswan, Shri Chirag

Paswan, Shri Ram Chandra

Paswan, Shri Ramvilas

Patel, Dr. K. C.

Patel, Shri Devji M.

Patel, Shri Dilip

Patel, Shri Lalubhai Babubhai

Patel, Shri Natubhai Gomanbhai

Patel, Shri Prahlad Singh

Patel, Shri Subhash

Patel, Shrimati Anupriya

Patel, Shrimati Jayshreeben

Pathak, Shrimati Riti

Patil, Shri A.T. Nana

Patil, Shri C. R.

Patil, Shri Kapil Moreshwar

Patil, Shri Sanjay Kaka

Patole, Shri Nana

Phule, Sadhvi Savitri Bai

Prabakaran, Shri K. R. P.

Prasad, Dr. Bhagirath

Pratap, Shri Krishan

Radhakrishnan, Shri Pon

Radhakrishnan, Shri T.

[@]Rai, Shri Nityanand

Raj, Dr. Udit

Raj, Shrimati Krishna

Rajbhar, Shri Harinarayan

Rajendran, Shri S.

Rajoria, Dr. Manoj

Rajput, Shri Mukesh

Raju, Shri Ashok Gajapathi

Raju, Shri Gokaraju Ganga

Ram, Shri Janak

Ram, Shri Vishnu Dayal

Ramachandran, Shri K. N.

Rao, Shri Konakalla Narayana

Rao (Avanthi), Shri Muthamsetti Srinivasa

Rao, Shri Rayapati Sambasiva

Rathod, Shri D.S.

Rathore, Col. Rajyavardhan

Rathore, Shri Hariom Singh

Rathwa, Shri Ramsinh

Raval, Shri Paresh

Rawat, Shrimati Priyanka Singh

Ray, Shri Bishnu Pada

Ray, Shri Ravindra Kumar

Reddy, Shri Ch. Malla

Reddy, Shri J.C. Divakar

Reddy, Shri P.V. Midhun

Rijiju, Shri Kiren

Rudy, Shri Rajiv Pratap

[@] Voted through slip.

Sahu, Shri Chandulal

Sahu, Shri Lakhan Lal

Sai, Shri Vishnu Dev

Saini, Shri Rajkumar

Sampla, Shri Vijay

Sangma, Shri Purno Agitok

Sanjar, Shri Alok

Sarmah, Shri Ram Prasad

Sarswati, Shri Sumedhanand

Sathyabama, Shrimati V.

Sawaikar, Adv. Narendra Keshav

Senguttuvan, Shri B.

Senthilnathan, Shri P. R.

Shah, Shrimati Mala Rajyalakshmi

Sharma, Dr. Mahesh

Sharma, Shri Ram Kumar

Sharma, Shri Ram Swaroop

@Shekhawat, Shri Gajendra Singh

Shetty, Shri Gopal

Shirole, Shri Anil

Shyal, Dr. Bhartiben D.

Siddeshwara, Shri G. M.

Sigriwal, Shri Janardan Singh

Simha, Shri Pratap

Singh, Dr. Bhola

Singh, Dr. Jitendra

Singh, Dr. Nepal

Singh, Dr. Satya Pal

@ Voted through slip.

Singh, Dr. Yashwant

Singh, Gen. (Retd) Vijay Kumar

Singh, Kunwar Bharatendra

Singh, Kunwar Haribansh

Singh, Rao Inderjit

Singh, Shri Abhishek

Singh, Shri Bharat

Singh, Shri Bhola

Singh, Shri Brijbhushan Sharan

Singh, Shri Dushyant

Singh, Shri Giriraj

Singh, Shri Hukum

Singh, Shri Kirti Vardhan

Singh, Shri Lallu

Singh, Shri Nagendra

Singh, Shri Pashupati Nath

Singh, Shri R. K.

Singh, Shri Rajnath

Singh (Raju Bhaiya), Shri Rajveer

Singh, Shri Rakesh

Singh, Shri Satyapal

Singh, Shri Sunil Kumar

Singh, Shri Sushil Kumar

Singh, Shri Uday Pratap

Singh, Shri Virendra

Sinha, Shri Jayant

Sinha, Shri Manoj

Solanki, Dr. Kirit P.

Somaiya, Dr. Kirit

Sonkar, Shri Vinod Kumar

Sonker, Shrimati Neelam

Sonowal, Shri Sarbananda

Srinivas, Shri Kesineni

Sriram, Shri Malyadri

Sriramulu, Shri B.

Sundaram, Shri P. R.

Swaraj, Shrimati Sushma

Tadas, Shri Ramdas C.

Tamta, Shri Ajay

Tanwar, Shri Kanwar Singh

Tasa, Shri Kamakhya Prasad

Teli, Shri Rameshwar

Teni, Shri Ajay Misra

Thakur, Shri Anurag Singh

Thambidurai, Dr. M.

Tiwari, Shri Manoj

Tripathi, Shri Sharad

Udasi, Shri Shivkumar

Udhayakumar, Shri M.

Usendi, Shri Vikram

Vanaroja, Shrimati R.

Vardhan, Dr. Harsh

Vasanthi, Shrimati M.

Vasava, Shri Parbhubhai Nagarbhai

Venugopal, Dr. P.

Verma, Dr. Anshul

Verma, Shri Bhanu Pratap Singh

Verma, Shri Parvesh Sahib Singh

Verma, Shri Rajesh

Verma, Shrimati Rekha

Vijaya Kumar, Shri S. R.

Wanga, Shri Chintaman Navasha

Yadav, Shri Hukmdeo Narayan

Yadav, Shri Laxmi Narayan

Yadav, Shri Om Prakash

Yadav, Shri Ram Kripal

Yediyurappa, Shri B.S.

ABSTAIN

Adsul, Shri Anandrao

@Barne, Shri Shrirang Appa

Gaikwad, Prof. Ravindra Vishwanath

@Gawali, Shrimati Bhavana Pundalikrao

Geete, Shri Anant Gangaram

Godse, Shri Hemant Tukaram

Jadhav, Shri Prataprao

Jadhav, Shri Sanjay Haribhau

Khaire, Shri Chandrakant

Kirtikar, Shri Gajanan

Lokhande, Shri Sadashiv

Raut, Shri Vinayak Bhaurao

Sawant, Shri Arvind

Shewale, Shri Rahul

Shinde, Dr. Shrikant Eknath

Shivajirao, Shri Adhalrao Patil

Vichare, Shri Rajan

@ Voted through slip.

HON. SPEAKER: Subject to correction*, the result of the division is:

Ayes: 098

Noes: 315

Abstain:15

The motion was negatived.

---

* **Ayes: 098** + S/Shri Sankar Prasad Datta, C.N. Jayadevan, Shrimati Renuka Sinha = **101**

Noes: 315 + S/Shri L.K. Advani, Chhotelal, Dharambir, Dr. K. Gopal, S/Shri Nityanand Rai, Gajendra Singh Shekhawat - Shri C.N. Jayadevan = **320**

Abstain: 015 + Shri Shrirang Appa Barne, Shrimati Bhavana Pundalikrao Gawali **= 17**

HON. SPEAKER: Shri Y.V. Subba Reddy, are you moving your Amendment no. 46 to Clause 4?

SHRI Y.V. SUBBA REDDY (ONGOLE): I am withdrawing Amendment No.46 to Clause 4. But, I am moving Amendment No.47 to Clause 5. I beg to move:

"Page 2, *after* line 27, *insert,-*

"Provided that multi cropped irrigated land shall not be acquired for projects referred to in this section.

Provided further that social impact assessment shall be carried before acquiring land for projects referred to in this Section."." (47)

HON. SPEAKER: The lobbies have already been cleared. I shall now put amendment No.47 moved by Shri Y.V. Subba Reddy to the vote of the House.

The question is:

Page 2, *after* line 27, *insert,-*

"Provided that multi cropped irrigated land shall not be acquired for projects referred to in this section.

Provided further that social impact assessment shall be carried before acquiring land for projects referred to in this Section."

The Lok Sabha divided:

DIVISION 9 **AYES** **19.28 hrs.**

Adhikari, Shri Sisir Kumar
Adhikari, Shri Suvendu
Ahmed, Shri Sultan
Ali, Shri Idris
Antony, Shri Anto
Anwar, Shri Tariq
Baite, Shri Thangso
Banerjee, Shri Abhishek
Banerjee, Shri Kalyan
Banerjee, Shri Prasun
Bhonsale, Shri Chh. Udayanraje
Biju, Shri P. K.
Bose, Prof. Sugata
Chandrappa, Shri B. N.
Chaudhury, Shri Jitendra
Chautala, Shri Dushyant
Chavan, Shri Ashok Shankarrao
Chowdhury, Shri A. H. khan
Chowdhury, Shri Adhir Ranjan
Dastidar, Dr. Kakoli Ghosh
Datta, Shri Sankar Prasad
Dev, Kumari Sushmita
Devegowda, Shri H.D.
Engti, Shri Biren Singh
Faizal, Mohammed
Geetha, Shrimati Kothapalli
George, Adv. Joice

Ghosh, Shrimati Arpita

Gogoi, Shri Gaurav

Goud, Dr. Boora Narsaiah

Gowda, Shri S.P. Muddahanume

Hansdak, Shri Vijay Kumar

Haque, Shri Mohd. Asrarul

Hazra, Dr. Anupam

Hooda, Shri Deepender Singh

Innocent, Shri

Jatua, Shri Choudhury Mohan

Jayadevan, Shri C. N

Kalvakuntla, Shrimati Kavitha

Karunakaran, Shri P.

Khan, Shri Saumitra

Kharge, Shri Mallikarjun

Kumar, Shri Kaushalendra

Kumar, Shri Santosh

Kumar, Shri Shailesh

Mann, Shri Bhagwant

Meinya, Dr. Thokchom

Moily, Shri M. Veerappa

Mondal, Shrimati Pratima

Mukherjee, Shri Abhijit

Muniyappa, Shri K.H.

Nagesh, Shri Godam

Naik, Prof. A.S.R.

[@]Naik, Shri B.V.

@Nath, Shri Kamal

[@] Voted through slip.

Noor, Shrimati Mausam

Owaisi, Shri Asaduddin

Pala, Shri Vincent H.

Poddar, Shrimati Aparupa

Premachandran, Shri N.K.

Rajesh, Shri M. B.

Raju, Shri C.S. Putta

Ramachandran, Shri Mullappally

Ranjan, Shri Rajesh

Ranjan, Shrimati Ranjeet

Reddy, Shri Gutha Sukender

Reddy, Shri Konda Vishweshwar

Reddy, Shri Mekapati Raja Mohan

Reddy, Shri P. Srinivasa

Reddy, Shri P.V. Midhun

Reddy, Shri Y. V. Subba

Renuka, Shrimati Butta

Rori, Shri Charanjeet Singh

[@]Roy, Prof. Saugata

Roy, Shrimati Sandhya

Ruala, Shri C.L.

Sahu, Shri Tamradhwaj

Sampath, Dr. A.

Sanghamita, Dr. Mamtaz

Saren, Dr. Uma

Satav, Shri Rajeev

Scindia, Shri Jyotiraditya M.

Shetty, Shri Raju

[@] Voted through slip.

Singh, Prof. Sadhu

Singh, Shri Ravneet

Sinha, Shrimati Renuka

Sule, Shrimati Supriya

Suman, Shri Balka

Suresh, Shri Kodikunnil

Teacher, Shrimati P.K. Shreemathi

Thakur, Shrimati Mamata

Tharoor, Dr. Shashi

Thomas, Prof. K.V.

Trivedi, Shri Dinesh

Uddin, Shri Tasleem

Varma, Shrimati Dev

Velagapalli, Shri Varaprasad Rao

Venugopal, Shri K. C.

Yadav, Shri Akshay

Yadav, Shri Dharmendra

Yadav, Shri Jai Prakash Narayan

Yadav, Shri Tej Pratap Singh

Yadav, Shrimati Dimple

Yellaiah, Shri Nandi

NOES

Adityanath, Yogi

Advani, Shri L.K.

Ahir, Shri Hansraj Gangaram

Ahlawat, Shrimati Santosh

Ahluwalia, Shri S.S.

Amarappa , Shri Karadi Sanganna

Ananthkumar, Shri

Angadi, Shri Suresh C.

Arunmozhithevan, Shri A.

Azad, Shri Kirti

Babu, Dr. Ravindra

Badal, Shrimati Harsimrat Kaur

Baheria, Shri Subhash Chandra

Bais, Shri Ramesh

Bala, Shrimati Anju

Balyan, Dr. Sanjeev

Bansode, Adv. Sharadkumar Maruti

Bhabhor, Shri Jasvantsinh Sumanbhai

Bhagat, Shri Sudarshan

Bhamre, Dr. Subhash Ramrao

Bharathi Mohan, Shri R.K.

[@]Bharti, Sushri Uma

Bhatt, Shrimati Ranjanben

Bhole, Shri Devendra Singh

Bhuria, Shri Dileep Singh

Bidhuri, Shri Ramesh

[@] Voted through slip.

Birla, Shri Om

Bohra, Shri Ramcharan

Brahmpura, Shri Ranjit Singh

Chakravarty, Shrimati Bijoya

Chand, Shri Nihal

Chandel, Kunwar Pushpendra Singh

Chandrakasi, Shri M.

Chandumajra, Shri Prem Singh

Chaudhary, Shri C. R.

Chaudhary, Shri Haribhai

Chaudhary, Shri P.P.

Chaudhary, Shri Pankaj

Chaudhary, Shri Ram Tahal

Chauhan, Shri Devusinh

Chauhan, Shri P. P.

Chhewang, Shri Thupstan

Chhotelal, Shri

[Ø]Chinnaiyan, Shri S. Selvakumara

[@]Choubey, Shri Ashwini Kumar

Choudhary, Col. Sonaram

Choudhary, Shri Babulal

Choudhary, Shri Birendra Kumar

Chouhan, Shri Nandkumar Singh

Chudasama, Shri Rajeshbhai

Danve, Shri Raosaheb Patil

Dattatreya, Shri Bandaru

Deka, Shri Ramen

[Ø] Corrected through slip for Noes.
[@] voted through slip.

Devi, Shrimati Rama

Devi, Shrimati Veena

Dharambir, Shri

Dhotre, Shri Sanjay

Dhurve, Shrimati Jyoti

Diwakar, Shri Rajesh Kumar

Dubey, Shri Nishikant

Dubey, Shri Satish Chandra

Dwivedi, Shri Harishchandra alias Harish

Elumalai, Shri V.

Fatepara, Shri Devjibhai G.

Gaddigoudar, Shri P.C.

Gadkari, Shri Nitin

Gaikwad, Dr. Sunil Baliram

Galla, Shri Jayadev

Gandhi, Shri Dilipkumar Mansukhlal

Gandhi, Shrimati Maneka Sanjay

Gangwar, Shri Santosh Kumar

Gautam, Shri Satish Kumar

Gavit, Dr. Heena Vijaykumar

Ghubaya, Shri Sher Singh

Giluwa, Shri Laxman

Girri, Shri Maheish

Gohain, Shri Rajen

Gopal, Dr. K.

Gopalakrishnan, Shri C.

Gopalakrishnan, Shri R.

Gowda, Shri D.V. Sadananda

Gupta, Shri Shyama Charan

Gurjar, Shri Krishanpal

Hari, Shri G.

Haribabu, Dr. Kambhampati

Hegde, Shri Anantkumar

Hemamalini, Shrimati

Jaiswal, Dr. Sanjay

Jardosh, Shrimati Darshana Vikram

Jat, Prof. Sanwar Lal

Jaunapuria, Shri Sukhbir Singh

Jayavardhan, Dr. J.

Jigajinagi, Shri Ramesh

Joshi, Dr. Murli Manohar

Joshi, Shri Pralhad

Jyoti, Sadhvi Niranjan

Kachhadia, Shri Naranbhai

Kaiser, Choudhary Mehboob Ali

Kamaraj, Dr. K.

Karandlaje, Kumari Shobha

Kashyap, Shri Virender

Kaswan, Shri Rahul

Kataria, Shri Rattan Lal

Kateel, Shri Nalin Kumar

Katheria, Dr. Ramshankar

Kaushik, Shri Ramesh Chander

Khadse, Shrimati Rakshatai

Khanduri AVSM, Maj. Gen. (Retd.) B.C.

Khanna, Shri Vinod

Kher, Shrimati Kirron

Khuba, Shri Bhagwanth

Kinjarapu, Shri Ram Mohan Naidu

Kishore, Shri Jugal

Kishore, Shri Kaushal

Koli, Shri Bahadur Singh

Koshyari, Shri Bhagat Singh

Kristappa, Shri N.

Kulaste, Shri Faggan Singh

Kumar, Dr. Arun

Kumar, Dr. Virendra

Kumar, Kunwar Sarvesh

Kumar, Shri Ashwini

Kumar, Shri Dharmendra

Kumar, Shri K. Ashok

Kumar, Shri P.

@Kumar, Shri Shanta

Kundariya, Shri Mohanbhai Kalyanjibhai

@Kushawaha, Shri Ravinder

Kushwaha, Shri Upendra

Lakhanpal, Shri Raghav

Lekhi, Shrimati Meenakashi

Maadam, Shrimati Poonamben

Maharaj, Dr. Swami Sakshiji

Mahato, Dr. Banshilal

Mahato, Shri Bidyut Baran

Mahendran, Shri C.

Malviya, Prof. Chintamani

Manjhi, Shri Hari

Marabi, Shri Kamal Bhan Singh

@ Voted through slip.

Maragatham, Shrimati K.

Marutharajaa, Shri R. P.

Maurya, Shri Keshav Prasad

Meena, Shri Arjun Lal

Meena, Shri Harish

Meghwal, Shri Arjun Ram

Mishra, Shri Anoop

Mishra, Shri Bhairon Prasad

Mishra, Shri Daddan

@Mishra, Shri Janardan

Mishra, Shri Kalraj

Mohan, Shri M. Murli

Mohan, Shri P.C.

Munda, Shri Karia

Nagar, Shri Rodmal

Nagarajan, Shri P.

Narasimham, Shri Thota

Nath, Shri Chand

Natterjee, Shri J.J.T.

Nete, Shri Ashok Mahadeorao

Nishad, Shri Ajay

Nishad, Shri Ram Charitra

Nishank, Dr. Ramesh Pokhriyal

Oram, Shri Jual

Paatle, Shrimati Kamla

Pal, Shri Jagdambika

Pandey, Dr. Mahendra Nath

Pandey, Shri Hari Om

@ Voted through slip.

Pandey, Shri Rajesh

Pandey, Shri Ravindra Kumar

Panneerselvam, Shri V.

Parasuraman, Shri K.

Parthipan, Shri R.

Paswan, Shri Chhedi

Paswan, Shri Chirag

Paswan, Shri Ram Chandra

Paswan, Shri Ramvilas

Patel, Dr. K. C.

Patel, Shri Devji M.

Patel, Shri Dilip

Patel, Shri Lalubhai Babubhai

Patel, Shri Natubhai Gomanbhai

Patel, Shri Prahlad Singh

Patel, Shri Subhash

Patel, Shrimati Anupriya

Patel, Shrimati Jayshreeben

Pathak, Shrimati Riti

Patil, Shri A.T. Nana

Patil, Shri C. R.

Patil, Shri Kapil Moreshwar

Patil, Shri Sanjay Kaka

Patole, Shri Nana

Phule, Sadhvi Savitri Bai

Prabakaran, Shri K. R. P.

Prasad, Dr. Bhagirath

Pratap, Shri Krishan

Radhakrishnan, Shri Pon

Radhakrishnan, Shri T.

Rai, Shri Nityanand

Raj, Dr. Udit

Raj, Shrimati Krishna

Raajha, Shri A. Anwhar

Rajbhar, Shri Harinarayan

Rajendran, Shri S.

Rajoria, Dr. Manoj

Rajput, Shri Mukesh

Raju, Shri Ashok Gajapathi

Raju, Shri Gokaraju Ganga

Ram, Shri Janak

Ram, Shri Vishnu Dayal

Ramachandran, Shri K. N.

Rao, Shri Konakalla Narayana

Rao (Avanthi), Shri Muthamsetti Srinivasa

Rao, Shri Rayapati Sambasiva

Rathod, Shri D.S.

Rathore, Col. Rajyavardhan

Rathore, Shri Hariom Singh

Rathwa, Shri Ramsinh

Raval, Shri Paresh

Rawat, Shrimati Priyanka Singh

Ray, Shri Bishnu Pada

Ray, Shri Ravindra Kumar

Reddy, Shri Ch. Malla

Reddy, Shri J.C. Divakar

Rijiju, Shri Kiren

Rudy, Shri Rajiv Pratap

Sahu, Shri Chandulal

Sahu, Shri Lakhan Lal

Sai, Shri Vishnu Dev

Saini, Shri Rajkumar

Sampla, Shri Vijay

Sangma, Shri Purno Agitok

Sanjar, Shri Alok

Sarmah, Shri Ram Prasad

Sarswati, Shri Sumedhanand

Sathyabama, Shrimati V.

Sawaikar, Adv. Narendra Keshav

Senguttuvan, Shri B.

Senthilnathan, Shri P. R.

Shah, Shrimati Mala Rajyalakshmi

Sharma, Dr. Mahesh

Sharma, Shri Ram Kumar

Sharma, Shri Ram Swaroop

Shekhawat, Shri Gajendra Singh

Shetty, Shri Gopal

Shirole, Shri Anil

Shyal, Dr. Bhartiben D.

Siddeshwara, Shri G. M.

@Sigriwal, Shri Janardan Singh

Simha, Shri Pratap

Singh, Dr. Bhola

Singh, Dr. Jitendra

@Singh, Dr. Nepal

Singh, Dr. Satya Pal

@ Voted through slip.

Singh, Dr. Yashwant

Singh, Gen. (Retd) Vijay Kumar

Singh, Kunwar Bharatendra

Singh, Kunwar Haribansh

Singh, Rao Inderjit

Singh, Shri Abhishek

Singh, Shri Bharat

Singh, Shri Bhola

Singh, Shri Brijbhushan Sharan

Singh, Shri Dushyant

Singh, Shri Giriraj

Singh, Shri Hukum

Singh, Shri Kirti Vardhan

Singh, Shri Lallu

Singh, Shri Nagendra

Singh, Shri Pashupati Nath

Singh, Shri R. K.

Singh, Shri Rajnath

Singh (Raju Bhaiya), Shri Rajveer

Singh, Shri Rakesh

Singh, Shri Satyapal

Singh, Shri Sunil Kumar

Singh, Shri Sushil Kumar

Singh, Shri Uday Pratap

Singh, Shri Virendra

Sinha, Shri Jayant

Sinha, Shri Manoj

Solanki, Dr. Kirit P.

Somaiya, Dr. Kirit

Sonkar, Shri Vinod Kumar

Sonker, Shrimati Neelam

Sonowal, Shri Sarbananda

Srinivas, Shri Kesineni

Sriram, Shri Malyadri

Sriramulu, Shri B.

Sundaram, Shri P. R.

Swaraj, Shrimati Sushma

Tadas, Shri Ramdas C.

Tamta, Shri Ajay

Tanwar, Shri Kanwar Singh

Tasa, Shri Kamakhya Prasad

Teli, Shri Rameshwar

Teni, Shri Ajay Misra

Thakur, Shri Anurag Singh

Thambidurai, Dr. M.

Tiwari, Shri Manoj

Tripathi, Shri Sharad

Udasi, Shri Shivkumar

Udhayakumar, Shri M.

Usendi, Shri Vikram

Vanaroja, Shrimati R.

Vardhan, Dr. Harsh

[@]Vasanthi, Shrimati M.

Vasava, Shri Parbhubhai Nagarbhai

Venugopal, Dr. P.

Verma, Dr. Anshul

Verma, Shri Bhanu Pratap Singh

[@] Voted through slip.

Verma, Shri Parvesh Sahib Singh

Verma, Shri Rajesh

Verma, Shrimati Rekha

Vijaya Kumar, Shri S. R.

Wanga, Shri Chintaman Navasha

Yadav, Shri Hukmdeo Narayan

Yadav, Shri Laxmi Narayan

Yadav, Shri Om Prakash

Yadav, Shri Ram Kripal

Yediyurappa, Shri B.S.

ABSTAIN

Adsul, Shri Anandrao

Barne, Shri Shrirang Appa

Gaikwad, Prof. Ravindra Vishwanath

Gawali, Shrimati Bhavana Pundalikrao

Geete, Shri Anant Gangaram

Godse, Shri Hemant Tukaram

Jadhav, Shri Prataprao

Jadhav, Shri Sanjay Haribhau

Khaire, Shri Chandrakant

Kirtikar, Shri Gajanan

Lokhande, Shri Sadashiv

Raut, Shri Vinayak Bhaurao

Sawant, Shri Arvind

Shewale, Shri Rahul

Shinde, Dr. Shrikant Eknath

Shivajirao, Shri Adhalrao Patil

Vichare, Shri Rajan

HON. SPEAKER: Subject to correction*, the result of the division is:

Ayes: 101

Noes: 311

Abstain: 18

The motion was negatived.

---

* The following Members also recorded/corrected their votes through slips:

Ayes: 101 + S/Shri B.V. Naik, Kamal Nath, Prof. Saugat Roy = **104**

Noes: 311 + Sushri Uma Bharti, S/Shri S. Selvakumara Chinnaiyan, Ashwini Kumar Choubey, Shanta Kumar, Ravindra Kushawaha, Janardhan Mishra, Janardan Singh Sigriwal, Dr. Nepal Singh, Shrimati M. Vasanthi = **320**

Abstain: 018 - Shri S. Selvakumara Chinnaiyan **= 017**

HON. SPEAKER: Shri Deepender Singh Hooda, are you moving your Amendment No. 48 to Clause 5?

SHRI DEEPENDER SINGH HOODA (ROHTAK): I am moving Amendment No.48. I beg to move:

> "Page 2, *after* line 27, *insert, -*
>
> "Provided that no such exemption shall be granted without first conducting a social impact assessment in line with the provisions of Charter II of the principal Act, unless the same is under 'urgency provisions' under section 40 of the principal Act."." (48)

मैडम, जैसे कि अभी कहा गया कि इस एक्ट के दो मुख्य स्तंभ हैं, एक किसानों की स्वीकृति...(व्यवधान) किसानों की स्वीकृति की आवश्यकता और दूसरा सोशल इम्पैक्ट स्टडी। पहले को सरकार ने खारिज कर दिया कि किसानों की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी ने कहा था कि दीपेन्द्र मेरे से छोटे हैं, मेरी बात मानेंगे, मैं भी उनसे इस बात के लिए कहूंगा कि वे मुझ से बड़े हैं और इसमें शायद वे मेरी बात मानें। ...(व्यवधान) एक अमैन्डमैन्ट में सोशल इम्पैक्ट स्टडी, एक प्रावधान ज्यादा जमीन एक्वायर न हो, उसके लिए आप अमैन्डमैन्ट लाये हैं, उसका हम स्वागत करते हैं, मगर उसके साथ-साथ हमने दो-तीन बातें और रखी थीं, जिनमें सोशल इम्पैक्ट स्टडी का जो मुख्य बिन्दु है, वह यह है कि अगर अलाइनमैन्ट में बदलाव की आवश्यकता हो या वहीं जैसे बावल का मैंने उदाहरण दिया, आसपास की जमीन में अगर संभव हो सके तो वह भी सरकार को देखने का प्रावधान होना चाहिए तो इस पर भी आप गंभीरता से विचार करेंगे। बड़ा होने के नाते मैं आपसे यह उम्मीद करूंगा।

श्री चौधरी बीरेन्द्र सिंह : मैं आदरणीय सदस्य को यह बताना चाहूंगा कि social impact assessment is left to the State Governments. If some State Government still wants to go with the social impact assessment, they are at liberty.

Secondly, you said that the land which is not cultivable should be looked. We have already introduced that provision. It is in the amendment itself that there would be a survey of the wasteland or land which is not cultivable and it would be kept, as you can say, as a store or some land bank or something like that. If that is available, land which is cultivable and which is multi-crop land will not be taken for acquisition. … (*Interruptions*)

SHRI DEEPENDER SINGH HOODA : I appreciate the reply but we press for social impact study. … (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Are you pressing?

SHRI DEEPENDER SINGH HOODA: Yes. I appreciate the response of the hon. Minister but we press for the inclusion of social impact assessment and I have moved my Amendment No. 48 to clause 5.

HON. SPEAKER: The question is:

"Page 2, *after* line 27, *insert*, --

Provided that no such exemption shall be granted without first conducting a social impact assessment in line with the provisions of Chapter II of the principal Act, unless the same is under 'emergency provisions' under section 40 of the principal Act."

… (*Interruptions*)

SHRI DEEPENDER SINGH HOODA: Madam, I want Division.

HON. SPEAKER: The Lobbies have already been cleared—

Now, the Lobbies have been cleared.

The question is:

"Page 2, *after* line 27, *insert*, --

Provided that no such exemption shall be granted without first conducting a social impact assessment in line with the provisions of Chapter II of the principal Act, unless the same is under 'emergency provisions' under section 40 of the principal Act."

The Lok Sabha divided:

DIVISION 10 **AYES** **19.32 hrs.**

Adhikari, Shri Sisir Kumar

Ahmed, Shri Sultan

Antony, Shri Anto

Anwar, Shri Tariq

Baite, Shri Thangso

Banerjee, Shri Abhishek

Banerjee, Shri Kalyan

Banerjee, Shri Prasun

Barman, Shri Bijoy Chandra

Bhonsale, Shri Chh. Udayanraje

Biju, Shri P. K.

Bose, Prof. Sugata

Chandrappa, Shri B. N.

Chaudhury, Shri Jitendra

Chavan, Shri Ashok Shankarrao

[@]Chowdhury, Shri A. H. khan

Chowdhury, Shri Adhir Ranjan

Dastidar, Dr. Kakoli Ghosh

Datta, Shri Sankar Prasad

De(Nag), Dr. Ratna

Dev, Kumari Sushmita

Devegowda, Shri H.D.

Engti, Shri Biren Singh

Faizal, Mohammed

Gawali, Shrimati Bhavana Pundalikrao

[@] Voted through slip.

Geetha, Shrimati Kothapalli

George, Adv. Joice

Ghosh, Shrimati Arpita

Gogoi, Shri Gaurav

Gowda, Shri S.P. Muddahanume

Hansdak, Shri Vijay Kumar

Haque, Shri Mohd. Asrarul

Hazra, Dr. Anupam

Hooda, Shri Deepender Singh

Innocent, Shri

Jatua, Shri Choudhury Mohan

Jayadevan, Shri C. N

Kalvakuntla, Shrimati Kavitha

Karunakaran, Shri P.

Khan, Shri Saumitra

Kharge, Shri Mallikarjun

Kumar, Shri Kaushalendra

Kumar, Shri Santosh

Kumar, Shri Shailesh

Mann, Shri Bhagwant

Meinya, Dr. Thokchom

Moily, Shri M. Veerappa

Mondal, Shrimati Pratima

Mukherjee, Shri Abhijit

Nagesh, Shri Godam

Naik, Prof. A.S.R.

Naik, Shri B.V.

Nath, Shri Kamal

Noor, Shrimati Mausam

Owaisi, Shri Asaduddin

Pala, Shri Vincent H.

Patil, Shri Bheemrao B.

Poddar, Shrimati Aparupa

Premachandran, Shri N.K.

Rajesh, Shri M. B.

Raju, Shri C.S. Putta

Ramachandran, Shri Mullappally

Ranjan, Shri Rajesh

Ranjan, Shrimati Ranjeet

Reddy, Shri Gutha Sukender

Reddy, Shri Konda Vishweshwar

Reddy, Shri Mekapati Raja Mohan

Reddy, Shri P. Srinivasa

Reddy, Shri Y. V. Subba

Renuka, Shrimati Butta

Roy, Prof. Saugata

Roy, Shrimati Sandhya

Ruala, Shri C.L.

Sahu, Shri Tamradhwaj

Sampath, Dr. A.

Sanghamita, Dr. Mamtaz

Saren, Dr. Uma

Satav, Shri Rajeev

Scindia, Shri Jyotiraditya M.

Shetty, Shri Raju

Singh, Prof. Sadhu

Singh, Shri Ravneet

Sinha, Shrimati Renuka

Sule, Shrimati Supriya

Suresh, Shri D.K.

Suresh, Shri Kodikunnil

Teacher, Shrimati P.K. Shreemathi

Thakur, Shrimati Mamata

Tharoor, Dr. Shashi

Thomas, Prof. K.V.

Tirkey, Shri Dasrath

Trivedi, Shri Dinesh

Uddin, Shri Tasleem

Varma, Shrimati Dev

Velagapalli, Shri Varaprasad Rao

Venugopal, Shri K. C.

Yadav, Shri Akshay

Yadav, Shri Dharmendra

Yadav, Shri Jai Prakash Narayan

Yadav, Shri Tej Pratap Singh

Yadav, Shrimati Dimple

Yellaiah, Shri Nandi

NOES

Adityanath, Yogi

Advani, Shri L.K.

Ahir, Shri Hansraj Gangaram

Ahlawat, Shrimati Santosh

Ahluwalia, Shri S.S.

Amarappa , Shri Karadi Sanganna

Ananthkumar, Shri

Angadi, Shri Suresh C.

Arunmozhithevan, Shri A.

Azad, Shri Kirti

Babu, Dr. Ravindra

Badal, Shrimati Harsimrat Kaur

Baheria, Shri Subhash Chandra

Bais, Shri Ramesh

Bala, Shrimati Anju

Balyan, Dr. Sanjeev

Bansode, Adv. Sharadkumar Maruti

Bhabhor, Shri Jasvantsinh Sumanbhai

Bhagat, Shri Sudarshan

Bhamre, Dr. Subhash Ramrao

Bharathi Mohan, Shri R.K.

@Bharti, Sushri Uma

Bhatt, Shrimati Ranjanben

Bhole, Shri Devendra Singh

Bhuria, Shri Dileep Singh

Bidhuri, Shri Ramesh

Birla, Shri Om

@ Voted through slip.

Bohra, Shri Ramcharan

Brahmpura, Shri Ranjit Singh

Chakravarty, Shrimati Bijoya

Chand, Shri Nihal

Chandel, Kunwar Pushpendra Singh

Chandrakasi, Shri M.

Chandumajra, Shri Prem Singh

Chaudhary, Shri C. R.

Chaudhary, Shri Haribhai

Chaudhary, Shri P.P.

Chaudhary, Shri Pankaj

Chaudhary, Shri Ram Tahal

Chauhan, Shri Devusinh

Chauhan, Shri P. P.

Chhewang, Shri Thupstan

@Chhotelal, Shri

Chinnaiyan, Shri S. Selvakumara

@Choubey, Shri Ashwini Kumar

Choudhary, Col. Sonaram

Choudhary, Shri Babulal

Choudhary, Shri Birendra Kumar

Chouhan, Shri Nandkumar Singh

Chudasama, Shri Rajeshbhai

Danve, Shri Raosaheb Patil

Dattatreya, Shri Bandaru

Deka, Shri Ramen

Devi, Shrimati Rama

Devi, Shrimati Veena

@ Voted through slip.

@Dharambir, Shri

Dhotre, Shri Sanjay

Dhurve, Shrimati Jyoti

@Diwakar, Shri Rajesh Kumar

Dubey, Shri Nishikant

Dubey, Shri Satish Chandra

Dwivedi, Shri Harishchandra alias Harish

Elumalai, Shri V.

Fatepara, Shri Devjibhai G.

Gaddigoudar, Shri P.C.

Gadkari, Shri Nitin

Gaikwad, Dr. Sunil Baliram

Galla, Shri Jayadev

Gandhi, Shri Dilipkumar Mansukhlal

Gandhi, Shrimati Maneka Sanjay

Gangwar, Shri Santosh Kumar

Gautam, Shri Satish Kumar

Gavit, Dr. Heena Vijaykumar

Ghubaya, Shri Sher Singh

Giluwa, Shri Laxman

Girri, Shri Maheish

Gohain, Shri Rajen

Gopal, Dr. K.

Gopalakrishnan, Shri C.

Gopalakrishnan, Shri R.

Gowda, Shri D.V. Sadananda

Gupta, Shri Shyama Charan

Gurjar, Shri Krishanpal

@ Voted through slip.

Hari, Shri G.

Haribabu, Dr. Kambhampati

Hegde, Shri Anantkumar

Hemamalini, Shrimati)

Jaiswal, Dr. Sanjay

Jardosh, Shrimati Darshana Vikram

Jat, Prof. Sanwar Lal

Jaunapuria, Shri Sukhbir Singh

Jayavardhan, Dr. J.

Jigajinagi, Shri Ramesh

Joshi, Dr. Murli Manohar

Joshi, Shri Pralhad

Jyoti, Sadhvi Niranjan

Kachhadia, Shri Naranbhai

Kaiser, Choudhary Mehboob Ali

Kamaraj, Dr. K.

Karandlaje, Kumari Shobha

Kashyap, Shri Virender

Kaswan, Shri Rahul

Kataria, Shri Rattan Lal

Kateel, Shri Nalin Kumar

Katheria, Dr. Ramshankar

Kaushik, Shri Ramesh Chander

Khadse, Shrimati Rakshatai

Khanduri AVSM, Maj. Gen. (Retd.) B.C.

Khanna, Shri Vinod

Kher, Shrimati Kirron

Khuba, Shri Bhagwanth

Kinjarapu, Shri Ram Mohan Naidu

Kishore, Shri Jugal

Kishore, Shri Kaushal

Koli, Shri Bahadur Singh

Koshyari, Shri Bhagat Singh

Kristappa, Shri N.

Kulaste, Shri Faggan Singh

Kumar, Dr. Arun

Kumar, Dr. Virendra

Kumar, Kunwar Sarvesh

Kumar, Shri Ashwini

Kumar, Shri Dharmendra

Kumar, Shri K. Ashok

Kumar, Shri P.

Kumar, Shri Shanta

Kundariya, Shri Mohanbhai Kalyanjibhai

Kushawaha, Shri Ravinder

Kushwaha, Shri Upendra

Lakhanpal, Shri Raghav

Lekhi, Shrimati Meenakashi

[@]Maadam, Shrimati Poonamben

Maharaj, Dr. Swami Sakshiji

Mahato, Dr. Banshilal

Mahato, Shri Bidyut Baran

Mahendran, Shri C.

Malviya, Prof. Chintamani

Manjhi, Shri Hari

Marabi, Shri Kamal Bhan Singh

Maragatham, Shrimati K.

[@] Voted through slip.

Marutharajaa, Shri R. P.

Maurya, Shri Keshav Prasad

Meena, Shri Arjun Lal

Meena, Shri Harish

Meghwal, Shri Arjun Ram

Mishra, Shri Anoop

Mishra, Shri Bhairon Prasad

Mishra, Shri Daddan

Mishra, Shri Janardan

Mishra, Shri Kalraj

Mohan, Shri M. Murli

Mohan, Shri P.C.

Munda, Shri Karia

Nagar, Shri Rodmal

Nagarajan, Shri P.

Narasimham, Shri Thota

Nath, Shri Chand

Natterjee, Shri J.J.T.

Nete, Shri Ashok Mahadeorao

Nishad, Shri Ajay

Nishad, Shri Ram Charitra

Nishank, Dr. Ramesh Pokhriyal

Oram, Shri Jual

Paatle, Shrimati Kamla

Pal, Shri Jagdambika

Pandey, Dr. Mahendra Nath

Pandey, Shri Hari Om

Pandey, Shri Rajesh

Pandey, Shri Ravindra Kumar

Panneerselvam, Shri V.

Parasuraman, Shri K.

Parthipan, Shri R.

Paswan, Shri Chhedi

Paswan, Shri Chirag

Paswan, Shri Ram Chandra

Paswan, Shri Ramvilas

Patel, Dr. K. C.

Patel, Shri Devji M.

Patel, Shri Dilip

Patel, Shri Lalubhai Babubhai

Patel, Shri Natubhai Gomanbhai

Patel, Shri Prahlad Singh

Patel, Shri Subhash

Patel, Shrimaiti Anupriya

Patel, Shrimati Jayshreeben

Pathak, Shrimati Riti

Patil, Shri A.T. Nana

Patil, Shri C. R.

Patil, Shri Kapil Moreshwar

Patil, Shri Sanjay Kaka

Patole, Shri Nana

Phule, Sadhvi Savitri Bai

Prabakaran, Shri K. R. P.

Prasad, Dr. Bhagirath

Pratap, Shri Krishan

Radhakrishnan, Shri Pon

Radhakrishnan, Shri R.

Radhakrishnan, Shri T.

Rai, Shri Nityanand

Raj, Dr. Udit

@Raj, Shrimati Krishna

Raajhaa, Shri A. Anwhar

Rajbhar, Shri Harinarayan

@Rajendran, Shri S.

Rajoria, Dr. Manoj

Rajput, Shri Mukesh

Raju, Shri Ashok Gajapathi

Raju, Shri Gokaraju Ganga

Ram, Shri Janak

Ram, Shri Vishnu Dayal

Ramachandran, Shri K. N.

Rao, Shri Konakalla Narayana

Rao (Avanthi), Shri Muthamsetti Srinivasa

Rao, Shri Rayapati Sambasiva

Rathod, Shri D.S.

Rathore, Col. Rajyavardhan

Rathore, Shri Hariom Singh

Rathwa, Shri Ramsinh

Raval, Shri Paresh

Rawat, Shrimati Priyanka Singh

Ray, Shri Bishnu Pada

Ray, Shri Ravindra Kumar

Reddy, Shri Ch. Malla

Reddy, Shri J.C. Divakar

Reddy, Shri P.V. Midhun

Rijiju, Shri Kiren

@ Voted through slip.

Rudy, Shri Rajiv Pratap

@Sahu, Shri Chandulal

Sahu, Shri Lakhan Lal

@Sai, Shri Vishnu Dev

Saini, Shri Rajkumar

Sampla, Shri Vijay

Sangma, Shri Purno Agitok

Sanjar, Shri Alok

Sarmah, Shri Ram Prasad

Sarswati, Shri Sumedhanand

Sathyabama, Shrimati V.

Sawaikar, Adv. Narendra Keshav

Senguttuvan, Shri B.

Senthilnathan, Shri P. R.

Shah, Shrimati Mala Rajyalakshmi

Sharma, Dr. Mahesh

Sharma, Shri Ram Kumar

Sharma, Shri Ram Swaroop

Shekhawat, Shri Gajendra Singh

Shetty, Shri Gopal

Shirole, Shri Anil

Shyal, Dr. Bhartiben D.

Siddeshwara, Shri G. M.

Sigriwal, Shri Janardan Singh

Simha, Shri Pratap

Singh, Dr. Bhola

Singh, Dr. Jitendra

Singh, Dr. Nepal

@ Voted through slip.

Singh, Dr. Satya Pal

Singh, Dr. Yashwant

Singh, Gen. (Retd) Vijay Kumar

Singh, Kunwar Bharatendra

Singh, Kunwar Haribansh

Singh, Rao Inderjit

Singh, Shri Abhishek

Singh, Shri Bharat

Singh, Shri Bhola

Singh, Shri Brijbhushan Sharan

Singh, Shri Dushyant

Singh, Shri Giriraj

Singh, Shri Hukum

Singh, Shri Kirti Vardhan

Singh, Shri Lallu

Singh, Shri Nagendra

[@]Singh, Shri Pashupati Nath

Singh, Shri R. K.

Singh, Shri Rajnath

Singh (Raju Bhaiya), Shri Rajveer

Singh, Shri Rakesh

Singh, Shri Satyapal

Singh, Shri Sunil Kumar

Singh, Shri Sushil Kumar

Singh, Shri Uday Pratap

Singh, Shri Virendra

Sinha, Shri Jayant

Sinha, Shri Manoj

[@] Voted through slip.

Solanki, Dr. Kirit P.

Somaiya, Dr. Kirit

Sonkar, Shri Vinod Kumar

Sonker, Shrimati Neelam

Sonowal, Shri Sarbananda

Srinivas, Shri Kesineni

Siriram, Shri Malyadri.

Sriramulu, Shri B.

Sundaram, Shri P. R.

Swaraj, Shrimati Sushma

Tadas, Shri Ramdas C.

Tamta, Shri Ajay

Tanwar, Shri Kanwar Singh

Tasa, Shri Kamakhya Prasad

Teli, Shri Rameshwar

Teni, Shri Ajay Misra

Thakur, Shri Anurag Singh

Thambidurai, Dr. M.

Tiwari, Shri Manoj

Tripathi, Shri Sharad

Udasi, Shri Shivkumar

Udhayakumar, Shri M.

Usendi, Shri Vikram

Vanaroja, Shrimati R.

Vardhan, Dr. Harsh

Vasanthi, Shrimati M.

Vasava, Shri Parbhubhai Nagarbhai

Venugopal, Dr. P.

Verma, Dr. Anshul

Verma, Shri Bhanu Pratap Singh

Verma, Shri Parvesh Sahib Singh

Verma, Shri Rajesh

Verma, Shrimati Rekha

Vijaya Kumar, Shri S. R.

Wanga, Shri Chintaman Navasha

Yadav, Shri Hukmdeo Narayan

Yadav, Shri Laxmi Narayan

Yadav, Shri Om Prakash

Yadav, Shri Ram Kripal

Yediyurappa, Shri B.S.

ABSTAIN

Adsul, Shri Anandrao

Barne, Shri Shrirang Appa

Chautala, Shri Dushyant

Gaikwad, Prof. Ravindra Vishwanath

Geete, Shri Anant Gangaram

Godse, Shri Hemant Tukaram

Jadhav, Shri Prataprao

Jadhav, Shri Sanjay Haribhau

Khaire, Shri Chandrakant

Kirtikar, Shri Gajanan

Lokhande, Shri Sadashiv

Raut, Shri Vinayak Bhaurao

Rori, Shri Charanjeet Singh

Sawant, Shri Arvind

Shewale, Shri Rahul

Shinde, Dr. Shrikant Eknath

Shivajirao, Shri Adhalrao Patil

Vichare, Shri Rajan

HON. SPEAKER: Subject to correction*, the result of the Division is:

Ayes: 101
Noes: 311
Abstain:18

The motion was negatived.

HON. SPEAKER: Prof. Prem Singh Chandumajra, are you moving your Amendment No. 49 to clause 5?

श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा (आनंदपुर साहिब) : मैडम स्पीकर, मैंने जो अमैन्डमैन्ट दी थी, हमारी पार्टी शिरोमणि अकाली दल के कुछ सुझाव थे, जो किसानों के हित में थे। माननीय मंत्री जी ने उनमें से 95 परसैन्ट स्वीकार कर लिये, मैं उन्हें बधाई भी देता हूं और धन्यवाद भी करता हूं तथा मैं यह उम्मीद भी करता हूं कि जो एकाध रह गया है, जो कंसैन्सज का है, उसकी प्रोटैक्शन हमने आप ही कर ली। हमारे सदस्य यहां जो बोले हैं, उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि किसान की सहमति कि बिना पंजाब में एक इंच जमीन एक्वायर नहीं करने दी जायेगी, इसलिए मैं मंत्री जी को धन्यवाद देते हुए इसे वापस लेता हूं और मैं इसे मूव नहीं कर रहा हूं।

HON. SPEAKER: Now, the question is:

"That Clause 5, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 5, as amended, was added to the Bill.

Clause 6 Amendment of Section 24

HON. SPEAKER: The Minister may now move Amendment No. 57 to clause 6.

Amendment made:

---

* The following Members also recorded/corrected their votes through slips:

Ayes: 101 + Shri A.H. Khan Chowdhury = **102**

Noes: 311 + Sushri Uma Bharti, S/Shri Chhotelal, Ashwini Kumar Choubey, Dharambir, Rajesh Kumar Diwakar, Shrimati Poonamben Maadam, Shrimati Krishna Raj, S/Shri S. Rajendran, Chandulal Sahu, Vishnu Dev Sai, Pashupati Nath Singh = **322**

Abstain: 018

"Page 2, lines 34 and 35, *for* "or in any account maintained for this purpose" *substitute* "or in any designated account maintained for this purpose."

(Shri Chaudhary Birender Singh)

HON. SPEAKER: The question is:

"That Clause 6, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 6, as amended, was added to the Bill.

HON. SPEAKER: The question is:

"That Clause 6, as amended, stand part of the Bill.

The motion was adopted.

Clause 6, as amended, was added to the Bill.

Motion Re: Suspension of Rule 80 (i)

THE MINISTER OF RURAL DEVELOPMENT, MINISTER OF PANCHAYATI RAJ AND MINISTER OF DRINKING WATER AND SANITATION (SHRI CHAUDHARY BIRENDER SINGH): I beg to move:

"That this House do suspend clause (i) of rule 80 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha in so far as it requires that an amendment shall be within the scope of the Bill and relevant to the subject matter of the clause to which it relates, in its application to Government amendment No.58 to the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement (Amendment) Bill, 2015 and that this amendment may be allowed to be moved. "

HON. SPEAKER: The question is:

"That this House do suspend clause (i) of rule 80 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha in so far as it requires that an amendment shall be within the scope of the Bill and relevant to the subject matter of the clause to which it relates, in its application to Government amendment No.58 to the Right to Fair

Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement (Amendment) Bill, 2015 and that this amendment may be allowed to be moved. ”

The motion was adopted.

New Clause 6A

Amendment made:

Page 2, *after* line 35, *insert*—

“6A. In the principal Act, in section 31, in sub-section (2), in clause (h), after the words ‘affectd families’, the words ‘including compulsory employment to at least one member of such affected family of a farm labourer’ shall be inserted”. (58)

(Shri Chaudhary Birender Singh)

HON. SPEAKER: Shri Deepender Singh Hooda to move Amendment No.63 to Government Amendment No.58 to New Clause 6A.

SHRI DEEPENDER SINGH HOODA: I would request for the indulgence of the hon. Minister. He has proposed an amendment under Sl. No.58, in the List No. 13 of the amendments. When it says ‘compulsory employment to at least one member of such affected family of farm labourer’ I press for including ‘two per cent compulsory reservation in Government jobs’ to all the people who have lost their land. Private companies though make such provision cannot give jobs. So, for farmers who lose all their land, I would request the Government to consider giving 2 per cent reservation in the Government job both, in the State and Central Government. I beg to move:

“That in the amendment proposed by Shri Birender Singh and printed as Sl.No.58, in List No.13 of amendments,-

after “compulsory employment to at least one member of such affected family of a farm labourer”

insert "a two per cent compulsory reservation in Government jobs to all people whose lands have been so acquired". (63)

HON. SPEAKER: I shall now put Amendment No.63 to Clause 6A, moved by Shri Deepender Singh Hooda, to the vote of the House.

The Amendment was put and negatived.

HON. SPEAKER: The question is:

"That New Clause 6A be added to the Bill."

The motion was adopted.

New clause 6A was added to the Bill.

HON. SPEAKER: The question is:

"That Clause 7 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 7 was added to the Bill.

Motion Re: Suspension of Rule 80 (i)

THE MINISTER OF RURAL DEVELOPMENT, MINISTER OF PANCHAYATI RAJ AND MINISTER OF DRINKING WATER AND SANITATION (SHRI CHAUDHARY BIRENDER SINGH): I beg to move:

"That this House do suspend clause (i) of rule 80 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha in so far as it requires that an amendment shall be within the scope of the Bill and relevant to the subject matter of the clause to which it relates, in its application to Government amendment No.59 to the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement (Amendment) Bill, 2015 and that this amendment may be allowed to be moved. "

HON. SPEAKER: The question is:

"That this House do suspend clause (i) of rule 80 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha in so far as it requires that an amendment shall be within the scope of the Bill and

relevant to the subject matter of the clause to which it relates, in its application to Government amendment No.59 to the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement (Amendment) Bill, 2015 and that this amendment may be allowed to be moved. ”

The motion was adopted.

New Clause 7A

Amendment made:

Page 2, *after* line 37, *insert*—

“Insertion of new section 67A. Hearing to be held by Authority in district or districts to decide grievances.	7A. In the principal Act, after section 67, the following section shall be inserted, namely:-- 67A. The Authority shall, after receiving reference under section 64 and after giving notice of such reference to all parties concerned, hold the hearing in the district where the land acquisition takes place for settlement of the objections raised in the reference… ” (59)	

(Shri Chaudhary Birender Singh)

HON. SPEAKER: The question is:

“That New Clause 7A be added to the Bill.”

The motion was adopted.

New Clause 7A was added to the Bill.

Clause 8 Amendment of Section 46

Amendment made:

> "Page 2, lines 42 to 44, *for* "no court shall take cognizance of such offence except with the previous sanction of the appropriate Government, in the manner provided in section 197 of the Code of Criminal Procedure, 1973.", *substitute* "the court shall take cognizance of such offence provided the procedure laid down in section 197 of the Code of Criminal Procedure, 1973 is followed."
>
> (60)
>
> *(Shri Chaudhary Birender Singh)*

HON. SPEAKER: Shri Tathagata Satpathy – not present.

The question is:

"That Clause 8, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 8, as amended, was added to the Bill.

Clause 9 Insertion of new section 67A

HON. SPEAKER: Prof. Saugata Royji, are you moving amendment No. 6 to Clause 9.

PROF. SAUGATA ROY (DUM DUM): Madam, I am moving my amendment but not pressing.

I beg to move:

"Page 2, line 46,-

for "or for five years, whichever is later,"

substitute "subject to a maximum of six years."."

HON. SPEAKER: I shall now put Amendment No.6 to Clause 9 moved by Prof. Saugata Roy to the vote of the House.

The Amendment was put and negatived.

HON. SPEAKER: Shri P. Karunakaranji, are you moving your Amendment No. 28 to Clause 9?

SHRI P. KARUNAKARAN (KASARGOD): I beg to move:

"Page 2, line 46,-

for "a period specified for setting up of any project or for five years, whichever is later,"

substitute "a period not exceeding two years.". " (28)

Madam, this is a very important amendment. The Government says that a period specified for setting up of any project is for five years and more. It means that the corporates may get five years' time and it is only after five years that we can see whether the land is utilized or not. So, it is really a loss to the Government and also the nation.

HON. SPEAKER: I shall now put Amendment No.28 to Clause 9 moved by Shri P. Karunakaran to the vote of the House.

SHRI P. KARUNAKARAN: Madam, I want Division.

HON. SPEAKER: The Lobbies have already been cleared.

The question is:

"Page 2, line 46,-

for "a period specified for setting up of any project or for five years, whichever is later,"

substitute "a period not exceeding two years."."

The Lok Sabha divided:

DIVISION 11 **AYES** **19.42 hrs.**

@Adhikari, Shri Sisir Kumar
Adhikari, Shri Suvendu
Ahmed, Shri Sultan
Ali, Shri Idris
Antony, Shri Anto
Anwar, Shri Tariq
Baite, Shri Thangso
Banerjee, Shri Abhishek
Banerjee, Shri Kalyan
Banerjee, Shri Prasun
Barman, Shri Bijoy Chandra
Bhonsale, Shri Chh. Udayanraje
Biju, Shri P. K.
Bose, Prof. Sugata
Chandrappa, Shri B. N.
Chaudhury, Shri Jitendra
Chautala, Shri Dushyant
Chavan, Shri Ashok Shankarrao
Chowdhury, Shri A. H. khan
@Chowdhury, Shri Adhir Ranjan
Dastidar, Dr. Kakoli Ghosh
Datta, Shri Sankar Prasad
De(Nag), Dr. Ratna
@Devegowda, Shri H.D.
Engti, Shri Biren Singh
Faizal, Mohammed

@ Voted through slip.

[@]Geetha, Shrimati Kothapalli

George, Adv. Joice

Ghosh, Shrimati Arpita

Gogoi, Shri Gaurav

Gowda, Shri S.P. Muddahanume

Hansdak, Shri Vijay Kumar

Haque, Shri Mohd. Asrarul

Hazra, Dr. Anupam

Hooda, Shri Deepender Singh

Innocent, Shri

Jatua, Shri Choudhury Mohan

Jayadevan, Shri C. N

Karunakaran, Shri P.

Khan, Shri Saumitra

Kharge, Shri Mallikarjun

Kumar, Shri Kaushalendra

Kumar, Shri Santosh

Kumar, Shri Shailesh

Mann, Shri Bhagwant

Meinya, Dr. Thokchom

Moily, Shri M. Veerappa

Mondal, Shrimati Pratima

Mukherjee, Shri Abhijit

Naik, Shri B.V.

Nath, Shri Kamal

Owaisi, Shri Asaduddin

Pala, Shri Vincent H.

Poddar, Shrimati Aparupa

[@] Voted through slip.

Premachandran, Shri N.K.

Rajesh, Shri M. B.

Raju, Shri C.S. Putta

Ramachandran, Shri Mullappally

Ranjan, Shri Rajesh

Ranjan, Shrimati Ranjeet

Reddy, Shri Gutha Sukender

Reddy, Shri Mekapati Raja Mohan

Reddy, Shri P. Srinivasa

Reddy, Shri Y. V. Subba

Renuka, Shrimati Butta

Rori, Shri Charanjeet Singh

[@]Roy, Prof. Saugata

Roy, Shrimati Sandhya

Ruala, Shri C.L.

Sahu, Shri Tamradhwaj

Sampath, Dr. A.

Sanghamita, Dr. Mamtaz

Saren, Dr. Uma

Satav, Shri Rajeev

Scindia, Shri Jyotiraditya M.

Shetty, Shri Raju

Singh, Prof. Sadhu

Singh, Shri Ravneet

@Sinha, Shrimati Renuka

Sule, Shrimati Supriya

Suresh, Shri D.K.

Suresh, Shri Kodikunnil

[@] Voted through slip.

Teacher, Shrimati P.K. Shreemathi

Thakur, Shrimati Mamata

Tharoor, Dr. Shashi

Thomas, Prof. K.V.

Trivedi, Shri Dinesh

Uddin, Shri Tasleem

Varma, Shrimati Dev

Velagapalli, Shri Varaprasad Rao

Venugopal, Shri K. C.

Yadav, Shri Akshay

Yadav, Shri Jai Prakash Narayan

Yadav, Shri Tej Pratap Singh

Yadav, Shrimati Dimple

NOES

Adityanath, Yogi

Advani, Shri L.K.

Ahir, Shri Hansraj Gangaram

Ahlawat, Shrimati Santosh

Ahluwalia, Shri S.S.

Amarappa , Shri Karadi Sanganna

Ananthkumar, Shri

Angadi, Shri Suresh C.

Arunmozhithevan, Shri A.

Azad, Shri Kirti

Babu, Dr. Ravindra

Badal, Shrimati Harsimrat Kaur

Baheria, Shri Subhash Chandra

Bais, Shri Ramesh

Bala, Shrimati Anju

Balyan, Dr. Sanjeev

Bansode, Adv. Sharadkumar Maruti

Bhabhor, Shri Jasvantsinh Sumanbhai

Bhagat, Shri Sudarshan

Bhamre, Dr. Subhash Ramrao

Bharathi Mohan, Shri R.K.

Bharti, Sushri Uma

Bhatt, Shrimati Ranjanben

Bhole, Shri Devendra Singh

Bhuria, Shri Dileep Singh

Bidhuri, Shri Ramesh

Birla, Shri Om

Bohra, Shri Ramcharan

Brahmpura, Shri Ranjit Singh

Chakravarty, Shrimati Bijoya

Chand, Shri Nihal

Chandel, Kunwar Pushpendra Singh

@Chandrakasi, Shri M.

Chandumajra, Shri Prem Singh

Chaudhary, Shri C. R.

Chaudhary, Shri Haribhai

Chaudhary, Shri P.P.

Chaudhary, Shri Pankaj

Chaudhary, Shri Ram Tahal

Chauhan, Shri Devusinh

Chauhan, Shri P. P.

Chhewang, Shri Thupstan

Chhotelal, Shri

Chinnaiyan, Shri S. Selvakumara

@Choubey, Shri Ashwini Kumar

Choudhary, Col. Sonaram

Choudhary, Shri Babulal

Choudhary, Shri Birendra Kumar

Chouhan, Shri Nandkumar Singh

Chudasama, Shri Rajeshbhai

Danve, Shri Raosaheb Patil

Dattatreya, Shri Bandaru

Deka, Shri Ramen

Devi, Shrimati Rama

Devi, Shrimati Veena

Dharambir, Shri

@ Voted through slip.

Dhotre, Shri Sanjay

Dhurve, Shrimati Jyoti

@Diwakar, Shri Rajesh Kumar

Dubey, Shri Nishikant

Dubey, Shri Satish Chandra

Dwivedi, Shri Harishchandra alias Harish

Elumalai, Shri V.

Fatepara, Shri Devjibhai G.

Gaddigoudar, Shri P.C.

Gadkari, Shri Nitin

Gaikwad, Dr. Sunil Baliram

Galla, Shri Jayadev

Gandhi, Shri Dilipkumar Mansukhlal

@Gandhi, Shrimati Maneka Sanjay

Gangwar, Shri Santosh Kumar

Gautam, Shri Satish Kumar

Gavit, Dr. Heena Vijaykumar

Ghubaya, Shri Sher Singh

Giluwa, Shri Laxman

Girri, Shri Maheish

Gohain, Shri Rajen

Gopal, Dr. K.

Gopalakrishnan, Shri C.

Gopalakrishnan, Shri R.

Gowda, Shri D.V. Sadananda

Gupta, Shri Shyama Charan

Gurjar, Shri Krishanpal

Hari, Shri G.

@ Voted through slip.

Haribabu, Dr. Kambhampati

Hegde, Shri Anantkumar

Hemamalini, Shrimati)

Jaiswal, Dr. Sanjay

Jardosh, Shrimati Darshana Vikram

Jat, Prof. Sanwar Lal

Jaunapuria, Shri Sukhbir Singh

Jayavardhan, Dr. J.

Jigajinagi, Shri Ramesh

Joshi, Dr. Murli Manohar

Joshi, Shri Pralhad

Jyoti, Sadhvi Niranjan

Kachhadia, Shri Naranbhai

Kaiser, Choudhary Mehboob Ali

Kamaraj, Dr. K.

Karandlaje, Kumari Shobha

Kashyap, Shri Virender

Kaswan, Shri Rahul

Kataria, Shri Rattan Lal

Kateel, Shri Nalin Kumar

Katheria, Dr. Ramshankar

Kaushik, Shri Ramesh Chander

Khadse, Shrimati Rakshatai

Khanduri AVSM, Maj. Gen. (Retd.) B.C.

Khanna, Shri Vinod

Kher, Shrimati Kirron

Khuba, Shri Bhagwanth

Kinjarapu, Shri Ram Mohan Naidu

Kishore, Shri Jugal

Kishore, Shri Kaushal

Koli, Shri Bahadur Singh

Koshyari, Shri Bhagat Singh

Kristappa, Shri N.

Kulaste, Shri Faggan Singh

Kumar, Dr. Arun

Kumar, Dr. Virendra

Kumar, Kunwar Sarvesh

Kumar, Shri Ashwini

Kumar, Shri Dharmendra

Kumar, Shri K. Ashok

Kumar, Shri P.

[@]Kumar, Shri Shanta

Kundariya, Shri Mohanbhai Kalyanjibhai

Kushawaha, Shri Ravinder

Kushwaha, Shri Upendra

Lakhanpal, Shri Raghav

Lekhi, Shrimati Meenakashi

Maadam, Shrimati Poonamben

Maharaj, Dr. Swami Sakshiji

Mahato, Dr. Banshilal

Mahato, Shri Bidyut Baran

Mahendran, Shri C.

Malviya, Prof. Chintamani

Manjhi, Shri Hari

Marabi, Shri Kamal Bhan Singh

Maragatham, Shrimati K.

Marutharajaa, Shri R. P.

[@] Voted through slip.

Maurya, Shri Keshav Prasad

@Meena, Shri Arjun Lal

Meena, Shri Harish

Meghwal, Shri Arjun Ram

Mishra, Shri Anoop

Mishra, Shri Bhairon Prasad

Mishra, Shri Daddan

Mishra, Shri Janardan

Mishra, Shri Kalraj

Mohan, Shri M. Murli

Mohan, Shri P.C.

Munda, Shri Karia

Nagar, Shri Rodmal

Nagarajan, Shri P.

Naik, Prof. A.S.R.

Narasimham, Shri Thota

Nath, Shri Chand

Natterjee, Shri J.J.T.

Nete, Shri Ashok Mahadeorao

Nishad, Shri Ajay

Nishad, Shri Ram Charitra

Nishank, Dr. Ramesh Pokhriyal

Oram, Shri Jual

Paatle, Shrimati Kamla

@Pal, Shri Jagdambika

Pandey, Dr. Mahendra Nath

Pandey, Shri Hari Om

Pandey, Shri Rajesh

@ Voted through slip.

Pandey, Shri Ravindra Kumar

Panneerselvam, Shri V.

Parasuraman, Shri K.

Parthipan, Shri R.

Paswan, Shri Chhedi

Paswan, Shri Chirag

Paswan, Shri Ram Chandra

Paswan, Shri Ramvilas

Patel, Dr. K. C.

Patel, Shri Devji M.

Patel, Shri Dilip

Patel, Shri Lalubhai Babubhai

Patel, Shri Natubhai Gomanbhai

Patel, Shri Prahlad Singh

Patel, Shri Subhash

Patel, Shrimaiti Anupriya

Patel, Shrimati Jayshreeben

Pathak, Shrimati Riti

Patil, Shri A.T. Nana

Patil, Shri C. R.

Patil, Shri Kapil Moreshwar

Patil, Shri Sanjay Kaka

Patole, Shri Nana

Phule, Sadhvi Savitri Bai

Prabakaran, Shri K. R. P.

Prasad, Dr. Bhagirath

Pratap, Shri Krishan

[@]Radhakrishnan, Shri Pon

Radhakrishnan, Shri T.

Rai, Shri Nityanand

Raj, Dr. Udit

Raj, Shrimati Krishna

Raajhaa, Shri A. Anwhar

Rajbhar, Shri Harinarayan

Rajendran, Shri S.

Rajoria, Dr. Manoj

Rajput, Shri Mukesh

Raju, Shri Ashok Gajapathi

Raju, Shri Gokaraju Ganga

Ram, Shri Janak

Ram, Shri Vishnu Dayal

Ramachandran, Shri K. N.

Rao, Shri Konakalla Narayana

Rao (Avanthi), Shri Muthamsetti Srinivasa

Rao, Shri Rayapati Sambasiva

Rathod, Shri D.S.

Rathore, Col. Rajyavardhan

Rathore, Shri Hariom Singh

Rathwa, Shri Ramsinh

Raval, Shri Paresh

Rawat, Shrimati Priyanka Singh

Ray, Shri Bishnu Pada

Ray, Shri Ravindra Kumar

Reddy, Shri Ch. Malla

Reddy, Shri J.C. Divakar

[@] Voted through slip.

Rijiju, Shri Kiren

Rudy, Shri Rajiv Pratap

@Sahu, Shri Chandulal

Sahu, Shri Lakhan Lal

Sai, Shri Vishnu Dev

Saini, Shri Rajkumar

Sampla, Shri Vijay

Sangma, Shri Purno Agitok

Sanjar, Shri Alok

Sarmah, Shri Ram Prasad

Sarswati, Shri Sumedhanand

Sathyabama, Shrimati V.

Sawaikar, Adv. Narendra Keshav

Senguttuvan, Shri B.

Senthilnathan, Shri P. R.

Shah, Shrimati Mala Rajyalakshmi

Sharma, Dr. Mahesh

Sharma, Shri Ram Kumar

Sharma, Shri Ram Swaroop

Shekhawat, Shri Gajendra Singh

Shetty, Shri Gopal

Shirole, Shri Anil

Shyal, Dr. Bhartiben D.

Siddeshwara, Shri G. M.

Sigriwal, Shri Janardan Singh

Simha, Shri Pratap

Singh, Dr. Bhola

Singh, Dr. Jitendra

@ Voted through slip.

Singh, Dr. Nepal

Singh, Dr. Satya Pal

Singh, Dr. Yashwant

Singh, Gen. (Retd) Vijay Kumar

Singh, Kunwar Bharatendra

Singh, Kunwar Haribansh

Singh, Rao Inderjit

Singh, Shri Abhishek

@Singh, Shri Bharat

Singh, Shri Bhola

Singh, Shri Brijbhushan Sharan

Singh, Shri Dushyant

Singh, Shri Giriraj

Singh, Shri Hukum

Singh, Shri Kirti Vardhan

Singh, Shri Kirti Vardhan

Singh, Shri Lallu

Singh, Shri Nagendra

Singh, Shri Pashupati Nath

Singh, Shri R. K.

Singh, Shri Rajnath

Singh (Raju Bhaiya), Shri Rajveer

Singh, Shri Rakesh

Singh, Shri Satyapal

Singh, Shri Sunil Kumar

Singh, Shri Sushil Kumar

Singh, Shri Uday Pratap

Singh, Shri Virendra

@ Voted through slip.

Sinha, Shri Jayant

Sinha, Shri Manoj

Solanki, Dr. Kirit P.

Somaiya, Dr. Kirit

Sonkar, Shri Vinod Kumar

@Sonker, Shrimati Neelam

Sonowal, Shri Sarbananda

Srinivas, Shri Kesineni

Sriramulu, Shri B.

Sundaram, Shri P. R.

@Swaraj, Shrimati Sushma

Tadas, Shri Ramdas C.

Tamta, Shri Ajay

Tanwar, Shri Kanwar Singh

Tasa, Shri Kamakhya Prasad

Teli, Shri Rameshwar

Teni, Shri Ajay Misra

Thakur, Shri Anurag Singh

Thambidurai, Dr. M.

Tiwari, Shri Manoj

Tripathi, Shri Sharad

Udasi, Shri Shivkumar

Udhayakumar, Shri M.

Usendi, Shri Vikram

Vanaroja, Shrimati R.

Vardhan, Dr. Harsh

@Vasanthi, Shrimati M.

Vasava, Shri Parbhubhai Nagarbhai

@ Voted through slip.

Venugopal, Dr. P.

Verma, Dr. Anshul

Verma, Shri Bhanu Pratap Singh

Verma, Shri Parvesh Sahib Singh

Verma, Shri Rajesh

Verma, Shrimati Rekha

Vijaya Kumar, Shri S. R.

Wanga, Shri Chintaman Navasha

Yadav, Shri Hukmdeo Narayan

Yadav, Shri Laxmi Narayan

Yadav, Shri Om Prakash

Yadav, Shri Ram Kripal

Yediyurappa, Shri B.S.

ABSTAIN

Adsul, Shri Anandrao

Barne, Shri Shrirang Appa

Gaikwad, Prof. Ravindra Vishwanath

Gawali, Shrimati Bhavana

Geete, Shri Anant Gangaram

Godse, Shri Hemant Tukaram

Jadhav, Shri Prataprao

Jadhav, Shri Sanjay Haribhau

Khaire, Shri Chandrakant

Kirtikar, Shri Gajanan

Lokhande, Shri Sadashiv

[@]Raut, Shri Vinayak Bhaurao

@Sawant, Shri Arvind

Shewale, Shri Rahul

Shinde, Dr. Shrikant Eknath

Shivajirao, Shri Adhalrao Patil

@Vichare, Shri Rajan

[@] Voted through slip.

HON. SPEAKER: Subject to correction*, the result of the Division is:

Ayes: 89
Noes: 308
Abstain:14

The motion was negatived.

HON. SPEAKER: The question is:

"That Clause 9 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 9 was added to the Bill.

Clause 10 Substitution of new Section for Section 87

HON. SPEAKER: Shri N.K. Premachandran, are you moving Amendment No.16 to Clause 10?

SHRI N.K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): I beg to move:

"Page 3, lines 7 and 8,-

for "1st January, 2015",
substitute "31st December, 2014"." (16)

Madam, my amendment is very simple. I am only seeking a clarification from the hon. Minister. All the other provisions in this Bill have come into effect from 31st December, 2014 except the determination of date of compensation as per this section which would come into effect from 1st January, 2015. What is the

* The following Members also recorded/corrected their votes through slips:

Ayes: 089 + S/Shri Sisir Kumar Adhikari, Adhir Ranjan Chowdhury, H.D. Devegowda, Shrimati Kothapalli Geetha, Prof. Saugat Roy, Shrimati Renuka Sinha = **095**

Noes: 308 + S/Shri M. Chandrakasi, Ashwini Kumar Choubey, Rajesh Kumar Diwakar, Shrimati Maneka Sanjay Gandhi, S/Shri Shanta Kumar, Arjun Lal Meena, jagdambika Pal, Pon Radhakrishnan, Chandulal Sahu, Bharat Singh, Shrimati Neelam Sonker, Shrimati Sushma Swaraj, Shrimati M. Vasanthi = **321**

Abstain: 014 + S/Shri Vinayak Bhaurao Raut, Arvind Sawant, Rajan Vichare **= 017**

reason due to which this is one day after? That is the only clarification I want. If the Government clarifies, I will not move it.

HON. SPEAKER: Mr. Minister, if you do not want to reply, let him move his amendment.

SHRI N.K. PREMACHANDRAN: The Government is not responding, therefore, I have moved my amendment.

HON. SPEAKER: I shall now put Amendment No. 16 moved by Shri N.K. Premachandran to the vote of the House.

The amendment was put and negatived.

HON. SPEAKER: Now, Amendment No. 41 to Clause 10, Shri Mahtab is not there. Now, I will come to Amendment No. 51 to Clause 10. Shri Premachandran, are you moving?

SHRI N.K. PREMACHANDRAN: I am not moving this amendment because already, official amendment has come. So, the pertinence of clause 4 is not there. Hence, I am not moving it.

HON. SPEAKER: The question is:

"That clause 10 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 10 was added to the Bill.

Clause 11 Amendment of Section 105

HON. SPEAKER: Shri Premachandrarn, are you moving Amendment No. 17 to Clause 11?

SHRI N.K. PREMACHANDRAN: I beg to move:

"Page 3, *omit* lines 13 and 14."

I want lines 13 and 14 to be omitted which is in respect of two years.

HON. SPEAKER: I shall now put Amendment No. 17 to Clause 11 moved by Shri Premachandran to the vote of the House.

The Amendment was put and negatived.

HON. SPEAKER: The question is:

"That Clause 11 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 11 was added to the Bill.

Clause 12 was added to the Bill.

Clause 1 Short title and commencement

HON. SPEAKER: Shri Vincent Pala, are you moving Amendment Nos. 1 and 2 to Clause 1?

SHRI VINCENT H. PALA (SHILLONG): I am not moving Amendment Nos. 1 and 2 to Clause 1.

HON. SPEAKER: The question is:

"That Clause 1, the Enacting Formula and the Long Title stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 1, the Enacting Formula and the Long Title were added to the Bill.

HON. SPEAKER: Now the Minister may move that the Bill, as amended, be passed.

… (*Interruptions*)

SHRI CHAUDHARY BIRENDER SINGH: I beg to move:

"That the Bill, as amended, be passed."

HON. SPEAKER: Motion moved:

"That the Bill, as amended, be passed."

SHRI P. KARUNAKARAN (KASARGOD): They have not accepted any of our demands. We strongly protest against the Bill. It is only assisting the corporates.… (*Interruptions*)

SHRI MALLIKARJUN KHARGE (GULBARGA): Madam, they have not accepted even one amendment moved by us. We have already suggested them that it should be referred to the Standing Committee. They are refusing to send it to the Standing Committee. So, we protest and we are walking out.

<u>19.48 hrs</u>

At this stage, Shri Mallikarjun Kharge and some other hon. Members left the House.

… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: The question is:

"That the Bill, as amended, be passed."

The motion was adopted.

HON. SPEAKER: Now, the Lobbies may be opened.

Hon. Members, nine Government amendments have been adopted including two new clauses which have been added to the Bill.

I, therefore, direct that the subsequent clauses may be renumbered, Mr. Minister, accordingly and consequential changes wherever required may be made.

Now the House stands adjourned to meet again at 11 a.m. tomorrow.

<u>19.50 hrs</u>

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock
On Wednesday, March 11, 2014/Phalguna 20, 1936 (Saka).